रामेश्वर प्रसाद और अन्य ।

बनाम

भारत संघ और अन्य

24 जनवरी, 2006

[न्यायमूर्तिगण वाई. के. सभरवाल, सीजे , के. जी. बालाकृष्णन, बी. एन. अग्रवाल, अशोक भान और अरिजीत पासायत]

भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 32/226,356,74 और 163:

अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का उपयोग-घोषणा जारी करना-राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक संतुष्टि-पूर्ववर्ती शर्तें-न्यायिक समीक्षा का दायरा।

अनुच्छेद 356 और 74-कर्तव्य की प्रकृति के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टिघोषणा जारी करने की सिफारिश करने से पहले मंत्रिपरिषद की तथ्य, आयोजित किए गए: राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद को गुमराह किया है। अनुच्छेद 356-शक्ति की प्रकृति और दायरा-आयोजित, एक आपातकालीन शक्ति है लेकिन एक पूर्ण शक्ति नहीं। अनुच्छेद 32,226 और प्रस्तावना-हस्तक्षेप का दायरा। अनुच्छेद 356,163 और 174 (2) (बी)-राज्य विधानसभा का विघटन परीक्षण-आवश्यकता अनुच्छेद 356,174 (2) (बी), 85 (2) (बी) और अनुसूची एक्स-नवनिर्वाचित विधानसभा आधारों का विघटन जिस पर विचार किया जाना है-हंग विधानसभा -

दलों/विधायकों का पुनर्गठन-अनैतिक साधन/खरीद-फरोख्त उस आधार पर विघटन की सिफारिश-न्यायिक समीक्षा का दायरा

ऐसी स्थितियाँ। अनुच्छेद 159,163,164,174 (2) (बी) और 356-चुनाव के बाद नई सरकार की स्थापना-राज्यपाल का कर्तव्य। अनुच्छेद 79,168,245 और 246-संसद-अधिनियमों की प्रकृति-कब विधायी।

अनुच्छेद 356,174 (2) (बी), 85,32 और 226-की असंवैधानिकता अनुच्छेद 356 के तहत राज्य की विधानसभा को भंग करने की घोषणा, राहत को ढालने की शक्ति। अनुच्छेद 157 और 155-राज्यपाल-नियुक्ति के लिए मानदंड सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में दिए गए सुझाव-पालन की आवश्यकता अनुच्छेद 163,153,154 और 159-राज्यपाल-पद की प्रकृति और भूमिका की-शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन-विवेकाधीन शक्तियां-का दायरा। अनुच्छेद 361-राज्यपालों और राष्ट्रपति को दी गई प्रतिरक्षा का दायरा चर्चा की।

अनुच्छेद 327,324,329,174,168,172,83,85 और 79-"उचित संविधान" या विधान सभा का अस्तित्व में आना जब होता है। शब्द और वाक्यांश: " आपातकाल "-का अर्थ भाग XVIII के संदर्भ में संविधान। " विलय "-- का अर्थ अनुच्छेद 4 अनुसूची X के संदर्भ में संविधान। " आवश्यक "का अर्थ विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में संविधान के तहत राज्यपाल।

इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने वैधता को चुनौती दी है

लोक प्रतिनिधित्व की धारा 73 के तहत जारी 4 मार्च, 2005 की चुनाव आयोग की अधिसूचना को बहाल करने का भी अनुरोध किया। निर्वाचित सदस्यों के नामों को अधिसूचित करने वाला अधिनियम, 1951। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि आरोपों में

राज्यपाल की खरीद-फरोख्त की रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत थी और काल्पनिक। तथ्यों को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करना राज्यपाल का दायित्व था।विधायकों से; कि संविधान की योजना के तहत दलबदल या खरीद-फरोख्त के आधार पर विलय और अयोग्यता के संबंध में निर्णय अध्यक्ष में निहित है; और यह कि राज्यपाल 564 कर सकता है।

उस आधार पर कार्य करने का प्रयास नहीं किया है और खुद को इस तरह के अधिकार से अभिभूत किया है। एस. आर. बोम्मई और अन्य मामलों में इस न्यायालय के नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए। वी. भारत संघ और ओआरएस। , [1994] 3 एस. सी. सी. 1, यह तर्क दिया गया कि राज्यपाल की कार्रवाई कानून में दुर्भावनापूर्ण है; तर्कहीन,

किसी भी ठोस सामग्री के बिना निष्कर्ष पर पहुंचे और है केवल इप्स डिक्सिट पर आधारित और इस प्रकार, कानून में टिकाऊ नहीं था। यह तर्क दिया गया था कि न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में इस न्यायालय को विवादित अधिसूचना और इसके परिणामस्वरूप 4 तारीख की चुनाव आयोग की अधिसूचना द्वारा गठित विधान सभा को बहाल किया गया

मार्च, 2005। यह आगे तर्क दिया गया कि निर्वाचित उम्मीदवारों से पहले भी

और संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान की सदस्यता लेते हुए, विधानसभा को भी निलंबित एनिमेशन के तहत नहीं रखा जा सका और 1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 73 के तहत अधिसूचना जारी होने की तारीख को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

राज्यपाल के न होने के सवाल पर दलीलें सुनने के बाद संविधान के अनुच्छेद 361 (1) द्वारा प्रदत्त उन्मुक्ति को देखते हुए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह, इस न्यायालय ने सरकार की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि राज्यपाल को नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है, और बाद में विस्तृत कारणों से पालन किए जाने वाले आदेश में संक्षिप्त कारण देने के लिए।

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले बिंदु इस प्रकार हैं:

(1) क्या अनुच्छेद के तहत विधानसभा को भंग करने की अनुमति है? 17

(2) (ख) संविधान की पहली बैठक हुए बिना? क्या 23 मई, 2005 की उद्घोषणा भंग करती हैबिहार की विधानसभा अवैध और असंवैधानिक है?

(3) यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या यह है? 7 मार्च, 2005 या 4 मार्च को यथास्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक,2005 ?

(4) अनुच्छेद 361 का क्या दायरा है जो राज्य को प्रतिरक्षा प्रदान करता है? राज्यपाल?

विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, 7 तारीख के एक संक्षिप्त आदेश द्वारा अक्टूबर, 2005 की अधिसूचना दिनांक 23 मई, 2005 को 565 मानी गई थी।

असंवैधानिक लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विधानसभा को बहाल करने के लिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश जैसा कि 7 मार्च, 2005 को था, इसे अस्वीकार कर दिया गया था। समर्थन में विस्तृत कारण बताते हुए रिट याचिकाओं का निपटान 7 अक्टूबर, 2005 के अपने आदेश के अनुसार, न्यायालय ने पकड़ना: प्रति बहुमत (वाई. के. सभरवाल, अपने लिए सीजेआई और बी. एन. अग्रवाल और

अशोक भान, जेजे।) ;

1.1 . आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 73 चुनाव का आदेश देती है। आयोग सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद अधिसूचना जारी करेगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण चुनाव आयोग के पास निहित है। अनुच्छेद 327 में प्रावधान है कि संसद किसी राज्य की विधानसभा के चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में सभी मामलों और विधानमंडल के सदन के 'उचित गठन' को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, सिवाय चुनाव याचिका के।

प्राधिकारी और ऐसी रीति से जो उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित की जाए। अनुच्छेद 327 धारा के साथ पढ़ा जाता है।

73 आर. पी. अधिनियम, 1951 में इस बात का प्रावधान है कि सदन या विधानसभा का 'विधिवत गठन' कब किया जाएगा। कोई भी प्रावधान, संवैधानिक या वैधानिक, यह निर्धारित नहीं करता है कि 'उचित संविधान' केवल अनुच्छेद 324,327 और 329 के उद्देश्यों के लिए है और राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करने में

सक्षम बनाने के उद्देश्य से नहीं है। जहाँ तक अनुच्छेद 172 पर आधारित तर्क का संबंध है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि

1951 यह भी कि विधानसभा के मानित संविधान को केवल उक्त अधिनियम या संविधान के अनुच्छेद 324,327 और 329 के विशिष्ट उद्देश्य के लिए सीमित नहीं करता है। संविधान। उक्त खंड में प्रावधान है कि धारा 73 के तहत अधिसूचना जारी करने से राज्य की अवधि प्रभावित नहीं होगी।

विधान सभा, यदि कोई हो, उक्त अधिसूचना जारी होने से तुरंत पहले कार्य कर रही है। वास्तव में, खंड (ख) इस निष्कर्ष को और मजबूत करता है कि विधान सभा की अवधि देय अवधि से अलग है।

उसका संविधान। वर्तमान मामले में यह न्यायालय विधानसभा की अवधि के सवाल से संबंधित नहीं है, बल्कि इस सवाल से संबंधित है कि क्या

विधानसभा का विधिवत गठन किया गया था या नहीं ताकि राज्यपाल अनुच्छेद 174 (2) (बी) के तहत विघटन की शक्ति का प्रयोग कर सकें। भारत का संविधान एक 'उचित संविधान' को अभिनिर्धारित नहीं करता है

भाग XV के तहत चुनाव और भाग VI के अध्याय II और III के तहत कार्यपालिका और राज्य विधानमंडल के प्रयोजनों के लिए चुनाव। भारत के संविधान के प्रवर्तन से पहले मौजूद पूर्व उल्लिखित प्रावधान भी आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 73 के तहत विधानसभा के मानित गठन के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं रखते हैं। अनुच्छेद 274 (2) (बी) के तहत विघटन की शक्ति। [609 - सी-एच; 610-ए, बी]

1.2 . सभा, सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, विधिवत माना जाता है धारा 73 के तहत अधिसूचना जारी करने पर गठित किया गया और इसकी अवधि इसके नियत संविधान से अलग है। व्याख्या जो हो सकती है

संवैधानिक टूटने की स्थिति से बचा जाना चाहिए, जब तक कि प्रावधान इतने स्पष्ट न हों कि किसी अन्य व्याख्या की आवश्यकता न हो। [611 - ए-बी]

1.3 . किसी भी विधानसभा का गठन केवल धारा 73 के तहत किया जा सकता है। आर. पी. अधिनियम, 1951 और संविधान के अनुच्छेद 188 की आवश्यकता से पता चलता है कि विधानसभा अपनी पहली बैठक से पहले ही अस्तित्व में आ जाती है।

शुरू होता है। [611 - सी-डी]

2002 का विशेष संदर्भ संख्या 1 (गुजरात विधानसभा चुनाव मामला) (2002) 8 एस. सी. सी. 237, पर भरोसा किया। के. के. अबू बनाम भारत संघ और ओआरएस।, आकाशवाणी (1965) केरल 229, अनुमोदित। उदय नारायण सिन्हा बनाम। यू. पी. और अन्य राज्य।, आकाशवाणी [1987] सभी। 203 , अस्वीकृत।

2.1 . 23 मई, 2005 की घोषणा असंवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत विधानसभा को भंग किया जा सकता है। इस संतुष्टि पर आदेश दिया जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार को संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा इस तरह की संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। 567 तक इसकी अनुमति है।

राज्यपाल से रिपोर्ट की प्राप्ति और अन्य सामग्री पर संतोष प्राप्त करना। राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही इस तरह की संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। राष्ट्रपति के पास अन्य प्रासंगिक मामलों में राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति है। अनुच्छेद 356 द्वारा अनुध्यात संतुष्टि तक पहुँचने के लिए सामग्री। द. अभिव्यक्ति या अन्यथा 'व्यापक आयाम का है। [611 - एच; 612-ए, बी]

2.2 . वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है कि संतुष्टि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। केवल राज्यपाल की रिपोर्टों के आधार पर। यह भारत संघ का मामला नहीं है कि उसने राज्यपाल की रिपोर्टों के अलावा किसी अन्य सामग्री पर भरोसा किया है। 1612 - सी, डी. आई.

2.3 . आज प्रचलित एक अस्थिर प्रणाली के आलोक में, यह प्रासंगिक है के कार्य में राज्यपालों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना लोकतांत्रिक ढांचा। राज्यपाल की भूमिका की इस आधार पर काफी आलोचना हुई है कि कुछ राज्यपाल उनसे अपेक्षित निष्पक्षता के गुणों को प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं। [612 - एच; 614-बी]

2.4 . अनुच्छेद 163 (1) में पाई जाने वाली अभिव्यक्ति "आवश्यक" के बारे में कहा गया है - यह दर्शाता है कि राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग केवल तभी कर सकता है जब ऐसा करने की एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह तर्क दिया गया है कि "संविधान द्वारा या उसके तहत" अभिव्यक्ति का अर्थ है कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता संविधान के किसी भी स्पष्ट प्रावधान से या आवश्यक निहितार्थ से उत्पन्न हो सकती है। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ऐसी आवश्यकता संविधान के तहत बनाए गए नियमों और आदेशों से भी उत्पन्न हो सकती है। यह देखते हुए कि राज्यपाल को केंद्र और राज्य के प्रति "दोहरी जिम्मेदारी" निभाने की आवश्यकता है, सरकारिया आयोग ने कुछ विवादास्पद

परिस्थितियों में राज्यपालों की भूमिका का मूल्यांकन करने की मांग की है, जैसे कि प्रमुख की नियुक्ति में।

मंत्री, बहुमत सुनिश्चित करने में, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने में, विधानसभा को भंग करने में, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने में और विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने में। [615 - सी-ई]

2.5 . यह देखा जाता है कि एक दिन एक व्यक्ति उतनी ही सक्रिय राजनीति में होता है चूंकि वह मुख्यमंत्री या मंत्री या पार्टी का पद धारण करता है और लगभग अगले दिन या, किसी भी मामले में, उसके तुरंत बाद, उसी व्यक्ति को दूसरे राज्य में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है।शीतलन अवधि। आम तौर पर, पार्टी 568 से अलगाव की उम्मीद करना मुश्किल है।

संवैधानिक कार्यों को करते हुए ऐसे व्यक्ति से राजनीति राज्यपाल के रूप में। [620 - बी-सी]

2.6 . निर्विवाद रूप से, एक राज्यपाल को संरक्षित करने का कर्तव्य सौंपा जाता है, संविधान और कानूनों की रक्षा करना और उनकी रक्षा करना एक संगत कर्तव्य है और लोकतंत्र को संरक्षित करने का दायित्व और राजनीतिक दलबदल के 'कैंकर' को भारतीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंगों में घुसने की अनुमति नहीं देना। लेकिन उस पर वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, यह न्यायालय यह स्वीकार करने में असमर्थ है कि राज्यपाल ने 27 अप्रैल और 21 मई, 2005 की रिपोर्टों द्वाराउपरोक्त उद्देश्य। प्रासंगिक होने की तो बात ही छोड़िए, राज्यपाल के पास यह मानने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि राजनीतिक व्यवस्था का कोई वैध पुनर्गठन नहीं था। दलों और वहां प्रेरित करके लोकतंत्र का घोर विरूपण किया गया था अनुचित, अवैध, अनैतिक और असंवैधानिक तरीकों से दलबदल। [624 - एच; 625-ए, बी।

2.7 . 27 अप्रैल, 2005 की रिपोर्ट में (1) गंभीर प्रयास का उल्लेख है। विभाजन के लिए दलों को लक्षित करना; (4) उच्च दबाव वाले कदम; (5) जाति, पद, धन आदि जैसे विभिन्न प्रलोभन देना। ; और (6) घोड़े का व्यापार। कर्नाटक और नागालैंड के राज्यपालों द्वारा लगभग इसी तरह की रिपोर्ट भेजी गई थी। जिसके परिणामस्वरूप कर्नाटक और नागालैंड की विधानसभा भंग हो गई, जिसे बोम्मई के मामले में अमान्य कर दिया गया। इसके अलावा, यह तर्क कि केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल, 2005 की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की, कोई प्रासंगिकता नहीं है और इस पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि सवाल यह है कि राज्यपाल ने जिस तरह से बहुत तेजी से और अनुचित जल्दबाजी के साथ कदम उठाया, जिसमें यह पाया

गया कि एक राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करने के करीब हो सकता है और ऐसी स्थिति आ गई थी जहां सरकार बनाने के लिए दावा किया जा सकता है।

सरकार ने 21 मई, 2005 की रिपोर्ट पेश की। इस संदर्भ में राज्यपाल का कहना है कि व्यवस्था को विकृत करके हासिल किए गए बहुमत के आधार पर सरकार स्थापित करने के बजाय, यह बेहतर होगा कि लोगों/मतदाताओं को लोगों से जनादेश प्राप्त करने का एक और अवसर प्रदान किया जाए। इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि इसका उद्देश्य किसी विशेष राजनीतिक दल को दावा करने से रोकना था, न कि चिंता का घोषित उद्देश्य राजनीतिक प्रणाली को विकृत करने की अनुमति नहीं देना था, जैसा कि आग्रह किया गया था। इस तरह का पाठचक्रम पूरी तरह से अवैध और अनियमित है और इसे दुर्भावनापूर्ण के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए। सरकार बनाने के दावे को रोकने के लिए विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कथित रूप से इस आधार पर की गई है कि

प्रलोभन द्वारा प्रणाली की विकृति द्वारा बहुमत प्राप्त किया गया था, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी बिना 569 के ऐसी सामान्य धारणाओं पर आधारित थी।

कोई भी सामग्री जो बनाना काफी आसान है यदि कोई राजनीतिक दल नहीं

पूर्ण बहुमत प्राप्त करना शासन से बाहर रखा जाना है। बिना किसी आधार के कोई भी धारणा नहीं की जा सकती थी कि एक समूह द्वारा नितीश कुमार द्वारा सरकार बनाने के दावे का समर्थन करने का कारण केवल उपरोक्त विकृतियाँ थीं। वह अवस्था नहीं पहुँच पाई थी। इसकी अनुमति नहीं थी।

पहुँचने के लिए। यदि इतना बहुमत प्रस्तुत किया गया होता और राज्यपाल एक वैध राय बनाते कि दावा करने वाली पार्टी सक्षम नहीं होती

राज्य को स्थिर सरकार प्रदान करना, वह एक अलग स्थिति हो सकती है। किसी भी परिस्थिति में, राज्यपाल की कार्रवाई को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है, जब इसका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल को सरकार के गठन का दावा करने से रोकना हो। चुनाव के बाद, हर वास्तविक प्रयास

ऐसा बनाया जाना है जो एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना में मदद करता है, चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल हो। [625 - सी-एच; 626-ए]

2.8 . नैतिकता का सवाल निश्चित रूप से बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है।

बात है। यह कई संवैधानिक विशेषज्ञों, कानूनी दिग्गजों, न्यायविदों और राजनीतिक नेताओं का ध्यान आकर्षित कर रहा है। नैतिकता की अवधारणा भी समय-समय पर जमीनी वास्तविकताओं

और स्थिति की मजबूरी को ध्यान में रखते हुए बदलती रही है, जिसमें एकल पार्टी सरकार के विपरीत गठबंधन शासन के पहलू और प्रासंगिकता शामिल है। एंट। आर्थिक क्षेत्र में भी नैतिकता की अवधारणा सरकार की नीति और प्राथमिकताओं का विषय रही है। सरकार दे सकती है

प्रोत्साहन, जिसे आदर्श रूप से अनैतिक और अनैतिक माना जा सकता है, लेकिन जहां तक सरकार का संबंध है, यह देना आवश्यक हो सकता है

काले धन का पता लगाने के लिए प्रोत्साहन। इस तरह के पहलुओं को उच्च संवैधानिक अधिकारियों द्वारा मामले के आधार पर, मामले के तथ्यों और मामले के व्यक्तिगत सांचे के आधार पर निर्धारित किया जाना मुश्किल हो सकता है। संवैधानिक कार्यकर्ता। इन सभी अभेद्यताओं के साथ, संविधान के आधार पर विधानसभाओं के विघटन पर विचार नहीं करता है

ऐसी अनैतिकताओं की धारणा इस संतुष्टि के निर्माण के लिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें सरकार भारत के संविधान की नहीं हो सकती है। [628 - ए-डी]

2.9 . संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 ने अवधि निर्धारित की

राज्यों पर संघ की प्राथमिकता। यह समझाया गया है कि अनुच्छेद 355 को लागू करने का कारण राज्य और केंद्र सरकारों के कामकाज का स्पष्ट रूप से सीमांकन करना और राज्य के मामलों में संघ द्वारा किसी भी प्रकार के सिद्धांतहीन आक्रमणों को रोकना था। यह महसूस किया गया कि अनुच्छेद 355 और 356 की स्पष्ट भाषा के माध्यम से, संघ संवैधानिक रूप से केवल कुछ 570 के तहत हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होगा।

प्रावधानों में निर्धारित सीमित परिस्थितियाँ। [632 - बी, सी। 2.10 . राजस्थान राज्य के मामले में, एक व्यापक सहमति थी और सात न्यायाधीशों में से पाँच जिन्हें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण या "पूरी तरह से बाहरी या" पर किया गया है।

अप्रासंगिक आधार "। कुछ न्यायाधीशों ने इस नियम को संकीर्ण शब्दों में कहा है और कुछ अन्य ने थोड़ा कम संकीर्ण शब्दों में कहा है, लेकिन एक भी न्यायाधीश ने ऐसा नहीं किया है।

कि घोषणा न्यायिक जांच से मुक्त है। यह याद रखना चाहिए कि उस समय खंड (5) न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित करता था। घोषणा की और फिर भी उन्होंने कहा कि न्यायालय दुर्भावना के आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है। निश्चित रूप से खंड (5) को हटाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

न्यायिक समीक्षा का दायरा बढ़ाया है लेकिन इसका विस्तार किया है। [632 - जी, एच; 633-ए, बी]

2.11 . जब वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच की जाती है

न्यायिक समीक्षा का दायरा जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है जो बोम्मई के मामले में बहुमत की राय के अनुपात निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि विवादित उद्घोषणा को चुनौती सफल होनी चाहिए। बोम्मई के मामले में निर्धारित आदेश द्वारा सरकार के खिलाफ मामला पूरी तरह से कवर किया गया है। प्रलोभन या खरीद-फरोख्त का कोई अनुमान केवल इस कारण से नहीं लगाया जा सकता है कि कुछ विधायकों ने अपने नेता की सार्वजनिक मुद्रा के विरोध में विचार व्यक्त किया और निर्णय लिया कि

किसी अन्य राजनीतिक दल के नेता द्वारा सरकार के गठन का समर्थन करना। अल्पसंख्यक सरकारें अनजान नहीं हैं। यह भी अज्ञात नहीं है

कि राज्यपाल, किसी दी गई परिस्थिति में, सरकार बनाने के दावे को स्वीकार नहीं कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि दावा करने वाला दल या समूह राज्य को एक स्थिर सरकार प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। यह भी अज्ञात है कि धारणाओं के विभिन्न मतभेदों के बावजूद, पार्टी, समूह या विधायक अभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं जिससे पतन हो सकता है।

सरकार के चुनाव का सामना करने के लिए तैयार नहीं होने सहित विभिन्न कारणों से। ये और कई अन्य अभेद्यताओं के परिणामस्वरूप विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक भी एक साथ आ सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि प्रलोभन और खरीद-फरोख्त की धारणा की ओर ले जाए।

[649 - सी-एफ]

2.12 . कर्नाटक के विघटन के मामलों के विपरीत और

नागालैंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं को भंग करने के मामलों पर विचार करते हुए, बोम्मई में यह माना गया कि राज्यपालों की रिपोर्टों से पता चलता है कि राज्य सरकारें आंतरिक अशांति से राज्य के नागरिकों और संपत्ति की रक्षा करने में बुरी तरह विफल रही हैं, यह पाया गया कि राज्यपाल की रिपोर्ट 571

ये प्रासंगिक सामग्री पर आधारित हैं और उचित सत्यापन के बाद इन्हें प्रामाणिक बनाया जाता है। इन निष्कर्षों के आलोक में इन तीनों राज्यों के संबंध में घोषणा की वैधता को सर्वसम्मति से बरकरार रखा गया था।

[649 - जी-एच; 650-ए]

2.13 . यह न्यायालय के लिए, न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में, जांच करने के लिए खुला है।

यह प्रश्न कि क्या राज्यपाल की रिपोर्ट प्रासंगिक सामग्री पर आधारित है या नहीं; क्या इसे प्रामाणिक बनाया गया है या नहीं; और क्या तथ्यों का विधिवत सत्यापन किया गया है या नहीं। इन कारकों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप बहुमत ने कर्नाटक की राज्य विधानसभाओं को भंग करने की घोषणा की।

और नागालैंड अमान्य के रूप में, [659-डी]

2.14 . वर्तमान मामले में, रिपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है

राज्यपाल। प्रासंगिक सामग्री के अभाव में बहुत कम उचित सत्यापन के कारण, राज्यपाल की रिपोर्ट को राज्यपाल का व्यक्तिगत निर्देश माना जाना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत कठोर और चरम कार्रवाई को राज्यपाल के केवल भ्रम, संदेह, सनक और कल्पनाओं पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह न्यायालय मूक दर्शक बने नहीं रह सकता।

संविधान का विध्वंस। यह याद रखना चाहिए कि यह न्यायालय विवेक पर पहरा देने वाला है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, राज्यपाल मुख्य खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन राज्यपाल ने जो कहा है, उसके बारे में जल्दबाजी में इसे एक सुसमाचार सत्य के रूप में स्वीकार करने से पहले मंत्रिपरिषद को राज्यपाल की रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों को सत्यापित करना चाहिए। स्पष्ट रूप से, राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद को गुमराह किया है जिसके कारण मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह दी जा रही है जिससे विवादित घोषणा का मुद्दा सामने आया है। [659 - एफ-एच; 660-ए]

2.15 . वर्तमान मामले में, बोम्मई के मामले की तरह, कोई सामग्री नहीं है

राज्यपाल के उपदेश को छोड़कर जो कुछ भी हो। ऐसी कार्रवाई जिसके परिणामस्वरूप किसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने का दावा करने से रोका जा सके

यह निष्कर्ष कि सरकार बनाने का दावा करने वाला बहुमत राज्य को स्थिर सरकार प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन यह कहना पूरी तरह से अलग बात है कि उन्होंने अवैध तरीकों से बहुमत हासिल किया है। और इसलिए, सरकार बनाने के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बाद के मामले में, मामले को लोगों के विवेक और इच्छा पर छोड़ना पड़ सकता है, या तो उसी सदन में जिसे विपक्ष द्वारा लिया जा रहा है या चुनाव में लोगों द्वारा

निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जा सकता है। यदि आप अत्यधिक ठोस सामग्री रखते हैं, तो यह संवैधानिक 572 के लिए पूरी तरह से तर्कहीन होगा।

[

2006] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार बनाने के लिए बहुमत द्वारा किए गए दावे को अस्वीकार करने का अधिकार

केवल इस आधार पर कि बहुमत पेशकश द्वारा प्राप्त किया गया है प्रलोभन और रिश्वत जो सौदे की आड़ में हुए हैं

विधान के विघटन की सिफारिश करने की सामान्य आपातकालीन शक्ति विधानसभा निश्चित रूप से सुशासन का सहारा लेने का विषय नहीं है

या बिना किसी प्रामाणिक के बताए गए कारणों से राजनीति की सफाई

सामग्री। ये ऐसे मामले हैं जिन्हें दूसरों के विवेक पर छोड़ देना बेहतर है। जिसमें विपक्ष और मतदाता शामिल हैं। [661 - डी-जी]

2.16 . प्रस्ताव जिसने वापस जाने के बीच एक विकल्प दिया

निर्वाचक मंडल और अनुचित तरीके से प्राप्त बहुमत को स्वीकार करना, केवल पहला ही वास्तविक विकल्प है, स्वीकार करने के योग्य होने के लिए बहुत व्यापक और व्यापक है।

इस तरह के प्रस्ताव को एक प्रासंगिक विचार के रूप में स्वीकार करना अनुच्छेद 356 के तहत असाधारण शक्ति विघटन की बाढ़ का द्वार खोल सकती है।

और इसके दूरगामी खतरनाक और खतरनाक परिणाम हैं। यह भी हो सकता है

चुनाव के बाद के गठबंधनों और पुनर्गठनों को अनैतिक होने के आधार पर अस्वीकार करने के लिए एक हैंडल होना, देश या राज्य को किसी अन्य चुनाव में धकेलना। यह पहलू खंडित फैसलों की स्थिति और गठबंधन सरकारों के गठन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि दो या दो से अधिक दल एक साथ आ जाते हैं, तो इस तरह की अवैधता के आधार पर उनके बहुमत के दावे को अस्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। ये हैं।

राजनीतिक दलों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पहलुओं को बेहतर छोड़ दिया जाता है, जिन्हें निश्चित रूप से अपने लिए स्वस्थ और नैतिक मानक निर्धारित करने चाहिए, लेकिन, किसी भी मामले में, अंतिम निर्णय मतदाताओं और विपक्ष के सदस्यों वाली विधायिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए। [662 - डी।

2.17 . प्रथम दृष्टया बहुमत वाले राजनीतिक दल को अनुमति देनी होगी।

सरकार के साथ बने रहना या सरकार बनाने की अनुमति, जैसा भी मामला हो। दोनों श्रेणियों में, अंततः सदन के पटल पर बहुमत साबित करना होगा। विवाद मूल मुद्दे को भी नजरअंदाज कर देता है। यह है कि प्रथम दृष्टया, बहुमत रखने वाली पार्टी को भी सरकार चलाने से रोका जा सकता है या सरकार बनाने के दावे को इस कथित धारणा पर अस्वीकार कर दिया जा सकता है कि उक्त बहुमत अवैध तरीकों से प्राप्त किया गया था। कथित तौर पर "राजनीतिक गुट" की श्रेणी में आने वाले ऐसे बुनियादी मुद्दों को इस आधार पर बंद करने का कोई सवाल ही नहीं है कि ऐसे कई अभेद्य मुद्दे हैं जिनके लिए कोई न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानक नहीं हैं और इस प्रकार, न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं। [663 - ई-जी] 573

रामेश्वर प्रसाद बनाम. यू. ओ. आई.

2.18 . एक से अधिक कारणों से, यह न्यायालय स्वीकार करने में असमर्थ है

प्रकृति की घोषणा का एक विधायी अधिनियम होने का विवाद। सबसे पहले, यदि तर्क को स्वीकार किया जाता, तो बोम्मई के मामले में कर्नाटक और नागालैंड के मामले में घोषणा को अवैध और अमान्य नहीं माना जाता। दूसरा, बहुमत की राय में इस तर्क को विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था। तर्क यह था कि वर्तमान प्रकृति की घोषणा कानून के स्वरूप को मानती है और इसे केवल उस आधार पर निरस्त किया जा सकता है जिस पर किसी कानून को निरस्त किया जा सकता है। इस तर्क को खारिज करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि संसद का प्रत्येक अधिनियम कानून बनाने के बराबर नहीं है और न ही इसके परिणामस्वरूप कानून बनता है और संसद कई कार्य करती है। अन्य कार्य। ऐसे कार्यों में से एक अनुच्छेद 356 के खंड (3) के तहत घोषणा का अनुमोदन है। इस तरह की मंजूरी को किसी भी तरह की कल्पना से 'कानून' नहीं कहा जा सकता है। इसका कानूनी चरित्र पूरी तरह से अलग है। यह एक संवैधानिक कार्य है, जो अनुच्छेद 356 के खंड (1) के तहत शक्ति के प्रयोग पर एक रोक है। यह खंड (1) के तहत शक्ति का उचित प्रयोग सुनिश्चित करने के हित में परिकल्पित एक सुरक्षा है। यह निश्चित रूप से न तो विधान है और न ही विधायी। [664 - डी-एफ]

2.19 . हालांकि बोम्मई ने न्यायिक समीक्षा का दायरा बढ़ाया है, लेकिन

राजस्थान राज्य के मामले में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार भी, संतुष्टि के अस्तित्व को हमेशा इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह दुर्भावनापूर्ण है या पूरी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक आधारों पर आधारित। इस तथ्य के अलावा कि राजस्थान राज्य के मामले में न्यायिक समीक्षा का संकीर्ण न्यूनतम क्षेत्र अब बोम्मई के मामले में इसके विस्तार को देखते हुए देश का कानून नहीं है, लेकिन वर्तमान मामला जब सीमित न्यायिक समीक्षा लागू करके विचार किया जाता है, तो भी न्यायिक जांच में खड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें संतुष्टि पूरी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक आधार पर आधारित है। इसका मुख्य आधार किसी पार्टी को सरकार बनाने का दावा करने से रोकना है।

[665 - बी-सी]

2.20 . अंततः न्यायिक समीक्षा का दायरा क्या निर्धारित करता है

दिए गए मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ और यही कारण है कि कर्नाटक और नागालैंड के संबंध में घोषणाएँ खराब मानी जाती थीं, न कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से संबंधित। 1668 - एच; 669-ए]

2.21 . दलबदल से संबंधित दसवीं अनुसूची का प्रावधान,

भ्रष्ट आचरण, चुनावी अपराधों और अयोग्यता से संबंधित 1951 के आर. आर. अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधान 574 में सार्वजनिक जीवन की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा उपाय हैं।

लोकतंत्र। लेकिन, जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, इनकी उस स्तर पर कोई प्रासंगिकता नहीं थी जब विधानसभा का विघटन किया गया था। किसी भी सामग्री के अस्तित्व के बिना अनुशंसित। इस धारणा के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि दावा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के

आधार पर नहीं किया जा सकता है और राजनीतिक दलों को तोड़कर हेरफेर पर आधारित हो सकता है। [669 - एफ, जी।

2.22 . इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि शपथ के तहत निर्धारित किया गया है

अनुच्छेद 159 राज्यपाल से अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने और अपनी क्षमता के अनुसार संविधान और कानूनों का संरक्षण, रक्षा और रक्षा करने की अपेक्षा करता है। राज्यपाल, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए या अन्यथा, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो करने के लिए निषिद्ध है। संविधान राज्यपाल को आदेश देता है कि चुनाव के समापन के बाद, चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्त लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। यदि राज्यपाल एक ऐसी स्थिति पैदा करके इसके विपरीत कार्य करता है जिसके द्वारा एक पक्ष को दावा करने से भी रोका जाता है और भंग करने की सिफारिश करता है -

उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एकमात्र अपरिहार्य निष्कर्ष यह निकाला जाना चाहिए कि अधिकार क्षेत्र का प्रयोग पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है। 21 मई, 2005 की राज्यपाल की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि एलजेपी पार्टी के 17-18 विधायक जद (यू) की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब होगा कि जद (यू) इसमें शामिल हो सकता है।

सरकार बनाने का दावा करने की स्थिति। आगे यह धारणा कि उक्त सदस्यों का कदम स्वयं विभिन्न का संकेत था उन्हें प्रलोभन दिया गया है और उस आधार पर एक आकर्षित

यह धारणा कि सरकार बनाने के लिए किया गया दावा संवैधानिक प्रावधानों और उसमें बनाए गए सुरक्षा उपायों को प्रभावित करेगा और लोगों के फैसले को विकृत करेगा, मनमाना होगा। इससे पता चलता है कि जे. डी. यू. को सरकार बनाने का दावा करने से रोकने का तरीका था। उस स्तर पर, ऐसे दृष्टिकोण को दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में, उस स्तर पर उक्त अनुसूची के प्रावधान

कोई प्रासंगिकता नहीं थी। यह राज्यपाल द्वारा संविधान के प्रावधानों के बारे में 'धारणा' या 'धारणा' का मामला नहीं है। यह एक स्पष्ट मामला है जहां किसी राजनीतिक दल द्वारा सरकार के गठन को किसी न किसी तरह रोकने का प्रयास किया गया था-एक ऐसा क्षेत्र जो राज्यपाल के कार्यों, कर्तव्यों और दायित्वों के संबंध में पूरी तरह से निषिद्ध है। इस प्रकार यह पूरी तरह से असंवैधानिक कार्य था। [669 - एच; 670-ए-ई]

2.23 . यह सच है जैसा कि विभिन्न रिपोर्टों में बार-बार कहा गया है और

विभिन्न संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि दलबदल भारतीय लोकतंत्र के लिए अभिशाप रहा है, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि 575

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई.

दलबदल से कानून में अनुमत तरीके से निपटा जाना चाहिए।

[670 - एफ]

2.24 . यदि कोई राजनीतिक दल अन्य राजनीतिक दल के समर्थन से या

अन्य विधायक सरकार बनाने का दावा करते हैं और संतुष्ट करते हैं

एक स्थिर सरकार बनाने के लिए अपने बहुमत के बारे में राज्यपाल, सरकार के गठन से इनकार नहीं कर सकते हैं और बहुमत के दावे को खारिज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका व्यक्तिपरक आकलन है कि बहुमत को अवैध और अनैतिक तरीकों से फंसाया गया था। ऐसी कोई शक्ति निहित नहीं की गई है राज्यपाल। ऐसी शक्ति बहुसंख्यक शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ होगी। राज्यपाल एक निरंकुश राजनीतिक लोकपाल नहीं हैं। यदि ऐसी शक्ति राज्यपाल और/या राष्ट्रपति में निहित है, तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। किसी राज्य द्वारा कुप्रशासन का आधार

बहुमत वाली सरकार अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए उपलब्ध नहीं है। भ्रष्टाचार या इसी तरह की बुराइयों और बुराइयों का इलाज कहीं और है, न कि अनुच्छेद 356 (1) में। इसी तरह, यह माना जाना चाहिए कि दलबदल के लिए दसवीं अनुसूची के तहत शक्ति सदन के अध्यक्ष के पास है, न कि राज्यपाल के पास। दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति न्यायिक प्रकृति की है। राज्यपाल स्वयं उपरोक्त न्यायिक शक्ति ग्रहण नहीं कर सकता है और उस धारणा के आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि दसवीं अनुसूची का उल्लंघन होगा और इसका उपयोग विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करने के कारण के रूप में किया जाएगा।

[670 - जी, एच; 671-ए-डी]

2.25 . राज्यपाल, एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी की आवश्यकता होती है।

ए के सदस्यों की अयोग्यता जैसे विवादों से बाहर रखा जाना। विधान सभा और इसलिए, संविधान में अनुच्छेद 192 (2) जैसे प्रावधान हैं जो राज्यपाल को चुनाव आयोग की राय प्राप्त करने और संवैधानिक योजना में ऐसी राय के अनुसार कार्य करने का प्रावधान करते हैं। जहाँ तक संसद सदस्य का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 103 (2) में इसी तरह का प्रावधान है।

[671 - डी, ई]

S.R.Bommai और ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस। , [1994] 3 एससीसी 1,

पीछा किया।

हरगोविंद पंत बनाम डॉ. रघुकुल तिलक और अन्य। , [1979] 3 एससीसी 458;

किहोतो होलोहन बनाम। ज़चिल्लू और ओआरएस। , [1992] सप. 2 एस. सी. सी. 651; मारू राम बनाम। भारत संघ और ओआरएस। , [1981] 1 एस. सी. सी. 107; केहर सिंह और अन्र। वी. भारत संघ और एएनआर। , [1989] 1 एस. सी. सी. 204; मारू राम बनाम। भारत संघ, [1981] 1 576

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2006] 1 एस सी आर।

एस. सी. सी. 107; पुनः दिल्ली विधि अधिनियम, 1912, अजमेर-मेरवाड़ा (विधियों का विस्तार) अधिनियम, 1947 और भाग सी राज्य (विधि) अधिनियम, 1950] एससीआर 747;

जयंतीलाल अमृत लाल शोधन बनाम। एफ. एन. राणा और अन्य। , [1964] 5 एस. सी. आर. 294; रमेशचंद्र कचारदास पोरवाल और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। ,

| 1981] 2 एससीसी 722; ए. के. रॉय बनाम भारत संघ और अन्य। , [1982] 1 एस. सी. सी. 27; बेरियम केमिकल्स लिमिटेड और एन. आर. वी. कंपनी विधि बोर्ड और अन्य। , [1966]

सपल। एस. सी. आर. 311; वृंदावन नायक बनाम। भारत निर्वाचन आयोग और ए. एन. आर. ,

[1965] 3 एस. सी. आर. 53 और भारत निर्वाचन आयोग और ए. एन. आर. वी. डॉ.

सुब्रमण्यम स्वामी और अन्र। , (1996) 4 एस. सी. सी. 104, संदर्भित।

सिविल सेवा संघ परिषद v. सिविल सेवा मंत्री, [1984]

3 सभी। ई. आर. 935; पुहलहोफर बनाम। हिलिंगडन, लंदन बरो काउंसिल, [1986] 1 सभी। ई. आर. 467; आर. के. गर्ग और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। , [1981] 4 एस. सी. सी. 675 और मुहम्मद शरीफ बनाम। पाकिस्तान संघ, पी. एल. डी. 1988 (एल. ए. एच.) 725, का उल्लेख किया गया है।

केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट (1988)

(अध्याय IV, VI); वी. आर. कृष्ण अय्यर, ए कांस्टीटचूशनल मिसेलनी (दूसरा संस्करण, लखनऊः ईस्टर्न बुक कं., 2003) पी. 44 ; संविधान सभा की बहस (खंड VIII, संशोधित संस्करण): भारत के संविधान का निर्माण-चुनिंदा दस्तावेज (खंड IV, बी. शिव राव (संस्करण), नई दिल्ली। यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कं, 2004) पी। 86 ; पी. वी. राजमन्नार की रिपोर्ट

समिति (1969), केंद्र-राज्य संबंधों पर रिपोर्ट देने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित जांच समिति; श्री एम. सी. की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग (1967) के अध्ययन दल की रिपोर्ट। सीतलवाड़; कर्नाटक सरकार के राज्यपाल के कार्यालय पर श्वेत पत्र (22 सितंबर)। 1983); हार्वर्ड लॉ रिव्यू, Vol.116 (2002-2003); डिज़ाइनिंग फ़ेडरलिज़्म-ए थ्योरी ऑफ़ सेल्फ-सस्टेनेबल फ़ेडरल इंस्टीटचूशन-एक लेख। ; टी. के. थोपः डॉ. अम्बेडकर और संविधान का अनुच्छेद 356, [1993] 4 एस. सी. सी. (जनवरी) 1; संविधान सभा की बहस (खंड IX, संशोधित संस्करण) पीपी. 175-177 , संदर्भित किया गया।

3. लिए गए दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, न्यायालय कर सकता था

विधानसभा के विघटन से पहले की यथास्थिति का आदेश। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के 7 अक्टूबर, 2005 के आदेश के संदर्भ में, ऐसी राहत को अस्वीकार कर दिया गया था। जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए और व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हुए व्यापक जनहित इसके कारण हैं। आक्षेपित के परिणामस्वरूप

घोषणा करते हुए, भारत के चुनाव आयोग ने न केवल 577 के राज्य में होने वाले चार चरणों के चुनाव की तैयारी की थी

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई.

बिहार ने लेकिन बहस के समापन से पहले पहले दो चरणों के संबंध में अधिसूचना भी जारी की थी। इसके अलावा, इन दो चरणों के संबंध में, पहले 7 अक्टूबर, 2005 में नामांकन करने और उनकी जांच करने की अंतिम तिथि भी समाप्त हो गई थी। चुनाव के पहले चरण के संबंध में, अंतिम तिथि भी

नामांकन वापस लेने की अवधि भी समाप्त हो गई और मतदान 18 अक्टूबर, 2005 के लिए निर्धारित किया गया था। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और एक उन्नत चरण में थी। न्यायिक नोटिस इस तथ्य का लिया जा सकता है कि काफी

राशि खर्च की गई होगी; चुनाव की प्रक्रिया में भारी तैयारी की गई होगी और जमीनी कार्य किए गए होंगे और वह भी विचाराधीन राज्य जैसे राज्य में चुनाव के लिए। इन बाद के घटनाक्रमों और विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित संख्या को ध्यान में रखते हुए, राज्य को अनिश्चितता के एक और दौर में नहीं डालना उचित समझा गया। विचित्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, घोषणा की असंवैधानिकता के बावजूद, यथास्थिति को पूर्व निर्देशित नहीं करके और इसके परिणामस्वरूप चल रही चुनाव प्रक्रिया को इस उम्मीद के साथ पूरा करने की अनुमति देकर राहत को ढाला गया कि मतदाता फिर से खंडित निर्णय नहीं दे सकते हैं और एक या एक अन्य राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत दे सकते हैं-भारतीय मतदाता जो अत्यधिक बुद्धिमत्ता रखते हैं और अतीत में ऐसे विभिन्न अवसरों पर इस अवसर पर खड़े हुए हैं। [671 - जी, एच; 672-ए-डी]

4.1 . अनुच्छेद 361 (1) के एक सादे पठन से पता चलता है कि

राष्ट्रपति या राज्यपाल को गुमराह करने और नोटिस जारी करने पर रोक है क्योंकि वे अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। अधिकांश कार्रवाई मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर की जाती है। से व्यक्तिगत प्रतिरक्षा

अनुच्छेद 361 में दी गई जवाबदेहिता उनके कार्यों को दी जाने वाली चुनौती को बाधित नहीं करती है। कानून के तहत, उन कार्यों सहित ऐसी कार्रवाइयों, जिनमें चुनौती दुर्भावना के आरोपों पर आधारित हो सकती है, का भारत संघ या राज्य द्वारा बचाव किया जाना आवश्यक है, जैसा भी मामला हो। यहां तक कि ऐसे मामलों में भी जहां व्यक्तिगत दुर्भावनाओं का आरोप लगाया

जाता है और स्थापित किया जाता है, सरकारों के लिए यह आग्रह करना खुला नहीं होगा कि दी गई छूट के कारण इसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, कार्रवाई का बचाव करने वाले प्रत्यर्थी को या तो अभिलेख पर सामग्री के आधार पर या यहां तक कि उस व्यक्ति का हलफनामा दायर करने के लिए अदालत को संतुष्ट करना है जिसके खिलाफ व्यक्तिगत दुर्भावना का आरोप लगाया गया है।

बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 361 शपथ पत्र दाखिल करने पर रोक नहीं लगाता है यदि कोई स्वयं दाखिल करना चाहता है। बार केवल नोटिस जारी करने या राष्ट्रपति या राज्यपाल को जवाबदेह बनाने की अदालत की शक्ति के खिलाफ है। बार को देखते हुए, न्यायालय राष्ट्रपति या राज्यपाल को न्यायालय की सहायता के लिए शपथ पत्र दाखिल करने का भी निर्देश जारी नहीं कर सकता है। स्वयं के 578 पर एक शपथ पत्र दाखिल करना

[

2006] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शपथपत्र दाखिल करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्देश जारी करने की तुलना में इच्छा एक बात है। अनुच्छेद 361 (1) के तहत व्यक्तिगत प्रतिरक्षा पूरी है और इसलिए राष्ट्रपति या राज्यपाल बनाए जाने का कोई सवाल ही नहीं है।

दुर्भावनापूर्ण आरोपों के संबंध में न्यायालय के प्रति जवाबदेह।

[674 - बी-एफ]

4.2 . कानून की स्थिति यह है कि राज्यपाल को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

प्रतिरक्षा। राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और निष्पादन के लिए या किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है।

उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और निष्पादन में उसके द्वारा किया जाना अभिप्रेत है। तथापि, अनुच्छेद 361 (1) द्वारा प्रदत्त उन्मुक्ति दुर्भावनापूर्ण आधार सहित कार्रवाई की वैधता की जांच करने की न्यायालय की शक्ति को नहीं छीनती है। [676 - एफ, जी]

संघ कार्बाइड निगम, आदि, आदि। भारत संघ, आदि।, [1991]

4 एस. सी. सी. 584; श्री प्रतापसिंह रावजीरू रूने और अन्य। वी. जीवीए एंड ओआरएस के राज्यपाल। आकाशवाणी (1999) बॉम्बे 53; के. ए. मथियालगन और अन्य। वी. तमिलनाडु के राज्यपाल और अन्य। ए. आई. आर. (1973) मद्रास 198; बिमान चंद्र बनाम।

राज्यपाल, पश्चिम बंगाल आकाशवाणी (1952) कलकत्ता 799; (1) करकुरे बनाम। टी. एल. शेवडे एयर (1952) नागपुर 330; राज्य वी। कवास मानेकस्लाव नानावती एयर (1960) बॉम्बे 502 और पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। वी. सल्लेन्द्र नाथ बोस ए. आई. आर. 1964 कलकत्ता 184, संदर्भित।

पुनः में - रिचर्ड निक्सन (1982) 457 यू. एस. 731, संदर्भित।

प्रति के. जी. बालाकृष्णन, जे. (बहुमत से सहमत, सिवाय इसके कि

यह प्रश्न कि क्या बिहार विधानसभा को भंग करने की 23 मई, 2005 की घोषणा अवैध और असंवैधानिक है):

1.1 . न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकता है जब कोई आदेश दिया जाता है।

अनुच्छेद 356 के तहत पारित किए जाने को दुर्भावना के आधार पर या पूरी तरह से बाहरी या अप्रासंगिक आधारों पर अदालत के समक्ष चुनौती दी जाती है और फिर अदालत के पास इसकी जांच करने का अधिकार क्षेत्र होगा। यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 356 के तहत पारित एक घोषणा चरित्र में विधायी है और न्यायिक जांच के दायरे से बाहर है। [683 - ई]

1.2 . एस. आर. बोम्मई के निर्णय से यह समझा जा सकता है कि

बहुमत का विचार था कि जहां तक न्यायिक समीक्षा का दायरा और दायरा बहुत सीमित है जब अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा पर सवाल उठाया जाता है और इसी तरह के मापदंड उस मामले में लागू होंगे जहां एक अधिसूचना 579 है।

रामेश्वर प्रसाद बनाम. यू. क्यू. 1.

राज्य विधानसभा को भंग करने के लिए अनुच्छेद 174 (2) (बी) के तहत पारित किया गया।

यह दलील कि विधानसभा को भंग करने वाली अधिसूचना विधायी प्रकृति की है और इसे केवल विधायी क्षमता के अभाव या संविधान के अधिकार से बाहर के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती।

स्वीकार कर लिया। [690 - सी-ई]

1.3 . संविधान के अनुच्छेद 74 (2) को देखते हुए अदालत नहीं जा सकती है।

यह प्रश्न कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को किस प्रकार की सलाह दी गई थी। राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति निरपेक्ष नहीं है; इसमें नियंत्रण और संतुलन है। यह सच है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति का गंभीर महत्व है और यह कभी-कभी

विधिवत गठित सरकार को बर्खास्त करके और विधिवत गठित विधानसभा को भंग करके राज्य के लोगों की इच्छा को पूर्ववत करना। ऐसी शक्ति के किसी भी दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जाना चाहिए यदि इसका उपयोग दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए या अप्रासंगिक आधारों के आधार पर पूरी तरह से बाहरी कारणों से किया जाता है। न्यायालय निश्चित रूप से राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत सामग्री में जा सकता है जिसके कारण राज्य विधानसभा को भंग करने का निर्णय लिया गया।

[690 - ई-जी]

1.4 . बिहार राज्य को भंग करने की राष्ट्रपति की घोषणा

राज्यपाल द्वारा भेजी गई दो रिपोर्टों के अनुसार विधानसभा जारी की गई थी। यह याद किया जा सकता है कि अनुच्छेद 356 (1) राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा 7 मार्च, 2005 को जारी की गई थी। इसके बाद, 22 अप्रैल, 2005 को राज्यपाल ने एक रिपोर्ट भेजी जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। या तो व्यक्तिगत रूप से या तत्कालीन चुनाव पूर्व संयोजन के साथ या चुनाव के बाद के गठबंधन के साथ, एक लोकप्रिय सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं जिसमें वे एक साधारण व्यक्ति के समर्थन का दावा कर सकते हैं।

243 के सदन में 122 का बहुमत। राज्यपाल ने यह भी संकेत दिया था कि विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के माध्यम से एकत्र की गई कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट हैं कि धन, जाति, पद आदि जैसे विभिन्न प्रलोभन के माध्यम से लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जीतने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बाद, बिहार के राज्यपाल ने एक और रिपोर्ट भेजी और उसके आधार पर, बिहार राज्य विधानसभा को 23 मई, 2005 को भंग कर दिया गया। 21 मई, 2005 की रिपोर्ट में राज्यपाल ने अपनी पिछली रिपोर्ट को दोहराया कि किसी भी पक्ष ने ऐसा नहीं किया था

243 सदस्यीय सदन में 122 के साधारण बहुमत का समर्थन। उस रिपोर्ट में, राज्यपाल ने यह भी कहा था कि एलजेपी विधायक जद (यू) की ओर बढ़ रहे हैं और उन्हें विभिन्न प्रलोभन दिए गए हैं और यह एक खतरनाक विशेषता थी और राज्यपाल भी 580 में से थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2006] आई एस. सी. आर.

राय है कि यह संवैधानिक प्रावधानों और उसमें बनाए गए सुरक्षा उपायों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा था और लोगों के फैसले को विकृत कर रहा था।

| 690 -

एच; 691-ए-डी।

1.5 . यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रिट याचिकाकर्ताओं का कोई मामला नहीं है कि

जद (यू) या किसी अन्य गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया था और उन्होंने सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से संपर्क किया था। इस अदालत के समक्ष यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि जद (यू) या भाजपा के साथ उसका गठबंधन कभी राज्यपाल से यह प्रार्थना करते हुए मिला था कि उन्हें मिल गया था।

सरकार बनाने का अधिकार। यह दलील कि वे सरकार बनाने वाले थे और उस योजना को विफल करने के लिए राज्यपाल ने एक रिपोर्ट भेजी

जिसके तहत उस योजना को विफल करने के लिए विधानसभा को भंग कर दिया गया था, वह बिना किसी आधार के है। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 17 या 18 सदस्य

एलजेपी जद (यू)-भाजपा गठबंधन में शामिल हो गई थी, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं दी गई है कि वे वास्तव में सरकार बनाने के लिए गठबंधन में शामिल हुए थे। याचिकाकर्ताओं में से एक ने एक पत्र प्रस्तुत किया है और वही है

सभी विधायकों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए और उनमें से कुछ के संबंध में, कुछ अन्य ने अपने हस्ताक्षर किए थे। इसलिए, यह कहना गलत है कि राज्यपाल ने राजनीतिक दल के नेतृत्व में सरकार के गठन को रोकने के लिए जल्दबाजी में विधानसभा को भंग करने के लिए कदम उठाए थे

जे डी (यू)। यदि किसी जिम्मेदार राजनीतिक दल के पास कोई मामला था कि उन्होंने बहुमत का समर्थन प्राप्त कर लिया था या बहुमत का समर्थन प्राप्त करने वाले थे या थे

कुछ लोगों के समर्थन से अल्पमत सरकार बनाने की स्थिति में

राजनीतिक दलों और अगर उनकी याचिका को राज्यपाल द्वारा खारिज कर दिया जाता, तो स्थिति पूरी तरह से अलग होती। तत्काल मामले में ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा के लगभग तीन महीने बाद राज्य विधानसभा को भंग करने का आदेश पारित किया गया था

356 (1) . जब ऐसी स्थिति थी, तो एकमात्र संभव तरीका खोज करना था

एक नया चुनाव और यदि यह राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह सत्ता का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग था और विधानसभा का विघटन पूरी तरह से बाहरी या अप्रासंगिक आधारों पर था। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक, मेघालय और नागालैंड के मामलों में, एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार काम कर रही थी और जब यह आरोप लगाया जाता है कि उसने विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया है, तो प्राथमिक कर्तव्य विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करना और विधानसभा में ताकत का परीक्षण करना था। वर्तमान मामले में ऐसी स्थिति उपलब्ध नहीं थी। यह स्पष्ट था कि कोई भी राजनीतिक दल या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था और जब उचित अवधि की प्रतीक्षा के बाद विधानसभा को भंग कर दिया गया था, तो इसे 581 पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई.

इस आधार पर कि राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कुछ खरीद-फरोख्त चल रही है और कुछ विधायक प्रलोभन से जीते जा रहे हैं। ये निश्चित रूप से ऐसे तथ्य हैं जिन पर राज्यपाल को विचार करना चाहिए। यदि किसी भी गलत तरीके से सरकार का गठन किया जाता है, तो इसे लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार नहीं कहा जा सकता है। यदि राज्यपाल को एक उचित आशंका और विश्वसनीय जानकारी मिली है कि राजनीतिक दलों द्वारा बहुमत प्राप्त करने के लिए इस तरह के अनैतिक साधन अपनाए जा रहे हैं, तो वे निश्चित रूप से राष्ट्रपति के ध्यान में लाए जाने वाले मामले हैं और कम से कम वे अप्रासंगिक मामले नहीं हैं। राज्यपाल निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। उनकी रिपोर्ट की मंत्रिपरिषद द्वारा जांच की जाएगी और संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसलिए, यह नहीं कहा

जा सकता है कि बिहार राज्य विधानसभा को भंग करने का निर्णय पूरी तरह से अप्रासंगिक आधारों पर आधारित शक्ति का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग है। [691 - ई-एच; 692-ए-एफआई

एस. आर. बोम्मई और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। , [1994] 3 एस. सी. सी. 1; राज्य

राजस्थान और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। , (1977) 3 एस. सी. सी. 592 में रिपोर्ट किया गया; बेरियम केमिकल्स लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. कंपनी विधि बोर्ड और अन्य। , [1966] पूरक। 3 एस. सी. आर. 311 और एम. ए. राशिद और अन्य। वी. केरल राज्य (1975) 2 एस. सी. आर. 93 पर निर्भर था।

" सिविल सेवा संघ और अन्य की परिषद। वी. सिविल सेवा मंत्री

(1985) एसी 374 जीसीएचक्यू लॉर्ड डिप्लॉक, संदर्भित।

जे. अरिजीत पसायत के अनुसार। (को छोड़कर बहुमत से असहमति

राज्यपाल को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 361 का दायरा, जो बहुमत से सहमत है):

1.1 . कभी-कभी एक शक्ति को कर्तव्य के साथ जोड़ा जाता है। इस प्रकार एक सीमित

प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ न्यायिक समीक्षा हमेशा न्यायालयों के लिए उपलब्ध होती है। बोम्मई के मामले में विस्तार के बाद भी राज्यपालों की कार्रवाई के संबंध में न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश को अन्य प्रशासनिक आदेशों के समान नहीं रखा जा सकता है। जैसा कि बोम्मई के मामले में फैसले के पैरा 376 में देखा गया है कि न्यायिक समीक्षा का दायरा दिए गए मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। ऐसे मामले हो सकते हैं जो न्यायिक पूर्वानुमान को स्वीकार नहीं करते हैं। वे सिद्धांत जो तब लागू होते हैं जब एक प्रशासनिक

चुनौती दी गई कार्रवाई को अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा के संबंध में की गई चुनौतियों के लिए सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि, बोम्मई के मामले में जो स्पष्ट रूप से देखा गया है, उसे देखते हुए अनुच्छेद 356 (1) के तहत घोषणा विधायी नहीं है। [714 - जी, एच; 715-ए] 582

1.2 . विवेक के साथ सौंपे गए व्यक्ति को, कहने के लिए, निर्देश देना चाहिए।

कानून में खुद की संपत्ति। उसे उन मामलों पर ध्यान देना चाहिए जिन पर वह विचार करने के लिए बाध्य है। उसे उन मामलों को अपने विचार से बाहर करना चाहिए जो उस पर विचार करने के लिए अप्रासंगिक हैं। अगर वह उन नियमों का पालन नहीं करता है

उसे वास्तव में अनुचित व्यवहार करने वाला कहा जा सकता है। इसी तरह, कुछ ऐसा हो सकता है जो इतना बेतुका हो कि कोई भी समझदार व्यक्ति कभी सपने में भी नहीं देख सकता कि यह प्राधिकरण की शक्तियों के भीतर है। यह संवैधानिक और प्रशासनिक कानून का एक अलिखित नियम है कि जब भी कोई निर्णय लेने का कार्य किसी वैधानिक संस्था की व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए सौंपा जाता है।

कार्यात्मक रूप से, अप्रासंगिक और दूरस्थ को छोड़कर, केवल प्रासंगिक और निकटवर्ती मामलों में अपने दिमाग को लागू करने का एक अंतर्निहित दायित्व है।

[715 - बी, सी}

1.3 . वेड्सबरी सिद्धांत को अक्सर इस अर्थ में गलत समझा जाता है कि

न्यायालय द्वारा अनुचित माने जाने वाले किसी भी प्रशासनिक निर्णय को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। सही समझ

वेडनसबरी सिद्धांत यह है कि एक निर्णय को वेडनसबरी अर्थों में अनुचित कहा जाएगा यदि (i) यह पूरी तरह से अप्रासंगिक सामग्री या पूरी तरह से अप्रासंगिक विचार पर आधारित है, (ii) इसने एक बहुत ही प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी की है जिसे उसे ध्यान में रखना चाहिए था, या (iii) यह इतना बेतुका है कि कोई भी समझदार व्यक्ति कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकता था। [715 - डी, ई।

1.4 . बिना किसी समर्थन योग्य आधार के दुर्भावनापूर्ण आरोप अंतिम है।

एक हारे हुए वादी का कमजोर प्रयास, अन्यथा यह न्यायिक समीक्षा के दायरे पर एक धुआंधार पर्दा बनाएगा। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके आसपास

इस मामले का भाग्य घूमता है। राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायसंगत है। यह दुर्भावनापूर्ण आधार पर या पूरी तरह से बाहरी या अप्रासंगिक आधारों पर आधारित होने के आधार पर चुनौती देने के लिए खुला होगा। पर्याप्तता या

रिपोर्ट में दर्शाई गई तथ्यात्मक स्थिति की शुद्धता न्यायिक समीक्षा के लिए खुली नहीं है। सामग्री की सच्चाई या शुद्धता पर न्यायालय द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता है और न ही यह सामग्री की पर्याप्तता में जाएगा और यह राष्ट्रपति की राय के स्थान पर अपनी राय भी नहीं लेगा। हस्तक्षेप केवल तभी किया जाता है जब सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला हो या जिसे कभी-कभी सत्ता पर धोखाधड़ी कहा जाता है। न्यायालय शक्ति के दुरुपयोग या दुरुपयोग को हल्के में नहीं लेगा और इस तथ्य के लिए छूट देगा कि निर्णय लेने वाला प्राधिकारी स्थिति का सबसे अच्छा न्यायाधीश है। यदि राज्यपाल ने किसी को दावा करने से रोकने के एकमात्र उद्देश्य से विघटन के लिए अपनी राय बनाई होती तो यह स्पष्ट रूप से अनावश्यक और तर्कहीन होता। यह सवाल कि क्या ऐसा व्यक्ति एक स्थिर सरकार बनाने की स्थिति में होगा, अनिवार्य रूप से व्यक्तिपरक है।

रामेश्वर प्रसाद बनाम. यू. ओ. आई.

राज्यपाल की राय; निश्चित रूप से वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित होगी। द. इसलिए बुनियादी मुद्दा यह है कि क्या राज्यपाल ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाहरी और अप्रासंगिक सामग्रियों पर कार्रवाई की कि स्थिर सरकार की कोई संभावना नहीं थी। [717 - डी, जी]

1.5 . कानून में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त स्थिति यह है कि मतदाताओं में शुद्धता

निर्वाचित प्रतिनिधि की प्रक्रिया और आचरण को अलग नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक आवश्यकताओं से "। लोकतंत्र "और" स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव "अविभाज्य जुड़वां हैं। लगभग एक अविभाज्य नाभि है

डोर उन्हें जोड़ती है। लोकतंत्र में छोटे मतदाता का अत्यधिक महत्व होता है और उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपहरण नहीं किया जा सकता है।

चुनाव। अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने की उनकी स्वतंत्रता एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की नींव है। लेकिन निर्वाचित होने के बाद, यदि निर्वाचित उम्मीदवार निष्पक्षता और शुद्धता

के मार्ग से विचलित हो जाता है और एक हो जाता है " क्रय योग्य वस्तु "वह न केवल मतदाताओं के साथ विश्वासघात करता है, बल्कि

लोकतंत्र की शुद्ध धारा को प्रदूषित करता है। [724 - सी, डी]

1.6 . यह नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता है कि एक दावे को रोकने से

राज्यपाल तर्कहीन रूप से या बाहरी परिसरों में कार्य नहीं करता है। यदि राज्यपाल ने किसी को भी दावा करने से रोकने के उद्देश्य से कार्रवाई की होती तो उनकी कार्रवाई कमजोर होती। का आचरण

राज्यपाल को संदेह हो सकता है और वर्तमान मामले में ऐसा हो सकता है, लेकिन यदि दूषित साधनों को अपनाने के बारे में उनकी राय परखी गई सामग्री द्वारा समर्थित है, तो निश्चित रूप से यह बाहरी या तर्कहीन नहीं हो सकता है। यह सब होगा

यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। यदि राज्यपाल किसी विशेष मामले में बिना परीक्षित या निर्विवाद सामग्री के केवल यह टिप्पणी करता है कि दागी साधन अपनाए जा रहे हैं, तो वह न्यायिक समीक्षा को आकर्षित करेगा। लेकिन इस मामले में कुछ ऐसी सामग्री है जिस पर राज्यपाल ने कार्रवाई की है। यह अंततः वस्तुनिष्ठ सामग्री के आधार पर व्यक्तिपरक संतुष्टि का मामला है। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर एक बात बहुत स्पष्ट है अर्थात कोई दावा नहीं किया गया था और इसके विपरीत रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि क्या पेश किया जा रहा था। याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं रिट याचिकाओं के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों के नंगे अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दस्तावेजों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। { 726 - एफ-एच; 727-ए]

1.7 . मानवाधिकारों के प्रति न्यायिक प्रतिक्रिया को कानूनी तरीके से बाधित नहीं किया जा सकता है।

बाजीगरी। न्याय की सच्चाई के अलावा कोई पसंद नहीं है। तर्कसंगतता, तर्कसंगतता, वैधता के साथ-साथ दार्शनिक रूप से मौलिक अधिकारों के अर्थ को रंग प्रदान करता है। जो नैतिक रूप से गलत है वह राजनीतिक रूप से सही नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने स्वयं अपने दावों को दस्तावेजों पर आधारित किया है जो 584 हैं।

[2006] 1 एस सी आर।

जहाँ तक बहुमत के दावे का संबंध है, वास्तविकता की छाया भी नहीं है। अगर राज्यपाल को लगता कि जो किया जा रहा था वह नैतिक था गलत, इसे राजनीतिक रूप से सही नहीं माना जा सकता है। यह उनकी धारणा है। यह गलत हो सकता है। इसे संविधान द्वारा विशेष रूप से नहीं लिखा जा सकता है।

जहाँ तक उसकी शक्तियों का संबंध है। लेकिन अंततः यह एक धारणा है। गलत होने के बावजूद इसे बाहरी या तर्कहीन नहीं कहा जा सकता है। इसलिए राज्यपाल का आचरण चाहे कितना भी संदिग्ध क्यों न हो, और भले ही यह स्वीकार किया जाए कि उन्होंने जल्दबाजी में काम किया था, लेकिन यह उनकी कार्रवाई को असाधारण कहने का आधार नहीं हो सकता है। ईमानदारी के बारे में संदेह की छाया दुर्भावना के बारे में एक अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाती है। समान धारणाएँ

राज्यपालों द्वारा किए जाने से अराजक परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। मानवीय त्रुटियाँ हो सकती हैं। इसलिए, संबंधित राज्यपाल को सावधानी और सावधानी के साथ सावधानी से कार्य करना होगा और परीक्षण की गई और निर्विवाद सामग्री से अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं; अन्यथा नहीं। [727 - बी-ई]

एस. आर. बोम्मई और अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस।, [1994] 3 एस. सी. सी. 1; राज्य

राजस्थान और ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस।, [1977] 3 एस. सी. सी. 592; ओम कुमार और अन्य। वी. भारत संघ, [2001] 2 एस. सी. सी. 386; भारत संघ और ए. एन. आर. वी. जी. गनयुथम, [1997] 7 एस. सी. सी. 463; क्लैरियंट इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्र। वी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, [2004] 8 एससीसी 524; श्रीमती. शालिनी सोनी और ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस।, [1980] 4 एस. सी. सी. 544; एस. पार्थसारथी बनाम। ए. पी. राज्य (1974) 3 एस. सी. सी. 459 पंजाब राज्य बनाम। वी. के. खन्ना और अन्य।, [2001] 2 एस. सी. सी. 330; बेरियम केमिकल्स लिमिटेड और एन. आर. वी. कंपनी विधि बोर्ड और अन्य।, ए. आई. आर. (1967) एस. सी. 295; किहोतो होलोहन बनाम। ज़चिल्लू और ओआरएस।, (1992) पूरक 2 एस. सी. सी. 651; ज्योति बसु और अन्य। वी. देवी घोषाल और ओआरएस।, [1982] 1 एस. सी. सी. 691; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) और अन्र। वी. भारत संघ और एएनआर।, [2003] 4 एस. सी. सी. 399; भूपिंदर शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, [2003] 8 एस. सी. सी. 551 और बी. आर. कपूर बनाम। तमिलनाडु और अन्र राज्य।, ए. आई. आर. (2001) एस. सी. 3435 पर भरोसा किया गया।

उदय नारायण सिन्हा बनाम। यू. पी. और अन्य राज्य।, आकाशवाणी (1987) इलाहाबाद

293 ; के. के. अबू बनाम भारत संघ, आकाशवाणी (1965) केरल 229; 2002 (2002) की विशेष संदर्भ संख्या 1 8 एस. सी. सी. 237 और ए. के. कौल और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और एएनआर।, [1995] 4 एस. सी. सी. 73, संदर्भित।

वेड्सबरी मामला (1948 (1) के. बी. 223; सिविल सेवा संघ परिषद

वी. सिविल सेवा मंत्री, (1983) 1 एसी 768; आर. वी. लंकाशायर सीसी, एक्स पी हडलस्टन, [1986। 2 ऑल ईआर 941 (सीए)] और फ्रैंकलिन बनाम। नगर और देश योजना मंत्री, [1947] 2 सभी ई. आर. 289 (एच. एल.), संदर्भित।

केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट (1988), पैरा 585

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई.

4 और 8. राज्यपालों की समिति की रिपोर्ट (1971); संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट; संविधान सभा

1.6.1949 (अनुच्छेद 143 पर), 2.6.1949 (अनुच्छेद 153 पर), 3.6.1949 (अनुच्छेद 188,277,278 और 278-ए पर) और 4.8.1949 (अनुच्छेद 188,277 और 278 और 278-ए पर) पर आयोजित बहस, संदर्भित।

वेड: प्रशासनिक कानून (9 वां संस्करण); मैटलैंड: संवैधानिक

इतिहास; डाइसी: संविधान का कानून; 1929 में प्रकाशित लॉर्ड हेवर्ट द्वारा नई निरंकुशता और वाल्टर एफ. मर्फी द्वारा संविधान, संविधानवाद और लोकतंत्र का उल्लेख किया गया।

2.1 . राज्यपाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं।

लोकतांत्रिक व्यवस्था। जब उनकी विश्वसनीयता इन आरोपों के आधार पर दांव पर है कि वह अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहे थे या

सही तरीके से कार्य करता है, यह किसी विशेष राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में चुने गए व्यक्ति पर एक दुखद प्रतिबिंब है। राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति को पद का गौरव बढ़ाना

चाहिए और उन कर्तव्यों और कार्यों से अनजान एक प्रतीकात्मक व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो उससे किए जाने की उम्मीद की जाती है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि अन्य दलों द्वारा उन राज्यपालों पर पक्षपात और दुर्भावना के आरोप लगाए जाते हैं जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंधित या संबंधित थे, और यदि राज्यपाल किसी भी समय सत्तारूढ़ दल के पदाधिकारी थे। केंद्र में जब कोई दूसरा दल सत्ता में आता है तो स्थिति नहीं बदलती है। विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाना सुविधाजनक प्रतीत होता है। सरकारिया आयोग और राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करके इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बचा जा सकता था और किया जा सकता था।

राज्यपालों की नियुक्ति के मामले में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए आयोग। यह पक्षकारों के लिए सुविधाजनक नहीं प्रतीत होता है क्योंकि वे एक विशेष समय पर स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं और जब स्थिति उनके लिए अनुकूल नहीं लगती है तो गाली देना चाहते हैं। यह उन राजनीतिक दलों की नैतिकता पर एक दुखद प्रतिबिंब है जो राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण करने का अवसर नहीं छोड़ते हैं। जल्द से जल्द उपचारात्मक उपाय किए जाने से लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा।

[788 - ई-एच; 789-ए]

2.2 . यह संविधान की कमी नहीं है जो इसके लिए जिम्मेदार है

स्थिति। यह स्पष्ट रूप से उन लोगों के लिए जिम्मेदार है जो योग्यता के अलावा अन्य विचारों पर राज्यपालों का चुनाव करते हैं। यह एक परेशान करने वाली विशेषता है, और अगर मीडिया रिपोर्टों पर विश्वास किया जाए, तो राज भवन तेजी से पार्टी कार्यालयों के विस्तार में बदल रहे हैं और राज्यपाल एक विशेष पार्टी के पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यह 586 के लिए स्वस्थ नहीं है।

2.3 . केंद्र-राज्य संबंधों में प्रमुख भूमिका राज्यपाल की होती है जो

संघ और राज्य के बीच एक सेतु है। संस्थापक पिताओं

जानबूझकर राज्यपाल के पद के लिए चुनाव से बचा जाता था, जैसा कि यू. एस. ए. में भाषाई रूढ़िवाद से कार्यालय को अलग करने के लिए प्रचलित है। राष्ट्रपति को भाग VI, अध्याय II में अनुच्छेद 155 के तहत उन्हें राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। की कार्यकारी शक्ति

राज्य अनुच्छेद 154 द्वारा उसमें निहित है और उसके द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल संविधान और कानून की रक्षा और रक्षा करने की शपथ के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। अतः राज्यपाल के पद का उद्देश्य संविधान के कार्यकरण की संवैधानिक प्रक्रिया की सुरक्षा और निर्वाह सुनिश्चित करना है।

कार्यकारी चुने गए और उन्हें अंपायर की भूमिका दी गई। जब राज्य में संवैधानिक गतिरोध होता तो वह एक मध्यस्थ होते और वह एक निष्पक्ष भूमिका निभाने में सक्षम होते। ऐसा प्रशासनिक तंत्र होगा जिसके माध्यम से राज्य में संवैधानिक संकट का समाधान किया जाएगा। अतः राज्यपाल को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। अपने दोहरे अविभाजित में

राज्य के प्रमुख के रूप में उसे निष्पक्ष रूप से राष्ट्रपति की सहायता करनी चाहिए। संवैधानिक संकट के समय राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख के रूप में उन्हें संयम लाना चाहिए। यह संबंध तब स्पष्ट होता है जब किसी को पता चलता है कि अनुच्छेद 356 को सामान्य रूप से राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया जाएगा। उसे ईमानदारी से और उच्च स्तर के संवैधानिक ज्ञान के साथ काम करना चाहिए।

शपथ के संदर्भ में, राष्ट्रपति को सूचित करें कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और राज्य सरकार को आवश्यक विस्तृत तथ्यात्मक आधार के साथ संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। प्रत्येक उच्च पद के प्रत्येक अधिभोगकर्ता का यह दायित्व है कि वह अपने उच्च पद में उस शक्ति के बारे में लगातार जागरूक रहे जिसका उपयोग जनहित में और केवल सार्वजनिक भलाई के लिए किया जाना है, और इसका उपयोग किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए या केवल उस पद के वर्तमान धारक की व्यक्तिगत स्थिति को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना है। [789 - सी-एच; 790-ए, बी]

2.4 . अनुच्छेद 356, जैसा कि अंत में अपनाया गया है, के कार्यों को सीमित करता है

राज्यपाल राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दें कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। यह निर्णय कि क्या अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा जारी की जा सकती है, राष्ट्रपति के पास है, यानी केंद्र सरकार। महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति "राज्यपाल से

रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा" शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं यदि वह संतुष्ट हैं कि स्थिति के लिए 587 की आवश्यकता है।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई.

ऐसी घोषणा जारी करना। [795 - ए, बी]

2.5 . अनुच्छेद 356 का सहारा लेना राज्यपाल के लिए अंतिम उपाय होना चाहिए।

ढूँढने के लिए। इस संबंध में राज्यपाल की अक्सर आलोचना की जाती है कि वे कभी-कभी केंद्र सरकार के इशारे पर काम करते हैं। यह आलोचना मुख्य रूप से राज्यपालों के सामने आने वाली स्थितियों की सराहना की कमी से उत्पन्न होती है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के परिणामस्वरूप आम तौर पर राष्ट्रपति राज्यपाल को कार्यकारी कार्य सौंप देते हैं जो उनकी मंत्रिपरिषद से संबंधित होते हैं। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे कोई भी राज्यपाल हल्के में स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रपति शासन के तहत वह राष्ट्रपति के पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण के तहत राज्य के प्रशासन के संबंध में कार्य करता है और साथ ही राष्ट्रपति के आदेश के आधार पर उसके साथ कार्य करता है। राज्य के प्रमुख के रूप में, राज्यपाल का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण राज्य का प्रशासन टूट न जाए। उसे समान रूप से इस जिम्मेदारी का ध्यान रखना होगा कि

राज्य में सरकार को हल्के में परेशान या प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। इन्हें सुनिश्चित करने में न केवल राज्यपाल बल्कि राजनीतिक दलों को भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। राजनीतिक दल निर्वाचक मंडल के जनादेश के साथ सत्ता में आते हैं और उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी विधायिका की होती है। संसदीय सरकार के मानदंडों का उनके द्वारा सबसे अच्छा रखरखाव किया जाता है।

[795 - सी-एफआई

2.6 . यह केवल राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में नहीं है कि एक राज्यपाल

अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर सकते हैं। राज्यपाल को राज्य में किसी भी गंभीर आंतरिक गड़बड़ी, या विशेष रूप से बाहरी आक्रमण के अस्तित्व या खतरे की संभावना के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियों में भी राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 356 के अनुसार कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना आवश्यक हो सकता है।

राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में कोई सटीक दिशा-निर्देश निर्धारित करना मुश्किल है। राज्यपाल को प्रत्येक अवसर पर अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कार्य करना होता है, मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र को यथासंभव बनाए रखा जाना चाहिए।

[795

- एफ-एच; 796-ए [

2002 का विशेष संदर्भ संख्या 1, [2002] 8 एस. सी. सी. 237, संदर्भित।

वेड्स इंट्रोडक्शन ऑफ डाइसीज लॉ ऑफ द कांस्टीटच्यूशन (1962) संस्करण।

संदर्भित किया गया।

3. आर. पी. अधिनियम की धारा 73 की वैधता को कोई चुनौती नहीं है।

जो किसी भी तरह से संविधान के किसी भी प्रावधान के खिलाफ नहीं है। कि इस प्रकार, आर. पी. अधिनियम की धारा 73 के संचालन से विधानसभा विधिवत 588 थी।

[

2006] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गठित किया गया। यह रुख कि राज्यपाल सदस्यों को शपथ दिलाने और उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन के लिए सत्र बुलाने के लिए बाध्य था, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है और यह किसी भी संवैधानिक जनादेश द्वारा समर्थित नहीं है। राज्यपाल पर कोई बाध्यता नहीं थी कि

एक सत्र बुलाना या एक मंत्रिमंडल स्थापित करना जब तक कि उस संबंध में पूर्व-आवश्यकताएं पूरी नहीं की गईं। राज्यपाल की रिपोर्टों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि मुख्यमंत्री चुनने या मंत्रिमंडल के गठन के लिए सत्र बुलाना संभव नहीं था। भले ही काल्पनिक रूप से यह माना जाता है कि विघटन अधिसूचनाएं अस्थिर हैं, फिर भी पूर्व स्थिति की बहाली वर्तमान मामले में उचित राहत नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राज्यपाल के समक्ष किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी हिस्सेदारी का दावा नहीं किया गया था। दस्तावेजों ने यह दिखाने के लिए भरोसा किया कि बहुमत में प्रामाणिकता की कमी है और उनमें से कुछ पर हेरफेर की मुहर भी है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुँच गए थे। निर्विवाद रूप से,

चुनाव आयोग ने विस्तृत व्यवस्था की थी। घड़ी को पीछे रखना और आंकड़ों को सीधे पूर्व स्थिति में लाना अनुचित होगा। [798 - ई-एच; 799-ए]

4. एक जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है जहां स्टैंड है

लिया गया कदम उन लोगों द्वारा लिए गए रुख के विपरीत था जो किसी भी कार्रवाई से प्रभावित हैं। ऐसे मामले में जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यही यहां का मामला है। [803 - ई]

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लिखित याचिका (सिविल) सं. 257

2005 .

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

मिलन के. बनर्जी, एजी, गुलाम ई. वाहनवती, एसजी, गोपाल सुब्रमण्यम,

एएसजी, सोली जे. सोराबजी, रंजीत कुमार, पी. पी. राव, एच. एल. अग्रवाल, मनिंदर सिंह, सुश्री प्रतिभा एम. सिंह, प्रीतेश कपूर, अभिनव मुखर्जी, सुनील

फर्नांडिस, ए. के. प्रसाद, सौरभ मिश्रा, सुश्री जसप्रित कौर, सत्यजीत कुमार, सुश्री श्वेता सिंह, रे विक्रम नाथ, सैयद अली अहमद, सैयद तनवीर अहमद, गिरधर उपाध्याय, एस. एस. बंदोपाध्याय, विनीता जी. उपाध्याय, अवधेश कुमार सिंह, राजीव शर्मा, आर. डी. उपाध्याय, सैयद तनवीर अख्तर, आर. डी. उपाध्याय, पी. एस. नरसिम्हा, श्रीधर पोटराजू, अनंगा भट्टाचार्य, अविजीत कुमार लाला, आशुतोष पांडे, बी. के. प्रसाद, आर. एम. शर्मा, सुश्री सुषमा सूरी, नवीन प्रकाश, सुश्री संध्या गोस्वामी, गौरव अग्रवाल, एस. मुराल।

न्यायालय का निर्णय रामेश्वर प्रसाद बनाम द्वारा दिया गया था।

सत्ता ने सदन का विश्वास खो दिया था। वर्तमान मामला अपनी तरह का है जहां विधानसभा की पहली बैठक से पहले भी इसे इस आधार पर भंग करने का आदेश दिया गया है कि इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अवैध तरीकों से बहुमत जुटाना और राज्य में सरकार बनाने का दावा करना और यदि ये प्रयास जारी रहते हैं, तो यह संवैधानिक प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ के बराबर होगा।

एक दूरगामी परिणाम जो उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत विधानसभा को भंग करने का आदेश इस आधार पर दिया जा सकता है कि किसी राजनीतिक दल द्वारा अवैध तरीकों से बहुमत प्राप्त किया गया है। हम सबसे पहले उन परिस्थितियों पर ध्यान देंगे जिनके कारण विवादित अधिसूचना जारी की गई।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

बिहार राज्य के चुनाव को चुनाव आयोग द्वारा 17 दिसंबर, 2004 को अधिसूचित किया गया था। उक्त चुनावों के लिए तीन स्थानों पर मतदान हुआ था

चरण, अर्थात 3 फरवरी, 2005,5 फरवरी, 2005 और 13 फरवरी, 2005। वोटों की गिनती 27 फरवरी, 2005 को हुई थी। उक्त परिणाम

चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा की गई थी। 4 मार्च, 2005 को निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में 'आर. पी. अधिनियम, 1951') की धारा 73 के अनुसरण में अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें पार्टी संबद्धता के साथ सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुने गए सदस्यों के नामों को विधिवत अधिसूचित किया गया था।

बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं और विधानसभा के 122 सदस्यों का पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए (बिहार में) लघु 'एम. एल. ए.'), आवश्यक है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (संक्षेप में 'एन. डी. ए.'), भारतीय जनता पार्टी (के लिए) वाले दलों का एक राजनीतिक गठबंधन

संक्षिप्त में 'भाजपा') और जनता दल (यूनाइटेड) (संक्षिप्त में 'जद (यू)') 92 विधायकों के समर्थन के साथ सबसे बड़ा चुनाव पूर्व संयोजन था। पार्टी-बुद्धिमान ताकत

विधानसभा में निम्नानुसार था:

" (1) _एनडीए ई

92

75

(2) राजद

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

☎ (3) एलजेपी

29

कांग्रेस (1)

10

(4)

सीपीआई (एमएल)

(5)

07

(6)

समाजवादी पार्टी

04

03

(7)

एनसीपी

बहुजन समाज पार्टी

02

(8)

17

निर्दलीयों

(9)

(10) अन्य

09 "

6 मार्च, 2005 की रिपोर्ट राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई थी, जिसमें नवगठित विधानसभा को निलंबित एनिमेशन में रखने की व्यवस्था की गई थी

ई उपस्थित। यह नीचे लिखा है:

" आदरणीय राष्ट्रपति जी,

वर्तमान बिहार विधानसभा समाप्त हो गई है।

6 मार्च, 2005। चुनाव आयोग की अधिसूचना के साथ

नए संविधान के संबंध में हाल के चुनावों का संदर्भ

विधानसभा ने संख्या 308/B.R.-L.A./2005 दिनांक 4 मार्च 2005 के माध्यम से जारी किया

और 464/बिहार-एल. ए./2005, दिनांक 4 मार्च, 2005 संलग्न है।

(संलग्नक-I)

2. सामने आए परिणामों के आधार पर, निम्नलिखित पार्टी है बुद्धिमान स्थिति:

75

1 .

आर. जे. डी

टी.

55

2 .

जे. डी (यू)

:

3 .

बी जे पी।

37

:

कांग (आई)

10

4 .

;

02

5 .

बी एस पी।

:

29

6 .

एलजेपी।

:

03

7 .

सीपीआई.

01

8 .

सीपीआई. (एम)

07

9 .

सीपीआई. (एमएल.)

:

10. एनसीपी.

03

:

04

11. एसपी।

:

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

591

12. स्वतंत्रः

17

243

आर. जे. डी. और उसकी गठबंधन स्थिति इस प्रकार हैः

75

आर. जे. डी

आई.

:

2. कांग. (आई)

10

:

03 (समर्थन पत्र

ई 3. सीपीआई.

:

आर. सी. डी. नहीं)

4 .

सीपीआई. (एम)

01

5 .

एनसीपी.

03

92

एन. डी. ए. गठबंधन की स्थिति इस प्रकार है:

37

बी जे पी।

1 .

जे. डी (यू)

55

2 .

:

92

3. वर्तमान सी. एम., बिहार, श्रीमती. राबड़ी देवी ने मुझसे आईडी1 पर मुलाकात की और अपने मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है और उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा है।

4. एलजेपी के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल दोपहर में मुझसे मिला और उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष श्री राम विलास पासवान द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र (अनुलग्नक II) प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि वे न तो राजद का समर्थन करेंगे और न ही भाजपा का।

सरकार। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम जतान सिन्हा ने भी 28.2.2005 की शाम को मुलाकात की।

5. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल नारायण सिंह ने समर्थकों के साथ मुझसे आईडी1 पर मुलाकात की। उन्होंने एक पत्र (अनुलग्नक III) प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि गठबंधन की संयुक्त ताकत के अलावा

92 (भाजपा और जद (यू) के पास 10 से 12 अन्य निर्दलीयों का समर्थन है। पत्र में राजद को सरकार बनाने की अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया गया है।

6. समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ददन सिंह ने एक पत्र (अनुलग्नक IV) भेजा है जिसमें राजद की सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट का समर्थन नहीं करने के उनके फैसले का संकेत दिया गया है

[2006] 1

एस सी आर।

या सरकार के गठन में एनडीए। वह मुझसे 2.3.2005 पर भी मिले थे। 7. श्री राम नरेश राम, भाकपा के नेता (एमएल-लिब.) , विधानमंडल

पार्टी ने 4 अन्य लोगों के साथ मुझसे मुलाकात की और एक पत्र प्रस्तुत किया (अनुलग्नक)

कि वे सरकार के गठन में किसी भी समूह का समर्थन नहीं करेंगे।

8. लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम विलास पासवान ने 15 अन्य लोगों के साथ मुझसे मुलाकात की और एक और पत्र (अनुलग्नक VI) सौंपा। वे.

उन्होंने अपने पिछले रुख को दोहराया है।

9. राजद ने मुझसे पूर्वाह्न में 5.3.2005 पर मुलाकात की और उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया जो निम्नलिखित लोगों के समर्थन का संकेत देता है।

पार्टियाँ:

कांग (आई)

1 .

10

:

2 .

एनसीपी

03

:

सीपीआई (एम)

3 .

01

;

बीएसपी

4 .

02

:

(एन के रूप में प्रतिलिपि संलग्न करें। VII)

उपरोक्त के साथ राजद के पास केवल 91 होंगे।

उन्होंने आगे दावा किया है कि कुछ निर्दलीय सदस्य राजद का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि, यह खुलासा नहीं किया गया है कि वे कितने निर्दलीय विधायकों से समर्थन की उम्मीद करते हैं और न ही उनके नाम।

भले ही हम पूरे निर्दलीयों को कुल 17 का विस्तार करने के लिए मान लें

राजद गठबंधन को समर्थन, जिसकी संयुक्त ताकत 91 है, कुल 108 होगा, जो अभी भी न्यूनतम आवश्यकता से कम है। 243 के सदन में 122।

10. श्री सुशील कुमार मोदी, सांसद के नेतृत्व में एनडीए के प्रतिनिधिमंडल ने 5.3.2005 की शाम को मुझसे मुलाकात की। उन्होंने आगे कोई पत्र जमा नहीं किया है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि उनके 92 के चुनाव पूर्व गठबंधन के अलावा, 10 अन्य निर्दलीय भी उनका समर्थन करेंगे और उन्होंने आगे कहा कि वे अलग से पत्र जमा करेंगे। यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यह मानते हुए भी कि उनके पास 10 निर्दलीयों का समर्थन है, उनकी ताकत केवल 102 होगी, जो बहुमत से कम है। न्यूनतम आवश्यकता 122।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

593

11. छह निर्दलीय विधायक मुझसे 5.3.2005 पर मिले और एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है।

सरकार और वे दूसरों का समर्थन प्राप्त करने में सक्षम होंगे (अनुलग्नक VIII)। उन्होंने अपने दावे का समर्थन करने वाला कोई प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

12. मैंने कानूनी विशेषज्ञों और मामले के कानूनों से भी परामर्श किया है, विशेष रूप से ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 1918 में रिपोर्ट किए गए मामले में जहां उच्चतम न्यायालय ने रिपोर्ट के पैरा 365 में निष्कर्ष का सारांश दिया है।

प्रासंगिक भाग पैरा 2 है, अर्थात, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर सभी लोगों द्वारा गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

चिंतित हैं। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्यपाल को चयन की प्रक्रिया से गुजरते हुए एक नेता का चयन करना चाहिए जिनके अपने निर्णय में विधानसभा में बहुमत हासिल करने की सबसे अधिक संभावना है। श्री वी. एन. शुक्ला (10 वां संस्करण) द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 पर चर्चा करते हुए लिखी गई पुस्तक "भारत का संविधान" में इस विषय पर चर्चा की गई है जिसमें राज्यपाल द्वारा चयन के तरीके को निम्नलिखित शब्दों में उद्धृत किया गया है:

" सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल को कोई संदेह नहीं होना चाहिए
किसके लिए नियुक्त किया जाना उचित व्यक्ति है; यह नेता है

विधान सभा में बहुमत वाला दल, लेकिन परिस्थितियाँ

यह तब उत्पन्न हो सकता है जब यह संदेह हो कि वह नेता कौन है और
राज्यपाल को चयन में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़ सकता है।

सी. एम. संवैधानिक योजना के तहत जो परिकल्पना करता है कि

एक व्यक्ति जिसे विधानमंडल का विश्वास प्राप्त है
अकेले सी. एम. के रूप में नियुक्त किया जाए।

पैरा 153 में ऊपर निर्दिष्ट बोम्मई के मामले में, एस. सी. ने उस स्थिति के संबंध में कहा है जहाँ, मैं उद्धृत करता हूँ:

" आम चुनाव के बाद कोई राजनीतिक दल या गठबंधन नहीं हुआ

दलों या समूह का पूर्ण बहुमत हासिल करने में सक्षम है

वैकल्पिक रूप से, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है
स्थिर सरकार बनाने में सक्षम है, यह पूरी तरह से मामला होगा

किसी भी राजनीतिक दल की स्थिर बनाने में असमर्थता

बहुसंख्यक सदस्यों का विश्वास हासिल करने वाली सरकार

विधानमंडल से। यह संवैधानिक विफलता का मामला होगा।

मशीनरी। "[2006] 1 एस. सी. आर.

594

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. मैंने सभी संभावनाओं का पता लगाया और ऊपर बताए गए तथ्यों से, मैं हूँ

इस बात से पूरी तरह संतुष्ट कि कोई राजनीतिक दल या दलों या समूहों का गठबंधन
नहीं

विधान सभा में बहुमत के दावे को साबित करने में सक्षम है,

और सभी राजनीतिक दलों के साथ विकल्पों का पता लगाया और

समूहों और निर्दलीयों के विधायक, एक ऐसी स्थिति सामने आई है जिसमें नहीं
ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक दल या समूह सरकार बनाने में सक्षम हैं

सदन में बहुमत प्राप्त करना। इस प्रकार, यह एक पूर्ण मामला है

किसी भी राजनीतिक दल की स्थिर सरकार बनाने में असमर्थता

बहुसंख्यक सदस्यों का विश्वास बढ़ाना। यह एक मामला है
संवैधानिक तंत्र की विफलता।

14. बिहार के राज्यपाल के रूप में मैं एक लोकप्रिय सरकार बनाने में सक्षम नहीं हूं।

बिहार में, चुनाव परिणामों से पैदा हुई स्थिति के कारण

ऊपर बताया गया है।

15. इसलिए, मैं अनुशंसा करता हूं कि वर्तमान नवगठित

सभा को वर्तमान के लिए निलंबित एनिमेशन में रखा जाए, और

भारत के राष्ट्रपति से ऐसी उचित कार्रवाई/निर्णय लेने का अनुरोध किया जाता है,

आवश्यकतानुसार "।

चूँकि कोई भी राजनीतिक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था,

बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 7 मार्च, 2005 को अधिसूचना जारी की गई थी। सभा को निलंबित एनिमेशन में रखा गया था। उसी तारीख की एक अन्य अधिसूचना भी जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण के अधीन, बिहार के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोग की जा सकेंगी।

राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा का उद्देश्य देना था

राजनीतिक पुनर्गठन की प्रक्रिया के माध्यम से राज्य में बहुमत वाली सरकार बनाने की संभावना का पता लगाने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया के लिए समय और स्थान, जैसा कि 21 मार्च, 2005 को राज्य सभा में गृह मंत्री श्री शिवराज वी. पाटिल के भाषण में परिलक्षित होता है, जब बिहार विनियोग (खाते पर वोट) विधेयक, 2005 पर चर्चा की गई थी। गृह मंत्री ने कहा:

" ..... लेकिन, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। हम बहुत ज्यादा नहीं हैं।

बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके खुशी हो रही है। रहने दीजिए।

सदन के किसी भी सदस्य के मन में कोई संदेह नहीं है; हम नहीं हैं

खुश हैं। चुनाव के बाद हमें खुशी होती अगर सरकार होती।

निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा गठित किया गया होगा। ऐसा नहीं था।

संभव है और यही कारण है कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

लेकिन हम रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

595

यह कहने में आनंद नहीं ले सकता कि "देखो हमने यह किया"। हम खुश नहीं हैं।

इसके बारे में। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि राष्ट्रपति शासन जारी न रहे।

लंबे समय तक। यह जितनी जल्दी गायब हो जाए, बिहार के लिए उतना ही अच्छा होगा। लोकतंत्र के लिए और उस व्यवस्था के लिए जिसका हम अपने देश में पालन कर रहे हैं। लेकिन,

इस संबंध में कौन कदम उठाएगा? यह निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।

जिन्हें इस संबंध में कदम उठाने होंगे। राज्यपाल कर सकते हैं और, मैं करूँगा

मैं इस सदन में अनुरोध करना चाहता हूं कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को बात करनी चाहिए एक-दूसरे के लिए और एक ऐसी स्थिति पैदा करें जिसमें यह संभव हो जाए

सरकार बनाने के लिए। भले ही यह अल्पमत की सरकार हो

थोड़ा सा अंतर, कोई समस्या नहीं है। "

गृह मंत्री ने राष्ट्र को एक गंभीर आश्वासन दिया कि

राष्ट्रपति शासन लगाना अस्थायी और क्षणिक था और इसका उद्देश्य था एक लोकप्रिय सरकार बनाने की संभावना का पता लगाना।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, बलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी

कई राजनीतिक दलों और निर्दलीय विधायकों ने लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए बहुमत वाली सरकार प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के संदर्भ में अपनी स्थिति पर फिर से विचार किया और समर्थन की घोषणा की

श्री नितीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए। इस तरह की पहली घोषणा 17 निर्दलीय विधायकों के पूरे समूह द्वारा 8 अप्रैल, 2005 को की गई थी। हस्ताक्षरित घोषणा पत्र इन विधायकों द्वारा मीडिया को जारी किया गया था। के समर्थन से 17 एनडीए का समर्थन आधार 109 निर्दलीय विधायकों तक बढ़ गया। बाद में समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के समर्थन की घोषणा के साथ यह संख्या बढ़कर 115 हो गई।

बिहार के राज्यपाल ने 27 अप्रैल, 2005 को बिहार के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजी।

भारत, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहते हुए कि विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं/नेताओं के साथ बैठक के माध्यम से एकत्र की गई समाचार पत्रों की रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टों और प्राप्त खुफिया रिपोर्टों ने लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर भी विभिन्न तत्वों को धन, जाति, पदों आदि जैसे विभिन्न प्रलोभनों के माध्यम से संपर्क करने की प्रवृत्ति का संकेत दिया, जो एक परेशान करने वाली विशेषता थी। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, स्थिति तेजी से एक ऐसे परिदृश्य की ओर बढ़ रही थी जिसमें यदि इस प्रवृत्ति को तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया तो परिणामी राजनीतिक अस्थिरता निर्वाचित विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रहे विभिन्न राजनीतिक दलों/समूहों द्वारा की जा रही खरीद-फरोख्त को और बढ़ावा देगी। कि लोगों को नए सिरे से चुनाव के माध्यम से अपना जनादेश देने का एक और मौका दिए बिना स्थिति को नियंत्रित करना संभव नहीं होगा। रिपोर्ट को पूरी तरह से नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" आदरणीय राष्ट्रपति जी,

मैं 6 मार्च को अपने डी. ओ. No.33/जी. बी. के लिए एक संदर्भ आमंत्रित करता हूं,

2005 जिसके माध्यम से विधानसभा के परिणामों का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है

चुनाव कराए गए और रखने के लिए एक सिफारिश भी की गई

नवगठित विधानसभा (चुनाव द्वारा गठित) आयोग की अधिसूचना No.308/बी. आर.-एल. ए. / 2005 4 मार्च को,

2005 और 464/बिहार-एल. ए./2005, दिनांक 4 मार्च, 2005)

एनिमेशन को निलंबित करना और उचित निर्देश/निर्णय जारी करना। उसी के आलोक में, राष्ट्रपति एक जारी करने के लिए प्रसन्न थे

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा अधिसूचना NO.G.S.R. 162 (ई), दिनांक 7 मार्च, 2005 और

घोषणा को संसद द्वारा अनुमोदित और अनुमोदित किया गया है।

2. जैसा कि कोई भी पक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या तत्कालीन पूर्व के साथ नहीं था

चुनाव संयोजन या चुनाव के बाद गठबंधन संयोजन एक लोकप्रिय सरकार बनाने का दावा कर सकता है जिसमें वे 243 सदस्यीय सदन में 122 के साधारण बहुमत का दावा कर सकते हैं, मेरे पास उपरोक्त रिपोर्ट को उक्त सिफारिश के साथ भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

3. मुझे यह समझने के लिए दिया गया है कि गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं

जद (यू) और भाजपा राज्य में बहुमत हासिल करने और सरकार बनाने का दावा करने के लिए। जद-यू और भाजपा के संपर्कों ने सूचित किया है कि एलजेपी के विधायकों को विभिन्न तरीकों से जीत लिया गया है और

दूसरों को जीतने का प्रयास किया जा रहा है। जद-यू विभाजन पैदा करने के लिए कांग्रेस पर भी निशाना साध रहा है। जे. डी.-यू. सर्कल में यह महसूस किया जाता है कि यदि एल. जे. पी. विभाजित नहीं होती है तो भी वह समर्थन के साथ सरकार बना सकती है।

निर्दलीय, एन. सी. पी., बी. एस. पी. और एस. पी. के विधायक और मुख्य कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद कांग्रेस के दो-तिहाई विधायक। जद (यू) और भाजपा के विधायक इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि इस महीने के अंत तक या मई के पहले सप्ताह तक जद (यू) सरकार बनाने की स्थिति में होगी। जद-यू/भाजपा के उच्च दबाव वाले कदम राजद के उन विधायकों को भी प्रभावित कर रहे हैं जो अशांत हो गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लालू प्रसाद पर राजद के विधायकों का बहुत दबाव है। यादव को भी

केंद्र में यू. पी. ए. की तर्ज पर कांग्रेस, एल. जे. पी. और अन्य लोगों के समर्थन से बिहार में सरकार बनाना या उन्हें कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहना।

4. संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग ने यह भी देखा है कि निर्वाचित 597 लोगों की बढ़ती अस्थिरता के कारण

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

सरकारों को गैर-सैद्धांतिक और अवसरवादी माना जाता था

समय-समय पर राजनीतिक पुनर्गठन। स्थिरता की एक उचित डिग्री

यह देखा कि राजनीतिक दलों के सदस्यों का संरेखण बदल रहा है इसलिए खुले तौर पर वास्तव में हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जाता है।

संवैधानिक योजना के तहत एक राजनीतिक दल पहले जाता है

इस तरह के कार्यक्रमों के आधार पर चुनाव। की 10 वीं अनुसूची संविधान इस आधार पर पेश किया गया था कि राजनीतिक औचित्य

और नैतिकता की मांग है कि अगर चुनाव के बाद ऐसे व्यक्ति बदल जाते हैं

उसकी संबद्धता, जिसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इस आधार पर

एक पार्टी के प्रति वफादारी एक आदर्श है, जो साझा मान्यताओं पर आधारित है। ए.

विभाजित पार्टी को मतदाता संदेह के साथ देखते हैं। 5. हाल के दिनों में समाचार पत्रों की रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टें एकत्र की गईं

पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं/नेताओं के साथ बैठक के माध्यम से और

मेरे द्वारा प्राप्त खुफिया रिपोर्ट, लाभ की प्रवृत्ति का संकेत देती हैं

पार्टी और पार्टी के बाहर भी विभिन्न माध्यमों से संपर्क किया जा रहा है धन, जाति, पद आदि जैसे प्रलोभन, जो एक परेशान करने वाली विशेषता है।

यह संवैधानिक प्रावधानों और बनाए गए सुरक्षा उपायों को प्रभावित करेगा।

उसमें। इस तरह का कोई भी कदम लोगों के फैसले को विकृत भी कर सकता है क्योंकि

हाल के चुनावों के परिणामों से पता चलता है। अगर इन प्रयासों की अनुमति दी जाती है

जारी रखने के लिए तब यह छेड़छाड़ के बराबर होगा

संवैधानिक प्रावधान। 6. उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान

स्थिति तेजी से एक परिदृश्य की ओर बढ़ रही है जिसमें यदि प्रवृत्ति नहीं है

तुरंत गिरफ्तार किया गया, इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ेगी

विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा घोड़ों के व्यापार को बढ़ावा देना / समूह निर्वाचित विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा न हो

लोगों को दूसरा मौका दिए बिना स्थिति को नियंत्रित करना संभव है

एक नए चुनाव के माध्यम से अपना जनादेश देने का अवसर।

7. मैं इन तथ्यों को लेने के लिए माननीय राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐसी कार्रवाई जो उचित समझी जाए।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) ने राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार का विरोध करने के लिए चुनाव लड़ा था

दल (राजद), जो फिर से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 598 का एक घटक है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2006] 1 एस सी आर।

(यूपीए) केंद्र में। नई विधानसभा में इसके 29 विधायक थे। एलजेपी के नेता श्री राम विलास पासवान ने यह रुख अपनाया था कि वे इसका विरोध कर रहे हैं राजद के साथ-साथ भाजपा के नेतृत्व में एनडीए। एलजेपी के विधायक विद्रोह के मूड में थे। एलजेपी से संबंधित लगभग 22 विधायक या पर एकत्र हुए

21 मई, 2005 के आसपास और उक्त पार्टी के रुख में एक प्रमुख राजनीतिक पुनर्गठन की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। उनके अनुसार, मूल राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा समर्थित विधायी शाखा के 22 एलजेपी सदस्य बाद में अपनी पार्टी का जद (यू) में विलय करने के लिए आम सहमति पर पहुंचे। कि, इसके साथ राजनीतिक ताकतों का पुनःध्रुवीकरण पूरा हो गया था। के अनुसार

बिहार के राज्यपाल जद (यू) के नेतृत्व वाली सरकार ने 21 मई, 2005 को दिल्ली में अपने शिविर कार्यालय से भारत के राष्ट्रपति को एक और रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में यह दोहराया गया कि मीडिया की रिपोर्टों के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी, विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के साथ-साथ खुफिया रिपोर्टों से भी लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर जीत हासिल

करने की प्रवृत्ति का संकेत मिला। उनके विचार में राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि राज्य के हित में वह विधानसभा वांछनीय होगी जिसे निलंबित एनिमेशन में रखा गया है। भंग किया जाए ताकि लोगों/मतदाताओं को उचित समय पर लोगों से जनादेश प्राप्त करने का एक और अवसर प्रदान किया जा सके। 21 मई, 2005 की रिपोर्ट को पूरी तरह से इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है:

" आदरणीय राष्ट्रपति जी,

मैं 27 अप्रैल के अपने डी. ओ. पत्र No.52/जी. बी. का संदर्भ आमंत्रित करता हूं।

2005 जिसके माध्यम से मैंने प्रयासों का विस्तृत विवरण दिया था

कुछ दलों विशेष रूप से जद (यू) और भाजपा द्वारा एक गठबंधन बनाने के लिए

बहुमत और राज्य में सरकार बनाने का दावा करना। मेरे पास था

बताया गया कि एलजेपी से संबंधित लगभग 16-17 विधायकों को लुभाया जा रहा था

विभिन्न तरीकों से ताकि एलजेपी में विभाजन हो सके। ध्यान दें।

इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया गया कि राजद के विधायक भी बन गए थे

जे. डी.-यू. द्वारा उठाए गए उपरोक्त कदमों के आलोक में अशांत।

जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी में विधानसभा चुनाव के बाद यह

वर्ष, कोई भी राजनीतिक दल या तो व्यक्तिगत रूप से या तब के साथ

चुनाव से पहले या चुनाव के बाद गठबंधन 599

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. जे [सभरवाल, सी. जे.]

एक लोकप्रिय सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं क्योंकि वे कर सकते हैं

122 के साधारण बहुमत के समर्थन का दावा नहीं करते. 243 के सदन में

और इसलिए राष्ट्रपति के तहत एक घोषणा जारी करने के लिए प्रसन्न था
संविधान का अनुच्छेद 356 अधिसूचना सं। जीएसआर 162 (ई)

दिनांक 7 मार्च, 2005 और विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था

एनिमेशन।

हाल के दिनों में मीडिया के माध्यम से मुझे जो रिपोर्टें मिली हैं

और विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के माध्यम से भी, साथ ही
खुफिया रिपोर्ट, निर्वाचित प्रतिनिधियों पर जीत की प्रवृत्ति का संकेत देती है

लोगों से। एलजेपी के एक विधायक की भी रिपोर्ट मिली है।
पार्टी के महासचिव कौन हैं जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है और

17-18 अधिक शायद जद-यू की ओर बढ़ रहे हैं जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं।

कि विभिन्न प्रलोभन दिए गए हैं जो बहुत परेशान करने वाले हैं

और खतरनाक विशेषता। अलग गुट द्वारा गठबंधन करने के लिए कोई भी कदम

किसी भी अन्य पक्ष के साथ बहुमत हासिल करने और एक बनाने का दावा करने के
लिए

उसमें बनाए गए सुरक्षा उपाय और लोगों के फैसले को विकृत करते हैं जैसा कि
दिखाया गया है। हाल के
चुनावों के परिणामों से। अगर इन प्रयासों की अनुमति दी जाती है

यह संवैधानिक प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ के बराबर होगा।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं

माना जाता है कि यदि प्रवृत्ति को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो यह हो
सकता है

स्थिति को नियंत्रित करना संभव नहीं है। इसलिए मेरे विचार में एक स्थिति है

राज्य में उत्पन्न हुआ है जिसमें यह हित में वांछनीय होगा
राज्य जिसे विधानसभा ने वर्तमान में निलंबित एनिमेशन में रखा है

भंग कर दिया गया, ताकि लोगों/मतदाताओं को एक प्रदान किया जा सके

उचित समय पर लोगों से जनादेश प्राप्त करने का अधिक अवसर

उचित समय पर निर्णय लिया जाना चाहिए "।

राज्यपाल की रिपोर्ट भारत संघ को 22 तारीख को प्राप्त हुई थी

मई, 2005 और उसी दिन, केंद्रीय मंत्रिमंडल की दोपहर लगभग 1 बजे बैठक हुई और राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार करने का निर्णय लिया और भारत के राष्ट्रपति को फैक्स संदेश भेजा, जो पहले ही मास्को के लिए रवाना हो चुके थे, जिसमें बिहार की विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की गई थी। यह संदेश था

भारत के राष्ट्रपति ने 0152 बजे मास्को में अपने शिविर कार्यालय में उनका स्वागत किया। (आईएसटी)। भारत के राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी और उसी के माध्यम से भेजा फैक्स संदेश जो 0350 बजे प्राप्त हुआ था। (भारतीय समयानुसार) 23 मई, 2005 को। उचित प्रक्रिया के बाद औपचारिक रूप से 1430 बजे अधिसूचना जारी की गई। (आई. एस. टी.) 23 मई, 2005 को बिहार विधानसभा को भंग कर दिया गया जो इन 600 में विवादित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2006] 1 एस सी आर।

रिट याचिकाएँ।

अनुच्छेद के तहत जारी 23 मई, 2005 की चुनौती देने वाली घोषणा

356 बिहार विधान सभा को भंग करने का आदेश देने वाला संविधान,
याचिकाकर्ताओं ने आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 73 के तहत जारी 4 मई, 2005 की चुनाव आयोग की अधिसूचना को बहाल करने का भी अनुरोध किया है।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, भंग करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त

सभा यह है कि राष्ट्रपति का संतोष होना चाहिए कि एक स्थिति है

जिसके अंतर्गत किसी राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। कि यह संतुष्टि ठोस सामग्री पर आधारित होनी चाहिए। विघटन की शक्ति का उपयोग रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है

राज्य में बहुमत वाली सरकार प्रदान करने की संभावना। श्री नितीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को 135 से अधिक विधायकों का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई। राज्यपाल। सरकार के गठन को रोकने के लिए मंत्रिमंडल की आधी रात की बैठक जल्दबाजी में बुलाई गई थी। राज्य में बहुमत वाली सरकार की संभावना को सुरक्षित करने के लिए एक सार्थक और वास्तविक प्रयास करना राज्यपाल का दायित्व था। उनके अनुसार राज्यपाल का इरादा श्री नितीश कुमार के नेतृत्व में सरकार के गठन को रोकना था। कि यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध या अस्तित्व में नहीं थी कि धन या बाहुबल के उपयोग के माध्यम से किसी भी राजनीतिक दलबदल का प्रयास किया जा रहा था। ऐसी किसी भी सामग्री के अभाव में अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग शक्ति के प्रयोग पर एक स्पष्ट धोखाधड़ी थी।

राज्यपाल की खरीद-फरोख्त की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप तथ्यात्मक थे

गलत और काल्पनिक। यह राज्यपाल का दायित्व था कि वह व्यक्तिगत रूप से विधायकों से तथ्यों का सत्यापन करे। कि संविधान की योजना के तहत दलबदल या खरीद-फरोख्त के आधार पर विलय और अयोग्यता के संबंध में निर्णय अध्यक्ष में निहित है। राज्यपाल उस आधार पर कार्रवाई करने का प्रयास नहीं कर सकते थे और खुद को इस तरह के अधिकार से अभिभूत कर सकते थे। इस न्यायालय के नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए

एस. आर. बोम्मई और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य।, [1994] 3 एस. सी. सी. 1 में, यह तर्क दिया गया था कि राज्यपाल की कार्रवाई कानून में दुर्भावनापूर्ण है; अतार्किक, बिना किसी ठोस सामग्री के निष्कर्ष पर पहुंचने का समर्थन करने के लिए और केवल अस्पष्टता पर आधारित है और इस प्रकार, कानून में टिकाऊ नहीं थी। यह तर्क दिया गया था कि न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में इस न्यायालय को विवादित अधिसूचना 601 को रद्द कर देना चाहिए।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

और परिणामस्वरूप द्वारा गठित विधान सभा को पुनर्स्थापित करना

निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 4 मार्च, 2005।

Mr.Soli सोराबजी ने चुनौती के समर्थन में तर्कों का नेतृत्व किया

विवादित अधिसूचना की वैधता यह तर्क देते हुए कि बोम्मई के मामले (उपरोक्त) में निर्धारित कानून के आलोक में जांच करने पर विधानसभा का विघटन स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए और कम से कम 7 मार्च, 2005 तक की यथास्थिति का निर्देश दिया जा सकता है।

Mr.Viplav शर्मा, अधिवक्ता, रिट याचिका No.258 में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए

2005 के Mr.Sorabjee के तर्कों को अपनाते हुए आगे तर्क दिया गया कि निर्वाचित उम्मीदवारों द्वारा शपथ लेने और सदस्यता लेने से पहले, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा विचार किया गया है, विधानसभा को भी आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 73 के तहत अधिसूचना जारी करने की तारीख को निलंबित एनीमेशन और यथास्थिति के तहत नहीं रखा जा सकता है।

श्री नरसिम्हा, याचिकाकर्ता के लिए लिखित याचिका (सी) No.353 में उपस्थित होते हुए,

आई. डी. 1 के तर्कों को भी अपनाया गया, लेकिन साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि एक बार भी इसकी बैठक से पहले विधानसभा को भंग करने का आदेश देना कानूनी रूप से अनुमत नहीं है और विधायकों को संविधान द्वारा विचार के अनुसार शपथ दिलाई जा रही है। यह श्री विप्लव शर्मा का भी निवेदन था। प्रत्यर्थी भारत संघ की ओर से तर्कों का नेतृत्व विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री मिलन बनर्जी ने किया, जिसके बाद क्रमशः विद्वान सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री गुलाम वाहनवती और श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने तर्क दिए। श्री पी. पी. राव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बिहार राज्य की ओर से तर्क दिया। हम सभी अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट और बहुत सक्षम सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं।

राज्यपाल के न होने के सवाल पर दलीलें सुनने के बाद

संविधान के अनुच्छेद 361 (1) द्वारा प्रदत्त उन्मुक्ति को देखते हुए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह, हमने 8 सितंबर, 2005 के अपने आदेश के संदर्भ में सरकार की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि राज्यपाल को संक्षिप्त कारण बताते हुए नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है, ताकि बाद में विस्तृत कारणों का पालन किया जा सके। उक्त आदेश इस प्रकार है:

" इस सवाल पर कि क्या राज्यपाल को इसमें शामिल किया जा सकता है

राज्यपाल के रूप में क्षमता और क्या उन्हें नोटिस जारी किया जा सकता है

किए गए कथन और प्रार्थनाओं के संदर्भ में रिट याचिकाओं पर

याचिकाओं में निहित और आदेश में उजागर किए गए अन्य पहलू
दिनांक 31 अगस्त, 2005 को हमने श्री सोली जे. सोराबजी को सुना है, जिन्होंने [2006] 1 एस. सी. आर. का ज्ञान प्राप्त किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के महान्यायवादी और श्री गोपाल सुब्रमण्यम को पता चला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल।

भारत का संविधान राज्यपाल को इस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है -

अनुच्छेद 361 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 361 (1), अन्य बातों के साथ, प्रदान करता है कि

राज्यपाल इस अभ्यास के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा और अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रदर्शन या किसी भी कार्य के लिए

अभ्यास और प्रदर्शन में उसके द्वारा किया गया या किया जाना अभिप्रेत है

उन शक्तियों और कर्तव्यों। यह विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

न्यायालय राज्यपाल को नोटिस जारी नहीं कर सकता है। जबकि हम स्वीकार करते हैं प्रस्तुत करना लेकिन, साथ ही, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि

राज्यपाल को दी गई प्रतिरक्षा राज्यपाल की शक्ति को प्रभावित नहीं करती है।

घोषणा पर हुए हमले की न्यायिक जांच करेगी अदालत

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत जारी किया गया दुर्भावनापूर्ण होना या अति अधिकार होना। यह सरकार के लिए होगा

न्यायालय को संतुष्ट करना और चुनौती के ऐसे आधार का पर्याप्त रूप से सामना करना।

एक दुर्भावनापूर्ण कार्य पूरी तरह से शक्ति के दायरे से बाहर है और इसका कोई अधिकार नहीं है।

कानून की नजर में अस्तित्व। यहाँ तक कि, अभिव्यक्ति "होने का तात्पर्य है अनुच्छेद 361 में "किया गया" उन कार्यों को शामिल नहीं करता है जो दुर्भावनापूर्ण या अतिवादी हैं।

अधिकार और, इस प्रकार, सरकार के तहत घोषणा का समर्थन

दुर्भावना या घोषणा के अधिकार के बाहर होने का आधार नहीं होगा न्यायालय द्वारा जाँच की गई। इस स्तर पर, हमने जांच नहीं की है

सवाल यह है कि क्या राज्यपाल द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण था

फिडे या अल्ट्रा वायर्स या नहीं। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर अभी भी बहस होनी बाकी है।

ये हमारे संक्षिप्त कारण हैं। हम बाद में विस्तृत कारण देंगे।

उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के तहत, हमारे लिए आने वाले बिंदु

इनैशन हैं:

(1) क्या अनुच्छेद के तहत विधानसभा को भंग करने की अनुमति है?

174 (2) (ख) संविधान की पहली बैठक हुए बिना?

(2) क्या 23 मई, 2005 की उद्घोषणा भंग करती है

बिहार की विधानसभा अवैध और असंवैधानिक है?

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

603

(3) यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या यह है?

7 मार्च, 2005 या 4 मार्च को यथास्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक

मार्च, 2005?

(4) अनुच्छेद 361 का क्या दायरा है जो राज्य को प्रतिरक्षा प्रदान करता है?

राज्यपाल?

विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, 7 अक्टूबर को एक संक्षिप्त आदेश द्वारा,

23 मई, 2005 की अधिसूचना को असंवैधानिक माना गया थामामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राहत निर्देश

7 मार्च को बनी विधानसभा को बहाल करने के लिए,

अस्वीकार कर दिया गया। 7 अक्टूबर का आदेश इस प्रकार है:

" बिहार विधान सभा के आम चुनाव थे

फरवरी 2005 के महीने में आयोजित। चुनाव आयोग ने

भारत, जन प्रतिनिधित्व की धारा 73 के अनुसरण में

4 मार्च, 2005 की अधिसूचना के संदर्भ में अधिनियम, 1951 ने निर्वाचित सदस्यों के नाम।

चूंकि कोई भी दल या दलों का गठबंधन सुरक्षित होने की स्थिति में नहीं था

122 सीटें ताकि विधानसभा में बहुमत हो, के राज्यपाल

बिहार ने 6 मार्च, 2005 को भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट दी। जिसके बाद 7 मार्च की अधिसूचना जी. एस. आर. 162 (ई) के संदर्भ में,

2005 , संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत शक्तियों के प्रयोग में जारी किया गया

भारत में, राज्य को राष्ट्रपति शासन के तहत लाया गया और सभा को निलंबित एनिमेशन में रखा गया था। एक अन्य अधिसूचना द्वारा

उसी तारीख, 7 मार्च, 2005 को G.S.R.163 (E), यह अधिसूचित किया गया था कि

भारत के राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण की गई सभी शक्तियाँ, - राष्ट्रपति के अधीक्षण निर्देश और नियंत्रण के अधीन,

राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है। गृह मंत्री

21 मार्च, 2005 को दिए गए एक भाषण में जब बिहार विनियोग

(लेखा पर वोट) विधेयक, 2005 पर राज्यसभा में चर्चा हो रही थी।

बिहार में और खुश होता अगर सरकार होती चुनाव के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा गठित। वह था,

हालांकि, यह संभव नहीं था और इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। यह भी कहा गया था कि सरकार यह नहीं देखना चाहेगी कि

राष्ट्रपति शासन लंबे समय तक जारी रहता है लेकिन यह निर्वाचित लोगों के लिए है।

इस संबंध में कदम उठाने के लिए प्रतिनिधि; राज्यपाल पूछ सकते हैं

उनसे अनुरोध करें और वह यह भी अनुरोध करेंगे कि निर्वाचित

प्रतिनिधियों को एक-दूसरे से बात करनी चाहिए और [2006] आई. एस. सी. आर. में स्थिति पैदा करनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिससे उनके लिए सरकार बनाना संभव हो जाता है। 7 मार्च, 2005 की राष्ट्रपति घोषणा को मंजूरी दी गई थी लोकसभा की बैठक 19 मार्च, 2005 को और राज्यसभा की बैठक 21 मार्च, 2005 को हुई थी।

बिहार के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को दो प्रतिवेदन दिए।

(ख) संविधान और विधानसभा के अनुच्छेद 356 के तहत जारी 7 मार्च, 2005 की अधिसूचना G.S.R.162 (ई) के खंड (ए) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (2) का। बिहार राज्य को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया।

ये रिट याचिकाएं संविधान को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं।

23 मई, 2005 की उपरोक्त उद्घोषणा की वैधता। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सोली जे. सोराबजी और अधिवक्ता श्री पी. एस. नरसिम्हा और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित अधिवक्ता श्री विप्लव शर्मा ने इस चुनौती के समर्थन में विस्तृत दलीलें दी हैं।

सभा को बर्खास्त करने की कार्रवाई।

दूसरी ओर, श्री मिलन के. बनर्जी, अटॉर्नी-जनरल

भारत, श्री गुलाम ई. वाहनवती, सॉलिसिटर जनरल और श्री गोपाल

भारत संघ की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुब्रमण्यम और बिहार राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. पी. राव ने भी विवादित का समर्थन करते हुए विस्तृत दलीलें दीं।

23 मई, 2005 की घोषणा।

कानून के कई जटिल और महत्वपूर्ण प्रश्न दूरगामी हैं।

दोनों पक्षों से प्रभाव को संबोधित किया गया है। मौखिक दलीलों की सुनवाई के समापन के बाद, लिखित प्रस्तुतियाँ भी दी गई हैं।

विद्वान वकील द्वारा दायर किया गया।

बिहार राज्य में नए चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार

भारत के चुनाव आयोग द्वारा 3 सितंबर, 2005 को जारी किए गए नोट में बिहार विधानसभा के आम चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसके अनुसार मतदान होना है। 18 अक्टूबर, 2005 से शुरू होकर 19 नवंबर, 2005 को चौथे चरण के मतदान के साथ समाप्त होने वाले चार चरणों में आयोजित किया गया। उक्त प्रेस नोट के अनुसार, पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना की तारीख 23 सितंबर और 28 सितंबर, 2005, मतदान की तारीख 605 थी

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. 1. [सभरवाल, सी. जे.]

यह क्रमशः 18 अक्टूबर, 2005 और 26 अक्टूबर, 2005 है।
तीसरे और चौथे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी की जानी है।

19 क्रमशः 26 और 26 अक्टूबर, 2005।

सम्मिलित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, की घोषणा

विस्तृत कारणों के साथ निर्णय में कुछ समय लगने की संभावना है और,

इसलिए, इस स्तर पर, हम इस संक्षिप्त क्रम का उच्चारण कर रहे हैं

अदालत के आदेश का बाद में विस्तृत कारणों से पालन किया जाएगा।

तदनुसार, बहुमत की राय के अनुसार, यह न्यायालय निम्नानुसार आदेश देता है:

1 . 23 मई, 2005 की उद्घोषणा जिसमें

बिहार राज्य की विधानसभा असंवैधानिक है।

2. विवादित घोषणा की असंवैधानिकता के बावजूद,

लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए,

वर्तमान एक ऐसा मामला नहीं है जहां विवेकाधीन अभ्यास में यथास्थिति पूर्ववर्ती अधिकारिता का आदेश दिया जाना चाहिए

7 मार्च, 2005 की घोषणा जिसके तहत इसे रखा गया था निलंबित एनिमेशन के तहत "।

बिंदु संख्या 1-क्या विधानसभा को भंग करने की अनुमति है?

संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (बी) के तहत इसकी पहली बैठक के बिना

हो रहा है?

संविधान का अनुच्छेद 174 राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है।

सदन को बुलाना, सदन का सत्रावसान करना और विधानमंडल को भंग करना

विधान सभा की पहली बैठक से पहले ही उसे भंग करने की वैधता संविधान के अनुच्छेद 172 के तहत विचार किया गया। यह दावा किया गया है कि

याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री नरसिम्हा और श्री विप्लव शर्मा उपस्थित हुए।

व्यक्तिगत रूप से, कि अनुच्छेद 174 (2) (बी) के तहत एक विधानसभा को भंग किया जा सकता है इसकी पहली बैठक के बाद ही जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 172 द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

संविधान। तर्क यह है कि इसके बिना कोई विघटन नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि सदस्य शपथ लेते हैं और विधान सभा अस्तित्व में आती है।

जो मौजूद नहीं है, उसे भंग नहीं किया जा सकता है, वह समर्पण है। इस संबंध में,

विचार करने योग्य प्रश्न यह भी है कि क्या पहली बैठक की तारीख

विधान सभा को किसी की स्थिति के बिना तय किया जा सकता है

. सरकार बनाएँ।

आइए पहले हम प्रासंगिक संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों की जांच करें।

राज्यों से संबंधित संविधान के भाग VI में छह अध्याय हैं लेकिन

हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक अध्याय II और अध्याय III हैं। अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 वाला अध्याय II कार्यपालिका से संबंधित है, अध्याय III जिसमें शामिल हैं - अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 राज्य विधानमंडल से संबंधित है।

हमारे संविधान के तहत संघीय संरचना में विचार किया गया है कि

प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें एक राज्यपाल और

एक या दो सदन, जैसा कि अनुच्छेद 168 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि

प्रत्येक राज्य की विधान सभा में राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्य शामिल होंगे। इसलिए अनुच्छेद 170 चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया लाता है।

अनुच्छेद 164 एक कार्यकारी सरकार स्थापित करता है। यह आदेश देता है कि

राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 163) अनुच्छेद 154 के तहत प्रदान की गई राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करती है। अनुच्छेद 164 (2) में प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

जैसा कि अनुच्छेद 172 में दिया गया है, प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा,

जब तक जल्दी भंग नहीं किया जाता है, तब तक यह अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से पांच साल तक जारी रहेगा और अब और नहीं और पांच साल की उक्त अवधि की समाप्ति विधानसभा के विघटन के रूप में कार्य करेगी। अनुच्छेद 174 (1) में प्रावधान है कि राज्यपाल समय-समय पर सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाएगा जो वह उचित समझे, लेकिन एक सत्र में इसकी अंतिम बैठक और संसद में इसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि के बीच छह महीने का हस्तक्षेप नहीं होगा।

अगला सत्र। अनुच्छेद 174 (2) (बी) में प्रावधान है कि राज्यपाल समय-समय पर विधानसभा को भंग कर सकता है।

राज्य की विधान सभा का प्रत्येक सदस्य, इससे पहले

अपना स्थान ग्रहण करते हुए, राज्यपाल के समक्ष शपथ लें और हस्ताक्षर करें, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 188 में प्रावधान किया गया है।

आग्रह किया गया तर्क यह है कि बुलाने में राज्यपाल का कार्य

सदन और सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान देना

विधान सभा विशेषाधिकार, विशेषाधिकार या विवेक के मामले नहीं हैं। राज्यपाल के लेकिन उनके प्राथमिक और मौलिक संवैधानिक दायित्व हैं

जिस पर संसदीय लोकतंत्र, संघवाद के सिद्धांत और यहाँ तक कि

' 'शक्ति का पृथक्करण' निर्भर है। एक और तर्क यह है कि

राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व कार्यपालिका का गठन करना है।

सरकार।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

607

श्री नरसिम्हा के अनुसार राज्यपाल इन्हें पूरा करने में विफल रहे

संवैधानिक दायित्व। राज्यपाल द्वारा न तो कार्यकारी सरकार का गठन किया गया है और न ही विधानसभा का। दूसरी तरफ

हाथ, राज्यपाल ने अनुच्छेद के तहत विधानसभा को भंग करके अपने संवैधानिक दायित्व के प्रयोग के उद्देश्य को विफल कर दिया है

174 (2) (ख) विधान सभा का गठन किए बिना भी। कब

विधान सभा का गठन भी नहीं किया गया है, इसके विघटन का सवाल कहां है, यह तर्क दिया जाता है। निवेदन यह है कि भारतीय संविधान की योजना के तहत, विधानसभा को भंग करने की अनुमति नहीं है

इसकी पहली बैठक से पहले और अनुच्छेद 188 द्वारा आवश्यक शपथ या पुष्टि करने वाले सदस्य। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, भारतीय संविधान के तहत, विधान सभा का गठन विधिवत रूप से केवल सदन के बुलाए जाने पर और इसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से किया जाता है। अनुच्छेद 172 जो राज्य विधानमंडलों की अवधि का प्रावधान करता है, निम्नानुसार है:

" 172. राज्य विधानमंडलों की अवधि-(1) प्रत्येक विधान सभा
प्रत्येक राज्य का, जब तक कि जल्द ही भंग नहीं किया जाता है, (पाँच वर्ष) के लिए जारी रहेगा।

इसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से और अब नहीं और

(पाँच वर्ष) की उक्त अवधि की समाप्ति के रूप में कार्य करेगी

विधानसभा का विघटन:

बशर्ते कि उक्त अवधि, आपातकाल की घोषणा करते समय

संचालन में है, संसद द्वारा कानून द्वारा एक अवधि के लिए बढ़ाया जाना चाहिए

एक बार में एक वर्ष से अधिक और किसी भी मामले में इससे अधिक नहीं

घोषणा का संचालन बंद होने के बाद छह महीने की अवधि।

(2) किसी राज्य की विधान परिषद के अधीन नहीं होगी -

प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर जितनी जल्दी हो सके सेवानिवृत्त हो जाएगा। संसद द्वारा इस संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुसार

कानून द्वारा।

उपरोक्त संवैधानिक प्रावधान में निर्धारित किया गया है कि -

एक विधान सभा की गणना उसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से की जाएगी और पहली बैठक की तारीख से शुरू होने वाले पांच साल की समाप्ति पर, विधानसभा स्वचालित रूप से समय के साथ भंग हो जाती है। विधान सभा की पांच वर्ष से अधिक की अवधि उपरोक्त प्रावधान के जनादेश को देखते हुए अस्वीकार्य है कि विधान सभा पांच वर्ष के लिए जारी रहेगी और 'अब नहीं'। इन प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि विधान सभा का उचित गठन इसकी पहली बैठक के बाद ही हो सकता है जब सदस्य शपथ या प्रतिज्ञान 608 की सदस्यता लेते हैं।

[2006] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 188 के तहत। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 73 के तहत विधानसभा के वैधानिक मानित संविधान की, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए विधान सभा के उचित गठन को निर्धारित करने के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है -

भारत का संविधान।

याचिकाकर्ताओं की ओर से मौजूदा कानून का भी उल्लेख किया गया है।

भारत के संविधान के प्रवर्तन से पहले

राज्य परिषद और विधान सभा का प्रारंभ उनकी पहली बैठक की तारीख। यह इंगित किया गया था कि भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 63 (डी), जो भारतीय विधानमंडल से संबंधित है, प्रदान करती है कि -

राज्य परिषद पाँच वर्ष और प्रत्येक विधान सभा के लिए जारी रहेगी।

इसकी पहली बैठक की तारीख से तीन साल के लिए। इसी तरह, धारा 72 (बी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्यपाल की विधान परिषद तीन वर्षों तक जारी रहेगी। अपनी पहली बैठक के वर्षों बाद। भारत सरकार अधिनियम, 1919,1915 अधिनियम को निरस्त करते हुए, धारा 8 (1) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्यपाल की विधान परिषद

अपनी पहली बैठक से तीन साल तक जारी रहेगा और धारा 21 में प्रावधान किया गया है

कि प्रत्येक राज्य परिषद अपनी पहली बैठक से पांच साल और प्रत्येक विधान सभा तीन साल के लिए जारी रहेगी। इसी तरह, सरकार

1919 के अधिनियम को निरस्त करने वाले भारत अधिनियम, 1935 में भारत के अनुच्छेद 172 के समान प्रावधान था।

संविधान।

आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 73, जहाँ तक हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है,

यह निम्नानुसार है:

" 73. सदन के आम चुनावों के परिणामों का प्रकाशन

जनता और राज्य विधानसभाएँ। जहाँ आम चुनाव होता है

लोगों के एक नए सदन के गठन के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है या एक नई राज्य विधान सभा, जिसके द्वारा अधिसूचित किया जाएगा [

चुनाव आयोग] आधिकारिक राजपत्र में, जितनी जल्दी हो सके

[सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के परिणाम [इनके अलावा]

जिस तारीख को किसी भी कारण से मतदान नहीं किया जा सका था मूल रूप से धारा 30 के खंड (घ) के तहत या जिसके लिए समय निर्धारित किया गया है

चुनाव पूरा करने के लिए प्रावधानों के तहत विस्तार किया गया है

ऐसी अधिसूचना कि सदन या विधानसभा को माना जाएगा विधिवत गठित "।

वर्तमान मामले में, आर. पी. अधिनियम, 1951 609 की धारा 73 के तहत अधिसूचना

4 मार्च, 2005 को जारी किया गया था। विधान सभा का मानित गठन उक्त अधिसूचना के मुद्दे पर धारा 73 के तहत किया गया था।

सवाल यह है कि क्या विधान सभा का यह मानित संविधान है केवल आर. पी. अधिनियम, 1951 के उद्देश्य के लिए और संवैधानिक उद्देश्य के लिए नहीं।

अनुच्छेद 174 (2) (बी) के तहत विघटन की शक्ति का आह्वान करने के लिए प्रावधान। द.

सरकार का रुख यह है कि उपरोक्त कानूनी कल्पना को ध्यान में रखते हुए, विधान सभा का गठन सभी उद्देश्यों के लिए किया जाता है और,

इस प्रकार, विधान सभा को 'विधिवत गठित' माना जाता है 4 मार्च, 2005 और, इसलिए, राज्यपाल की शक्ति का प्रयोग कर सकता था

अनुच्छेद 174 (2) (बी) के तहत विघटन।

आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 73 चुनाव आयोग को आदेश देती है

सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद अधिसूचना जारी करना। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण चुनाव आयोग के पास निहित है। अनुच्छेद 327 में प्रावधान है कि संसद

किसी राज्य की विधान सभा के चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में सभी मामलों और विधानमंडल के सदन के 'उचित गठन' को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करना। अनुच्छेद 329 चुनाव को छोड़कर चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।

याचिका ऐसे प्राधिकारी के समक्ष और उस तरीके से प्रस्तुत की जाए जो उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान की जाए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के साथ पठित अनुच्छेद 327 में इस बात का प्रावधान है कि सदन या विधानसभा का 'विधिवत गठन' किया जाएगा: कोई भी प्रावधान, संवैधानिक या वैधानिक, यह निर्धारित नहीं करता है कि 'उचित संविधान' केवल अनुच्छेद 324,327 और 329 के उद्देश्यों के लिए है और राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से नहीं है। जहाँ तक अनुच्छेद 172 पर आधारित तर्क का संबंध है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विधान सभा का नियत गठन इसकी अवधि से अलग है जिसकी गणना इसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से पाँच वर्ष की

जाती है और अब नहीं। अनुच्छेद 174 (2) (बी) के तहत कोई प्रतिबंध नहीं है जो यह निर्धारित करता है कि

विधानसभा को भंग करने का प्रयास इसकी पहली बैठक के बाद ही किया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के परंतुक का खंड (बी) भी विधानसभा के मानित गठन को केवल उक्त के विशिष्ट उद्देश्य के लिए सीमित नहीं करता है। अधिनियम या संविधान के अनुच्छेद 324,327 और 329। उक्त खंड में प्रावधान है कि धारा 73 के तहत अधिसूचना जारी करने से राज्य विधानसभा की अवधि, यदि कोई हो, तुरंत कार्य करने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उक्त अधिसूचना जारी करने से पहले। वास्तव में, खंड (ख) इस निष्कर्ष को और मजबूत करता है कि विधान सभा की अवधि उसके नियत गठन से अलग है। वर्तमान मामले में हम विधानसभा की अवधि के सवाल से चिंतित नहीं हैं, बल्कि इस सवाल से चिंतित हैं कि क्या 610

[2006] आई एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधानसभा का विधिवत गठन किया गया था या नहीं ताकि राज्यपाल अनुच्छेद 174 (2) (बी) के तहत विघटन की शक्ति का प्रयोग करें। का संविधान

भाग VI के अध्याय II और III के तहत विधानमंडल। भारत के संविधान के प्रवर्तन से पहले मौजूद पूर्व उल्लिखित प्रावधान भी नहीं हैं। अनुच्छेद 274 (2) (बी) के तहत विघटन की शक्ति का प्रयोग करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के तहत विधानसभा के मानित संविधान के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिकता।

के. के. अबू बनाम. भारत संघ और ओआरएस। , आकाशवाणी (1965) केरल 229, एक विद्वान

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने सही निष्कर्ष निकाला कि न तो

अनुच्छेद 172 और न ही अनुच्छेद 174 में यह निर्धारित किया गया है कि किसी राज्य विधानमंडल का विघटन उसका कार्यकाल शुरू होने के बाद या उसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि के बाद ही हो सकता है। एक बार विधानसभा का गठन हो जाने के बाद, यह भंग

करने में सक्षम हो जाती है। इस निर्णय का उल्लेख हममें से एक (अरिजीत पसायत, जे.) ने स्पेशल में किया है।

2002 का संदर्भ संख्या 1 (गुजरात विधानसभा चुनाव के रूप में लोकप्रिय)

मामला) [2002] 8 एससीसी 237। संविधान के किसी भी प्रावधान में यह नहीं कहा गया है कि विघटन केवल राज्य विधानमंडल की पहली बैठक के बाद ही हो सकता है। याचिकाकर्ताओं के तर्क की स्वीकृति भी टूटने का कारण बन सकती है

संविधान से। किसी मामले में, एक स्थिर सरकार प्रदान करने के लिए आवश्यक शक्ति के अभाव में कोई भी सरकार बनाने का दावा करने के लिए आगे नहीं आ सकता है। यदि याचिकाकर्ताओं के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल न तो कार्यकारी सरकार नियुक्त कर पाएगा और न ही वह अनुच्छेद 174 (2) (बी) के तहत विघटन की शक्ति का प्रयोग कर पाएगा। संविधान कार्यकारी सरकार के बिना एक लाइव विधानसभा को अभिनिर्धारित नहीं करता है।

हालाँकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से इस पर निर्भरता रखी गई है

उदय के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ का निर्णय

नारायण सिन्हा बनाम। यू. पी. और अन्य राज्य।, AIR [1987] All.203]। असहमत होना

केरल उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 172 (1) के अनुसार विधानसभा की पहली बैठक के लिए तिथि की नियुक्ति के अभाव में,

आर. पी. की धारा 73 के तहत अधिसूचना के आधार पर गठित किया गया है अधिनियम, 1951 ताकि राज्यपाल को शक्ति का प्रयोग करके इसे भंग करने का अधिकार मिले।

अनुच्छेद 174 (2) के तहत। डिवीजन बेंच द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 73

राज्यपाल किसी भी सदन या सदन की पहली बैठक के लिए एक तिथि निर्धारित करेगा। विधानसभा ताकि उन्हें 611 से मिलने के लिए बुलाए जाने के बाद कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत। हम ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। सीमा। हमारे विचार में, सभा, सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, माना जाता है

धारा 73 के तहत अधिसूचना जारी करने पर विधिवत गठन किया जाना और

इसकी अवधि इसके नियत संविधान से अलग है। व्याख्या जो संवैधानिक टूटने की स्थिति पैदा हो सकती है जिससे बचा जाना चाहिए,

जब तक कि प्रावधान इतने स्पष्ट न हों कि किसी अन्य व्याख्या की आवश्यकता न हो।

यह मामला बाद की श्रेणी में नहीं आता है।

गुजरात विधानसभा चुनाव के मामले में, संविधान से पहले का मुद्दा

पीठ ने कहा कि क्या अनुच्छेद 174 (1) द्वारा अनुध्यात छह महीने की अवधि लागू होती है।

विघटित विधान सभा के लिए। उस प्रश्न पर विचार करते हुए और यह मानते हुए कि उक्त प्रावधान केवल वर्तमान विधानसभा पर लागू होता है

और एक भंग विधान सभा के लिए नहीं, यह माना गया था कि संविधान

किसी भी विधानसभा का गठन केवल आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 73 के तहत किया जा सकता है और

संविधान के अनुच्छेद 188 की आवश्यकता से पता चलता है कि विधानसभा अपनी पहली बैठक शुरू होने से पहले ही अस्तित्व में आ जाती है। (हमारे द्वारा दिया गया जोर)।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पहले बिंदु का जवाब दिया जाता है।

बिंदु संख्या 2: क्या 23 मई, 2005 की घोषणा

बिहार विधानसभा को भंग करना अवैध और असंवैधानिक है?

यह बिंदु मामले का केंद्र बिंदु है। संविधान का जवाब

विवादित अधिसूचना की वैधता ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा के दायरे और विस्तार पर निर्भर करती है जो बोम्मई के मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा निर्धारित की जाती है। दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने इस सवाल पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं कि अनुपात क्या है

बोम्मई का मामला।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विधानसभा को भंग करने की अधिसूचना

अवैध है क्योंकि यह राज्यपाल की रिपोर्ट पर आधारित है जो पीड़ित है

गंभीर कानूनी और तथ्यात्मक दुर्बलताएँ और व्यापक दुर्भावना से दूषित हैं जो अभिलेख से स्पष्ट है। यह तर्क दिया जाता है कि राज्यपाल की रिपोर्ट का उद्देश्य श्री नितीश कुमार के नेतृत्व वाले राजनीतिक दल को सरकार बनाने से रोकना था। निवेदन यह है कि ऐसा उद्देश्य होने के नाते, सिफारिश को स्वीकार करने की विघटन की परिणामी अधिसूचना योग्य है।

निरस्त किया जाए।

संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत, एक विधानसभा का विघटन

इस संतुष्टि पर आदेश दिया जा सकता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें 612

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2006] 1 एस सी आर।

राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल सकती है। राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा इस तरह की संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। राज्यपाल से रिपोर्ट की प्राप्ति और अन्य सामग्री पर संतुष्टि पर पहुंचने की अनुमति है।

राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही इस तरह की संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। राष्ट्रपति के पास पहुंचने के लिए अन्य प्रासंगिक सामग्री होने की स्थिति में राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति है।

अनुच्छेद 356 द्वारा अनुध्यात संतुष्टि। अभिव्यक्ति या अन्यथा 'व्यापक आयाम का है।

वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है कि संतुष्टि

ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार को चलाया नहीं जा सकता है

राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर। यह संघ का मामला नहीं है भारत का कि उसने रिपोर्टों के अलावा किसी अन्य सामग्री पर भरोसा किया है

राज्यपाल जिन्हें पहले विस्तार में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

राज्यपाल ने 6 मार्च, 2005 की रिपोर्ट में उल्लेख किया है -

बोम्मई के मामले के साथ-साथ सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर भी। अध्याय IV में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में व्यापक रूप से भूमिका के बारे में बताया गया है -

राज्यपालों। चूंकि इस मामले में विधानसभा का विघटन आधारित है।

केवल राज्यपाल की रिपोर्ट पर और मुद्दा भी भूमिका के बारे में है

राज्यपाल द्वारा खेला गया और भूमिका पर प्रस्तुतियाँ भी की गई हैं

जिसकी अपेक्षा राज्यपाल जैसे उच्च संवैधानिक पदाधिकारी से की जाती है, वह

पहले उस पहलू की जांच करना उपयोगी होगा।

राज्यपाल की भूमिका

केंद्र के मामलों में राज्यपाल की भूमिका एक प्रमुख मुद्दा रहा है।

राज्य संबंध। भारत के संविधान में सरकार के तीन स्तरों की परिकल्पना की गई है

संघ, राज्य और स्थानीय स्वशासन। कार्यात्मक से

दृष्टिकोण से, यह कहा गया है कि ऐसा संविधान "एक स्थिर प्रारूप नहीं है, बल्कि एक

गतिशील प्रक्रिया "[केंद्र-राज्य पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट

संबंध (1988)]। संघ-राज्य संबंधों के संदर्भ में यह उल्लेख किया गया है

कि "अपने सभी नियंत्रण और संतुलन के साथ प्रणाली की बहुत गतिशीलता लाती है

संघ-राज्य संबंधों के कार्यकरण में समस्याओं और संघर्षों के कारण।

आज प्रचलित एक अस्थिर प्रणाली के आलोक में, यह उचित है

के कार्य में राज्यपालों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दें
लोकतांत्रिक ढांचा। जून 2005 में राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए,

भारत के राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने 613 की प्रासंगिकता पर जोर दिया

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

सरकारिया आयोग की सिफारिशें और कहा कि "जबकि वहाँ

संविधान, के कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए कई नियंत्रण और संतुलन हैं
राज्यपाल को दिन से ऊपर उठने की स्वतंत्रता दी गई है -

दिन की राजनीति और केंद्रीय व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली मजबूरियों पर हावी होना
या राज्य प्रणाली "। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी इसी विषय पर बात की

इस अवसर पर कहा गया कि "आप राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि हैं और

इसलिए, आप राज्य स्तर की कार्रवाइयों और गतिविधियों के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्षय
लाते हैं।

हरगोविंद पंत बनाम। डॉ. रघुकुल तिलक और अन्य। [1979] 3 एससीसी 458,

इस मुद्दे पर अवलोकन करते हुए कि क्या एक राज्यपाल को एक के रूप में माना जा सकता है

" भारत सरकार के कर्मचारी ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है।

कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जिसका अर्थ है प्रभावी और

भारत सरकार, लेकिन यह केवल नियुक्ति का एक तरीका है

और यह राज्यपाल को सरकार का कर्मचारी या सेवक नहीं बनाता है।

भारत का "।

संविधान के अनुच्छेद 356 का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने तर्क दिया कि

" एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो उन्हें (राज्यपाल) निभानी है

संविधान एक रिपोर्ट बनाने का है जिसमें वह पाता है कि एक स्थिति उत्पन्न हो गई है

जिसमें राज्य सरकार को उसके अनुसार नहीं चलाया जा सकता है

संविधान के प्रावधानों के साथ "और आगे कहा कि राज्यपाल

कर्तव्य। वह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो इसके अधीन नहीं है भारत सरकार का
नियंत्रण "।

उसी को मजबूत करते हुए, न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर ने कहा है कि

नियुक्ति का तरीका कभी भी किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को वैध नहीं बना सकता है

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में भी मान्य नहीं होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। (वी. आर. कृष्ण अय्यर, एक संवैधानिक विविध

(दूसरा संस्करण, लखनऊः ईस्टर्न बुक कं., 2003) पी. 44) .

भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री जी. एस. पाठक ने कहा था -

1970 कि "उस क्षेत्र में जो परिषद की सलाह से बंधा है

मंत्री, स्पष्ट कारणों से, राज्यपाल को स्वतंत्र होना चाहिए

केंद्र "जैसा कि मामले हो सकते हैं" जहां। केंद्र की सलाह से टकराव हो सकता है राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से और ऐसे मामलों में

. राज्यपाल को केंद्र की "सलाह" को नजरअंदाज करना चाहिए और उनकी सलाह पर काम करना चाहिए।

मंत्रिपरिषद। "614

[2006] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ थीं

बोम्मई के मामले में यह कहा गया था कि "वह (राज्यपाल) अनुच्छेद 356 द्वारा विचार की गई स्थिति में इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए उतना ही बाध्य है जितना कि वह इसका उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं है जहां ऐसी स्थिति वास्तव में उत्पन्न नहीं हुई है" (पैरा 272 जीवन रेड्डी, जे. जोर हमारे द्वारा प्रदान किया गया)

राज्यपाल की भूमिका की काफी आलोचना हुई है

यह आधार है कि कुछ राज्यपाल उनसे अपेक्षित निष्पक्षता के गुणों को प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि "कई लोगों ने इसका पता मुख्य रूप से इस तथ्य से लगाया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वह राष्ट्रपति की खुशी के दौरान पद धारण करता है, यानी, वास्तव में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद।"

एक निर्वाचित राज्यपाल के सुझाव को अस्वीकार करते हुए, संविधान

विधानसभा ने बार-बार प्रांतीय/राज्य के साथ परामर्श पर जोर दिया

राज्यपाल की नियुक्ति से पहले की सरकार। सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के हवाले से कहा गया है कि "प्रांतीय मंत्रिमंडल से परामर्श करने की परंपरा आसानी से बढ़ सकती है" जैसा कि कनाडा में कहा गया था (कर्नाटक सरकार के राज्यपाल के कार्यालय पर श्वेत पत्र (22 सितंबर, 1983) सी. एफ. वी. आर. कृष्ण अय्यर, ए कांस्टीटचूशनल मिसेलनी (दूसरा संस्करण, लखनऊः ईस्टर्न बुक कं., 2003) पी. 45) . श्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में राज्यपाल की नियुक्ति पर बहस में यह भी कहा था कि एक राज्यपाल को "प्रांत के लिए स्वीकार्य होना चाहिए, उसे प्रांत की सरकार के लिए स्वीकार्य होना चाहिए और फिर भी उसे उस प्रांत की पार्टी मशीन का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।" उनकी राय थी कि एक नामित राज्यपाल के "केंद्र के साथ बहुत कम सामान्य संबंध" होंगे।

यह पूछना कि एक वस्तुनिष्ठ और प्रतिनिधि निकाय क्या हो सकता है

जो मेधावी आधार पर राज्यपालों की नियुक्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए हमारे संवैधानिक ढांचे में फिट होगा, सरकारिया आयोग ने कहा है कि "इस बात से कोई इनकार नहीं है कि ऐसी प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए जो चयन में निष्पक्षता और चयन के मानदंडों का पालन सुनिश्चित कर सके और

राजनीतिक दबावों से व्यवस्था को अलग रखें। इसके अलावा, नई प्रक्रिया अनिवार्य है। न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष भी देखा जाना चाहिए। (अध्याय IV "की भूमिका

राज्यपाल ", केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट (1988) पैरा 4.6.30 पर)। यह अनुशंसा करते हुए कि भारत के उपराष्ट्रपति और

राज्यपाल के चयन में प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श किया जाना चाहिए, सरकारिया आयोग ने नोट किया है कि "

परामर्श से चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता में काफी वृद्धि होगी। "

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

बहस का अन्य संबंधित मुद्दा विस्तार के बारे में था

एक नामित राज्यपाल रखने के लिए, राज्यपाल द्वारा 'अपने विवेकानुसार' निर्दिष्ट कार्यों के प्रयोग से संबंधित संविधान के मसौदे के विभिन्न अनुच्छेदों में दिए गए संदर्भों को हटा दिया गया था। (अध्याय IV "राज्यपाल की भूमिका", केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट (1988) पैरा 4.2.07 पर)। संविधान के अनुच्छेद 163 (तत्कालीन मसौदा अनुच्छेद 143) ने काफी चर्चा पैदा की, और कहा जाता है कि डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां देना जिम्मेदार होने के विपरीत नहीं था।

सरकार "। (संविधान सभा की बहस (खंड VIII, संशोधित संस्करण)। 00-502) .

अनुच्छेद 163 (1) में पाई जाने वाली अभिव्यक्ति "आवश्यक" को सूचित करने के लिए कहा गया है।

कि राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग केवल तभी कर सकता है जब

ऐसा करने के लिए बाध्यकारी आवश्यकता। यह तर्क दिया गया है कि "संविधान द्वारा या उसके तहत" अभिव्यक्ति का अर्थ है कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता संविधान के किसी भी स्पष्ट प्रावधान से या आवश्यक निहितार्थ से उत्पन्न हो सकती है। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ऐसी आवश्यकता संविधान के तहत बनाए गए नियमों और आदेशों से भी उत्पन्न हो सकती है।

यह देखते हुए कि राज्यपाल को "दोहरी जिम्मेदारी" निभाने की आवश्यकता है

संघ और राज्य-सरकारिया आयोग ने कुछ विवादास्पद परिस्थितियों में राज्यपालों की भूमिका का मूल्यांकन करने का प्रयास किया है, जैसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति में, बहुमत का पता लगाने में, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने में, विधानसभा को भंग करने में, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने में और विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने में।

यह पता लगाना कि राज्यपाल का पद इसके लिए अपरिहार्य है

राज्यपाल के कार्यकरण के लिए मानदंड एक के लिए मुश्किल बना देंगे संसदीय समिति या उच्चतम न्यायालय किसी विशिष्ट मामले की जांच करने के लिए

41 616

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्यपाल के खिलाफ आरोप "।

निर्देश का साधन:

संविधान सभा, प्रांतीय की रिपोर्ट के अनुसार

संविधान समिति ने निर्देश का एक दस्तावेज शामिल करने का निर्णय लिया था

संविधान की अनुसूची के रूप में राज्यपालों को। इस तरह की

लिखत को आवश्यक पाया गया, "क्योंकि नियुक्ति का तरीका और मंत्रियों की सलाह पर कार्य करने का निषेधाज्ञा स्वयं संविधान में निहित नहीं था।" (भारत का संविधान बनाना भारत का संविधान चुनें दस्तावेज़ (खंड IV, बी. शिव राव (संस्करण), नई दिल्ली। यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग सीपी, 2004) पी। 86. सुझाए गए निर्देशों का पूरा परीक्षण है -

पीपी में पुनः प्रस्तुत किया गया। 88-90) . भारत सरकार अधिनियम, 1935 में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस संप्रभु के निर्देशों के रूप में दिखाई दिया।

संविधान सभा द्वारा विचार किए गए निर्देशों की सुझाई गई सूची

मूल्य आधारित मानक शामिल हैं जो एक राज्यपाल से निर्वहन में अपेक्षित हैं

"स्थिर बहुमत" का निर्धारण करने के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में उनके कर्तव्य; मंत्रिपरिषद की नियुक्तियाँ जो "विधानमंडल का विश्वास हासिल करने के लिए सामूहिक रूप से सबसे अच्छी स्थिति में होंगी"; "संविधान के तहत नियुक्तियाँ करने के मामले में राज्यपाल की सहायता करने के लिए" विपक्ष के नेता सहित विधानमंडल के विधिवत निर्वाचित सदस्यों से युक्त एक सलाहकार बोर्ड का गठन करना, जैसे कि राज्य के लिए लेखा परीक्षक-इन-चीफ, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष; और राज्यपाल को वह सब करने के लिए अनिवार्य करना जो उनमें अच्छा प्रशासन के मानकों को बनाए रखने के लिए, सभी उपायों को बढ़ावा देने के लिए निहित है।

नैतिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए और राज्य के सार्वजनिक जीवन और सरकार में अपना उचित हिस्सा लेने के लिए आबादी के सभी वर्गों को फिट करने के लिए, और सभी वर्गों और पंथों के बीच सहयोग, सद्भावना और धार्मिक विश्वासों और भावनाओं के लिए आपसी सम्मान सुनिश्चित करने के लिए।

निर्देश संविधान की एक अनुसूची के रूप में प्रस्तावित किए गए थे

विधानसभा ने महसूस किया कि "उन्हें संविधान के मुख्य भाग में नहीं रखना बेहतर है, क्योंकि वे कानूनी नियमों के बजाय परंपराएं हैं।" हालाँकि, इसे संविधान के साथ नहीं जोड़ा गया था और इसके बारे में विलाप करते हुए, श्री ए. जी. नूरानी ने कहा है कि यदि अनुमति दी जाती तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस राष्ट्रपति और राज्यपालों के बीच संहिताबद्ध सम्मेलन हो सकते थे। (ए. जी. नूरानी, भारत में संवैधानिक प्रश्न-राष्ट्रपति, संसद और राज्य (नई दिल्ली-ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000) पी. 11)

पी. वी. राजमन्नार समिति (1969), जांच समिति ने रामेश्वर प्रसाद बनाम का गठन किया।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

617

तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र-राज्य संबंधों पर रिपोर्ट करना, और

श्री एम. सी. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग (1967) के अध्ययन दल ने कहा है कि "एक विशिष्ट प्रावधान"

राष्ट्रपति को जारी करने में सक्षम बनाने के लिए संविधान में जोड़ा जाना चाहिए

राज्यपालों को निर्देश के दस्तावेज। निर्देश के लिखतों को उन मामलों को इंगित करने वाले दिशा-निर्देश निर्धारित करने चाहिए जिनके संबंध में राज्यपाल को केंद्र सरकार से परामर्श करना चाहिए या जिसके संबंध में केंद्र सरकार उन्हें निर्देश जारी कर सकती है। (इस पर श्वेत पत्र

राज्यपाल का कार्यालय, कर्नाटक सरकार (22 सितंबर, 1983) वी. आर. कृष्ण अय्यर, ए कांस्टीटचूशनल मिसेलनी (दूसरा संस्करण, लखनऊ: ईस्टर्न बुक कं., 2003) पी. 47) . न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा है कि राज्यपालों के लिए दिशानिर्देशों को निर्धारित करने वाली

एक "पुस्तिका" को विधि आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए और संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

निर्देश के एक साधन के समान स्थिति में संदर्भ। हालाँकि, सरकारिया आयोग ने कहा है कि "राज्यपाल की बहुआयामी भूमिका और उनके कार्यों और कर्तव्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि एक नियम तैयार करना न तो संभव होगा और न ही वांछनीय होगा।

उसके द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए दिशानिर्देशों का व्यापक सेट। कोई भी दो स्थितियाँ जिनके लिए राज्यपाल को अपने विवेक का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, समान होने की संभावना नहीं है।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ:

द्वारा विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग पर विस्तार से व्याख्या करना

राज्यपाल, सरकारिया आयोग ने मुख्य रूप से निम्नलिखित की सिफारिश की है: ?

मुख्यमंत्री की नियुक्ति। यह स्पष्ट है कि नेता

पार्टी जिसके पास विधान सभा में पूर्ण बहुमत हो
राज्यपाल द्वारा हमेशा एक गठन करने के लिए बुलाया जाना चाहिए

सरकार। हालांकि, अगर एक खंडित जनादेश है, तो

आयोग एक विस्तृत चरण-दर-चरण दृष्टिकोण की सिफारिश करता है और आगे इस बात पर जोर दिया कि "राज्यपाल, के माध्यम से जा रहे हैं

(राज्यपाल का) निर्णय, में बहुमत हासिल करने की सबसे अधिक संभावना है सभा। राज्यपाल का व्यक्तिपरक निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भूमिका "। कई विवादित दावों का सामना करने पर आयोग ने

यह सुझाव देता है कि राज्यपाल की ओर से सबसे विवेकपूर्ण उपाय होगा सदन के पटल पर दावों का परीक्षण करना।

मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना-बहुमत की परीक्षा की सिफारिश करना

यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई मौजूदा प्रमुख 618 है, सदन का पटल

मंत्री के पास बहुमत बना हुआ है, आयोग स्पष्ट रूप से

राज्यपाल को केवल इस आधार पर मंत्रालय को बर्खास्त करने से मना करता है कि

उनकी "व्यक्तिपरक संतुष्टि"।

विधानसभा का विघटन सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, यदि अंततः
व्यवहार्य मंत्रालय उभरने में विफल रहा, एक राज्यपाल के सामने दो हैं

विकल्प वह या तो विधानसभा को भंग कर सकता है या सिफारिश कर सकता है
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, इसे केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया

विघटन के प्रश्न का निर्णय करना। आयोग ने कहा कि

दृढ़ विचार कि उचित मार्ग होगा "लोगों को अनुमति देना

राज्य स्वयं मामलों को सुलझाएँ "। आयोग ने की सिफारिश

कि "राज्यपाल को पहले विधानसभा को भंग करने पर विचार करना चाहिए और

संबंधित राजनीतिक दलों के नेताओं और प्रमुख से परामर्श करें
चुनाव आयुक्त "।

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का पैरा 4.11.04 विशेष रूप से

ऐसी स्थिति जहाँ कोई भी एक दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं करता है और राज्यपाल को मुख्यमंत्री के चयन में वरीयता के क्रम का पालन करना चाहिए। प्रस्तावित वरीयता क्रम इस प्रकार है:

1 . दलों का गठबंधन जो चुनाव से पहले बनाया गया था।

2 . सरकार बनाने का दावा करने वाली सबसे बड़ी एकल पार्टी

"निर्दलीयों" सहित अन्य लोगों के समर्थन से

3 . चुनाव के बाद दलों का गठबंधन, जिसमें सभी भागीदार शामिल हैं

सरकार में शामिल होने वाला गठबंधन।

4 . चुनाव के बाद दलों का गठबंधन, कुछ दलों के साथ

सरकार बनाने वाला गठबंधन और शेष दल,

जिसमें बाहर से सरकार का समर्थन करने वाले "निर्दलीय" भी शामिल हैं।

सरकारिया आयोग ने देखा है कि कई स्थितियों में

राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता, राज्यपालों ने एक स्थिर सरकार को शामिल करने या बनाए रखने के लिए संविधान के तहत सभी संभावित कदमों को समाप्त किए बिना अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। संबंधित राज्यपालों ने न तो विरोधी दलों को मंत्रालय बनाने का उचित मौका दिया और न ही विधानसभा को भंग करने के बाद मतदाताओं को नई अपील करने की अनुमति दी। लगभग इन सभी मामलों की इस आधार पर आलोचना की गई है कि राज्यपाल, जबकि

राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें देना पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यवहार किया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ऐसी स्थितियों में दृष्टिकोण की कोई एकरूपता नहीं रही है और इन पहलुओं पर अध्याय 619 में चर्चा की गई है।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

' आपातकालीन प्रावधान '।

अध्याय VI में, सरकारिया आयोग ने आपातकालीन प्रावधानों से निपटा

हमारे आयामों, विविधताओं, असमानताओं और "बहुआयामी" देश में इस तरह के प्रावधान की आवश्यकता के बारे में संविधान निर्माताओं की चिंता को ध्यान में रखते हुए

संभवत: विभाजित वफादारी वाले लोग "। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि इस तरह के आपातकाल की स्थिति में संघ के पास प्रमुख शक्तियां होंगी -

पूरे देश में प्रशासन और कानून के सभी पहलुओं को नियंत्रित और निर्देशित करना। उन्होंने महसूस किया कि संविधान की विफलता या टूटना किसी राज्य में मशीनरी को असंभव और एक स्थिति होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ऐसा उत्पन्न हो सकता है जिसमें राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।

सभी आपातकालीन प्रावधानों में आम धागा यह है कि रिसॉर्ट

इस तरह का प्रावधान असाधारण परिस्थितियों में होना चाहिए जब वास्तविक और गंभीर स्थिति हो जिसमें कठोर कार्रवाई की आवश्यकता हो।

सरकारिया आयोग और इस न्यायालय ने भी लगातार हो रही आलोचनाओं पर ध्यान दिया है

अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के उपयोग की आवृत्ति और तरीके दोनों के संबंध में निरंतर बढ़ती तीव्रता में। सरकारिया आयोग ने

यह देखा गया कि आलोचना की कब्र यह है कि केंद्र में सत्ता में पार्टी के राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए अक्सर इन प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है। कुछ उदाहरणों में स्थितियों का उल्लेख किया गया है

जिसे अनुच्छेद 356 की शक्ति को अवैध रूप से नहीं तो अनुचित तरीके से लागू किया गया था। यह ध्यान दिया जाता है कि संवैधानिक निर्माताओं का इरादा यह नहीं था कि यह शक्ति होनी चाहिए अच्छी सरकार प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। यह भी ध्यान देता है कि इस शक्ति का उपयोग केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि मंत्रालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं।

क्या यह मौजूदा सरकार का बहुमत खोने का मामला है

या नए चुनावों के बाद नई सरकार की स्थापना, विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करने में राज्यपाल का कार्य केवल संविधान के संरक्षण के उद्देश्य से होना चाहिए न कि राजनीति को बढ़ावा देने के लिए! एक या दूसरे पक्ष का हित।

चुनावों में खंडित निर्णयों के वर्तमान संदर्भ में, उपरोक्त

चर्चा बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में सुझाए गए मानदंड हैं:

((i) उसे जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए।
((ii) वह राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए; 620

सर्वोच्च न्यायालय सुधार

[2006] 1 एस सी आर।

(iii) वह एक अलग व्यक्ति होना चाहिए और बहुत अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए।

राज्य की स्थानीय राजनीति के साथ; और

((iv) वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने इसमें बहुत अधिक भाग नहीं लिया हो।

राजनीति आम तौर पर और विशेष रूप से हाल के दिनों में।

इसकी ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा इसे गंभीरता से विवादित नहीं किया गया है

दुर्भाग्य से, सभी राजनीतिक दलों द्वारा मानदंडों का लगभग पूर्ण उल्लंघन किया गया है। यह देखा गया है कि एक दिन व्यक्ति सक्रिय रहता है। राजनीति में जितना वह मुख्यमंत्री या मंत्री का पद संभालता है

या एक पार्टी पद और लगभग अगले दिन या, किसी भी मामले में, उसके तुरंत बाद, उसी व्यक्ति को दूसरे राज्य में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है।

कोई भी शीतलन अवधि। आम तौर पर, राज्यपाल के रूप में संवैधानिक कार्यों को करते समय ऐसे व्यक्ति से दलगत राजनीति से अलगाव की उम्मीद करना मुश्किल है।

इस मुद्दे पर हम और कुछ नहीं कहना चाहेंगे और इस पहलू को इस पर छोड़ देंगे

राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को चर्चा करने और बहस करने और यदि संभव हो, तो सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए लागू और स्वीकार्य कुछ सामान्य न्यूनतम मापदंडों के साथ एक राष्ट्रीय नीति पर पहुंचने का विवेक। खामियां

इस स्तर पर, हम एक अन्य पक्षीय मुद्दे पर विचार कर सकते हैं, अर्थात् दलबदल।

एक बड़ी बुराई होना।

निस्संदेह, दलबदल एक बड़ी बुराई है। इसके लिए तर्क दिया गया था कि

सरकार ने कहा कि पद के प्रलोभन, मौद्रिक विचार, दबाव आदि से प्रेरित सिद्धांतहीन दलबदल लोकतांत्रिक ताने-बाने को नष्ट कर रहे थे। इस बुराई को नियंत्रित करने के

लिए संविधान (पचास-दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चूंकि विधायी उपाय से दलबदल को रोकने का वांछित लक्षय हासिल नहीं किया जा सका, इसलिए संविधान (नब्बे-प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा कानून को और मजबूत किया गया। तर्क यह है कि राज्यपाल की कार्रवाई को इस बुराई को रोकने के लिए निर्देशित किया गया था, ताकि इस तरह के दलबदल के आधार पर सरकार का गठन न हो।

किहोतो होलोहन के मामले में निर्णय पर रिलायंस को रखा गया है।

वी. ज़चिल्लू और ओआरएस।, [1992] सप. (2) एस. सी. सी. 651 इस बात को सामने लाएगा कि दलबदल लोकतंत्र और दसवीं अनुसूची के पोषित मूल्यों को कमजोर करते हैं

इस बुराई का मुकाबला करने के लिए संविधान में जोड़ा गया था। यह भी सही है कि इस दिशा में कानून को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि दसवीं अनुसूची के मौजूदा प्रावधान दलबदल को रोकने के वांछित लक्षय को प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे, रामेश्वर प्रसाद v.

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

621

91 वें संशोधन द्वारा, दलबदल को उस प्रावधान को हटाकर और अधिक कठिन बना दिया गया था, जिसमें एक तिहाई से वफादारी के सामूहिक स्थानांतरण को दलबदल के रूप में नहीं माना गया था और दलबदल को पूरी तरह से अस्वीकार्य और केवल विलय की अनुमति दी गई थी

91 वें संशोधन द्वारा यथा संशोधित दसवीं अनुसूची में उपबंधित तरीके से दलों का गठन।

किहोतो के मामले में, चुनौती दसवीं अनुसूची की वैधता के लिए थी,

जैसे वह उस समय खड़ा था। तर्क यह था कि यह कानून संविधान के मूल ढांचे के लिए विनाशकारी था क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांत, भारतीय संविधानवाद की एक बुनियादी विशेषता का उल्लंघन करता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति के अधिकार और विवेक की स्वतंत्रता के लिए विनाशकारी है क्योंकि प्रावधान निर्वाचित लोगों को दंडित करने और अयोग्य घोषित करने का प्रयास करते हैं।

इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रयोग के लिए प्रतिनिधि जो संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली के निर्वाह के लिए आवश्यक हैं। यह भी आग्रह किया गया कि सिद्धांतहीन राजनीतिक दलबदल एक बुराई हो सकती है, लेकिन यह होगा

बहुत बड़ी बुराइयों की शुरुआत तब होती है जब रोग की तुलना में गंभीर उपचारों को अपनाया जाता है। ऐसा कहा जाता था कि दसवीं अनुसूची को रद्द करने का प्रयास किया जाता है

नहाने के पानी के साथ बच्चा।

[

उपरोक्त-प्रस्तुतियों से निपटते हुए, न्यायालय ने नोट किया कि, वास्तव में,

वास्तविक प्रश्न यह था कि क्या भारतीय संवैधानिक योजना के तहत, क्या पद और पद के प्रलोभन से प्रेरित गैर-सैद्धांतिक दलबदल की विधायी रूप से कथित राजनीतिक बुराई के खिलाफ संवैधानिक सुधारों से कोई प्रतिरक्षा है?

मौद्रिक प्रलोभन। यह नोट किया गया कि याचिका में उठाए गए बिंदु वास्तव में दूरगामी हैं और कोई छोटे महत्व के नहीं हैं-'प्रासंगिकता की भावना और अपरिचित सेटिंग्स के संवैधानिक रूप से बताए गए सिद्धांतों' का आह्वान करते हैं। एक ओर भारतीय लोकतंत्र के ताने-बाने के लिए वास्तविक और आसन्न खतरा था जो एक निश्चित स्तर के राजनीतिक व्यवहार से उत्पन्न था, जो अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त राजनीतिक गुणों और नैतिकता की घोर और पूर्ण उपेक्षा से स्पष्ट था। ये प्रवृत्तियाँ राजनीतिक जीवन के लहजे को नीचा दिखाती हैं और अपनी व्यापक प्रवृत्तियों में लोकतंत्र के पोषित मूल्यों के अस्तित्व के लिए खतरनाक और कमजोर होती हैं। इसके माध्यम से विधायी निर्धारण होता है उस बुराई का मुकाबला करने के लिए प्रायोगिक संवैधानिक प्रक्रियाएँ। दूसरी ओर, कुछ दुष्प्रभाव और परिणाम हो सकते हैं जो ईमानदार विरोधियों और कर्तव्यनिष्ठ विरोधियों को भी प्रभावित और आहत कर सकते हैं। इस तर्क पर विचार करते हुए कि संवैधानिक उपचार संविधान की बुनियादी विशेषताओं का उल्लंघन था, यह देखा गया कि यह तर्क संविधान के आवश्यक जैविक और विकासवादी चरित्र और एक जीवित व्यक्ति के रूप में इसके लचीलेपन की अनदेखी करता है।

बदलते समय और जरूरतों की माँगों और मजबूरियों के लिए व्यवस्था करने के लिए इकाई। इस देश के लोगों को यह विश्वास करने के लिए धोखा नहीं दिया गया था कि 622

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजनीतिक संबद्धताओं के अनैतिक और सिद्धांतहीन परिवर्तनों का खतरा है कुछ ऐसा जिसके खिलाफ कानून असहाय है और जिसे विवेक की स्वतंत्रता के एक आवश्यक सहवर्ती के रूप में सहन किया जाना है। अनैतिक राजनीतिक दलबदल थे

लोकतंत्र को एक जीवित और सार्थक विश्वास बनाने वाले उन मूल्यों के महत्वपूर्ण अंगों को खा जाने वाले 'कैंकर' के रूप में वर्णित किया गया है।

यह तर्क दिया गया कि राज्यपाल केवल सदस्यों को रोकने की कोशिश कर रहे थे

राजनीतिक दल की घोषित नीतियों से स्वतंत्र रूप से मतदान करने के लिए अपने सदस्यों की स्वतंत्रता की अवधारणा के रूप में सदन को पार करने से न केवल इसकी सार्वजनिक छवि और लोकप्रियता को शर्मिंदा किया जाएगा, बल्कि इसमें जनता का विश्वास भी कम होगा, जो अंतिम विश्लेषण में, इसके निर्वाह का स्रोत है-नहीं, वास्तव में, इसका अस्तित्व ही है। विवाद पैरा पर आधारित है

144 किहोतो के मामले में निर्णय जो इस प्रकार है:

" लेकिन एक राजनीतिक दल साझा मान्यताओं के बल पर काम करता है। इसका

अपनी राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक उपयोगिता ऐसी साझा मान्यताओं पर निर्भर करती है।

और सामान्य रूप से सदस्यों को आगे बढ़ाने के लिए इसके सदस्यों की ठोस कार्रवाई माने गए सिद्धांत। इसके सदस्यों को अपनी इच्छानुसार मतदान करने की कोई भी स्वतंत्रता

राजनीतिक दल की घोषित नीतियों से स्वतंत्र रूप से न केवल
इसकी सार्वजनिक छवि और लोकप्रियता को शर्मिंदा करता है लेकिन जनता को भी कमजोर करता है

इसमें विश्वास जो, अंतिम विश्लेषण में, इसका स्रोत है

जीविका नहीं, वास्तव में, इसका अस्तित्व ही है। अंतर-पार्टी वाद-विवाद हैं

बेशक एक अलग बात। लेकिन एक अलग सार्वजनिक छवि बनी हुई है।

एक ही राजनीतिक दल के सदस्यों को राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाता है।

परंपरा, एक वांछनीय स्थिति के रूप में। ग्रिफ़िथ और राइल

" संसद, कार्य, अभ्यास और प्रक्रिया "(1989 संस्करण. पृष्ठ 119)

कहो:

" साझा मान्यताओं पर आधारित होने के कारण पार्टी के प्रति वफादारी आदर्श है। ए.
विभाजित पार्टी को मतदाता संदेह के साथ देखते हैं। यह है।

सदस्यों के लिए अपने नेताओं की राय स्वीकार करना स्वाभाविक है और

विभिन्न प्रकार के मामलों पर प्रवक्ता जिन पर वे सदस्य
कोई विशेषज्ञ ज्ञान नहीं है। आम तौर पर सदस्य स्वीकार करेंगे।

असहमत होने पर भी पार्टी में बहुमत निर्णय लेते हैं। यह है।

इसलिए यह समझ में आता है कि एक सदस्य जो पार्टी को अस्वीकार करता है

सहानुभूति की तुलना में आलोचना। आवश्यकता पड़ने पर मतदान से दूर रहना
पार्टी द्वारा वोट देना कुछ हद तक अविश्वसनीयता का सुझाव देना है। वोट करने के लिए

पार्टी के खिलाफ बेवफाई है। परहेज़ में दूसरों के साथ शामिल होना या
दूसरे पक्ष के साथ मतदान करने से साजिश की गंध आती है। "

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 के उप-पैरा (1) का खंड (बी) देता है

अयोग्यता लागू करके इस सिद्धांत और भावना पर प्रभाव

एक सदस्य पर जो "किसी भी" के विपरीत मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है राजनीतिक दल द्वारा
जारी किए गए निर्देश। हालांकि, प्रावधान,

दो अपवादों को पहचानता है: एक जब सदस्य से प्राप्त होता है

स्वयं इस संभावना को समायोजित करता है कि ऐसे अवसर हो सकते हैं जब
एक सदस्य निर्देश के विपरीत मतदान कर सकता है या मतदान से दूर रह सकता है।

" पैराग्राफ 2 (1) के खंड (बी) में कोई निर्देश "क्या वास्तव में सभी पक्ष की ओर से दिए गए निर्देशों या चाबुकों के वैधानिक परिणाम होते हैं

या क्या असाधारण प्रकृति और विस्तार को ध्यान में रखते हुए

शक्ति और बहुत गंभीर परिणाम जो प्रवाहित होते हैं

अयोग्यता का अत्यधिक दंड अभिव्यक्ति को दिया जाना चाहिए इसका अर्थ है वस्तुओं द्वारा इंगित संदर्भों तक अपने संचालन को सीमित करना।

और दसवीं अनुसूची के उद्देश्य। हम इस पहलू से निपटेंगे।

अलग से "।

91 वें के उद्देश्यों और कारणों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था।

संविधान संशोधन। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित दल-बदल विरोधी कानून को मजबूत और संशोधित करने के लिए कुछ वर्गों में समय-समय पर इस आधार पर मांग की जाती थी कि ये प्रावधान दल-बदल को रोकने के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। दसवीं अनुसूची की इस आधार पर भी आलोचना की गई कि इसने व्यक्तिगत दलबदल को अवैध घोषित करते हुए बड़े पैमाने पर दलबदल की अनुमति दी। भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 में दिए गए विभाजन के मामले में अयोग्यता से छूट के प्रावधान की, विशेष रूप से, इसके अस्थिर करने वाले प्रभाव के कारण कड़ी आलोचना हुई थी

सरकार के बारे में।

रिलायंस को लॉर्ड डिप्लॉक की प्रदर्शनी में भी रखा गया है

सिविल सेवा संघ परिषद के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय v. सिविल सेवा मंत्री, [1984] 3 All.ER 935 ने तर्कहीनता के इस पहलू पर कि "यह किसी निर्णय पर लागू होता है, इतना अपमानजनक या तर्क या स्वीकृत नैतिक मानकों की अवहेलना हो सकती है कि कोई भी समझदार व्यक्ति जिसने 'तय किए जाने वाले प्रश्न पर अपना दिमाग लगाया था, उस पर नहीं पहुंच सकता था"। यह तर्क दिया जाता है कि राज्यपाल के पास सूचना के कई स्रोत हैं-624

जिनसे वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बिहार राज्य में जो प्रक्रिया चल रही थी, वह लोकतंत्र के ताने-बाने को ही नष्ट कर रही थी और इसलिए,

दृष्टिकोण को अपमानजनक या तर्क की अवज्ञा के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से, जब ऐसे मामलों में सबूत मुश्किल है या असंभव नहीं है क्योंकि रिश्वतखोरी अंधेरे की आड़ में होती है और सौदे गोपनीयता में किए जाते हैं। अत: यह तर्क दिया जाता है कि

कि राज्यपाल का दृष्टिकोण अनुमेय और वैध दृष्टिकोण है।

बोम्मई के मामले में लगभग इसी तरह के तर्क को खारिज कर दिया गया है। पुहलहोफर बनाम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का दूसरा निर्णय। हिलिंगडन,

लंदन बरो काउंसिल, [1986] 1 All.ER 467 474 पर उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किया गया है, बोम्मई के मामले में न्यायमूर्ति सावंत द्वारा विचार किया गया है। यह इस प्रस्ताव पर निर्भर था कि जहां किसी तथ्य का अस्तित्व या अस्तित्व न होना किसी सार्वजनिक निकाय के निर्णय और विवेक पर छोड़ दिया जाता है और उस तथ्य में 'स्पष्ट' से लेकर 'बहस योग्य' से लेकर 'न्यायसंगत कल्पना योग्य' तक का एक व्यापक वर्णक्रम शामिल होता है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उस तथ्य का निर्णय उस सार्वजनिक निकाय पर छोड़ दे जिसे संसद ने निर्णय लेने की शक्ति सौंपी है, सिवाय उस मामले के जहां यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक निकाय, जानबूझकर या अनजाने में, विपरीत तरीके से कार्य कर रहा है। लेकिन वर्तमान मामले में, राज्यपाल द्वारा किसी भी प्रासंगिक सामग्री के बिना तैयार किया जाने वाला निष्कर्ष, 'बहस योग्य' या 'सिर्फ कल्पना योग्य' की श्रेणी में नहीं आ सकता है, यह 'स्पष्ट रूप से विकृत' की श्रेणी में आएगा। तथ्यों पर, अपरिहार्य अनुमान यह है कि

राज्यपाल का एकमात्र उद्देश्य सरकार बनाने के दावे को रोकना था और यह मामला 'दुर्भावना' की श्रेणी में आएगा।

वर्तमान मामले में सवाल यह नहीं है कि विधायक मतदान का उल्लंघन कर रहे हैं

संविधान द्वारा संशोधित दसवीं अनुसूची के प्रावधानों (91 वीं) संशोधन), जैसा कि हम वर्तमान में दिखाएंगे।

निश्चित रूप से, किहोतो के सिद्धांतों के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता है।

दलबदल के बुरे प्रभावों के बारे में मामला लेकिन उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है
मुद्दे में बिंदु का निर्धारण। सदस्यों को मतदान करने से रोकने का चरण

जिस राजनीतिक दल से वे संबंधित थे, उनकी घोषित नीतियों के खिलाफ नहीं था

पहुँच गया। यदि विधायक इस तरह से मतदान करते हैं ताकि अयोग्य होने का खतरा हो,

वास्तव में, राज्यपाल की रिपोर्टों का उद्देश्य किसी भी मतदान और गतिरोध को रोकना था
सरकार बनाने का दावा।

निर्विवाद रूप से, एक राज्यपाल को संरक्षित करने, सुरक्षा करने का कर्तव्य सौंपा
जाता है

और संविधान और कानूनों की रक्षा करना, एक संगत कर्तव्य है और 625

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. 1. [सभरवाल, सी. जे.]

लोकतंत्र को संरक्षित करने का दायित्व और राजनीतिक 'कैंकर' की अनुमति नहीं देना

भारतीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंगों को तोड़ने के लिए दलबदल। लेकिन वर्तमान मामले के
तथ्यों पर, हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि राज्यपाल 27 तारीख की रिपोर्टों द्वारा

अप्रैल और 21 मई, 2005 ने उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। प्रासंगिक
होने की तो बात ही छोड़िए, राज्यपाल के पास यह मानने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि
राजनीतिक दलों का कोई वैध पुनर्गठन नहीं था और यह स्पष्ट था

अनुचित, अवैध, अनैतिक और असंवैधानिक तरीकों से प्रेरित दलबदल द्वारा लोकतंत्र को
विकृत करना।

27 अप्रैल, 2005 की रिपोर्ट में (1) धोखाधड़ी के गंभीर प्रयास का उल्लेख किया
गया है।

बहुमत; (2) विभिन्न तरीकों से विधायकों को जीतना; (3) विभाजन के लिए दलों को निशाना
बनाना; (4) उच्च दबाव वाले कदम; (5) जाति, पद, धन आदि जैसे विभिन्न प्रलोभन देना। ;
और (6) घोड़े का व्यापार। कर्नाटक और नागालैंड के राज्यपालों द्वारा लगभग इसी तरह की
रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कर्नाटक और नागालैंड की विधानसभा भंग हो गई,

जिसे बोम्मई के मामले में अमान्य कर दिया गया। इसके अलावा, यह तर्क कि केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल, 2005 की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की, कोई प्रासंगिकता नहीं है और इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

चूंकि सवाल यह है कि राज्यपाल किस तरह से बहुत तेजी से और अनुचित जल्दबाजी में आगे बढ़े, यह पाते हुए कि एक राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करने के करीब हो सकता है और स्थिति ऐसी हो गई थी कि सरकार बनाने का दावा किया जा सकता है, जिसके कारण 21 मई, 2005 की रिपोर्ट आई। यह इस संदर्भ में है कि राज्यपाल का कहना है कि स्थापित करने के बजाय व्यवस्था को विकृत करके हासिल किए गए बहुमत के आधार पर सरकार, यह बेहतर होगा कि लोगों/मतदाताओं को लोगों से जनादेश प्राप्त करने का एक और अवसर प्रदान किया जा सके। इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि इसका उद्देश्य किसी विशेष राजनीतिक दल को दावा करने से रोकना था, न कि चिंता का घोषित उद्देश्य राजनीतिक प्रणाली को विकृत करने की अनुमति नहीं देना था, जैसा कि आग्रह किया गया था। इस तरह का पाठ्यक्रम पूरी तरह से अवैध और अनियमित है और इसे दुर्भावनापूर्ण के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए। द.

पहुँच गया। वहाँ पहुँचने की अनुमति नहीं थी। यदि इतना बहुमत प्रस्तुत किया गया था और राज्यपाल एक वैध राय बनाते हैं कि पार्टी दावा कर रही है राज्य को स्थिर सरकार प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा, जो कि 1

626

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2006] 1 एस सी आर।

अलग स्थिति। किसी भी परिस्थिति में, राज्यपाल की कार्रवाई को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है, जब इसका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल को सरकार के गठन का दावा करने से रोकना हो। चुनाव के बाद, हर वास्तविक प्रयास ऐसा बनाया जाना है जो एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना में मदद करता है, चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल हो।

संविधान की व्याख्या और राजनीतिक दलों का महत्व

संविधान की व्याख्या के लिए प्रासंगिक सिद्धांतों के लिए, हमारा ध्यान

हार्वर्ड लॉ रिव्यू, वॉल्यूम में इज़राइल के सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अहरोन बराक जो कहते हैं, उसकी ओर आकर्षित किया गया था। 116 (2002-2003) विशेष रूप से संविधान की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के पहलू से संबंधित। विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित रूप में ध्यान दिया है:

" संविधान की व्याख्या करने का कार्य उससे काफी अलग है।

एक क़ानून बनाने का। एक क़ानून वर्तमान अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करता है। इसे आसानी से लागू किया जाता है और उतनी ही आसानी से निरस्त किया जाता है। एक संविधान, इसके विपरीत,

भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। इसका कार्य एक प्रदान करना है

सरकार के वैध अभ्यास के लिए निरंतर ढांचा
शक्ति और, जब किसी विधेयक या अधिकारों के चार्टर द्वारा जोड़ा जाता है,

व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं का निरंतर संरक्षण। एक बार लागू होने के बाद,
इसके प्रावधानों को आसानी से निरस्त या संशोधित नहीं किया जा सकता है। अत: यह आवश्यक है कि -

नए समाज से मिलने के लिए समय के साथ विकास और विकास में सक्षम होना,

राजनीतिक और ऐतिहासिक वास्तविकताओं की अक्सर इसके निर्माताओं द्वारा कल्पना नहीं की जाती है। द.

न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है और व्याख्या करने में आवश्यक है।

इसके प्रावधानों को ध्यान में रखें।

यह आगे कहा जाता है कि राजनीतिक प्रश्न सिद्धांत, विशेष रूप से, छूट देता है।

सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों को कांग्रेस और राष्ट्रपति को इस आधार पर सौंपा गया है कि संविधान इन क्षेत्रों के लिए अन्य शाखाओं को जिम्मेदारी देता है, या उनके संकल्प में विवेकाधीन, बहु-केंद्रित निर्णय शामिल होंगे जिनमें निर्णय के लिए असतत मानदंडों का अभाव है और इस प्रकार अधिक लोकतांत्रिक शाखाओं द्वारा बेहतर तरीके से संभाला जाता है।

वास्तव में, बोम्मई के मामले में न्यायिक समीक्षा का दायरा है

उन सिद्धांतों के अनुरूप जिन पर भरोसा करने की मांग की गई थी।

इस प्रस्ताव के समर्थन में कि संसद में लोकतंत्र है

राजनीतिक दलों का महत्व और संवैधानिक व्यवस्था की वह व्याख्या

प्रावधानों को राजनीतिक दलों पर आधारित उक्त बुनियादी संरचना को आगे बढ़ाना चाहिए, हमारा ध्यान डिज़ाइनिंग फ़ेडरलिज्म-ए थ्योरी ऑफ़ सेल्फ 627 लिखने की ओर आकर्षित किया गया था।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

स्थायी संघीय संस्थान और राजनीतिक दलों के बारे में क्या कहा जाता है

संघीय राज्य जो निम्नानुसार है:

" राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र का निर्माण किया और आधुनिक लोकतंत्र है पार्टियों के मामले में अकल्पनीय बचत।

स्काट्श्नाइडर

1942: आई.

यहाँ संघीय सरकार के संगठन में एक कारक है जो है

प्राथमिक महत्व लेकिन जिसके लिए सुनिश्चित या प्रदान नहीं किया जा सकता है

एक संविधान-एक अच्छी पार्टी प्रणाली

कहाँ

1953: 86

सामान्य सामाजिक स्थितियाँ जो भी हों, यदि कोई हों, जो संघीय व्यवस्था को बनाए रखती हैं।

सौदेबाजी, एक संस्थागत स्थिति है जो प्रकृति को नियंत्रित करती है

सभी मामलों में सौदा. जिससे मैं परिचित हूँ। यह वह है

पार्टी प्रणाली की संरचना, जिसे मुख्य माना जा सकता है

पृष्ठभूमि सामाजिक स्थितियों के बीच परिवर्तनशील हस्तक्षेप और

संघीय सौदे की विशिष्ट प्रकृति।

रिकर

1964: 136

एक ऐसे देश में जिसे हमेशा एकजुट बल की आवश्यकता थी

संस्थाओं, राष्ट्रीय दलों, अपने सभी दोषों के लिए, बनना था

एक शुरुआती घंटे में मशीनरी के प्राथमिक और आवश्यक भागों

राज्य के प्रति पुरुषों की निष्ठा को व्यक्त करने के लिए सरकार, आवश्यक वाहन।

हॉफस्टैडर

1969: 70-1

यह तर्क दिया जाता है कि राजनीतिक दल न केवल प्रांतीय शिकायतों को प्रसारित करने का मुख्य साधन हैं, बल्कि केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत प्रवृत्तियों को वैध बनाने का भी मुख्य साधन हैं। यह विवाद उस राजनीतिक दल के कथित रुख के खिलाफ एलजेपी के दो-तिहाई विधायकों के कथित रुख के संबंध में किया गया है।

पार्टी।

हमें डर है कि वर्तमान मामले के पहलू पर, उपरोक्त अवधारणा और

राजनीतिक दलों की प्रासंगिकता हमारे उद्देश्य के लिए यह तय करने के लिए काफी प्रासंगिक नहीं है कि राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सरकार के गठन के दावे का कथित रूप से समर्थन करने के लिए कथित रूप से जिस मार्ग को अपनाने का फैसला किया था, उसे क्यों और कैसे अपनाया था।

628

[2006] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नैतिकता

हम नैतिकता के उस पहलू से भी निपट सकते हैं जिस पर जोर दिया जाना चाहिए। द.

नैतिकता का सवाल निश्चित रूप से बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण मामला है। यह कई संवैधानिक विशेषज्ञों, कानूनी दिग्गजों, न्यायविदों और राजनीतिक नेताओं का ध्यान आकर्षित कर रहा है। नैतिकता की अवधारणा भी बदल रही है। समय-समय पर जमीनी वास्तविकताओं और स्थिति की मजबूरी को भी ध्यान में रखते हुए, जिसमें एकल पार्टी सरकार के विपरीत गठबंधन शासन के पहलू और प्रासंगिकता शामिल है। आर्थिक क्षेत्र में भी, अवधारणा

नैतिकता सरकार की नीति और प्राथमिकताओं का विषय रहा है। सरकार प्रोत्साहन दे सकती है, जिसे आदर्श रूप से अनैतिक माना जा सकता है।

और अनैतिक, लेकिन जहां तक सरकार का संबंध है, काले धन का पता लगाने के लिए प्रोत्साहन देना आवश्यक हो सकता है। आर. के. गर्ग और अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस।, [1981] 4 एस. सी. सी. 675, पैरा 18 और 31। ऐसे पहलुओं को उच्च संवैधानिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ना मुश्किल हो सकता है,

प्रत्येक मामले के आधार पर, मामले के तथ्यों और संवैधानिक अधिकारियों के व्यक्तिगत सांचे पर निर्भर करता है। इन सभी अभेद्यताओं के साथ, संविधान इस तरह की अनैतिकताओं की धारणा के आधार पर विधानसभाओं को भंग करने पर विचार नहीं करता है ताकि यह संतुष्टि हो सके कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें सरकार भारत के संविधान की नहीं हो सकती है।

अनुच्छेद 356 और बोम्मई का मामला

संविधान का अनुच्छेद 356 (1) इस प्रकार है:

" 356. (1) संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान राज्य। - (1) यदि राष्ट्रपति, राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर

राज्य या अन्यथा, संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें राज्य सरकार के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है

इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा

((क) सरकार के सभी या किसी भी कार्य को स्वयं ग्रहण करें।

राज्य की और निहित या प्रयोग करने योग्य सभी या कोई भी शक्तियाँ

राज्यपाल या राज्य के किसी अन्य निकाय या प्राधिकारी द्वारा

राज्य का विधानमंडल;

(ख) घोषणा करें कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां -

संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत प्रयोग करने योग्य;

(ग) ऐसे आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान करें जो प्रतीत होते हैं -

राष्ट्रपति का रामेश्वर प्रसाद को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय होना।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

629

राज्य में किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संविधान:
बशर्ते कि इस खंड की कोई भी बात राष्ट्रपति को प्राधिकृत नहीं करेगी

द्वारा निहित या प्रयोग करने योग्य किसी भी शक्ति को अपने पास ग्रहण करना

एक उच्च न्यायालय, या किसी के संचालन को पूरी तरह से या आंशिक रूप से निलंबित करना

उच्च न्यायालयों से संबंधित इस संविधान का प्रावधान।

अनुच्छेद 356 (1) के तहत शक्ति एक आपातकालीन शक्ति है लेकिन यह एक आपातकालीन शक्ति नहीं है।

पूर्ण शक्ति। आपातकाल का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जो सामान्य नहीं है, एक स्थिति

जो तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की मांग करता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को अनुच्छेद 355 द्वारा दिए गए दायित्व का निर्वहन करने के लिए असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है। यह रक्षा करने का एक उपाय है और संविधान की रक्षा करें। राज्यपाल संविधान और कानूनों के संरक्षण, सुरक्षा और रक्षा के लिए अनुच्छेद 159 द्वारा निर्धारित शपथ लेते हैं।

अपनी क्षमता से। अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति सशर्त है, शर्त यह है कि अनुच्छेद 356 (1) द्वारा राष्ट्रपति की संतुष्टि का गठन किया जाए। राष्ट्रपति की संतुष्टि मंत्रिपरिषद की संतुष्टि

है। के रूप में अनुच्छेद 74 (1) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है।

मंत्रियों का। अनुच्छेद 74 (2) के सादे पाठ में कहा गया है कि क्या मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को कोई, और यदि हां, तो क्या सलाह दी गई थी, इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, यह सूचित करता प्रतीत हो सकता है कि न्यायालय को ऐसी सलाह की जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन बोम्मई ने कहा है कि अनुच्छेद 74 (2) उस सामग्री की जांच के खिलाफ बाधा नहीं है जिसके आधार पर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा जारी की है। न्यायमूर्ति सावंत, पैरा 86 में कहते हैं कि:

" इसके अलावा क्या है, हालांकि अनुच्छेद 74 (2) न्यायिक समीक्षा को अब तक प्रतिबंधित करता है

मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह में कोई दिलचस्पी नहीं है
राष्ट्रपति या ऐसी सलाह के कारण। हालाँकि, अदालतें हैं,

जाँच में न्यायसंगत है कि क्या आधार पर कोई सामग्री थी

जिसके लिए सलाह दी गई थी, और क्या यह ऐसे लोगों के लिए प्रासंगिक था सलाह और राष्ट्रपति इस पर कार्रवाई कर सकते थे। अतः जब

अनुच्छेद 74 (2) में निहित निषेध उनके अधिकार को नकारता नहीं है
ऐसी किसी भी सामग्री के तथ्यात्मक अस्तित्व के बारे में जानें। ”

यह आगे कहा गया कि संसद 630 में जाने की हकदार होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2006] आई एस. सी. आर.

मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के आधार पर सामग्री और,

इसलिए, सामग्री के संबंध में गोपनीयता अलंघनीय नहीं रह सकती है। कहा गया है।

कि -

' जब उद्घोषणा को प्रथम दृष्टया चुनौती दी जाती है

इसकी अयोग्यता के संबंध में, बोझ संघ पर होगा

सरकार को यह संतुष्ट करने के लिए कि ऐसी सामग्री मौजूद है जो दर्शाती है कि

सरकार के अनुसार नहीं चलाया जा सका
संविधान के प्रावधान। चूंकि ऐसी सामग्री होगी

विशेष रूप से केंद्र सरकार की जानकारी के भीतर,

ऐसी सामग्री के अस्तित्व को साबित करना संघ पर होगा
सरकार "।

इसी तर्ज पर, जीवन रेड्डी, जे की राय है। :

" कला का खंड (2)। 74 , अपने उचित परिप्रेक्षय में समझा जाता है, इस प्रकार
है

एक सीमित पहलू तक सीमित। यह गोपनीयता की रक्षा और संरक्षण करता है

राष्ट्रपति और उनके मंत्रिपरिषद के बीच विचार-विमर्श।

वास्तव में, सी. आई. (2) यह उप-सेक का पुनरुत्पादन है। (4) एस. 10 का

भारत सरकार अधिनियम, 1935। (भारत सरकार अधिनियम ने किया

इसमें कला के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं है। 74 (1) जैसे वह पहले खड़ा था
या उपरोक्त संशोधनों के बाद)। सी. आई. का दायरा। (2) होना चाहिए

इसके वैध क्षेत्रों से परे विस्तारित नहीं किया जाएगा। किसी भी मामले में, यह नहीं
हो सकता है

परिषद को प्रतिरक्षा प्रदान करने के रूप में पढ़ा या समझा जाए

मंत्री या संबंधित मंत्री/मंत्रालय को समझाने, बचाव करने और

राष्ट्रपति के आदेशों और कार्यों को उनके प्रयोग में उचित ठहराएँ

कार्य। कला में निहित सीमित प्रावधान। 74 (2) नहीं कर सकते

उसके कार्यों पर एक न्यायालय में सवाल उठाया जाता है, यह परिषद के लिए है
राष्ट्रपति की कार्रवाई या आदेश के बाद से मंत्रियों को इसे उचित ठहराने के लिए

माना जाता है कि जो को कला के अनुसार लिया गया है। 74 (1) . जिस बारे में

किस मंत्री या किस मंत्रालय का कौन सा अधिकारी आगे आता है

आदेश/कार्रवाई का बचाव करना उन्हें तय करना है और अदालत को करना है

भारत सरकार की कार्यकारी शक्ति से संबंधित,
स्थिति बहुत सरल है। यह अधिनियम/आदेश का प्रतिनिधित्व नहीं करता है

राष्ट्रपति ने अपने कार्यों का अभ्यास किया/लिया और इसलिए वहाँ है
मंत्री द्वारा उन्हें कोई सहायता या सलाह देने का कोई अवसर नहीं। यह 631 है

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

भारत सरकार का अधिनियम/आदेश, हालांकि इसके नाम पर व्यक्त किया गया है

राष्ट्रपति। यह संबंधित मंत्री या मंत्रालय के लिए है, जिसे

कार्य रक्षा करने के लिए व्यवसाय के नियमों के तहत आवंटित किया जाता है और

इस तरह की कार्रवाई/आदेश को उचित ठहराएँ।

हमारी सम्मानजनक राय में, उपरोक्त दायित्व से बचा नहीं जा सकता है।

कला के तहत शरण लेकर। 74 (2) . तर्क है कि सलाह

राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई सामग्री में सामग्री भी शामिल है और इसलिए,
भारत संघ से सामग्री का खुलासा करने का आह्वान करना राशि होगी

सलाह का खुलासा करने के लिए मजबूर करना है, अगर हम ऐसा कह सकते हैं

आदरपूर्वक, मितव्ययिता में लिप्त होना। सामने रखी गई सामग्री
मंत्री/मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते हैं।

सलाह का हिस्सा बनें। सलाह वह है जो उक्त सामग्री पर आधारित है।
सामग्री सलाह नहीं है। राष्ट्रपति के समक्ष सामग्री रखी जा सकती है।

उसे प्रस्तुत किया जाना उचित है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि
के समर्थन में राष्ट्रपति के समक्ष रखी जाने वाली सामग्री

सलाह अपने आप में सलाह बन जाती है। कोई समझ सकता है कि क्या सलाह है

लिखित रूप में निविदा; ऐसे मामले में कि लेखन सलाह है और है

इस बात की सराहना करें कि सहायक सामग्री कैसे सलाह का हिस्सा बन जाती है।
उत्तरदाता यह नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति जो कुछ भी देखते हैं-या

राष्ट्रपति के सामने जो कुछ भी रखा जाता है वह निषिद्ध सामग्री बन जाती है।
और न्यायालय द्वारा देखा या तलब नहीं किया जा सकता है। कला. 74 (2) होना चाहिए।

संपूर्ण संविधान के संदर्भ में व्याख्या और समझाया गया

प्रणाली। इसके मापदंडों पर अनुचित जोर दिया जाएगा और इसका विस्तार किया
जाएगा। मूल्यवान
संवैधानिक गारंटी। इन कारणों से, हम पाते हैं कि क्या मुश्किल है

इस आधार पर राजस्थान राज्य में तर्क से सहमत होना, जहाँ तक

क्योंकि यह हमारे अधिकार के विपरीत है।

बोम्मई और असहमति ने न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार किया है

राजस्थान राज्य के मामले में लिए गए दृष्टिकोण से व्यक्त किया गया है।

उपरोक्त दृष्टिकोण व्यक्तिपरकता में भी वस्तुनिष्ठता को दर्शाता है। द.

संवैधानिकता या सरकार की संवैधानिक प्रणाली निरंकुशता का तिरस्कार करती है।

यह कानून के शासन पर आधारित है जिसमें व्यक्तिपरक संतुष्टि को संविधान के प्रावधानों द्वारा
प्रदान की गई निष्पक्षता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यह रेखा

मारू राम बनाम से भी स्पष्ट है। भारत संघ और ओआरएस। , [1981] 1 एससीसी 107।
बोम्मई की गहन जांच पर यह भी स्पष्ट होगा कि तीन विधानसभाओं के विघटन को अवैध घोषित
किया गया था, लेकिन इससे पहले कि हम उस 632 पर वापस लौटें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2006] आई एस. सी. आर.

निर्णय, इसकी आशंका सहित एक संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

हमारे संस्थापकों द्वारा व्यक्त किए गए दुर्व्यवहार पर ध्यान दिया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 ने प्राथमिकता के लिए कार्यकाल निर्धारित किया है।

राज्यों पर संघ का। यह समझाया गया है कि इसके लिए तर्क

अनुच्छेद 355 को लागू करना राज्य और केंद्र सरकारों के कामकाज का स्पष्ट रूप से सीमांकन करना और राज्य के मामलों में संघ द्वारा किसी भी प्रकार के गैर-सैद्धांतिक आक्रमणों को रोकना था। यह महसूस किया गया कि इसके माध्यम से

अनुच्छेद 355 और 356 की स्पष्ट भाषा के अनुसार, संघ

संवैधानिक रूप से प्रावधानों में निर्धारित कुछ सीमित परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है।

वर्तमान में अनुच्छेद 355 का उल्लेख करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने तर्क दिया था कि

" इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम प्रांतों को पूर्ण शक्तियां प्रदान कर रहे हैं

और उन्हें उनके अपने क्षेत्रों के भीतर संप्रभु बनाना यह प्रावधान करना आवश्यक है कि यदि प्रांतीय क्षेत्र पर कोई आक्रमण किया जाता है, तो यह इस दायित्व के कारण है। (टी. के. थोपे, डॉ. अम्बेडकर और संविधान का अनुच्छेद 356 [1993] 4 एस. सी. सी. (जर्नल) 1]। इस तर्क के अनुसार, डॉ. अम्बेडकर ने आगे समझाया कि अनुच्छेद 356 का सहारा लेने से पहले "राष्ट्रपति सबसे पहले एक ऐसे प्रांत को चेतावनी जारी करेंगे जिसने गलती की है, कि चीजें उस तरह से नहीं हो रही हैं जिस तरह से वे संविधान में होने वाले थे। यदि चेतावनी विफल हो जाती है तो उसके लिए दूसरी बात यह होगी कि वह प्रांत के लोगों को मामलों को खुद निपटाने की अनुमति देने के लिए चुनाव का आदेश दे। जब वे दो उपाय विफल हो जाएँगे तभी वह इस अनुच्छेद का सहारा लेंगे। डॉ. अम्बेडकर ने स्वीकार किया कि इन अनुच्छेदों का "दुरुपयोग किया जा सकता है" और वह "इस बात से पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकते कि इन अनुच्छेदों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने की संभावना है"। लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि

"इस तरह की आपत्ति संविधान के हर हिस्से पर लागू होती है जो केंद्र को प्रांतों को ओवरराइड करने की शक्ति देता है" और कहा कि "हमें उचित बात करनी चाहिए।

उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के लेखों को कभी भी लागू नहीं किया जाएगा और वे एक मृत पत्र बने रहेंगे। (संविधान सभा की बहस (खंड IX, संशोधित संस्करण)। 175-177) .

राजस्थान राज्य के अनुच्छेद 356 के तहत न्यायिक समीक्षा का दायरा। भारत संघः

राजस्थान राज्य के मामले में, पाँच के बीच व्यापक सहमति थी।

सात न्यायाधीशों में से कि न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण या "पूरी तरह से बाहरी या अप्रासंगिक आधारों" पर किया गया है।

कुछ विद्वान न्यायाधीशों ने नियम को संकीर्ण शब्दों में कहा है और कुछ अन्य ने 633 कहा है।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

खंड (5) को हटाने से न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित नहीं हुआ है, लेकिन इसका विस्तार किया है।

बोम्मई के मामले में न्यायमूर्ति रेड्डी ने ध्यान दिया है, जहाँ तक यह प्रासंगिक था,

राजस्थान राज्य (उपर्युक्त) के मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दी गई छह रायों में से प्रत्येक का अंतर्निहित अनुपात निम्नानुसार हैः

" बेग, सी. जे. की राय में कई सूत्र शामिल हैं -

सोचा। इन्हें संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता हैः

(i) अनुच्छेद 356 की भाषा और 1950 से चली आ रही प्रथा से पता चलता है। कि केंद्र सरकार राज्य के खिलाफ अपनी इच्छा को लागू कर सकती है

इस सवाल के संबंध में कि राज्य सरकारें कैसे
काम करना चाहिए और किसे सत्ता की बागडोर संभालनी चाहिए।

((ii) अनुच्छेद 365 (5) और अनुच्छेद 74 (2) के आधार पर ऐसा करना असंभव है -

राष्ट्रपति की संतुष्टि पर सवाल उठाने के लिए न्यायालय। यह तय करना है
केवल उन तथ्यों के आधार पर मामला जो स्वीकार किए गए हों।

राष्ट्रपति द्वारा या न्यायालय के समक्ष रखे जाने पर,
(iii) अनुच्छेद 356 (1) की भाषा बहुत व्यापक है। यह अपेक्षित है कि

इस शक्ति के प्रयोग को दिशा देने के लिए परंपराओं का विकास किया जाता है।

न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब शक्ति का व्यापक रूप से उपयोग
किया जाता है। विकृत और
अनुचित तरीके से पेटेंट का दुरुपयोग

एक अन्य स्थान पर यह कहते हुए कि यदि "एक संवैधानिक या कानूनी रूप से निषिद्ध
है या बाह्य या संपार्श्विक
उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की जाती है

घोषणा, इसे निरस्त किया जा सकता है। सवाल यह है
क्या किसी राज्य की विधान सभा में बहुमत वाले दल के पास है

निर्वाचक मंडल से पूरी तरह से अलग होना कोई मुद्दा नहीं है

तय करने के लिए अदालत।

((iv) केंद्र सरकार का आकलन है कि एक नया मौका है।

कुछ राज्यों में मतदाताओं को दिया जाना चाहिए और साथ ही

सवाल यह नहीं है कि विधानसभाओं को कब भंग किया जाए
अनुच्छेद 356 के लिए विदेशी। यह नहीं कहा जा सकता है कि द्वारा निर्धारित कारण

केंद्र सरकार द्वारा उनके द्वारा उठाए गए कदम प्रासंगिक नहीं हैं

अनुच्छेद 356 में अंतर्निहित उद्देश्यों के लिए।

हम तुरंत कह सकते हैं कि हम उनके साथ सम्मानजनक असहमति में हैं।

प्रस्ताव (i), (ii) और (iv) पूरी तरह से। जहाँ तक प्रस्ताव (iii) का संबंध है, यह लक्षय से बहुत दूर नहीं है और वास्तव में हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है, जैसा कि हम वर्तमान में दिखाएंगे। वाई. वी. चंद्रचूड़, जे. न्यायिक समीक्षा के दायरे पर, विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि जहां भारत संघ द्वारा बताए गए कारण पूरी तरह से बाहरी हैं, वहां न्यायालय दुर्भावना के आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है।

विश्वास करते हैं। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि न्यायिक जांच "यह देखने के सीमित उद्देश्य के लिए उपलब्ध है कि क्या कारणों में कोई तर्कसंगत संबंध है।

प्रस्तावित कार्रवाई के साथ "। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि पर निर्णय नहीं दे सकता है कि क्या स्थिति के बारे में कोई अन्य दृष्टिकोण उचित रूप से संभव है।

अपने समक्ष मामले के तथ्यों की ओर रुख करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपने जवाबी हलफनामे में दिए गए आधारों को अनुच्छेद 356 के लिए अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है। अदालत ने

मामले में गहराई से नहीं जा सकता है और न ही अदालत यह जांच करेगी कि क्या

जवाबी हलफनामे में बताए गए कारणों के अलावा कोई अन्य कारण थे।

पी. एन. भगवती और ए. सी. गुप्ता, जे. जे. विद्वान न्यायाधीशों ने कहा

उनकी राय में निम्नलिखित प्रस्तावः अनुच्छेद के तहत कार्रवाई

356 राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर लिया जाना चाहिए।

संतुष्टि उद्देश्यपूर्ण नहीं होती है। कोई न्यायिक रूप से खोज करने योग्य नहीं हैं

और प्रबंधनीय मानक जिनके द्वारा न्यायालय जांच कर सकता है राष्ट्रपति की संतुष्टि की शुद्धता। संतुष्टि मिलनी चाहिए

के मूल्यांकन के आधार पर यह काफी हद तक राजनीतिक प्रकृति का है

कई अभेद्य तथ्यों के अलावा विभिन्न तथ्य और कारक

जैसा कि कहा जा सकता है। हालाँकि, यदि शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण रूप से किया जाता है या पूरी तरह से बाहरी या अप्रासंगिक आधारों पर आधारित है, न्यायालय

इसकी जांच करने का अधिकार क्षेत्र होगा। खंड (5) भी प्रतिबंध नहीं है।

जब विवाद यह है कि कोई संतुष्टि नहीं थी।

अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का दायरा -

विद्वान न्यायाधीश आयोजित-एक संकीर्ण न्यूनतम क्षेत्र तक सीमित है: मई

कि ज्यादातर मामलों में, यह मुश्किल होगा, यदि असंभव नहीं है,

उपरोक्त पर अनुच्छेद 356 (1) के तहत शक्ति के प्रयोग को चुनौती दें।

सीमित आधार, क्योंकि तथ्य और परिस्थितियाँ जिन पर

संतुष्टि आधारित है, ज्ञात नहीं होगी। हालांकि, जहां यह 635 है।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

यह आधार कि यह दुर्भावनापूर्ण है या पूरी तरह से बाहरी है और अप्रासंगिक आधार "।

हम बड़े सम्मान के साथ कह सकते हैं कि हमें इससे सहमत होना मुश्किल लगता है।

उपरोक्त सूत्रीकरण कुल मिलाकर। हम केवल बयानों से सहमत हैं।

न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के अनुमेय आधारों के संबंध में और

खंड (5) का प्रभाव, जैसा कि उसने तब प्राप्त किया था। हम भी व्यापक रूप से सहमत हैं

पहला प्रस्ताव, हालांकि उसमें बताए गए पूर्ण शब्दों में नहीं।

गोस्वामी और उन्तवालिया, जे. जे. गोस्वामी की अलग-अलग राय और उन्तवालिया, जे. जे.। एक तथ्य पर जोर दें, अर्थात्, कि

काउंटर में बताए गए तथ्य-गृह मंत्री द्वारा दायर हलफनामा नहीं हो सकता है

कार्रवाई को "दुर्भावनापूर्ण, अप्रासंगिक या अप्रासंगिक" कहा जाए

अदालत में हमला नहीं किया जा सकता है।

फजल अली, जे. विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि:

1977 लोकसभा चुनाव को अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

यह नहीं कहा जा सकता है कि निकाले गए निष्कर्ष का अनुच्छेद के साथ कोई संबंध नहीं था

356. "

बोम्मई का मामला

नौ न्यायाधीशों की पीठ ने विघटन की वैधता पर विचार किया

कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों की विधानसभाएँ। छह राज्यों में से बहुमत ने कर्नाटक, नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं के विघटन को भी असंवैधानिक करार दिया। छह राय व्यक्त की गई हैं। कुछ मुद्दों पर सर्वसम्मति है, इसी तरह विभिन्न मुद्दों पर कई विचारों में विविधता है। कर्नाटक तथ्य

कर्नाटक के मामले में तथ्य यह था कि जनता पार्टी

राज्य विधानमंडल में बहुमत पार्टी ने सरकार का गठन किया था

1 अगस्त, 1988 को पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेगड़े के इस्तीफे के बाद 30 अगस्त, 1988 को श्री एस. आर. बोम्मई का नेतृत्व।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्यपाल ने राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा गया था कि जनता पार्टी में मतभेद थे जिसके कारण श्री हेगड़े ने इस्तीफा दे दिया था और नई पार्टी के गठन के बाद भी। जनता दल, मतभेद और दलबदल थे। समर्थन में, राज्यपाल ने उन्हें प्राप्त हुए 19 पत्रों का उल्लेख किया। उन्होंने आगे कहा कि उक्त विधायकों द्वारा समर्थन वापस लेने के मद्देनजर, मुख्यमंत्री श्री बोम्मई ने ऐसा नहीं किया विधानसभा में बहुमत प्राप्त करना और इसलिए संविधान के तहत यह अनुचित था कि राज्य को एक ऐसी कार्यपालिका द्वारा प्रशासित किया जाए जिसमें मंत्री परिषद हो जो सदन में बहुमत प्राप्त नहीं करती थी। उन्होंने यह भी कहा कि कोई अन्य

राजनीतिक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति से अनुशंसा की कि उन्हें अनुच्छेद 356 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। राज्यपाल ने 19 पत्रों की प्राप्ति के बाद या उससे पहले श्री बोम्मई के विचार का पता नहीं लगाया।

शिकायत की कि उनके हस्ताक्षर पहले के पत्रों पर प्राप्त किए गए थे गलत तरीके से प्रस्तुत किया और मंत्रालय के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की। राज्य मंत्रिमंडल की उसी दिन बैठक हुई और एक सप्ताह के भीतर यानी 27 अप्रैल, 1989 को विधानसभा का सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री और उनके कानून मंत्री ने उसी दिन राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें विधानसभा सत्र बुलाने के फैसले के बारे में सूचित किया। मुख्यमंत्री ने अपनी बात साबित करने की पेशकश की

सदन के पटल पर बहुमत, यहां तक कि यदि आवश्यक हो तो विधानसभा सत्र से पहले भी। हालाँकि, इसी प्रभाव के लिए, राज्यपाल ने उसी दिन, विशेष रूप से 20 अप्रैल, 1989 को राष्ट्रपति को एक और रिपोर्ट भेजी, जिसमें सात सदस्यों के मंत्रालय को अपना समर्थन देने और अपने पहले के पत्रों को वापस लेने के पत्रों का उल्लेख किया गया था। हालाँकि उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि 7 विधायकों के पत्र मुख्यमंत्री ने उन पर दबाव बनाकर प्राप्त किए थे और कहा कि खरीद-फरोख्त चल रही थी और माहौल खराब हो रहा था। अंत में, उन्होंने अपनी राय दोहराई कि मुख्यमंत्री ने सदन में बहुमत का विश्वास खो दिया है और दोहराया

संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत कार्रवाई के लिए उनका पूर्व अनुरोध। उसी दिन राष्ट्रपति ने सदन को भंग करने की घोषणा जारी की। द 637

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

इसके बाद अनुच्छेद द्वारा आवश्यक घोषणा को संसद द्वारा अनुमोदित किया गया।

356 (3) .

की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका

विघटन को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ यह मानते हुए खारिज कर दिया कि

राज्यपाल की रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों को अप्रासंगिक नहीं माना जा सकता है और यह कि राज्यपाल की संतुष्टि कि कोई अन्य पक्ष सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था, को स्वीकार करना पड़ा क्योंकि उनकी व्यक्तिगत सद्भावना नहीं थी।

पूछताछ की गई और उनकी संतुष्टि सभी के उचित मूल्यांकन पर आधारित थी

प्रासंगिक तथ्य। उच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य मामले में निर्धारित परीक्षण पर भरोसा किया और कहा कि प्रकट की गई सामग्री के आधार पर,

राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त संतुष्टि को दोष नहीं दिया जा सकता है।

नागालैंड के तथ्य

नागालैंड के मामले में, 7 अगस्त की राष्ट्रपति की घोषणा,

1988 राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अनुच्छेद 356 (1) के तहत जारी किया गया था। संबंधित में

नागालैंड विधानसभा में उस समय 60 विधायक थे, जिनमें से 34 कांग्रेस (आई) के, 18 नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के और आई नागा पीपुल्स के थे। पार्टी और सात निर्दलीय विधायक थे। 28 जुलाई, 1988 को सत्तारूढ़ कांग्रेस (आई) पार्टी के 34 में से 13 विधायकों ने अध्यक्ष को सूचित किया कि

विधानसभा ने कहा कि उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई है और उनसे सदन में उनके लिए अलग सीटें आवंटित करने का अनुरोध किया है। सत्र का उद्देश्य था 28 अगस्त, 1988 को शुरू हुआ। 30 जुलाई, 1988 के निर्णय द्वारा अध्यक्ष ने माना कि संविधान की दसवीं अनुसूची के अर्थ के भीतर पार्टी में विभाजन हुआ था। 31 जुलाई, 1988 को, अलग पार्टी बनाने वाले 13 दलबदल करने वाले विधायकों में से एक, श्री वामूजो ने राज्यपाल को सूचित किया कि उन्हें राज्य में तत्कालीन 59 सदस्यों में से 35 का समर्थन प्राप्त है।

विधानसभा और सरकार बनाने की स्थिति में था। 3 अगस्त, 1988 को राज्य के मुख्य सचिव ने श्री वामूज़ो को पत्र लिखा कि उनकी जानकारी के अनुसार, श्री वामूज़ो ने नई पार्टी बनाने वाले विधायकों को गलत तरीके से कैद कर लिया था। श्री वामूज़ो ने इन आरोपों का खंडन किया और उनसे पूछा कि

मुख्य सचिव स्वयं सदस्यों से सच्चाई की पुष्टि करेंगे। सत्यापन पर सदस्यों ने मुख्य सचिव को बताया कि जैसा कि आरोप लगाया गया है, उनमें से किसी को भी कैद नहीं किया गया है। 6 अगस्त, 1988 को राज्यपाल ने 13 विधायकों द्वारा एक नई पार्टी के गठन के बारे में भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजी। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त विधायक पैसे के लालच में थे।

उन्होंने आगे कहा कि उक्त विधायकों को श्री वामूज़ो और एक अन्य व्यक्ति द्वारा जबरन कैद में रखा गया था, और सत्तारूढ़ दल में विभाजन की कहानी सच नहीं थी। उन्होंने कहा कि नए समूह 638 को मान्यता देने में अध्यक्ष जल्दबाजी कर रहे थे

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2006] 1 एस सी आर।

13 सदस्यों में से और टिप्पणी की कि राज्य में घोड़ों का व्यापार चल रहा था। उन्होंने नागालैंड में विद्रोह का विशेष संदर्भ दिया और यह भी कहा कि विधानसभा के कुछ सदस्यों के साथ संपर्क थे।

विद्रोहियों। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि यदि मामलों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह राज्य की स्थिरता को प्रभावित करेगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। इसके बाद राष्ट्रपति ने विवादित घोषणा जारी की और सरकार को बर्खास्त कर दिया और विधानसभा को भंग कर दिया। नए समूह के नेता श्री वामूज़ो ने चुनौती दी

गुवाहाटी उच्च न्यायालय में उद्घोषणा की वैधता। याचिका की सुनवाई एक खंड पीठ ने की। पीठ ने प्रभावी संचालन पर मतभेद व्यक्त किया अनुच्छेद 74 (2) और इसलिए मामला तीसरे न्यायाधीश को भेजा गया था। लेकिन इससे पहले कि तीसरे विद्वान न्यायाधीश मामले की सुनवाई कर पाते, भारत संघ ने विशेष अनुमति देने के लिए इस न्यायालय का रुख किया जिसे मंजूरी दे दी गई और उच्च न्यायालय में कार्यवाही पर रोक लगा दी गई।

संविधान के अनुच्छेद 74 (2) के निहितार्थ से निपटना

सावंत ने अपनी और न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह की ओर से बोलते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह अदालत की नजरों से मुक्त है, लेकिन वह सामग्री जिसके आधार पर सलाह दी गई है।

इसे इससे दूर नहीं रखा जा सकता है और यह न्यायिक जांच के लिए खुला है। तथ्यों पर, न्यायमूर्ति सावंत ने यह विचार व्यक्त किया कि राज्यपाल को श्री वामूजो को सदन में अपनी ताकत का परीक्षण करने की अनुमति देनी चाहिए थी

तथ्य यह है कि राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 25 वर्षों के दौरान कम से कम 11 सरकारों का गठन किया गया था और उनकी जानकारी के अनुसार, कांग्रेस (1) विधायक मौद्रिक लाभों से लुभाए गए थे।

और यह राजनीतिक नैतिकता और संपूर्णता की अविश्वसनीय कमी थी।

मतदाताओं की इच्छाओं की अवहेलना।

मेघालय

जहाँ तक मेघालय के संबंध में उद्घोषणा का संबंध है,

जिसे भी अमान्य माना गया था। जिस आधार पर विघटन किया गया था अमान्य था संवैधानिक पदाधिकारी बाध्यकारी का एहसास करने में विफल रहा था

इस न्यायालय के आदेशों के कानूनी परिणाम और संवैधानिक दायित्व

उक्त आदेश को प्रभावी बनाना।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के तथ्य

जहाँ तक मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों के मामलों का संबंध है और

हिमाचल प्रदेश चिंतित है कि सरकारों को बर्खास्त करने की संख्या 639 थी।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

भारत और विदेशों में हिंसक प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ

पड़ोसी देश जहाँ 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद संरचना के विध्वंस के परिणामस्वरूप कुछ मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। कहा जाता है कि भारत संघ ने कई कदम उठाकर स्थिति से निपटने की कोशिश की है

इनमें कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है, जिन्होंने भाजपा के साथ मिलकर 6 दिसंबर, 1992 को कारसेवकों को अयोध्या की ओर कूच करने का आह्वान किया था। इन राज्यों के संबंध में घोषणा 15 जनवरी, 1993 को जारी की गई थी। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 (1) द्वारा विचार किए जाने पर विधानसभाओं को भंग करने की घोषणाएं जारी की

गईं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्यपाल की रिपोर्ट प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होती हैं और उचित सत्यापन के बाद उन्हें प्रामाणिक बनाया जाता है।

निष्कर्ष संख्या। I, II, IV, VI, VII, IX और X की राय में

न्यायमूर्ति सावंत इस प्रकार हैं:

" I. राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणा की वैधता
अनुच्छेद 356 (1) न्यायिक रूप से परीक्षण की सीमा तक समीक्षित है।

क्या यह किसी भी सामग्री के आधार पर जारी किया गया था या क्या

सामग्री प्रासंगिक थी या क्या घोषणा जारी की गई थी
शक्ति का दुर्भावनापूर्ण अभ्यास। जब प्रथम दृष्टया मामला बनता है

उद्घोषणा को चुनौती देते हुए, भार संघ पर है

सरकार यह साबित करने के लिए कि प्रासंगिक सामग्री वास्तव में मौजूद थी। इस तरह

सामग्री राज्यपाल की रिपोर्ट या इसके अलावा अन्य हो सकती है -

रिपोर्ट करें।

II. अनुच्छेद 74 (2) पर सामग्री की जांच के खिलाफ एक बाधा नहीं है

जिसके आधार पर राष्ट्रपति संतुष्ट हुए थे।

IV. चूंकि सी. एल. में निहित प्रावधान। (3) अनुच्छेद 356 का आशय है

क होने के लिए, उसके खंड (1) के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों पर जाँच करें,

राष्ट्रपति को इसके तहत शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी

बाद के खंड के उपखंड (ए), (बी) और (सी), अपरिवर्तनीय लेने के लिए

कम से कम संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने तक की कार्रवाई

घोषणा। यही कारण है कि राष्ट्रपति नहीं होंगे

शक्तियों का उपयोग करके विधान सभा को भंग करने में न्यायसंगत

जब तक कम से कम संसद के दोनों सदन घोषणा को मंजूरी नहीं दे देते।

VI. उचित मामलों में, न्यायालय के पास एक अंतरिम द्वारा शक्ति होगी।

निषेधाज्ञा, विधानमंडल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने पर रोक लगाने के लिए

विधानसभा वैधता [2006] 1 एस. सी. आर. के लिए चुनौती के अंतिम निपटान के लिए लंबित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायसंगत पूर्ति और उपचार से बचने के लिए घोषणा का

न्यायिक समीक्षा को निष्फल बनाया जा रहा है। लेकिन अदालत ऐसा नहीं करेगी।

उद्घोषणा जारी करने या किसी अन्य के प्रयोग में हस्तक्षेप करना।

उद्घोषणा के तहत शक्ति।

VII. पूर्व की यथास्थिति को बहाल करते समय, यह न्यायालय के लिए खुला रहेगा

राहत को उपयुक्त रूप से ढालना और उसके द्वारा की गई कार्रवाई को वैध घोषित करना। उस तारीख तक राष्ट्रपति। यह संसद और संसद के लिए भी खुला रहेगा।

राष्ट्रपति के उक्त कार्यों को मान्य करने के लिए राज्य का विधानमंडल।

कर्नाटक राज्य के मंत्रालय और विधानसभाएँ और मेघालय राज्य ने सिविल अपील संख्या 3645 में चुनौती दी

1989 और स्थानांतरण मामला संख्या। 5 और 1992 का 7 क्रमशः हैं

असंवैधानिक है। इस संबंध में 7 अगस्त, 1988 की घोषणा

नागालैंड राज्य को भी असंवैधानिक माना जाता है। हालांकि, देखने में

तथ्य यह है कि तब से नए चुनाव हुए हैं और नए

सभी विधानसभाओं और मंत्रालयों का गठन किया गया है

तीन राज्यों को उपरोक्त के परिणामस्वरूप कोई राहत नहीं दी गई है।

घोषणाएँ। हालाँकि, यह घोषित किया जाता है कि सभी कार्य जो हो सकते हैं
उद्घोषणा संचालित अवधि के दौरान लिया गया है, हैं

वैध है। 1989 की सिविल अपील सं. 3645 और स्थानांतरण मामला सं. 5

और 1992 के 7 को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के तदनुसार अनुमति दी गई है। सिविल

गुवाहाटी उच्च न्यायालय में तदनुसार लेकिन इसके बिना दायर याचिकाएँ लागतें।

X. 15 दिसंबर, 1992 की घोषणाएँ और कार्य

राष्ट्रपति द्वारा मंत्रालयों को हटाना और भंग करना

मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों में विधानसभाएँ

और हिमाचल प्रदेश उक्त घोषणाओं के अनुसार नहीं हैं असंवैधानिक है। सिविल अपील सं। 1692 , 1692 ए-1692 सी, 4627-30

तदनुसार 1993 की अनुमति दी गई है और स्थानांतरण मामला संख्या। 8 और 9 में से

1993 लागत के बारे में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिए जाते हैं।

न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने अपने और न्यायमूर्ति के लिए राय व्यक्त की है।

अल। निष्कर्ष संख्या। 2 , 3 , 7 , 8 और अनुच्छेद 434 में 12 प्रासंगिक हैं।

आर उद्देश्य और वही नीचे पढ़ा गया है:

" (2) कला द्वारा प्रदत्त शक्ति। 356 राष्ट्रपति पर एक रामेश्वर प्रसाद v है।

यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

641

ऐसी सामग्री जिसमें रिपोर्ट (ओं) शामिल या शामिल हो सकती है राज्यपाल एक पूर्व शर्त है। संतुष्टि का गठन किया जाना चाहिए

कला के तहत शक्ति के प्रयोग के संबंध में। 356 क्या योग्यता गंभीर है सभी संबंधित लोगों के हाथों में विचार

(3) हालाँकि विधान सभा को भंग करने की शक्ति कला के खंड (1) में निहित कहा जाए। 356 , समग्र संवैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति

इसका प्रयोग खंड (3) के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा घोषणा को अनुमोदित करने के बाद ही किया जाता है, न कि इससे पहले। इस तरह की मंजूरी तक,

राष्ट्रपति केवल खंड (1) के उपखंड (ग) के तहत विधान सभा से संबंधित संविधान के प्रावधानों को निलंबित करके विधान सभा को निलंबित कर सकते हैं। विधान सभा का विघटन निश्चित रूप से कोई मुद्दा नहीं है। इसका सहारा केवल वहीं लिया जाना चाहिए जहां इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक पाया जाता है।

घोषणा।

(7) अनुच्छेद 356 (1) के तहत घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय खारिज कर सकता है

घोषणा यदि यह दुर्भावनापूर्ण या पूरी तरह से अप्रासंगिक या बाहरी आधारों पर आधारित पाई जाती है। 44 वें (संशोधन) अधिनियम द्वारा खंड (5) (जिसे 38 वें (संशोधन) अधिनियम द्वारा पेश किया गया था) को हटाने से कार्रवाई की समीक्षा पर संदेह दूर हो जाता है। जब आह्वान किया जाता है, तो भारत संघ को उस सामग्री का उत्पादन करना होता है जिसके आधार पर कार्रवाई की गई थी। ऐसा करने से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि वह कार्रवाई का बचाव करना चाहता है। अदालत सामग्री की शुद्धता या इसकी पर्याप्तता में नहीं जाएगी। इसकी जांच यह देखने तक सीमित है कि क्या सामग्री कार्रवाई के लिए प्रासंगिक थी। भले ही सामग्री का हिस्सा है अप्रासंगिक, अदालत तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि कुछ सामग्री है जो की गई कार्रवाई के लिए प्रासंगिक है।

(8) यदि अदालत घोषणा को खारिज कर देती है, तो उसके पास यह शक्ति है कि

बर्खास्त सरकार को कार्यालय में बहाल करें और जहां भी विधानसभा को भंग या निलंबित किया गया हो, उसे पुनर्जीवित और फिर से सक्रिय करें। ऐसे मामले में, अदालत को यह घोषणा करने की शक्ति है कि घोषणा लागू होने की अवधि के दौरान किए गए कार्य, पारित आदेश और बनाए गए कानून अप्रभावित रहेंगे और उन्हें वैध माना जाएगा। हालाँकि, ऐसी घोषणा सरकार/विधान सभा या अन्य सक्षम प्राधिकारी को 642 की समीक्षा करने, निरस्त करने से नहीं रोकेगी।

[2006] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

या ऐसे अधिनियम आदेशों और कानूनों को संशोधित करें।

(12) मध्य के संबंध में 15 जनवरी, 1993 की घोषणाएँ

दीवानी अपीलों में संबंधित प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश

नं. 1692 , 1692 ए-1993 का 1692 सी, 1990 का 4627-4630, हस्तांतरित मामला

((ग) 1993 का सं. 9 और 1993 का सं. 8 क्रमशः हैं -

असंवैधानिक नहीं। दीवानी अपीलों की अनुमति है और निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एम. पी. (ग) 1993 की सं. 237 है

एक तरफ रख दें। हस्तांतरित मामलों को खारिज कर दिया जाता है "।

न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने भी निष्कर्षों के साथ सहमति व्यक्त की है।

न्यायमूर्ति सावंत के निर्णय में I, II और IV से VII ने अपनी और न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह की ओर से दिया।

न्यायमूर्ति पांडियन ने न्यायमूर्ति की राय से सहमति व्यक्त की है।

पी. बी. सावंत ने अपने निष्कर्ष I, II और IV से VIII पर लेकिन जहां तक तर्क और अन्य निष्कर्षों का संबंध है, विद्वान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेड्डी के निर्णय से सहमत हैं।

निर्दिष्ट कानून के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का दायरा निर्धारित करने के लिए

बोम्मई द्वारा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उस मामले में बहुमत की राय ने कर्नाटक और नागालैंड की विधानसभाओं के विघटन को अवैध घोषित कर दिया। बाद में किसी उपयुक्त स्थान पर, हम उस कारण पर ध्यान देंगे जिसके कारण यह घोषणा की गई।

न्यायमूर्ति के की अल्पमत राय में की गई कुछ टिप्पणियां।

रामास्वामी भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्वान न्यायाधीश ने कहा है कि

अनुच्छेद 356 (1) के तहत कार्रवाई के लिए प्रेरक कारक कभी भी केंद्र में सत्ता में पार्टी के लिए राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि यह केवल तभी होना चाहिए जब यह संतुष्ट हो कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। यह भी देखा गया है कि बार-बार होने वाले चुनाव लोगों के विश्वास और विश्वास को धोखा देंगे

भारी चुनाव के अलावा सरकार के संसदीय रूप में

राज्य और उम्मीदवारों के लिए व्यय। न्यायालय, यदि उसके समक्ष रखी गई सामग्री पर, यह पाता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त संतुष्टि

असंवैधानिक, अत्यधिक तर्कहीन या बिना किसी सांठगांठ के, तब न्यायालय घोषणा की सामग्री या उसमें प्रकट किए गए कारणों पर विचार करेगा और चरम मामलों में खोज आदेश के अनुसार प्रस्तुत की गई सामग्री पूरी तरह से अप्रासंगिक है या कार्रवाई के उद्देश्य के बीच कोई संबंध नहीं है।

राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्रवाई और संतुष्टि या कोई नहीं

उद्घोषणा के निकटवर्ती उद्देश्य के लिए तर्क। उस स्थिति में, न्यायालय घोषणा कर सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त संतुष्टि या तो 643 थी

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. 1. [सभरवाल, सी. जे.]

पूरी तरह से अप्रासंगिक आधारों या शक्ति के रंगीन प्रयोग और परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 356 के तहत जारी घोषणा को असंवैधानिक घोषित किया जाएगा।

यह स्पष्ट है कि न्यायमूर्ति अहमदी और न्यायमूर्ति रामास्वामी हालांकि

अल्पसंख्यक, फिर भी विद्वान न्यायाधीशों ने अत्यधिक तर्कहीन कार्रवाई पर नाराजगी जताई है।

अब, आइए हम न्यायमूर्ति सावंत की राय देखें, जिन्होंने खुद के लिए बात की।

और न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह और जिनके साथ न्यायमूर्ति पांडियन, न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी और न्यायमूर्ति अग्रवाल कर्नाटक और नागालैंड की विधानसभाओं को भंग करने की घोषणा की अयोग्यता के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सहमत हुए।

विद्वान न्यायाधीश ने राय दी है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि होनी चाहिए

वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित। वह सामग्री राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट में या अन्यथा या रिपोर्ट और अन्य स्रोतों दोनों से उपलब्ध हो सकती है। न्यायमूर्ति सावंत ने आगे कहा कि इस प्रकार उपलब्ध वस्तुनिष्ठ सामग्री से यह संकेत मिलना चाहिए कि राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ सामग्री का अस्तित्व यह दर्शाता है कि राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, यह एक शर्त है

उद्घोषणा के जारी होने से पहले पूर्ववर्ती।

पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का संदर्भ दिया गया है

उसी विषय पर, हालांकि पाकिस्तान के संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों के प्रावधानों की भाषा समान शब्दों में नहीं है। में।

मुहम्मद शरीफ बनाम। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, पी. एल. डी. 1988 (एल. ए. एच.) 725, सवाल यह था कि क्या 29 मई, 1988 को नेशनल असेंबली को भंग करने का राष्ट्रपति का आदेश पाकिस्तान संविधान के अनुच्छेद 58 (2) (बी) के तहत उन्हें प्रदान की गई शक्तियों के अनुसार था। उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह तर्क देना बिल्कुल सही नहीं है कि चूंकि यह राष्ट्रपति का विवेकाधिकार था, इसलिए उनकी राय के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ऐसे कारण होने चाहिए जो लोगों की नजर में उचित हों और न्याय की अदालत में कानून द्वारा समर्थित हों। वह भरोसा नहीं कर सकता था जिन कारणों का कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है, वे गंजे, अस्पष्ट, सामान्य हैं या जैसे कि हमेशा दिए जा सकते हैं और विनाशकारी प्रभावों के साथ दिए गए हैं (हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)। यह ध्यान रखना शिक्षाप्रद होगा कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति आर. एस. सिधवा ने क्या कहा था, जैसा कि में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

न्यायमूर्ति सावंत की रायः

" चाहे वह 'व्यक्तिपरक' या 'उद्देश्यपूर्ण' संतुष्टि हो
राष्ट्रपति या यह उनका 'विवेकाधिकार' या 'राय' है, यह काफी [2006] 1 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्पष्ट करें कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं
इच्छा या सनक पर संविधान। उसके पास तथ्य, परिस्थितियाँ होनी चाहिए।

जो अपने दर्जे के व्यक्ति को एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।
ऐसी गंभीर प्रकृति के विवेकाधिकार के प्रयोग की आवश्यकता वाली राय

कि लोगों के प्रतिनिधि जिन्हें मुख्य रूप से सौंपा गया है

राज्य के मामलों को चलाने के कर्तव्य के साथ हटा दिया जाता है

कलम का एक झटका। उसकी कार्रवाई की मांग की जानी चाहिए और

कानून के न्यायालय में चुनौती दिए जाने पर संविधान के तहत न्यायसंगत।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालतें उसके 'विवेकाधिकार' में हस्तक्षेप करने के लिए सतर्क होंगी। या 'स्थिति' के बारे में 'राय' का गठन लेकिन अगर वहाँ है

संविधान के तहत आदेश के लिए कोई आधार या औचित्य नहीं,
न्यायालयों को उनके अधीन दिए गए अपने कर्तव्य का पालन करना होगा

संविधान। ऐसा करते समय, वे प्रवेश नहीं करेंगे
राजनीतिक क्षेत्र जिसके लिए मतदाताओं को अपील प्रदान की जाती है।

दूसरे तर्क पर विचार करते हुए, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहा:

" यदि तर्क सही है तो अनुच्छेद 48 के खंड (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद प्रावधान को निरर्थक बना दिया जाएगा जैसे कि यह संविधान का हिस्सा नहीं था। यह स्पष्ट और प्रमाणिक है कि संविधान के निर्माण के किसी भी सिद्धांत के तहत संविधान के किसी भी पत्र या प्रावधान के किसी भी हिस्से को निरर्थक या अस्तित्वहीन नहीं कहा जा सकता है। अन्य विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग में तर्क सही हो सकता है लेकिन इसे राष्ट्रीय सभा के विघटन के संदर्भ में नियोजित नहीं किया जा सकता है। वैधता का ब्लैंकेट कवरेज और

अनुच्छेद 48 (2) के तहत विवेकाधिकार की निर्विवादता को तब छोड़ दिया गया था जब अनुच्छेद 58 (2) के तहत यह प्रावधान किया गया था कि 'अनुच्छेद 48 के खंड (2) के बावजूद। परिस्थितियाँ। विशिष्ट प्रावधान स्थिति को नियंत्रित करेगा। यह स्पष्ट रूप से

बताए जाने से भी बचेगा; अन्यथा यह माना जाता है कि यह अभिलेख न्यायालयों में है। इसलिए, यह तर्क देना बिल्कुल सही नहीं है कि चूंकि यह उनके 'विवेक' में था, इसलिए राष्ट्रपति अपनी 'राय' के आधार पर राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकते थे। उसके पास ऐसे कारण होने चाहिए जो लोगों की नजर में न्यायोचित हों और न्यायालय में कानून द्वारा समर्थित हों। यह समझ में आता है कि यदि राष्ट्रपति के पास कोई है

अपनी 'राय' में अपने 'विवेकाधिकार' का प्रयोग करने के लिए न्यायोचित कारण लेकिन खुलासा नहीं करना चाहता है, वह ऐसा कह सकता है और उस पर विश्वास किया जा सकता है या यदि उसे यह समझाने के लिए कहा जाता है कि वह सार्वजनिक रूप से कारण का खुलासा किए बिना न्यायालय को विश्वास में क्यों ले सकता है, तो यह राज्य की सुरक्षा के कारण हो सकता है। आखिरकार देशभक्ति 645 पदधारकों तक ही सीमित नहीं है।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

उस समय तक। वह केवल सीज़र की तरह यह नहीं कह सकता कि यह मेरी इच्छा है, राय है।

या भेदभाव। न ही ऐसे कारण बताएँ जिनका कार्रवाई से कोई संबंध न हो। गंजा, अस्पष्ट, सामान्य या जैसे कि हमेशा दिया जा सकता है और किया गया है

विनाशकारी प्रभावों के साथ दिया गया। "
समान तर्कों से निपटने के लिए, आर. एस. सिधवा, जे. ने इस प्रकार कहा:

विधानसभाओं को भंग करने के सभी कारणों का खुलासा करें
कला के तहत। 58 (2) (ख) और 112 (2) (ख)। यदि वे खुलासा करना नहीं चुनते हैं

सभी सामग्री, लेकिन केवल कुछ, यह उनका कबूतर है, मामले के लिए होगा

सामने रखी गई सीमित सामग्री की न्यायिक जांच पर निर्णय लिया गया

न्यायालय और यदि यह पूरी तरह से अप्रासंगिक या बाहरी होता है, तो वे

भुगतना पड़ता है। "

यह अच्छी तरह से तय है कि यदि संतुष्टि दुर्भावनापूर्ण है या इस पर आधारित है

पूर्णतः अप्रासंगिक या अप्रासंगिक आधारों पर, न्यायालय के पास इसकी जांच करने का अधिकार क्षेत्र होगा क्योंकि उस मामले में राष्ट्रपति को उस मामले के संबंध में कोई संतुष्टि नहीं होगी जिस पर उन्हें संतुष्ट करने की आवश्यकता है। उस पर

राजस्थान राज्य के मामले में की गई इन टिप्पणियों पर विचार अन्य निर्णय भी। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. , [1989] 1 एस. सी. सी. 204 और मारू राम बनाम। भारत संघ, [1981] 1 एस. सी. सी. 107, न्यायमूर्ति सावंत

यह निष्कर्ष निकाला गया कि अनुच्छेद 356 (1) के तहत उद्घोषणा जारी करने की शक्ति का प्रयोग कम से कम इस हद तक न्यायिक समीक्षा के अधीन है कि क्या उद्घोषणा के मुद्दे की पूर्व शर्तों को पूरा किया गया है या नहीं।

नहीं। इस परीक्षा में अनिवार्य रूप से जांच शामिल होगी कि क्या

राष्ट्रपति की संतुष्टि के लिए ऐसी सामग्री मौजूद थी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें राज्य सरकार को चलाया नहीं जा सकता था

संविधान के प्रावधानों के अनुसार। सामग्री के प्रश्न पर विचार करते समय, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह व्यक्तिगत सनक, इच्छा, दृष्टिकोण या राय या राष्ट्रपति का स्पष्ट निर्देश नहीं है, बल्कि

उसके सामने रखी गई सामग्री से लिया गया वैध निष्कर्ष जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति को आश्वस्त होना पड़ता है

या जानकारी का पर्याप्त प्रमाण होना चाहिए या चीजों की स्थिति के बारे में संदेह या अनिश्चितता से मुक्त होना चाहिए जो दर्शाता है कि विचाराधीन स्थिति उत्पन्न हुई है। (हमारे द्वारा दिया गया जोर)। यद्यपि, इसलिए, सामग्री की पर्याप्तता या अन्यथा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, सामग्री से प्राप्त निष्कर्ष की वैधता निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के लिए खुली है।

यह आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि जब घोषणा को 646 द्वारा चुनौती दी जाती है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसकी अयोग्यता के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला बनाते हुए, केंद्र सरकार पर यह संतुष्ट करने का बोझ होगा कि ऐसी सामग्री मौजूद है जो दर्शाती है कि सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। चूँकि ऐसी सामग्री साक्षय अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से केंद्र सरकार की जानकारी में होगी, इसलिए सबूत का भार केंद्र सरकार पर होगा।

इस प्रकार के मापदंडों के बारे में उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद

न्यायिक समीक्षा कि संतुष्टि व्यक्तिगत सनक, इच्छा, दृष्टिकोण, राय या प्रासंगिक सामग्री से वैध निष्कर्ष पर आधारित नहीं हो सकती है और यह कि निकाले गए निष्कर्ष की वैधता न्यायिक समीक्षा के लिए खुली थी, उस रिपोर्ट की बारीकी से जांच की गई थी जिसके आधार पर कर्नाटक विधानसभा को भंग करने की घोषणा जारी की गई थी, जैसा कि न्यायमूर्ति सावंत की राय के पैराग्राफ 118,119 और 120 से स्पष्ट है।

जो नीचे पढ़ा गया है:

" 118. उन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए जो हम इस संबंध में पहुंचे हैं

न्यायिक समीक्षा के मापदंड, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय

सबसे प्रासंगिक तथ्य को नजरअंदाज करने में एक त्रुटि की थी कि

सात विधायकों के परस्पर विरोधी पत्रों का दृष्टिकोण, यह अनुचित था

राज्यपाल की ओर से इस कार्य को अपने ऊपर घमंड करने के लिए कि

सबसे पहले, यह मानते हुए कि पहले के उन्नीस अक्षर वास्तविक थे और

उक्त विधायकों द्वारा उनकी स्वतंत्र इच्छा और इच्छा के बारे में लिखा गया था। वह.

उन्होंने उक्त विधायकों का साक्षात्कार लेने की भी परवाह नहीं की थी, लेकिन केवल

विधानमंडल के माध्यम से हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता की पुष्टि की सचिवालय। दूसरा, उन्होंने निर्णय लेने का काम भी अपने हाथों में ले लिया

कि उन्नीस में से सात विधायकों ने बाद में लिखा था

मुख्यमंत्री के दबाव के कारण पत्र और नॉट आउट

उनकी स्वतंत्र इच्छा से। उन्होंने फिर से उक्त व्यक्ति का साक्षात्कार लेने की भी परवाह नहीं की।

विधायक। तीसरा, यह ज्ञात नहीं है कि राज्यपाल को यह अधिकार कहां से मिला जानकारी कि दोनों के बीच घोड़ों का व्यापार चल रहा था

विधायक। यह मानते हुए भी कि यह सही और उचित था

उसके लिए पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए फर्श पर परीक्षण का इंतजार करना था

वह सदन जो मुख्यमंत्री की परीक्षा लेता है, उसने स्वेच्छा से जाने का बीड़ा उठाया था

राज्यपाल द्वारा चुने गए किसी भी दिन के माध्यम से। वास्तव में, राज्य मंत्रिमंडल

स्वयं विधानसभा की बैठक बुलाने की पहल की थी
27 अप्रैल, 1989 को, अर्थात उस तारीख से केवल एक सप्ताह पहले जिस दिन

राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजने का फैसला किया। अंत में, क्या है

इस प्रकरण के संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यपाल
कभी भी मुख्यमंत्री से 647 विधायकों को पेश करने के लिए नहीं कहा।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई.: [सभरवाल, सी. जे.]

उनके सामने जो मुख्यमंत्री का समर्थन कर रहे थे, अगर राज्यपाल को लगता कि स्थिति ने राज्य के शासन के लिए इतना गंभीर खतरा पैदा कर दिया है कि वह सदन में बहुमत परीक्षण के परिणाम का इंतजार नहीं कर सकते।

घर। हमारा विचार है कि यह एक ऐसा मामला है जहां सभी औचित्य के नियमों को हवा में फेंक दिया गया था और अनुचित जल्दबाजी की गई थी राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 356 (1) के तहत उद्घोषणा जारी करने के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित करने में स्पष्ट रूप से दुर्भावना दिखाई दी। राज्यपाल की उक्त रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा और इस प्रकार प्राप्त करने वाली परिस्थितियों में, इसलिए, समान रूप से नुकसान हुआ

ऐसी सामग्री जिसका न तो परीक्षण किया गया था और न ही परीक्षण की अनुमति दी गई थी राज्यपाल के इप्स डिक्सिट से अधिक नहीं। राज्यपाल की कार्रवाई अधिक आपत्तिजनक थी क्योंकि एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में, उन्होंने

उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे खुद को अधिक दृढ़ता से, सावधानी से संचालित करें और सावधानी से। इसके बजाय, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यपाल मंत्रालय को बर्खास्त करने और विधानसभा को भंग करने की जल्दबाजी में थे। यह घोषणा उक्त रिपोर्ट और तथाकथित अन्य जानकारी, जिसका खुलासा नहीं किया गया है, पर आधारित होने के कारण इसे रद्द किया जा सकता है।

(हमारे द्वारा दिया गया जोर)

119. इस संबंध में, इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि उन सभी मामलों में जहां मंत्रालय को समर्थन वापस लेने का दावा किया गया है कुछ विधायक, मंत्रालय की ताकत का परीक्षण करने के लिए उचित पाठ्यक्रम सदन के पटल पर परीक्षा आयोजित करना है। केवल यही उस ओर से खुले तौर पर और निष्पक्ष रूप से दावों और जवाबी दावों की मांग करने के लिए संवैधानिक रूप से निर्धारित मंच है। का मूल्यांकन

मंत्रालय की ताकत किसी की निजी राय का विषय नहीं है। व्यक्ति, चाहे वह राज्यपाल हो या राष्ट्रपति। यह सदन में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित और सुनिश्चित किए जाने में सक्षम है। इसलिए जब ऐसा प्रदर्शन संभव हो, तो इसे दरकिनार करना संभव नहीं है और इसके बजाय यह राज्यपाल या राज्यपाल की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर निर्भर करता है।

राष्ट्रपति। इस तरह का निजी मूल्यांकन व्यक्तिगत दुर्भावना की गंभीर आपत्तियों के लिए खुला होने के अलावा लोकतांत्रिक सिद्धांत के लिए एक अभिशाप है। यह संभव है कि कुछ दुर्लभ अवसरों पर, आधार-परीक्षण असंभव हो सकता है, हालाँकि ऐसी स्थिति की कल्पना करना मुश्किल है।

यह मानते हुए भी कि एक समस्या उत्पन्न होती है, ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वह लिखित रूप में सदन में बहुमत परीक्षण नहीं कराने के कारणों का उल्लेख करे। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह निर्णय देने में गलती की कि शक्ति परीक्षण न तो अनिवार्य था और न ही अनिवार्य या 648 था

[2006] 1 एस सी आर।

कि राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना पूर्व-आवश्यकता नहीं थी

अनुच्छेद 356 (1) के तहत कार्रवाई की सिफारिश करना। चूँकि हम पहले से ही

इसमें सरकारिया आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किया गया है।
कनेक्शन, उन्हें यहाँ दोहराना आवश्यक नहीं है।

(हमारे द्वारा दिया गया
जोर)

120. उच्च न्यायालय ने यह विचार रखने में और गलती की कि

राज्यपाल की रिपोर्ट में बताए गए तथ्य अप्रासंगिक नहीं थे जब
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री या राज्यपाल से कोई जानकारी लिए बिना

सातों विधायक आगे बढ़े कि उनका वापस लेना वास्तविक था या नहीं।
मामले में अपनी असत्यापित राय देना। आगे क्या भुला दिया गया था

उच्च न्यायालय द्वारा यह मानते हुए कि समर्थन वापस ले लिया गया था

19 विधायकों द्वारा मंत्रालय के लिए, यह राज्यपाल पर निर्भर था
यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी अन्य मंत्रालय का गठन किया जा सकता है। सवाल यह है

ऐसे मामलों में राज्यपाल की व्यक्तिगत सद्भावना अप्रासंगिक है।

यह पता लगाया जाना है कि क्या राज्यपाल आगे बढ़े थे
कानूनी रूप से और एक संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की सभी संभावनाओं का पता लगाया

राज्य में सरकार यह रिपोर्ट करने से पहले कि संवैधानिक

मशीनरी खराब हो गई थी। भले ही इसका मतलब स्थापित करना हो

इसे तब तक चुनने के लिए बाध्य है जब तक सरकार इसका आनंद ले सकती है
सदन का विश्वास। यह भी है सिफारिश

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपालों की पाँच सदस्यीय समिति

राज्यपालों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार

नवंबर 1970 में नई दिल्ली में और सरकारिया आयोग में
ऊपर उद्धृत किया गया। यह भी स्पष्ट है कि राज्यपाल की रिपोर्ट से परे,

राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने से पहले उनके सामने कोई अन्य सामग्री नहीं थी

उद्घोषणा। चूंकि राज्यपाल द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताए गए "तथ्य",

जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसके आधार पर उसकी अपनी राय थी -

अप्रमाणित सामग्री, परिस्थितियों में, वे शायद ही हो सकते हैं

एक वस्तुनिष्ठ सामग्री बनाने के लिए कहा जाता है जिस पर राष्ट्रपति हो सकता है

अभिनय किया। इसलिए जारी की गई घोषणा अमान्य थी।

(हमारे द्वारा दिया
गया जोर)

उच्च न्यायालय का विचार है कि राज्यपाल के आदेश में बताए गए तथ्य

रिपोर्ट को स्वीकार करना पड़ा, इस तथ्य के बावजूद कि राज्यपाल ने से सत्यापित पत्रों
पर 19 विधायकों के हस्ताक्षर की प्रामाणिकता प्राप्त की थी

विधानमंडल सचिवालय, इस आधार पर कि उन्होंने साक्षात्कार की परवाह नहीं की थी
विधायक और यह कि सात विधायकों की ओर से परस्पर विरोधी पत्र थे।

649

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

राज्यपाल द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि उन सात विधायकों ने मुख्यमंत्री के दबाव के कारण
बाद के पत्र लिखे थे और

उनकी अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं, विशेष रूप से जब राज्यपाल द्वारा उनका साक्षात्कार नहीं
लिया गया था, तो उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। यह भी देखा गया कि यह ज्ञात नहीं है कि
राज्यपाल को विधायकों के बीच चल रहे खरीद-फरोख्त की जानकारी कहां से मिली। आगे यह

निष्कर्ष निकला कि राज्यपाल ने औचित्य की सभी तोपों को हवा में फेंक दिया था और अनुच्छेद के तहत घोषणा जारी करने के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित करने में अनुचित जल्दबाजी दिखाई थी

356 (1) जो स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण था। यह देखा गया कि राज्यपाल द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताए गए तथ्य उनकी अपनी राय के आधार पर थे -

अप्रमाणित सामग्री और परिस्थितियों में उन्हें शायद ही वह वस्तुनिष्ठ सामग्री कहा जा सकता है जिस पर राष्ट्रपति कार्रवाई कर सकते थे।

जब वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच दायरे के आलोक में की जाती है

न्यायिक समीक्षा की, जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, जो बोम्मई के मामले में बहुमत की राय के अनुपात निर्णय का प्रतिनिधित्व करती है, यह स्पष्ट हो जाता है कि विवादित उद्घोषणा को चुनौती सफल होनी चाहिए।

हाथ में मामला सरकार के खिलाफ पूरी तरह से कवर किया गया है

बोम्मई के मामले में निर्धारित आदेश। कोई अनुमान नहीं हो सकता है कि

प्रलोभन या हॉर्स ट्रेडिंग केवल इस कारण से कि कुछ विधायकों ने अपने नेता की सार्वजनिक मुद्रा के विरोध में विचार व्यक्त किया और किसी अन्य राजनीतिक दल के नेता द्वारा सरकार के गठन का समर्थन करने का फैसला किया। अल्पसंख्यक सरकारें अनजान नहीं हैं। यह भी अज्ञात नहीं है कि राज्यपाल, किसी दी गई परिस्थिति में, सरकार बनाने के दावे को स्वीकार नहीं कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि दावा करने वाला दल या समूह राज्य को एक स्थिर सरकार प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। यह भी अज्ञात है कि धारणाओं के विभिन्न मतभेदों के बावजूद, पार्टी, समूह या विधायक अभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं जिससे सरकार गिर सकती है।

चुनाव का सामना करने के लिए तैयार नहीं होने सहित विभिन्न कारण। ये और कई अन्य अभेद्यताओं के परिणामस्वरूप विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक भी एक साथ आ सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि प्रलोभन और खरीद-फरोख्त की धारणा की ओर ले जाए।

कर्नाटक और नागालैंड के विघटन के मामलों के विपरीत,

मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं को भंग करने के मामलों पर विचार करते हुए बोम्मई में यह निर्णय लिया गया कि राज्यपालों की रिपोर्टों से पता चलता है कि राज्य सरकारें आंतरिक गड़बड़ी से राज्य के नागरिकों और संपत्ति की रक्षा करने में बुरी तरह

विफल रही हैं, यह पाया गया कि राज्यपाल की रिपोर्ट प्रासंगिक सामग्री पर आधारित हैं और 650 हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रामाणिक और उचित सत्यापन के बाद किया गया। इन निष्कर्षों के आलोक में घोषणा की वैधता को सर्वसम्मति से बरकरार रखा गया था -

ये तीन राज्य।

अब हम न्यायमूर्ति बी. पी. की राय में दिए गए तर्क पर लौटते हैं।

जीवन रेड्डी, अपने और न्यायमूर्ति अग्रवाल के लिए बोल रहे हैं।

जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, न्यायमूर्ति रेड्डी ने पैरा 324 में कही गई सीमा तक

राजस्थान राज्य मामले के तर्क के साथ अपनी असहमति व्यक्त की।

इससे पहले कि हम पैराग्राफ 389 की जांच करें, जिसमें जस्टिस रेड्डी ने कहा है,

संक्षेप में, उच्च न्यायालय की विशेष पीठ द्वारा रिट याचिका को खारिज करने में दिए गए आठ कारण और पैरा 391 में निहित विद्वान न्यायाधीश की राय, हम महसूस करते हैं कि बोम्मई के मामले की पूरी तरह से सराहना करने के लिए, जिसने कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले को उलट दिया, यह ध्यान रखना काफी उपयोगी होगा कि उच्च न्यायालय ने एस. आर. बोम्मई और अन्य में रिपोर्ट किए गए अपने फैसले के पैराग्राफ 28 से 34 में वास्तव में क्या कहा था। वी. भारत संघ और अन्य। , आकाशवाणी (1990) कर्नाटक 5]। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार हैं:

हम पाते हैं कि की गई आलोचना यह है कि द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है राज्यपाल ने कहा कि कोई अन्य पार्टी नहीं है जो गठन करने की स्थिति में हो

सरकार, न केवल अस्पष्ट है बल्कि तथ्यात्मक रूप से गलत है और इसलिए राष्ट्रपति के पास अपनी संतुष्टि के लिए कोई प्रासंगिक सामग्री नहीं थी

उनके द्वारा जारी की गई घोषणा।

उपरोक्त तर्क फिर से कारणों के लिए बिना किसी योग्यता के है:

(i) कि राज्यपाल ने उक्त संतुष्टि का गठन किया जो आवश्यक रूप से हो सकता है अपने स्वयं के प्रभावों का परिणाम बनें। किसी भी तरह से घटनाओं का वर्णन नहीं

संतुष्टि के मामले को आगे बढ़ाता है क्योंकि बहुत संतुष्टि

राज्यपाल भौतिक प्रासंगिक तथ्य का एक अभिन्न अंग है। यह भी हो सकता है कि राज्यपाल ने कई विधायकों से मुलाकात की होगी और उनसे पूछताछ की होगी

उन्हें। लेकिन उनके बीच जो हुआ वह रिकॉर्ड का विषय नहीं हो सकता है।

इस संदर्भ में जहां राज्यपाल की व्यक्तिगत निष्ठा नहीं है

प्रश्न, व्यक्त की गई उसकी संतुष्टि को इसके हिस्से के रूप में माना जाना है

प्रासंगिक भौतिक तथ्य इस अर्थ में कि बहुत संतुष्टि बताई गई है

उसमें अपने भीतर अन्य सभी आवश्यक विचारों को समझता है।

कारक, (ii) 19 अप्रैल, 1989 की रिपोर्ट को निम्नलिखित के साथ पढ़ा जाना चाहिए -

20 अप्रैल, 1989 की दूसरी रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि दूषित "और" घोड़ों के व्यापार "का उल्लेख किया गया था। विधायकों का दबाव ",

" रिपोर्ट 651 में उल्लिखित घोड़ा-व्यापार "और" दूषित करने वाला वातावरण "

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

पहली रिपोर्ट के पैरा 3 में दिए गए बयान पर भी विचार किया जा सकता है और इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि में समझा गया कि यदि मौजूदा मंत्रालय ने सदन में बहुमत खो दिया है, तो इसे छोड़ दिया जाता है

राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कि वह किसी और को मंत्रालय बनाने के लिए बुलाए, जिसके बारे में वह सोचता है कि वह सदन में बहुमत हासिल करने की स्थिति में है। इसके अलावा, हमारे सामने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि किसी अन्य पक्ष या व्यक्ति ने अपना दावा किया है एक स्थिर मंत्रालय बनाने के लिए; बल्कि, याचिकाकर्ताओं का पूरा मामला यह रहा है कि श्री एस. आर. बोम्मई की अध्यक्षता वाले मौजूदा मंत्रालय को सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। यह आधार था

यह सही नहीं माना गया जिसके लिए राज्यपाल द्वारा दी गई दोनों रिपोर्टों में भौतिक तथ्य दिए गए थे।

29. इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि बहुमत रखने वाले व्यक्ति को बहुमत साबित करने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यपाल को यह बताने के बजाय कि वह सदन में बहुमत साबित करेंगे, मुख्यमंत्री 113 विधायकों के हस्ताक्षर प्राप्त कर सकते थे और अपनी ताकत दिखाने के लिए राज्यपाल के सामने रख सकते थे। इसके अलावा, राज्यपाल की दूसरी रिपोर्ट भी कुछ भौतिक तथ्यों को बताती है; श्री एस. आर. बोम्मई को अपना समर्थन वापस लेने वाले कुछ एम. एल. ने फिर से दोलन और चपलता के साथ पहले के पत्रों को वापस ले लिया। वफादारी में उतार-चढ़ाव अस्वास्थ्यकर अभ्यास की ओर ले जाता है

रिपोर्ट में बताया गया है। लोकतांत्रिक संस्कृति का अपमान किया जा रहा था। राज्यपाल द्वारा वातावरण की चमक महसूस की गई। मौजूदा स्थिति के संदर्भ में राज्यपाल को निश्चित रूप से राष्ट्रपति को उपरोक्त तथ्यों की रिपोर्ट करने का अधिकार था। इसलिए हमारा दृढ़ मत है कि राज्यपाल की दो रिपोर्टों ने राष्ट्रपति को उन आवश्यक और प्रासंगिक तथ्यों से अवगत कराया जिनसे राष्ट्रपति ने

कला के तहत कार्रवाई के लिए स्थिति का आकलन कर सकते हैं। 356 संविधान से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30. श्री सोली सोराबजी द्वारा राज्यपाल की रिपोर्टों के खिलाफ किया गया एक और बड़ा हमला यह था कि रिपोर्ट में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि राज्य सरकार को नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।

संविधान। दूसरे शब्दों में, अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह दर्शाती हो कि राज्य में तंत्र का संवैधानिक पतन हुआ है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान वकील ने रिपोर्ट में दिए गए बयान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जिसमें कहा गया है:

मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी कार्यपालिका द्वारा प्रशासित
जिनका सदन में बहुमत नहीं है।

यहाँ कहा गया है कि अर्थ कानून के अनुसार नहीं है। किसी भी शब्दकोश का संदर्भ उस उपयुक्तता को दर्शाता है ' और 'अनुकूलता' विनिमेय हैं और इसलिए, जब कुछ उचित नहीं कहा जाता है तो यह अर्थ बताता है कि यह नहीं है

सुसंगत या कानून के अनुसार नहीं। इसलिए इस वाक्य में राज्यपाल का बयान स्पष्ट रूप से इस सच्चे सिद्धांत की अपनी समझ पर जोर देता है कि विधानमंडल में बहुमत का समर्थन नहीं रखने वाली कार्यपालिका, यदि सरकार का संचालन करती है, तो वह संविधान के अनुसार राज्य का प्रशासन नहीं करेगी। 31. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस निष्कर्ष से बच नहीं पाते हैं कि राज्यपाल की रिपोर्टों में बताए गए आधार और प्रदान की गई सामग्री न तो अप्रासंगिक हैं और न ही अस्पष्ट हैं, कि प्रकट किए गए कारण विशेष शक्ति के प्रयोग के साथ एक उचित संबंध रखते हैं और इसलिए राष्ट्रपति की संतुष्टि को निर्णायक माना जाना चाहिए, और यह कि इस निष्कर्ष के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि राष्ट्रपति की कार्रवाई 653 के शब्दों का घोर उल्लंघन है।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. 1. [सभरवाल, सी. जे.]

कला. 356 (1) .

32. श्री सोली सोराबजी ने यह भी तर्क दिया कि कथित 'जनता दल के गठन के दौरान अपनाए गए अनैतिक तरीकों' जैसे कारक

' मंत्रिमंडल का विस्तार ',' खरीद-फरोख्त 'और' दूषित हो रहा माहौल 'न केवल अस्पष्ट हैं, बल्कि संवैधानिक तंत्र की विफलता के सवाल से उनका कोई संबंध नहीं है। विद्वान वकील ने यह तर्क देते हुए भी बहुत जोर दिया कि राज्यपाल ने 19 विधायकों द्वारा दिए गए पत्रों पर कार्रवाई करके दल-बदल विरोधी कानून को दरकिनार कर दिया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य दल-बदल के खेल को हतोत्साहित करना है।

विधायक अपनी वफादारी बदलकर और उन पत्रों पर कार्रवाई करके

दल-बदल विरोधी कानून क्योंकि, यदि इन विधायकों ने सदन में अपना समर्थन वापस ले लिया होता और मंत्रालय के खिलाफ मतदान किया होता, तो उन्हें दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता। इन पत्रों पर भरोसा करना दल-बदल विरोधी कानून के अंतर्निहित उद्देश्य और सार के विपरीत है और इसलिए अवैध और निषिद्ध है। विद्वान वकील ने अपने तर्कों को यह तर्क देते हुए पुष्ट किया कि यदि जिन विधायकों ने पत्र लिखे थे, उनका शक्ति परीक्षण किया गया था

हो सकता है कि उन्होंने कई वैध कारणों से अपना विचार बदला हो जैसे (i) नेतृत्व के काम करने की शैली में बदलाव, (ii) नेतृत्व में बदलाव, (iii) पार्टी की एकता बनाए रखने के लिए अहसास, (iv) दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का सामना करने की अनिच्छा और (v) राष्ट्रपति शासन लगाने का बहाना नहीं देना। इस तर्क के समर्थन में कि शक्ति परीक्षण को हमेशा वैध और प्रासंगिक विधि के रूप में मान्यता दी गई है, श्री सोली सोराबजी ने बिजयानंद बनाम में उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। भारत के राष्ट्रपति, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पृष्ठ 173 para6.5.01, वामूज़ो बनाम में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का निर्णय। भारत संघ, (1988) 2 गौ एल. जे. 468 पी. 483 , राज्यपालों की समिति की रिपोर्ट दिनांक 1-10-1971, पृष्ठ 208,209,210,217-219,221-219,221-223 और 234, और 16-7-1970 पर अध्यक्षों के सम्मेलन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन पैरा 13 और 14।

33. हमारे विचार में, विद्वान वकील द्वारा आग्रह किए गए उपरोक्त विवाद/बिंदु किसी भी तरह से दोनों सामग्री के प्रभाव को नष्ट नहीं करते हैं। जिन आधारों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिपरक संतुष्टि प्राप्त की गई। राज्यपाल ने सभी तथ्यों को ईमानदारी से और सही तरीके से बताया है। वे बिल्कुल भी अस्पष्ट नहीं हैं और प्रकृति में कथात्मक हैं।

एस. सी. आर. क्या था?

राज्य में हो रहा है, राज्यपाल ने रिपोर्ट में खुलासा किया है। राज्यपाल इस बात का आकलन कर रहे थे कि क्या पहले याचिकाकर्ता के पास बहुमत है और वह (राज्यपाल) इस पर विचार करने के हकदार हैं।

किसी न किसी तरह से विधायकों का व्यवहार।

यह उम्मीद की जाती है कि प्रभावी होने के लिए सरकार को न केवल सदन में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, बल्कि सदन के बाहर बहुमत सदस्यों द्वारा भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए ताकि सरकार प्रभावी हो सके।

जब भी सदन की फिर से बैठक होती है, तब पदच्युत होने के बारहमासी दबाव में न रहें। हमने ऊपर उल्लिखित उड़ीसा और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों के निर्णयों को देखा है और पाया है कि वे अलग-अलग हैं। बिजयानंद के मामले में मुख्य तथ्य यह था कि

सदन में अपना बहुमत दिखाने वाले विपक्ष को मंत्रालय बनाने के लिए तैयार नहीं किया गया था, इसलिए कि उनके पास बहुमत नहीं था, बल्कि इसलिए कि राज्यपाल को उम्मीद थी कि बहुमत किसी भी समय गिर सकता है और कोई स्थिर मंत्रालय नहीं हो सकता है, और इस पहलू पर जी. के. मिश्रा, सी. जे. ने कहा कि राज्यपाल को चिंता नहीं है कि क्या मंत्रालय भविष्य में स्थिर हो सकता है। यदि विपक्ष के नेता द्वारा गठित मंत्रालय बाद में गिर गया होता, तो राज्यपाल के लिए सिफारिश करना उचित होता।

राष्ट्रपति शासन यदि उस समय कोई अन्य व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहीं था कि

बहुमत के समर्थन से एक वैकल्पिक मंत्रालय से। लेकिन, इसमें

तत्काल मामले में, स्थिति पूरी तरह से अलग है क्योंकि प्रारंभिक चरण में ही राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह इस बात से भी संतुष्ट हैं कि कोई अन्य पक्ष नहीं है जो इस स्थिति में हो।

सरकार बनाने के लिए।

वामूज़ो (1988 (2) गौ एल. जे. 468) के मामले में तथ्य इस प्रकार हैं:

" होकिशे सेमा ने 1987 में सरकार का गठन किया। चिशी ने कोशिश की

सरकार को गिराना और अस्थिर करना। इसे हासिल करने के लिए

अंत में उसने पैसे की पेशकश की और 13 के अलग समूह को कदम रखने का लालच दिया सत्तारूढ़ दल से बाहर। राज्यपाल ने प्रकरण को बुलाया

' राजनीतिक नैतिकता की अविश्वसनीय कमी और पूरी तरह से उपेक्षा

ब्रेकवे की ओर से निर्वाचक मंडल की इच्छाएँ
कांग्रेसियों '। कि इसलिए उनमें से किसी ने भी कभी व्यक्त नहीं किया था

अतीत में किसी भी समय मुख्यमंत्री को कोई भी शिकायत। द.

13 व्यक्तियों को के. एल. चिशी द्वारा जबरन कैद में रखा जाता है।

और वामूज़ो। पार्टी का विभाजन सच नहीं है। यह स्पष्ट है कि 655

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

जिसे सबसे गहरे रंग का राजनीतिक समूह कहा जा सकता है

उनकी अनुपस्थिति में कहा गया, महान नागा चरित्र और लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत। अध्यक्ष द्वारा मान्यता जल्दबाजी में दी गई। यह पूरी घटना राजनीतिक खरीद-फरोख्त और साजिशों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस बात का प्रमाण है कि वे समूह हैं

13 व्यक्ति स्वेच्छा से सत्तारूढ़ दल से अलग नहीं हुए हैं

यदि हम उन तथ्यों को देखें, तो फिर से हम पाते हैं कि उपरोक्त तथ्यों की मामले में दो भौतिक तथ्यों के साथ कोई समानता नहीं है। उक्त मामले में, जैसा कि उन तथ्यों पर पाया गया, यह माना गया कि राज्यपाल ने अपने अधिकार क्षेत्र और उसमें बताए गए तथ्यों का उल्लंघन किया है कला के प्रावधानों के लिए अप्रासंगिक पाए गए। 356 (1) , द्वारा

गुवाहाटी उच्च न्यायालय।

जहां तक सरकार आयोग की रिपोर्ट, राज्यपालों की समिति की रिपोर्ट और लोकसभा अध्यक्ष के अभिभाषण का संबंध है, उसमें व्यक्त किए गए विचार वास्तव में सराहनीय हैं और यह उम्मीद की जाती है कि जहां भी ऐसी कोई कठोर कार्रवाई की जाए, जैसे कि अनुच्छेद के तहत शक्ति का प्रयोग। 356 (1) , यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक संतुष्टि किसी भी अप्रासंगिक, तर्कहीन या विकृत आधार पर आधारित न हो। लेकिन, इस दृष्टिकोण से हमने तथ्यों को लिया है

इस मामले में, उन रिपोर्टों में व्यक्त किए गए विचार याचिकाकर्ताओं के लिए कोई सहायक नहीं हैं। इसके अलावा, ये सिफारिशें मौजूदा कानूनों को बदलने के लिए हैं, जिसका तात्पर्य है कि जब तक इन सिफारिशों को संवैधानिक रूप से लागू करने योग्य मानदंडों में ढाला नहीं जाता है, तब तक मौजूदा कानून प्रबल रहेगा।

34. श्री सोली सोराबजी ने अपनी इस बात को सामने लाने के लिए कि 19 विधायकों द्वारा समर्थन वापस लेने का तथ्य पूरी तरह से अप्रासंगिक था, दसवीं अनुसूची यानी दलबदल विरोधी कानून का स्पष्ट संदर्भ दिया था। यह तर्क उनकी इस बात को साबित करने के लिए आगे बढ़ाया गया था कि दल-बदल विरोधी कानून के संदर्भ में, शक्ति परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए सबसे प्रासंगिक, वैध और सुनिश्चित तरीका था कि क्या मंत्रिपरिषद

श्री एस. आर. बोम्मई के नेतृत्व में सदन में बहुमत था या नहीं। हम डरते हैं, हम विद्वान वकील के इस निवेदन से सहमत होने में असमर्थ हैं। में दसवीं अनुसूची की शुरूआत

संविधान ने किसी भी तरह से अनुच्छेद के तहत शक्ति के प्रयोग को प्रभावित नहीं किया है। 356 न ही इसने कला में संशोधन किया है। 356 किसी भी तरह से। संशोधन

संविधान में दसवीं अनुसूची को शामिल करने वाले निकाय के समक्ष कई निर्णय थे (विशेष रूप से कला के दायरे के बारे में राजस्थान मामला। 356. एक धारणा है कि कानून बनाने वाली संस्था

उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई मौजूदा व्याख्या से अवगत था कानून के किसी प्रावधान या किसी संवैधानिक प्रावधान पर। अगर कहा जाए तो

संवैधानिक प्रावधान (कला। 356) एक नया जोड़ते समय अछूता था

प्रावधान (कला। 356), हमें यह मान लेना होगा कि मौजूदा व्याख्या उक्त प्रावधान स्थिति को नियंत्रित करना जारी रखता है। यह नहीं है।

यह मानना संभव है कि कला को दी गई व्याख्या। 356 राजस्थान में

मामला, यदि इसे नियंत्रित करना जारी रखता है, तो इसकी प्रभावकारिता को नष्ट कर देगा

दसवीं अनुसूची। संविधान की दसवीं अनुसूची लागू होती है -

विधानमंडल के सदन के भीतर कार्य का लेन-देन। ऐसी

सदन के बाहर दलबदल की गतिविधि को किसी भी तरह से दंडित नहीं किया जाता है।

दसवीं अनुसूची के अनुसार। संविधान की विफलता की अवधारणा

सरकार का तंत्र बहुमत के नुकसान तक ही सीमित नहीं है

सदन में एक मंत्रालय द्वारा; यह कई कारणों से हो सकता है। इसलिए,

यदि विधानमंडल की बैठक को अनिवार्य माना गया था

अधीन कार्रवाई के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट से पहले की आवश्यकता

मंत्रालय की स्थिरता का आकलन करने के लिए (दसवीं अनुसूची के बाद) संविधान में जोड़ा गया), दसवीं अनुसूची होती

उपयुक्त शब्द, या कला। 356 इसे बदल दिया गया होगा।

पैरा 389 में न्यायमूर्ति रेड्डी ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने

ईटीशन निम्नलिखित तर्क दे रहा है:

" (1) अनुच्छेद 356 (1) के तहत घोषणा से मुक्त नहीं है

न्यायिक जांच। अदालत इस बात की जांच कर सकती है कि क्या संतुष्टि है

पूरी तरह से बाहरी सामग्री पर गठित किया गया है या क्या एक है

सामग्री और संतुष्टि के बीच तर्कसंगत संबंध।

(2) अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति का अर्थ है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। उसमें उल्लिखित संतुष्टि व्यक्तिपरक संतुष्टि है। यह

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी के विचार पर संतुष्टि का गठन किया जाता है तथ्य और परिस्थितियाँ।

(3) राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई दोनों रिपोर्ट आवश्यक हैं।

और प्रासंगिक तथ्य जो अनुच्छेद 356 के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक थे।

राज्यपाल की रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों को ऐसा नहीं कहा जा सकता है -

अप्रासंगिक। वे पूरी तरह से प्रासंगिक हैं।

(4) जहां राज्यपाल की "व्यक्तिगत ईमानदारी" पर सवाल नहीं उठाया जाता है, उनका संतोष कि कोई अन्य दल 657 बनाने की स्थिति में नहीं है

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

सरकार को सच के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और यह एक उचित आधार पर आधारित है सभी प्रासंगिक तथ्यों का मूल्यांकन।

(5) शक्ति परीक्षण न तो अनिवार्य था और न ही अनिवार्य। यह.

कार्रवाई की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट भेजने की पूर्व शर्त नहीं थी अनुच्छेद 356 (1) के तहत,

(6) संविधान में दसवीं अनुसूची की शुरूआत नहीं हुई है।

अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति की सामग्री को किसी भी तरह से प्रभावित करता है।

(7) चूँकि घोषणा की संतुष्टि पर जारी की जानी है

केंद्रीय मंत्रिपरिषद की राज्यपाल की रिपोर्ट को गलत नहीं ठहराया जा सकता है

कानूनी दुर्भावना के आधार पर।

(8) राजस्थान राज्य में बताए गए परीक्षण को लागू करना v. संघ का

भारत, न्यायालय को प्रकट की गई सामग्री के आधार पर यह अभिनिर्धारित करना चाहिए कि

राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिपरक संतुष्टि निर्णायक होती है और

गलती नहीं की जा सकती। इसलिए यह घोषणा आपत्तिजनक नहीं है।

उपरोक्त कारणों 1 और 2 को छोड़कर, अन्य कारणों को स्वीकार नहीं किया गया।

न्यायमूर्ति रेड्डी द्वारा। विद्वान न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि जहां राज्यपाल की व्यक्तिगत ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जाता है, उनकी संतुष्टि कि कोई भी पक्ष सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, को स्वीकार करना होगा क्योंकि यह सभी प्रासंगिक तथ्यों के उचित मूल्यांकन पर आधारित है। न्यायालय ने इस तर्क को भी स्वीकार नहीं

किया कि राज्यपाल की रिपोर्ट को दुर्भावना के आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता है। विद्वान न्यायाधीश ने कहा है कि यह प्रश्न कि क्या सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है, राज्यपाल द्वारा या उस मामले के लिए सदन के पटल को छोड़कर कहीं और निर्धारित किया जाने वाला विषय नहीं है। सदन वह स्थान है जहाँ लोकतंत्र सक्रिय है। यह राज्यपाल की व्यक्तिपरक संतुष्टि का सवाल नहीं है। यह नोट करना उपयोगी होगा कि पैराग्राफ 391 में क्या देखा गया है जो इस प्रकार है:

" 391. हमें यह भी कहना चाहिए कि बिंदु (7) के तहत अवलोकन समान रूप से है गलत जगह पर रखा गया। यह सच है कि अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई इस आधार पर की जाती है -

केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संतुष्टि का, लेकिन उस आधार पर

यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्यपाल की 'कानूनी दुर्भावना' अप्रासंगिक है।

जब लेख आधार पर बनाई जा रही संतुष्टि की बात करता है

राज्यपाल की रिपोर्ट की कानूनी दुर्भावना, यदि कोई हो, राज्यपाल की है। इसे अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता। राज्यपाल की रिपोर्ट नहीं हो सकती है

निर्णायक लेकिन इसकी प्रासंगिकता निर्विवाद है। अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई

यह केवल और विशेष रूप से ऐसी रिपोर्ट पर आधारित हो सकता है। राज्यपाल 658 हैं।

बहुत उच्च संवैधानिक पदाधिकारी। उसे निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए और

ईमानदारी से अपनी शपथ के अनुरूप। वह वास्तव में उसके खिलाफ रिपोर्ट कर रहा है

अपनी ही सरकार। यही कारण है कि अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि

उनकी रिपोर्ट पर अंतर्निहित विश्वास। यदि, तथापि, किसी मामले में उसकी रिपोर्ट है

कार्रवाई भी। के निर्णय में किए गए अन्य बिंदुओं के बारे में
उच्च न्यायालय, हमें कहना चाहिए कि उच्च न्यायालय कानून में गलत हो गया

राज्यपाल की रिपोर्ट को मंजूरी देने और बरकरार रखने में और

अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति। राज्यपाल की रिपोर्ट को दूषित किया जाता है

एक से अधिक धारणाएं कानून में पूरी तरह से अस्थिर हैं। द.
संविधान एक दायित्व नहीं बनाता है कि राजनीतिक दल

मंत्रालय के गठन में अनिवार्य रूप से बहुमत होना चाहिए

विधायिका। अल्पसंख्यक सरकारें अनजान नहीं हैं। क्या है?
यह आवश्यक है कि सरकार को विश्वास प्राप्त हो

घर। इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया प्रतीत होता है

राज्यपाल। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या परिषद

मंत्रियों ने सदन का विश्वास खो दिया है, यह कोई मुद्दा नहीं है
राज्यपाल द्वारा या उस मामले के लिए इसके अलावा कहीं और निर्धारित किया गया

घर का फर्श। हमारे लोकतंत्र में अंतर्निहित लोकतंत्र का सिद्धांत

संविधान का अनिवार्य रूप से अर्थ है कि ऐसा कोई भी प्रश्न होना चाहिए

सदन के पटल पर निर्णय लिया। घर वह जगह है जहाँ

स्वयं या स्वयं सत्यापन पर प्रश्न किया गया। यह एक नहीं है
उसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि के भीतर मामला। यह एक वस्तुनिष्ठ तथ्य है

सदन के तल पर स्थापित किया जाना। यह नोट करना संतोषजनक है

कि श्री आर. वेंकटरमन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने पुष्टि की है
यह विचार उनके राजाजी स्मारक व्याख्यान (हिंदुस्तान टाइम्स दिनांकित) में है।

24 फरवरी, 1994)।

उच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 28 से 34 में दिए गए महत्वपूर्ण कारण

रिट याचिका को खारिज करने के लिए इस न्यायालय का पक्ष नहीं लिया गया। कर्नाटक के संबंध में राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि इन परिस्थितियों में

यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्यपाल की रिपोर्ट में प्रासंगिक सामग्री शामिल थी या वह उस पर आधारित थी। राज्यपाल द्वारा अपना अनुमान लगाने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता था।

स्पष्ट रूप से, बोम्मई के मामले ने न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार किया। सच है,

न्यायमूर्ति रेड्डी की टिप्पणियाँ ऐसी स्थिति के संदर्भ में की गई थीं जहाँ निवर्तमान मुख्यमंत्री पर बहुमत का समर्थन खोने का आरोप है या सदन का विश्वास और 659 के बाद उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में नहीं

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

एक आम चुनाव जिसके संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की गई थी, लेकिन हमारे विचार में ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा के दायरे के सिद्धांत कोई अलग नहीं हो सकते हैं। कुल मिलाकर, वही सिद्धांत लागू होंगे जब

नवनिर्वाचित विधानसभा को भंग करने और राज्य को फिर से चुनाव में उतारने की सिफारिश।

न्यायमूर्ति रेड्डी, के राज्य विधानमंडलों के विघटन को बरकरार रखने के लिए

मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राज्यपाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य सरकार ने

आंतरिक अशांति से नागरिकों और राज्य की संपत्ति की रक्षा करने में बुरी तरह विफल रहे और उक्त रिपोर्ट के आधार पर, राष्ट्रपति ने अपेक्षित संतुष्टि का गठन किया। मध्य प्रदेश राज्य की परिस्थितियों से निपटने के लिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि 'राज्यपाल की रिपोर्ट प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होती हैं और उन्हें प्रामाणिक और उचित सत्यापन के बाद बनाया जाता है'। (हमारे द्वारा दिया गया जोर)

इस प्रकार, यह न्यायालय के लिए, न्यायिक समीक्षा के अभ्यास में, जांच करने के लिए खुला है

यह प्रश्न कि क्या राज्यपाल की रिपोर्ट प्रासंगिक सामग्री पर आधारित है या नहीं; क्या इसे प्रामाणिक बनाया गया है या नहीं; और क्या तथ्यों का विधिवत सत्यापन किया गया है या नहीं। इन कारकों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप बहुमत ने कर्नाटक और नागालैंड की राज्य विधानसभाओं के विघटन को अमान्य घोषित कर दिया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम द्वारा आग्रह किए गए तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं

एल. डी. भारत के लिए अटॉर्नी जनरल, भारत के सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त

सॉलिसिटर जनरल, सरकार की ओर से उपस्थित होते हुए कि राज्यपाल की रिपोर्ट स्वयं सामग्री है और न्यायिक समीक्षा के दायरे में उस सामग्री में जाने की अनुमति नहीं है जिस पर राज्यपाल की रिपोर्ट आधारित हो सकती है और यह सवाल कि क्या राज्यपाल द्वारा इसका विधिवत सत्यापन किया गया था। या नहीं। वर्तमान मामले में, हमारे पास राज्यपाल की रिपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रासंगिक सामग्री के अभाव में बहुत कम उचित सत्यापन, की रिपोर्ट

राज्यपाल को राज्यपाल के व्यक्तिगत उपदेश के रूप में माना जाना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत कठोर और चरम कार्रवाई को राज्यपाल के केवल भ्रम, संदेह, सनक और कल्पनाओं पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह न्यायालय संविधान के विध्वंस को देखते हुए मूक दर्शक नहीं रह सकता है। होना ही है। याद रखें कि यह न्यायालय विवेक पर पहरा देने वाला है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, राज्यपाल मुख्य खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन राज्यपाल ने जो कहा है, उसके बारे में जल्दबाजी में इसे एक सुसमाचार सत्य के रूप में स्वीकार करने से पहले मंत्रिपरिषद को राज्यपाल की रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों को सत्यापित करना चाहिए। स्पष्ट रूप से, राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद को गुमराह किया है जिससे 660 सहायता मिलती है

और मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली सलाह के कारण विवादित उद्घोषणा जारी की जाती है।

की कमी के सरकार की ओर से आग्रह किए गए तर्क के बारे में

न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानक और इसलिए, न्यायालय को इस तरह के मानकों को छोड़ देना चाहिए

राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाने वाले जटिल प्रश्न, जैसे कि बिहार की स्थिति, कई अभेद्य, बारीकियों, निहितार्थ और पेचीदगियों से भरे हुए हैं और ये भी हैं

कई यदि और लेकिन न्यायिक जांच के लिए अतिसंवेदनशील नहीं हैं, तो तर्क की असमर्थता स्पष्ट हो जाती है जब निर्णय के प्रकाश में इसकी जांच की जाती है

कर्नाटक और नागालैंड की विधानसभाओं को भंग करने की चुनौती को बरकरार रखते हुए बोम्मई का मामला। इन दोनों विधानसभाओं के विघटन का बचाव करने वाले इसी तरह के तर्क को नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष समर्थन नहीं मिला,

हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। वहाँ भी, तर्क था कि घोड़े को आंकने के लिए कोई न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानक नहीं थे-व्यापार, दबाव, वातावरण को दूषित किया जा रहा था, गलत कारावास, धन द्वारा प्रलोभन, नागालैंड में विद्रोहियों के साथ संपर्क। इस तर्क को खारिज कर दिया गया।

जब न्यायालय ने विघटन की वैधता पर विचार किया तो स्थिति अलग थी।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की विधानसभाएँ।

न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी की राय के पैराग्राफ 432 और 433 में

बोम्मई के मामले में, 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस की घटनाओं, उक्त तिथि से पहले दिए गए आश्वासनों, विध्वंस के बाद उत्पन्न हुई असाधारण स्थिति, मौजूदा तनावपूर्ण सांप्रदायिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राज्यपालों की रिपोर्ट सहित अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री पर, यह कहना संभव नहीं था कि राष्ट्रपति के पास पहले कोई प्रासंगिक सामग्री नहीं थी। जिसके आधार पर वे संतोष व्यक्त कर सके कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकारें कार्रवाई और उसके परिणामों से खुद को अलग नहीं कर सकती हैं और एक ही पार्टी द्वारा नियंत्रित इन सरकारों, जिनके प्रमुख प्रकाशकों ने संरचना को ध्वस्त करने के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया था, को भाजपा नेताओं के कृत्यों और कार्यों से अलग नहीं किया जा सकता है। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि इन भाजपा सरकारों का विश्वास

पार्टी के कृत्यों और आचरण को देखते हुए धर्मनिरपेक्षता का संदेह था

इन सरकारों को नियंत्रित करना और यह कि विध्वंस के बाद विकसित हुई अस्थिर स्थिति में, इन राज्यों की सरकार को चलाया नहीं जा सकता है

संविधान के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय सक्षम नहीं है

यह कहने के लिए कि ऐसी कोई प्रासंगिक सामग्री नहीं थी जिस पर वह 661 हो सकता है

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

उत्पादित सामग्री की शुद्धता पर सवाल उठाते हैं और यह कि भले ही इसका हिस्सा हो कार्रवाई के लिए प्रासंगिक नहीं है। न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि

कार्रवाई को बनाए रखने के लिए कुछ प्रासंगिक सामग्री। इस पंक्ति की सराहना करने के लिए

तर्क करते हुए, यह ध्यान में रखना होगा कि वही विद्वान न्यायाधीश, जबकि

कर्नाटक और नागालैंड विधानसभाओं के विघटन की वैधता की जांच करना,

न्याय की राय में दिए गए तर्क और निष्कर्षों से सहमत होना सावंत ने कहा कि राज्यपाल द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया था, वह कुछ भी नहीं थी

लेकिन उनका इप्स डिक्सिट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उक्त विघटन अवैध था।

बहुमत की राय और उसके सही अनुपात की सराहना तभी की जा सकती है जब यह ध्यान में रखा जाए कि बहुमत ने विघटन को अमान्य घोषित कर दिया है।

कर्नाटक और नागालैंड की विधानसभाएँ और के विघटन को वैध माना गया

मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की विधानसभाएँ। एक बार जब इस कारक को पूर्ण ध्यान में रखा जाता है, तो यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि समान तथ्यों की धारणा या किसी भी न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानकों की कमी के तर्क का कोई आधार नहीं होगा।

वर्तमान मामले में, बोम्मई के मामले की तरह, कोई सामग्री नहीं है

राज्यपाल के उपदेश को छोड़कर जो कुछ भी हो। ऐसी कार्रवाई जिसके परिणामस्वरूप किसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने का दावा करने से रोका जा सके

इस तरह की काल्पनिक धारणाओं पर चुनाव, अगर खड़ा होने दिया जाता है, तो लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए विनाशकारी होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचना एक बात है कि सरकार बनाने का दावा करने वाला बहुमत राज्य को स्थिर सरकार प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन यह कहना पूरी तरह से अलग बात है कि उन्होंने अवैध तरीकों से बहुमत हासिल किया है और इसलिए सरकार बनाने के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बाद के मामले में, मामले को

लोगों के विवेक और इच्छा पर छोड़ना पड़ सकता है, या तो उसी सदन में जिसे विपक्ष द्वारा लिया जा रहा है या चुनाव में लोगों द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जा सकता है। अत्यधिक ठोस सामग्री के बिना, संवैधानिक प्राधिकरण के लिए सरकार बनाने के लिए बहुमत द्वारा किए गए दावे को केवल इस आधार पर अस्वीकार करना पूरी तरह से तर्कहीन होगा कि बहुमत प्रलोभन और रिश्वत की पेशकश से प्राप्त किया गया है जो सौदे अंधेरे में हुए हैं लेकिन उनके अज्ञात स्रोतों ने ऐसे सौदों की पुष्टि की है। विधान सभा को भंग करने की सिफारिश करने की असाधारण आपातकालीन शक्ति का उपयोग निश्चित रूप से बिना किसी प्रामाणिक सामग्री के बताए गए कारणों से सुशासन या राजनीति के शुद्धिकरण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये ऐसे मामले हैं जिन्हें विपक्ष और मतदाताओं सहित अन्य लोगों के विवेक पर छोड़ देना बेहतर है।

यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान अनुचित जल्दबाजी का मामला नहीं है।

राज्यपाल इस प्रवृत्ति को देखने के लिए चिंतित थे और वैध रूप से आ सकते हैं

' वैचारिक पुनर्गठन ", तब निर्णय प्रभावी होगा और इस तरह के पुनर्गठन समूह चुनाव जीतेंगे, जो विघटन के परिणामस्वरूप आयोजित किए जाएंगे। यह आग्रह किया जाता है कि मतदाताओं के पास वापस जाने और स्वीकार करने के बीच एक विकल्प दिया जाए अनुचित तरीके से प्राप्त बहुमत, केवल पहला ही वास्तविक विकल्प है। यह प्रस्ताव बहुत व्यापक और व्यापक है जिसे स्वीकार करने की योग्यता नहीं है। इस तरह की स्वीकृति

के तहत असाधारण शक्ति का आह्वान करने के लिए एक प्रासंगिक विचार के रूप में एक प्रस्ताव

अनुच्छेद 356 विघटनों की बाढ़ का द्वार खोल सकता है और इसके दूरगामी खतरनाक और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। यह चुनाव के बाद के गठबंधनों और पुनर्गठनों को अनैतिक होने के आधार पर अस्वीकार करने का एक तरीका भी हो सकता है, जो देश या राज्य को किसी अन्य चुनाव के लिए मजबूर कर सकता है। यह पहलू खंडित फैसलों की स्थिति और गठबंधन सरकारों के गठन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि चुनाव के बाद दो या दो से अधिक दल एक साथ आते हैं, तो यह हो सकता है

इस तरह की अवैधता के कथित आधार पर उनके बहुमत के दावे को नकारना मुश्किल है। ये ऐसे पहलू हैं जिन्हें राजनीतिक दलों द्वारा निर्धारित किया जाना बेहतर है, जिन्हें निश्चित रूप से अपने लिए स्वस्थ और नैतिक मानक निर्धारित करने चाहिए, लेकिन, किसी भी मामले में, अंतिम निर्णय मतदाताओं और मतदाताओं पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

विधायिका में विपक्ष के सदस्य भी शामिल होते हैं।

उपरोक्त बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, हम एक स्थिति में दो उदाहरण दे सकते हैं।

जहाँ कोई भी राजनीतिक दल अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सका:

1 . चुनाव के बाद, दो या दो से अधिक राजनीतिक दल एक साथ आते हैं

गठन के लिए उस आधार पर बहुमत और हिस्सेदारी का दावा

सरकार। मीडिया में रिश्वत लेने की खबरें आ सकती हैं

किसी एक राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों को प्रस्ताव दिया गया बहुमत का हिस्सा बनने के लिए उसकी सहमति के लिए। यदि विवाद

उत्तरदाताओं को स्वीकार किया जाना है, फिर संवैधानिक

पदाधिकारी सरकार के गठन को इस तरह से अस्वीकार कर सकता है

सदन को बहुमत से भंग करें या इसे भंग करने की सिफारिश करें। इस आधार पर कि ऐसे समूह को दावा करने से रोका जाना चाहिए

सरकार बनाने के लिए और इसलिए, एक स्थिति उत्पन्न हुई है

जिसे राज्य सरकार चला नहीं सकती है।

संविधान के प्रावधानों के अनुसार।

2 . एक राजनीतिक दल के साथ सरकार बनाने का दावा करता है

स्वतंत्र निर्वाचित उम्मीदवारों का समर्थन ताकि बहुमत प्राप्त करने के लिए कम संख्या। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक

रिपोर्ट, अंधेरे की आड़ में, रिश्वत की बड़ी राशि का भुगतान किया गया था

रामेश्वर प्रसाद प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र निर्वाचित उम्मीदवारों को विशेष पार्टी द्वारा v.

यू. क्यू. 1. [सभरवाल, सी. जे.]

सरकार के गठन के लिए उनका समर्थन। प्रत्यर्थियों के तर्क को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि बिना किसी ठोस सामग्री के संवैधानिक पदाधिकारी सरकार के गठन को अस्वीकार कर सकता है या इस तरह का दावा किए जाने से पहले ही इसे भंग करने की सिफारिश कर सकता है ताकि सरकार बनाने के लिए दावा किए जाने को रोका जा सके। सरकार।

हमें डर है कि अनुच्छेद 356 (1) के तहत उपरोक्त या इसी तरह की घटनाओं के तहत कार्रवाई का सहारा लेना स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य होगा। ये हैं।

$

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि एक स्थिति है संवैधानिक पदाधिकारी जिसके अंतर्गत राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।

वाई.

यह तर्क कि सरकार की स्थापना विघटन के परिणामस्वरूप मौजूदा सरकार को हटाने से अलग है

बोम्मई के मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष तथ्यात्मक स्थिति और इसलिए, इन विभिन्न स्थितियों में समान मापदंडों को लागू नहीं किया जा सकता है, जिन पर पहले ही विचार किया जा चुका है। इसके अलावा, यह याद रखना चाहिए कि प्रथम दृष्टया बहुमत वाले राजनीतिक दल को सरकार में बने रहने या सरकार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा भी मामला हो। दोनों श्रेणियों में, अंततः सदन के पटल पर बहुमत साबित करना होगा। विवाद मूल मुद्दे को भी नजरअंदाज कर देता है। यह है कि प्रथम दृष्टया, बहुमत रखने वाली पार्टी को भी सरकार चलाने से रोका जा सकता है या सरकार बनाने के दावे को इस कथित धारणा पर अस्वीकार कर दिया जा सकता है कि उक्त बहुमत अवैध तरीकों से प्राप्त किया गया था। इस तरह के बुनियादी मुद्दों के कथित रूप से आने का कोई सवाल ही नहीं है।
"राजनीतिक गुट" की श्रेणी को इस आधार पर बंद किया जा रहा है कि कई अभेद्य हैं जिनके लिए कोई न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानक नहीं हैं और,

इस प्रकार, न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर।
आगे यह तर्क कि 'स्थिति' अभिव्यक्ति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार को इसके अनुसार नहीं चलाया जा सकता है

अनुच्छेद 356 में संविधान के प्रावधानों से पता चलता है कि शक्ति निवारक और/या उपचारात्मक दोनों है और इसलिए, एक संवैधानिक पदाधिकारी राजनीतिक प्रक्रिया की शुद्धता के आधार पर दलों या निर्वाचित उम्मीदवारों के एक समूह को सरकार के गठन से वंचित करने के अपने अधिकारों के भीतर होगा।

1 664

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2006] 1 एस सी आर।

हम जो पहले ही कह चुके हैं, उसे देखते हुए इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर कोई लाभ नहीं होगा। भले ही निवारक हो, सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है।

एक अन्य तर्क यह है कि अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति है

चरित्र में विधायी और इसलिए, परीक्षण के लिए प्रासंगिक मापदंड

केवल विधायी कार्रवाई की वैधता पर विचार करने की आवश्यकता है और उस प्रकाश में 'दुर्भावनापूर्ण' या 'तर्कहीन' या 'बाहरी' जैसी अभिव्यक्तियों को अंततः यह पता लगाने के लिए देखा जाना चाहिए कि क्या कार्रवाई अधिकार से बाहर है या नहीं। विवाद यह है कि दुर्भावना की अवधारणा आम तौर पर विधायी कार्रवाई की वैधता तय करते समय कार्यकारी कार्रवाई के संदर्भ में समझा जाना अनुपलब्ध है। निवेदन यह है कि दुर्भावनापूर्ण या

बाहरी विचार को एक विधायी अधिनियम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जिसे चुनौती देने पर जांच का दायरा बहुत सीमित होता है।

एक से अधिक कारणों से, हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं

विचाराधीन प्रकृति की घोषणा एक विधायी अधिनियम है। सबसे पहले, यदि तर्क को स्वीकार किया जाता, तो बोम्मई के मामले में कर्नाटक और नागालैंड के मामले में घोषणा को अवैध और अमान्य नहीं माना जाता। दूसरा, अनुच्छेद 377 में न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी की बहुमत की राय में इस तर्क को विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था। विवाद यह था कि

वर्तमान प्रकृति की घोषणा कानून के स्वरूप को मानती है और इसे केवल उस आधार पर निरस्त किया जा सकता है जिस पर किसी कानून को निरस्त किया जा सकता है। इस तर्क को खारिज करते हुए यह माना गया कि संसद का प्रत्येक अधिनियम यह कानून बनाने के बराबर नहीं है और इसका परिणाम यह नहीं है कि संसद कई अन्य कार्य करती है। ऐसे कार्यों में से एक अनुच्छेद 356 के खंड (3) के तहत घोषणा का अनुमोदन है। इस तरह की मंजूरी को किसी भी तरह की कल्पना से 'कानून' नहीं कहा जा सकता है। इसका कानूनी चरित्र पूरी तरह से अलग है। यह एक संवैधानिक कार्य है, जो अनुच्छेद 356 के खंड (1) के तहत शक्ति के प्रयोग पर एक रोक है। यह खंड (1) के तहत शक्ति का उचित प्रयोग सुनिश्चित करने के हित में परिकल्पित एक सुरक्षा है। यह निश्चित रूप से न तो विधान है और न ही विधायी।

श्री सुब्रमण्यम, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, हालांकि,

तर्क दिया कि बोम्मई का मामला इस धारणा पर आगे बढ़ा कि अनुच्छेद 356 (1) के तहत घोषणा विधायी नहीं है, लेकिन जब उस मुद्दे की पुनः के मामलों में पहले के निर्णयों के संदर्भ में गहराई से जांच की जाती है: दिल्ली विधि अधिनियम, 1912, अजमेर-मेरवाड़ा (विधियों का विस्तार) अधिनियम, 1947 और भाग सी राज्य (विधि) अधिनियम, 1950 [1951 एस. सी. आर. 747 पृष्ठ 970 971 पर]; जयंतीलाल अमृत लाल शोधन बनाम। एफ. एन. राणा और अन्य।, [1964] 5 एस. सी. आर. 294 205-206 पर; रमेशचंद्र कचारदास पोरवाल और अन्य। महाराष्ट्र राज्य 665

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

* & ओआरएस।, [1981] 2 एस. सी. सी. 722], ए. के. रॉय बनाम। भारत संघ और अन्य।, [1982] आई. एस. सी. सी. 271, यह स्पष्ट होगा कि पैरा 377 में न्यायमूर्ति रेड्डी के निष्कर्ष की आवश्यकता है।

इन निर्णयों के आलोक में फिर से देखें। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

नौ न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय हम पर बाध्यकारी है।

हालांकि बोम्मट ने न्यायिक समीक्षा का दायरा बढ़ाया है, लेकिन जा रहा है

राजस्थान राज्य के मामले में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार भी,

संतुष्टि को हमेशा इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह दुर्भावनापूर्ण है या

यह पूरी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक आधारों पर आधारित है। इसके अलावा कि

राजस्थान राज्य के मामले में न्यायिक समीक्षा का संकीर्ण न्यूनतम क्षेत्र अब बोम्मई के मामले में इसके विस्तार को देखते हुए देश का कानून नहीं है।

मामला लेकिन वर्तमान मामला तब भी जब सीमित न्यायिक आवेदन द्वारा विचार किया जाता है

समीक्षा, न्यायिक जांच का सामना नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ संतुष्टि इस पर आधारित है

पूरी तरह से बाहरी और अप्रासंगिक आधार। मुख्य आधार रोकने के लिए है सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टी।

राजस्थान राज्य के मामले में, पैरा 185 में, न्यायमूर्ति उन्तवालिया ने टिप्पणी की

कि यह न्यायालय ऐसे आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन नहीं है जो अधिकार से बाहर, पूरी तरह से अवैध या दुर्भावनापूर्ण है क्योंकि ऐसी स्थिति में यह

कानून का कोई आदेश नहीं होना चाहिए। आगे यह देखते हुए कि यह अक्षम और खतरनाक है

न्यायालय के लिए निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करके तथ्यों की जांच करके निष्कर्ष निकालना, लेकिन साथ ही यह कहना भी उतना ही असमर्थनीय होगा कि न्यायालय आदेश को रद्द करने के लिए शक्तिहीन होगा, यदि उसके चेहरे पर, या, निषिद्ध क्षेत्र की परिधि के चारों ओर जाकर, न्यायालय आदेश को असाधारण शक्तियों के केवल ढोंग या रंगीन अभ्यास के रूप में पाता है।

संविधान के कुछ अनुच्छेदों के तहत दिया गया है और इस प्रकार किसी दिए गए मामले में यह निष्कर्ष निकालना संभव हो सकता है कि यह सत्ता के प्रयोग में धोखाधड़ी है।

वर्तमान मामले में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राज्यपाल की कार्रवाई केवल एक दिखावा थी, जिसका वास्तविक उद्देश्य एक राजनीतिक दल को सरकार बनाने का दावा करने से रोकना था।

न्यायमूर्ति रेड्डी की राय का उल्लेख करते हुए, बोम्मई के मामले में, यह था

उत्तरदाताओं के लिए तर्क दिया कि बेरियम केमिकल्स लिमिटेड और ए. एन. आर. में अपनाया गया दृष्टिकोण। वी. कंपनी विधि बोर्ड और अन्य।, [1966] सपल। एस. सी. आर. 311 और अन्य मामले जहां कानूनी या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चुनौती के तहत कार्रवाई की जाती है, वर्तमान की तरह संवैधानिक कार्रवाई की वैधता का परीक्षण करते समय लागू नहीं होते हैं। विवाद के उचित मूल्यांकन के लिए, यह हो सकता है पूर्ण पैराग्राफ 372 और 373 में पुनः प्रस्तुत करने के लिए उपयोगी होगा जिन पर कुछ टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था। वही नीचे पढ़ा गया है:

" 372. [2006] 1 एस. सी. आर. के विभिन्न बिंदुओं को पेश करने वाले विभिन्न निर्णयों पर ध्यान दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब अनुच्छेद 356 (1) के तहत किसी घोषणा पर सवाल उठाया जाता है तो हम अब इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा का दायरा और पहुंच क्या होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देते समय, हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति एक असाधारण चरित्र की है जो यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि राज्यों की सरकार संविधान के अनुसार चलती है। हम हैं।

समान रूप से जागरूक है कि इस शक्ति का कोई भी दुरुपयोग या दुरुपयोग हमारी संवैधानिक प्रणाली के साथ तबाही मचाने के लिए बाध्य है। हमने जिस सरकार को अपनाया है, उसे ध्यान में रखते हुए, शक्ति वास्तव में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की है, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री हैं। ए में

मतलब, यह वास्तव में एक शक्ति नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति पर एक दायित्व है

संवैधानिक सरकार के संरक्षण के हित में

राज्यों। यह एक ऐसी शक्ति नहीं है जिसकी कल्पना केंद्र में सत्ता में बैठे राजनीतिक दल के हितों को संरक्षित करने या बढ़ावा देने के लिए की गई है और न ही इसे ऐसा हथियार माना जाता है जिससे आप अपने राजनीतिक हितों पर हमला कर सकें।

विरोधी। इस शक्ति की बहुत विशालता-इच्छा को पूर्ववत करना

यह तुरंत दिखाई देता है लेकिन कुछ वर्षों के बाद एक दुष्चक्रपूर्ण रूप में सामने आता है। हवा बोओ और तुम बवंडर काटोगे। बुद्धि संयम में निहित है न कि अधिकता में।

(हमारे द्वारा दिया गया जोर)

इसके अलावा, विद्वान न्यायाधीश कहते हैं कि:

" 373. जब भी अनुच्छेद 356 के तहत किसी घोषणा पर सवाल उठाया जाता है, तो अदालत निस्संदेह इस धारणा के साथ शुरुआत करेगी कि यह वैध थी।

जारी किया गया लेकिन यह हस्तक्षेप करने में संकोच नहीं करेगा यदि घोषणा की अयोग्यता या असंवैधानिकता स्पष्ट रूप से की गई है

बाहर निकलें। ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करना अदालत पर डाले गए कर्तव्य का त्याग करने के बराबर होगा-सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय

संविधान द्वारा। अब, वे कौन से आधार हैं जिन पर

अदालत हस्तक्षेप कर सकती है और घोषणा को रद्द कर सकती है? उपरोक्त निर्णयों पर चर्चा करते समय, हमने भगत सिंह बनाम में प्रिवी काउंसिल द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की अस्वीकार्यता का संकेत दिया है।

सम्राट, आकाशवाणी (1931) पी. सी. 111 और राजा सम्राट बनाम। बंगाली लाल सरमा,

आकाशवाणी (1945) पीसी 48। यह 1931 और 1944 के वर्षों में था, जब न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ने अपनी वर्तमान प्रभावशीलता हासिल की थी।

घोषणा न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। तथ्यों और परिस्थितियों पर इस मामले में, उसने कार्रवाई को उचित पाया। अब, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर आते हुए, यह कहा जाना चाहिए-जैसा कि संकेत दिया गया है।

पाकिस्तानी संविधान की धारा 58 (2) (बी) द्वारा राष्ट्रपति पर। संघीय सरकार और राष्ट्रीय सरकार को बर्खास्त करने की शक्ति विधानसभा केवल राष्ट्रपति और राष्ट्रपति में निहित है। उसे करना पड़ता है।

उस शक्ति का प्रयोग अपने व्यक्तिगत विवेक और निर्णय में करें। पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक व्यक्ति, भले ही वह व्यक्ति भी लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। यह हमारे संविधान के बारे में सच नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है न कि अपनी व्यक्तिगत क्षमता में। इसके अलावा,

संसद द्वारा अनुमोदन की जाँच होती है जिसमें उस राज्य के सदस्य भी शामिल होते हैं (जिस राज्य की सरकार/विधान सभा के खिलाफ कार्रवाई की जाती है)। जहाँ तक बेरियम केमिकल्स में

इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का संबंध है, यह एक क़ानून द्वारा बनाए गए प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि से संबंधित निर्णय है। उस समय विकसित सिद्धांतों को अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक शक्ति के प्रयोग तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह सर्वोच्च द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक उच्च संवैधानिक शक्ति है

राष्ट्र के संवैधानिक पदाधिकारी, यह उचित नहीं हो सकता है

वैधानिक या प्रशासनिक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई के मामले में लागू परीक्षणों को अपनाना-और न ही किसी भी दर पर, उनकी संपूर्णता में। हम इसके बजाय राजस्थान राज्य में इस न्यायालय द्वारा विकसित सूत्रीकरण को अपनाएंगे जैसा कि हम वर्तमान में विस्तार से बताएंगे। हम इसे भी मान्यता देते हैं, जैसा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने C.C.S.U में किया था। सिविल सेवा मंत्री, (1985) अधिनियम 374 में कहा गया है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वे भी शामिल हैं जिनमें विस्तार से बताया गया है कि न्यायालय इस मामले को लगभग पूरी तरह से राष्ट्रपति/केंद्र सरकार पर छोड़ देगा। अदालत प्रवेश करने से रोक देगी

उन अखाड़ों, उन कार्यों की प्रकृति के कारण। वे ऐसे मामले नहीं हैं जिनसे निपटने के लिए अदालत तैयार है। अदालत ने उन मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया है क्योंकि वे अपनी प्रकृति से न्यायिक समीक्षा को स्वीकार नहीं करते हैं। विदेश नीति, अन्य देशों के साथ संबंध, रक्षा नीति, विदेशी शक्तियों के साथ संधि करने की शक्ति, युद्ध और शांति से संबंधित मुद्दे 668 हैं।

[2006] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कुछ मामले जहां अदालत किसी भी मामले पर विचार करने से इनकार कर देगी न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका। लेकिन शक्ति के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

अनुच्छेद 356 के तहत। यह एक और मामला है कि किसी मामले में अदालत हो सकता है कि हस्तक्षेप न करें। यह पुष्टि करना आवश्यक है कि घोषणा के तहत

अनुच्छेद 356 (1) न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है, हालांकि मानदंड

यह व्यक्तिपरक संतुष्टि के सामान्य मामले से भिन्न हो सकता है।

उपरोक्त अनुच्छेदों को अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है और होना चाहिए

यह ध्यान में रखते हुए देखा गया कि विद्वान न्यायाधीश ने कर्नाटक और नागालैंड विधानसभा के विघटन को अमान्य कर दिया। जो भी हो, वर्तमान मामले में,

आक्षेपित अधिसूचना की वैधता को प्रशासनिक कार्यों की वैधता को निर्धारित करने के लिए उपलब्ध सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर नहीं आंका जा रहा है।

इसके अलावा, न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी की राय का पैरा 376 बहुत महत्वपूर्ण है।

निर्देशात्मक और इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:

" हम मानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया की कुछ अंतर्निहित सीमाएँ हैं। यह.

प्रशासन के बजाय विवादों के निर्णय के लिए अधिक उपयुक्त है

देश को। शासन का कार्य कार्यपालिका का कार्य है। द.

माना जाता है कि कार्यपालिका को पता होना चाहिए कि देश का प्रशासन कैसे करना है, जबकि

न्यायपालिका का कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए सीमित है कि सरकार

संविधान और कानूनों के अनुसार किया जाता है।

न्यायपालिका, जैसा कि उसे करना चाहिए, की राय को उचित महत्व देती है

इस तरह के मामलों में कार्यकारी लेकिन यह कहने के लिए नहीं है, यह करने के लिए टाल देता है पूरी तरह से कार्यपालिका की राय। अंततः क्या दायरा निर्धारित करता है

न्यायिक समीक्षा दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को संदर्भित करती है। ए.

मामला मेघालय और कर्नाटक के मामलों की तरह स्पष्ट हो सकता है।

जहाँ न्यायालय बिना किसी हिचकिचाहट के पा सकता है कि घोषणा खराब है। मध्य प्रदेश से संबंधित मामले भी हो सकते हैं।

राजस्थान और हिमाचल प्रदेश-जहाँ स्थिति इतनी जटिल है,

अभेद्य से भरा और एक तेजी से विकसित होने वाला जो अदालत को लगता है

ऐसा मामला नहीं है जो न्यायिक पूर्वानुमान को स्वीकार करता है, कि यह एक मामला है

जिसे निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए और उसके द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए

कार्यकारी और स्वयं लोगों द्वारा अंतिम विश्लेषण में हो सकता है।

हम जो कहते हैं उसे प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका है
हमारे सामने ठोस मामले हैं।

(हमारे द्वारा दिया गया जोर)

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अंततः क्या दायरा निर्धारित करता है।

न्यायिक समीक्षा के लिए दिए गए मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ हैं और यह 669 है।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. 1. [सभरवाल, सी. जे.]

इस कारण से कर्नाटक और नागालैंड के संबंध में घोषणाओं को खराब माना गया न कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से संबंधित घोषणाओं को।

हम संभावित आधार पर तर्क से प्रभावित नहीं हैं

यदि एलजेपी पार्टी के विधायकों ने सरकार बनाने के लिए नितीश कुमार के दावे का समर्थन किया था तो दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता। उस स्तर पर, इस बात को ध्यान में रखना पूरी तरह से असाधारण था कि कुछ सदस्यों को अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा यदि वे किसी विशेष पार्टी का समर्थन करते हैं। जिस राजनीतिक दल से वे संबंधित हैं, उसके घोषित रुख के खिलाफ। यह जटिल सवाल कि क्या मामला विलय की अनुमेय श्रेणी में आएगा या नहीं, इस पर विचार नहीं किया जा सका। मान लीजिए

यह विलय के अनुमेय क्षेत्र में नहीं आता था और विधायक अयोग्यता का जोखिम अर्जित करते थे, यह विधायक या उपयुक्त पदाधिकारी को तय करना होता है न कि राज्यपाल को अयोग्यता

ग्रहण करनी होती है और इस तरह विघटन की सिफारिश करके दावा करने से रोकें। वर्तमान उद्देश्य के लिए, हमारे लिए विलय और/या मानित विलय से संबंधित दसवीं अनुसूची के पैरा 4 की जांच करना आवश्यक नहीं है। इस दृष्टिकोण से यह प्रश्न उठाया जाना चाहिए कि मूल पक्ष के पहले विलय के बिना विधायक दल का विलय नहीं हो सकता है, इसकी जांच करना आवश्यक नहीं है। इस तर्क को उठाया जाना चाहिए कि भले ही एलजेपी विधायक दल के दो-तिहाई विधायक विलय के लिए सहमत हो गए हों, लेकिन कानूनी रूप से मूल पार्टी के विलय के बिना कोई विलय नहीं हो सकता है और उस स्थिति में भी उन दो-तिहाई विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता। वर्तमान में, इस प्रश्न पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल द्वारा इसे भंग करने की सिफारिश नहीं की जा सकती थी।

दलबदल से संबंधित दसवीं अनुसूची का प्रावधान,

भ्रष्ट आचरण, चुनावी अपराधों और अयोग्यता से संबंधित 1951 का आर. पी. अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधान लोकतंत्र में सार्वजनिक जीवन की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा उपाय हैं।

लेकिन, जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, उनकी उस स्तर पर कोई प्रासंगिकता नहीं थी जब विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की गई थी।

किसी भी सामग्री का अस्तित्व जो भी हो। इस धारणा के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि दावा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं किया जा सकता है और राजनीतिक दलों को तोड़कर हेरफेर पर आधारित हो सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि अनुच्छेद 159 के तहत निर्धारित शपथ

राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे और अपनी क्षमता के अनुसार संविधान और कानूनों का संरक्षण, रक्षा और रक्षा करे। राज्यपाल, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए या अन्यथा, कुछ भी नहीं कर सकता [2006] 1 एस. सी. आर.

जो करना वर्जित है। संविधान राज्यपाल को आदेश देता है कि चुनाव के समापन के बाद, चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्त लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक लोकप्रिय

सरकार के गठन के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। यदि राज्यपाल एक ऐसी स्थिति पैदा करके इसके विपरीत कार्य करता है जिसमें एक पक्ष को दावा करने से भी रोका जाता है और सिफारिश करता है

उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विघटन, एकमात्र अपरिहार्य अनुमान जिसे खींचा जाना है यह है कि अधिकार क्षेत्र का प्रयोग पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है। हम पहले ही 21 मई, 2005 की राज्यपाल की रिपोर्ट का उल्लेख कर चुके हैं।

यह कहते हुए कि एलजेपी पार्टी से संबंधित 17-18 विधायक जद (यू) की ओर बढ़ रहे हैं जिसका मतलब होगा कि जद (यू) गठन करने का दावा करने की स्थिति में हो सकता है। सरकार। आगे यह धारणा कि उक्त सदस्यों का कदम स्वयं इस बात का संकेत था कि उन्हें विभिन्न प्रलोभन दिए गए थे और उस आधार पर यह धारणा बनाई गई थी कि सरकार बनाने के लिए किया जाने वाला दावा संवैधानिक प्रावधानों और बनाए गए सुरक्षा उपायों को प्रभावित करेगा।

इसमें लोगों के फैसले को विकृत करना मनमाना होगा। इससे पता चलता है कि जे. डी. यू. को सरकार बनाने का दावा करने से रोकने का तरीका था। उस स्तर पर, ऐसे दृष्टिकोण को दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में, उस स्तर पर उक्त अनुसूची के प्रावधान

कोई प्रासंगिकता नहीं थी। यह 'धारणा' या 'धारणा' का मामला नहीं है

राज्यपाल द्वारा संविधान के प्रावधान। यह एक स्पष्ट मामला है जहां किसी राजनीतिक दल द्वारा सरकार के गठन को किसी न किसी तरह रोकने का प्रयास किया गया था-एक ऐसा क्षेत्र जो कार्य, कर्तव्यों के रूप में पूरी तरह से निषिद्ध है।

और राज्यपाल के दायित्वों से संबंधित हैं। इस प्रकार यह पूरी तरह से एक असंवैधानिक अधिनियम।

यह सच है जैसा कि विभिन्न रिपोर्टों और विभिन्न लोगों द्वारा बार-बार कहा गया है।

संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि दलबदल भारतीय लोकतंत्र के लिए अभिशाप रहा है, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि दलबदल कानून में अनुमत तरीके से निपटा जाना चाहिए।

यदि कोई राजनीतिक दल किसी अन्य राजनीतिक दल या अन्य के समर्थन से

विधायक का सरकार बनाने का दावा और राज्यपाल को संतुष्ट करता है एक स्थिर सरकार बनाने के लिए बहुमत, राज्यपाल गठन से इनकार नहीं कर सकते

सरकार के और उनके व्यक्तिपरक होने के कारण बहुमत के दावे को ओवरराइड करते हैं

यह आकलन करना कि बहुमत को अवैध और अनैतिक तरीकों से फंसाया गया था। नहीं। ऐसी शक्ति राज्यपाल के पास निहित की गई है। ऐसी शक्ति होगी

बहुसंख्यक शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ। राज्यपाल निरंकुश नहीं हैं।

राजनीतिक लोकपाल। यदि ऐसी शक्ति राज्यपाल और/या राज्यपाल में निहित है

राष्ट्रपति जी, परिणाम भयानक हो सकते हैं। माल की जमीन

671 के लिए बहुमत वाली राज्य सरकार द्वारा प्रशासन उपलब्ध नहीं है।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. एल [सभरवाल, सी. जे.]

अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का उपयोग करना। भ्रष्टाचार या इसी तरह की बुराइयों और बुराइयों का इलाज कहीं और है, न कि अनुच्छेद 356 (1) में। इसी तरह, यह माना जाना चाहिए कि दलबदल के लिए दसवीं अनुसूची के तहत शक्ति सदन के अध्यक्ष के पास है, न कि राज्यपाल के पास। दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति न्यायिक प्रकृति की है। इस सवाल से निपटने के लिए कि क्या सदन के सदस्यों की अयोग्यता की शक्ति विशेष रूप से न्यायपालिका के बहिष्कार के लिए सदन के पास निहित है, जो कि ब्रिटेन में कुछ ब्रिटिश विधायिका प्रथाओं पर आधारित थी, जहां तक भारत का संबंध है, यह कहा गया था।

किहोतो के मामले में कि:

" अतः यह दावा करना अनुचित है कि निर्धारक

दसवीं अनुसूची में अध्यक्ष या अध्यक्ष की अधिकारिता है -

यह न्यायिक शक्ति नहीं है और गैर-न्यायोचित विधायी क्षेत्र के भीतर है।

राज्यपाल स्वयं उपरोक्त न्यायिक शक्ति ग्रहण नहीं कर सकता है और

उस धारणा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि दसवीं अनुसूची का उल्लंघन होगा और इसका उपयोग विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करने के कारण के रूप में किया जाएगा।

राज्यपाल, एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

विधान सभा के सदस्यों की अयोग्यता जैसे विवादों से बाहर और इसलिए, संविधान में अनुच्छेद 192 (2) जैसे प्रावधान हैं जो राज्यपाल को चुनाव आयोग की राय प्राप्त करने और इस तरह की राय के अनुसार कार्य करने का प्रावधान करते हैं। जहाँ तक संसद सदस्य का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 103 (2) में इसी तरह का प्रावधान है। भारत निर्वाचन आयोग और ए. एन. आर. [1965] 3 एस. सी. आर. 53 और भारत निर्वाचन आयोग और ए. एन. आर. वी. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी और अन्र। , [1996] 4 एससीसी 104।

उपरोक्त सभी कारणों से, 23 मई, 2005 की घोषणा

असंवैधानिक माना जाता है।

बिंदु संख्या 3: यदि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है,

क्या 7 मार्च, 2005 को यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक है या

4 मार्च, 2005?

बिन्दु सं. पर उपरोक्त दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप। 2 , हम कर सकते हैं

विधानसभा के विघटन से पहले की यथास्थिति का आदेश दिया। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के 7 अक्टूबर, 2005 के आदेश के संदर्भ में, ऐसी राहत को अस्वीकार कर दिया गया था। आधार [2006] 1 एस. सी. आर. को ध्यान में रखते हुए, कारण व्यापक लोक हित हैं।

वास्तविकताएँ और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना। विवादित घोषणा के परिणामस्वरूप, भारत के चुनाव आयोग ने न केवल बिहार राज्य में होने वाले चार चरणों के चुनाव की तैयारी की थी, बल्कि बहस के समापन से पहले पहले दो चरणों के संबंध में अधिसूचना भी जारी की थी। इसके अलावा, इन दो चरणों के संबंध में, 7 अक्टूबर, 2005 से पहले, यहां तक कि अंतिम चरण नामांकन करने और उनकी जांच करने की तारीख भी समाप्त हो गई थी। चुनाव के पहले चरण के संबंध में, नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि भी समाप्त हो गई थी और मतदान 18 अक्टूबर,

2005 के लिए निर्धारित किया गया था। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और एक उन्नत चरण में थी। न्यायिक नोटिस इस तथ्य का लिया जा सकता है कि काफी राशि खर्च की गई होगी; भारी

चुनाव की प्रक्रिया में की गई तैयारी और जमीनी कार्य और वह भी विचाराधीन राज्य जैसे राज्य में चुनाव के लिए। इन बाद के घटनाक्रमों और विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित संख्या को ध्यान में रखते हुए, राज्य को अनिश्चितता के एक और दौर में नहीं डालना उचित समझा गया। विचित्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, घोषणा की असंवैधानिकता के बावजूद, राहत को यथास्थिति को पूर्व निर्देशित नहीं करके ढाला गया था

और इसके परिणामस्वरूप इस उम्मीद के साथ चल रही चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति दी जाती है कि मतदाता फिर से खंडित निर्णय नहीं दे सकते हैं और एक या अन्य राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत दे सकते हैं-भारतीय मतदाता जो अत्यधिक बुद्धिमत्ता रखते हैं और अतीत में ऐसे विभिन्न अवसरों पर इस अवसर पर खड़े हुए हैं।

बिंदु संख्या 4: अनुच्छेद 361 का क्या दायरा है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है

राज्यपाल?

8 सितंबर, 2005 के आदेश द्वारा, हमने माना कि

भारत अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल को प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 361 (1), अन्य बातों के साथ, यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल

अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और निष्पादन के लिए या उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और निष्पादन में उसके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय को उत्तरदायी। हमने प्रत्यर्थियों की ओर से की गई दलीलों को स्वीकार किया कि इस अनुच्छेद को देखते हुए राज्यपाल को नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है, साथ ही यह भी ध्यान में रखते हुए कि दी गई प्रतिरक्षा इस न्यायालय की न्यायिक जांच करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करती है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत जारी उद्घोषणा पर दुर्भावनापूर्ण या अधिकार से परे होने के आधार पर किया गया हमला है और यह सरकार पर होगा कि वह न्यायालय को संतुष्ट करे और चुनौती के ऐसे आधार को पर्याप्त रूप से पूरा करे। दुर्भावनापूर्ण कार्य पूरी तरह से शक्ति के दायरे से बाहर है और कानून की नजर में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम, आगे मानते हैं कि 673

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

अनुच्छेद 361 में 'कथित रूप से किया जाना' अभिव्यक्ति में ऐसे कार्य शामिल नहीं हैं जो दुर्भावनापूर्ण या अधिकार से परे हैं और इस प्रकार, अनुच्छेद 356 (1) के तहत घोषणा का समर्थन करने वाली सरकार को चुनौती का सामना करना होगा। अनुच्छेद 361 के तहत दी गई प्रतिरक्षा का मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में, दुर्भावनापूर्ण या अधिकार से बाहर होने के आधारों की अदालत द्वारा जांच नहीं की जाएगी। यह आदेश उस समय दिया गया था जब हमने इस सवाल की जांच नहीं की थी कि क्या राज्यपाल द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण था।

या अल्ट्रा वायर्स या नहीं। इस सवाल पर बाद में बहस की गई।

8 सितंबर, 2005 के हमारे आदेश में संक्षिप्त कारण देते हुए

हमने कहा कि विस्तृत कारण बाद में दिए जाएंगे।

अनुच्छेद 361 (1) राष्ट्रपति और राज्यपाल को सुरक्षा प्रदान करता है।

यह नीचे लिखा है:

" 361. राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण। — (1) राष्ट्रपति, या किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख,

के अभ्यास और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह होना

उसके पद की शक्तियाँ और कर्तव्य या किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए

उन शक्तियों के प्रयोग और प्रदर्शन में उसके द्वारा किया जाए और

कर्तव्य:

बशर्ते कि राष्ट्रपति के आचरण को इसके अंतर्गत लाया जा सके

अनुच्छेद 61: बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी अर्थ नहीं लगाया जाएगा किसी भी व्यक्ति के उचित कार्यवाही लाने के अधिकार को सीमित करने के रूप में

भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के विरुद्ध।
(2) किसी भी तरह की आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रखी जाएगी।

राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, किसी भी न्यायालय में

उनका कार्यकाल।

(3) राष्ट्रपति की गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई प्रक्रिया नहीं, या

कोनो राज्यक राज्यपाल अपन कार्यकालक अवधिमे कोनो न्यायालयसँ जारी करतैक -

कार्यालय।

(4) कोई दीवानी कार्यवाही नहीं जिसमें उनके खिलाफ राहत का दावा किया गया हो।

राष्ट्रपति या स्लेट के राज्यपाल की स्थापना उनके कार्यकाल के दौरान की जाएगी।

किए गए या उद्देश्यपूर्ण किसी कार्य के संबंध में किसी भी न्यायालय में पद की अवधि उसके द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में किया जाना, चाहे वह पहले हो या बाद में

उन्होंने अध्यक्ष के रूप में या इस तरह के स्टेल, आई. एस. सी. आर. के राज्यपाल के रूप में अपना पद संभाला।

लिखित सूचना दिए जाने के बाद अगले दो महीने की समाप्ति तक

यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंप दिया गया या छोड़ दिया गया

उनके कार्यालय में कार्यवाही की प्रकृति, कार्रवाई का कारण बताते हुए

इसके लिए, पक्ष का नाम, विवरण और निवास स्थान

जिसे ऐसी कार्यवाही शुरू की जानी है और वह राहत जो वह दावा करते हैं "।

उपरोक्त लेख के एक सादे पठन से पता चलता है कि एक पूर्ण लेख है

राष्ट्रपति या राज्यपाल को गुमराह करने और नोटिस जारी करने पर रोक

क्योंकि वे अभ्यास के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं हैं और

अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करना। अधिकांश कार्रवाई सहायता पर की जाती है।

और मंत्री परिषद की सलाह। जवाबदेह होने से व्यक्तिगत प्रतिरक्षा

अनुच्छेद 361 में प्रदान की गई चुनौती को नहीं रोकता है जो उनके लिए की जा सकती है

क्रियाएँ। कानून के तहत, ऐसी कार्रवाइयां जिनमें वे कार्रवाइयां भी शामिल हैं जिनमें चुनौती होती है

दुर्भावनापूर्ण आरोपों पर आधारित हो सकता है जिसका बचाव करने की आवश्यकता है

भारत संघ या राज्य, जैसा भी मामला हो। ऐसे मामलों में भी जहां

व्यक्तिगत दुर्भावनाओं का आरोप लगाया जाता है और स्थापित किया जाता है, यह इसके लिए खुला नहीं होगा

सरकारों का आग्रह है कि इसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि

प्रतिरक्षा प्रदान की गई। ऐसी स्थिति में, यह प्रत्यर्थी के लिए है

या तो सामग्री के आधार पर न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए कार्रवाई का बचाव करना

अभिलेख पर या यहाँ तक कि उस व्यक्ति का शपथ पत्र दाखिल करना जिसके खिलाफ ऐसा है व्यक्तिगत दुर्भावना के आरोप लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 361 दाखिल करने पर रोक नहीं लगाता है।

एक शपथ पत्र यदि कोई स्वयं दाखिल करना चाहता है। बार केवल सत्ता के खिलाफ है

न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को नोटिस जारी करने या बनाने के लिए

जवाबदेह। बार को देखते हुए, न्यायालय राष्ट्रपति को निर्देश जारी नहीं कर सकता है या राज्यपाल को न्यायालय की सहायता के लिए शपथ पत्र दाखिल करने के लिए भी। एक की फाइलिंग

पूर्ण और इसलिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल का कोई सवाल ही नहीं है। दुर्भावनापूर्ण आरोपों के संबंध में भी न्यायालय को जवाबदेह बनाया जाना।

संघ कार्बाइड निगम आदि में, आदि। भारत संघ, आदि।,

वेंकटाहा! लिया ने रिचर्ड निक्सन के प्रसिद्ध मामले का उल्लेख किया [(1982) 457 यू. एस. 731] ऐसी प्रतिरक्षा की आवश्यकता के लिए सैद्धांतिक आधार के बारे में। कहा गया है।

" संविधान का अनुच्छेद 361 (2) राष्ट्रपति और

राज्यपाल को उनके व्यक्तिगत कार्यों और आदेशों के संबंध में भी छूट है।

कि इस दौरान उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। उनका कार्यकाल। इस तरह की आवश्यकता के लिए सैद्धांतिक आधार के रूप में

प्रतिरक्षा, 675 से संबंधित एक मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [सभरवाल, सी. जे.]

नागरिक दायित्व से प्रतिरक्षा (रिचर्ड निक्सन बनाम। अर्नेस्ट फिट्जगेराल्ड, 457

यूएस 731: 73 लॉ एड 2 डी 349) ने कहा:

..... इस न्यायालय ने अनिवार्य रूप से जनता की चिंताओं पर भी विचार किया है

नीति, विशेष रूप से हमारे इतिहास और संरचना से प्रकाशित

हमारी सरकार का। "

..... राष्ट्रपति के मामले में इतिहास की जांच और

यद्यपि नीति हमारे मामले द्वारा स्वतंत्र रूप से अनिवार्य है,

अभिसरण करें। क्योंकि अधिकांश के माध्यम से प्रेसीडेंसी मौजूद नहीं थी

सामान्य कानून का विकास, किसी भी ऐतिहासिक विश्लेषण को करना चाहिए

उचित रूप से किए गए "सार्वजनिक नीति" विश्लेषण के प्रकार के साथ एक संघीय अदालत द्वारा। इस जांच में नीतियां और सिद्धांत शामिल हैं।

जिसे राष्ट्रपति की प्रकृति में निहित माना जा सकता है

प्रभावी सरकार प्राप्त करने के लिए संरचित प्रणाली में कार्यालय

के तहत, एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य "शक्तियों का पृथक्करण"।

(एल एड p.367)

" ..... राष्ट्रपति के संविधान की विशेष प्रकृति को देखते हुए
कार्यालय और कार्य, हम निरपेक्ष को पहचानना उचित समझते हैं

"बाहरी" के भीतर के कार्यों के लिए नुकसान दायित्व से राष्ट्रपति की प्रतिरक्षा

उनकी आधिकारिक जिम्मेदारी की परिधि।

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान और कानूनों के तहत राष्ट्रपति

विभिन्न क्षेत्रों में विवेकाधीन जिम्मेदारियां हैं, जिनमें से कई

वे बहुत संवेदनशील होते हैं। कई मामलों में इसका निर्धारण करना मुश्किल होगा।
राष्ट्रपति के असंख्य "कार्यों" में से कौन सा शामिल था

विशेष कार्रवाई "।

श्री के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ

प्रतापसिंह रावजीराव राणे और ओआरएस बनाम। गोवा के राज्यपाल और अन्य। , एयर

(1999) बॉम्बे 53 ने सही माना है कि उनके आधिकारिक कृत्यों के संबंध में,
राज्यपाल दुर्भावनापूर्ण प्रभार के संबंध में भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है।

यह कि ऐसी स्थिति में राज्यपाल को दुर्भावनापूर्ण आरोपों से निपटने का कर्तव्य नहीं कहा जा
सकता है। का संवैधानिक कानून

भारत, चौथा संस्करण। H.M.Seervai द्वारा उक्त में सही ढंग से भरोसा किया गया है

निर्णय। के. ए. मथियालगन और अन्य में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा की गई
टिप्पणियां। वी. तमिलनाडु के राज्यपाल और अन्य। एयर

(1973) मद्रास 198 में कहा गया कि राज्यपाल का कर्तव्य होगा कि वह [2006] आई.
एस. सी. आर. से निपटें।

676

न्यायालय की सहायता करने के लिए दुर्भावनापूर्ण आरोपों का सही वर्णन किया गया है

सीरवई की टिप्पणी पूरी तरह से व्यक्तिगत के साथ सीधे संघर्ष में है राज्यपाल की प्रतिरक्षा।

'कथित रूप से किया जाना' शब्द व्यापक आयाम के हैं। बिमान में

चंद्र वी. राज्यपाल, पश्चिम बंगाल, आकाशवाणी (1952) कलकत्ता 799 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

अनुच्छेद 361 इसके अभ्यास और प्रदर्शन के संबंध में प्रतिरक्षा प्रदान करता है कार्यालय की शक्ति और कर्तव्य और उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और निष्पादन में उसके द्वारा किया गया या किया जाने वाला कोई कार्य।

G.D.Karkare v में। T.L.Shevde, AIR (1952) नागपुर 330 का अर्थ है

अभिव्यक्ति 'किए जाने का तात्पर्य' यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कोई भी कार्य, हालांकि संविधान के अनुसरण में नहीं किया गया है, फिर भी इसे यह संरक्षण दिया जा सकता है।

यदि अधिनियम संविधान के अनुसरण में किए जाने का दावा करता है या करना चाहता है।

यह आगे समझाया गया कि हालांकि राज्यपाल के लिए उत्तरदायी नहीं है

न्यायालय की प्रक्रिया लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय उसकी कार्रवाई की जांच नहीं कर सकता है और निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के अभाव में राहत प्रदान नहीं कर सकता है।

राज्य में वी। कवास मानेकशॉ नानावती, आकाशवाणी (1960) बॉम्बे 502 पूर्ण

उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 361 केवल व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करता है

राज्यपाल को। यह आवश्यक नहीं है कि राज्यपाल कार्यवाही में एक पक्ष होना चाहिए। कार्यों की वैधता पर विचार किया जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है

राज्यपाल की अनुपस्थिति। पश्चिम बंगाल राज्य में और अन्य। वी. सलेंद्रा

नाथ बोस, ए. आई. आर. (19640 कलकत्ता 184) ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक नागरिक निवारण के बिना नहीं है, भले ही वह राज्यपाल को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं कर सकता है, लेकिन उसे राहत दी जा सकती है।

अतः कानून की स्थिति यह है कि राज्यपाल को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

प्रतिरक्षा। राज्यपाल इस अभ्यास के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है और

अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों का निष्पादन या किए गए किसी कार्य के लिए या

उन लोगों के अभ्यास और प्रदर्शन में उनके द्वारा किए जाने का तात्पर्य शक्तियाँ और कर्तव्य। हालाँकि, अनुच्छेद 361 (1) द्वारा दी गई प्रतिरक्षा,

कार्रवाई की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय की शक्ति को छीन लें

दुर्भावना के आधार पर भी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विवादित उद्घोषणा को दिनांकित रखते हुए

23 आरडी मई, 2005 असंवैधानिक, हमने राहत को ढाला है और इनकार कर दिया है पूर्व स्थिति प्रदान करें और परिणामस्वरूप चल रहे कार्य को पूरा करने की अनुमति दी जाए

चुनाव प्रक्रिया।

सभी याचिकाओं का उसी के अनुसार निपटारा किया जाता है।

677

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [बालाकृष्णन, जे.]

के. जी. बालाकृष्णन, जे. मुझे मसौदे में पढ़ने का लाभ मिला है

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, श्री वाई. के. सभरवाल द्वारा तैयार किया गया निर्णय और मैं खुद को निर्णय में तैयार किए गए बिंदु संख्या 2 पर निर्णय से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं। अन्य सभी बिंदुओं पर, मैं कानून की व्याख्या को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूं और विद्वान प्रमुख द्वारा प्रस्तावित निर्णय से सहमत हूं।

न्याय। बिन्दु संख्या 2 इस प्रकार है: - "

(2) क्या 23 मई, 2005 की उद्घोषणा भंग करती है बिहार की विधानसभा अवैध और असंवैधानिक है?

प्रश्न तय करने के लिए कुछ तथ्यात्मक विवरण आवश्यक हैं। चुनाव.

बिहार राज्य विधानमंडल का चुनाव फरवरी, 2005 के महीने में हुआ था और चुनाव के परिणाम 23 मार्च, 2005 को घोषित किए गए थे। बिहार राज्य विधानमंडल के लिए चुने गए सदस्यों के नाम चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किए गए थे। कुछ राजनीतिक समूहों और राजनीतिक दलों ने भाग लिया

और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (संक्षेप में 'एनडीए'), एक गठबंधन जिसमें शामिल हैं

भारतीय जनता पार्टी (संक्षेप में 'भाजपा') और जनता दल (यूनाइटेड) (संक्षेप में)

" जद (यू) ने सबसे अधिक विधायकों का समर्थन हासिल किया। विधानसभा में पार्टी की ताकत इस प्रकार थी:

“ (1) _एनडीए

92

(2) राजद

75

(3) एलजेपी

29

(4) कांग्रेस (1)

10

(5) सीपीआई (एमएल)

07

(6) समाजवादी पार्टी

04 .

(7) एनसीपी

03

(8) बहुजन समाज पार्टी

02

(9) निर्दलीयों

17

(10)

अन्य

09 "

में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए

बिहार राज्य में विधानसभा के 122 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता थी। एन. डी. ए. केवल 92 सीटें हासिल कर सका और कोई अन्य राजनीतिक दल या समूह नहीं आया। सरकार बनाने के लिए एन. डी. ए. का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ें। राजद भी इसी दुविधा में था। श्री राम विलास पासवान के नेतृत्व में एक अन्य राजनीतिक दल एलजेपी ने राज्य विधानमंडल में 29 सीटें जीती थीं। यह राजनीतिक 678

[2006] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पार्टी ने एनडीए या राजद को समर्थन नहीं दिया। जैसा कि कोई भी नहीं बना सकता था

सरकार, बिहार राज्य के राज्यपाल ने 6 मार्च, 2005 को भारत के राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने और विधानसभा को कुछ समय के लिए निलंबित रखने के लिए एक रिपोर्ट भेजी। 7 मार्च, 2005 को बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और

सभा को निलंबित एनिमेशन में रखा गया था। 7 मार्च, 2005 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा पारित यह आदेश नहीं है।

हमारे सामने अधिकांश याचिकाओं में चुनौती दी गई। एक याचिका में, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 7 मार्च, 2005 को जारी अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है, लेकिन याचिकाकर्ता अपनी दलीलों को साबित नहीं कर सका और चुनौती देने में ही बहुत देरी हुई है।

जबकि विधानसभा निलंबित एनिमेशन में थी, दोनों राजनीतिक

संसद के समक्ष गृह मंत्री ने इस आशय का बयान दिया कि राष्ट्रपति शासन लंबे समय तक जारी नहीं रहेगा और अगर निर्वाचित लोगों द्वारा सरकार का गठन किया जाता तो उन्हें खुशी होती। प्रतिनिधि और यह कि निर्वाचित प्रतिनिधि को एक-दूसरे से बात करनी चाहिए और ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिसमें उनके लिए सरकार बनाना संभव हो। राजनीतिक दलों के बीच चर्चा जारी रही होगी।

27 अप्रैल, 2005 को बिहार के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजी।

भारत का जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें खुफिया रिपोर्ट प्राप्त हुई थी

कहा जाता है कि कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों से पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर के गुटों द्वारा धन, जाति और पदों आदि जैसे विभिन्न प्रलोभन के साथ संपर्क किया गया था और यह एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति थी। उन्होंने यह भी आगाह किया कि अगर इस प्रवृत्ति पर तुरंत अंकुश नहीं लगाया गया तो राजनीतिक अस्थिरता और गहरी हो जाएगी और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा खरीद-फरोख्त की जाएगी और स्थिति को नियंत्रित करना संभव नहीं होगा।

और लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का एक नया अवसर दिया जाना चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि 27 अप्रैल, 2005 को भेजे गए पत्र के अनुसार

बिहार के राज्यपाल ने राष्ट्रपति से कहा, राष्ट्रपति ने कोई निर्णय नहीं लिया राज्य विधानसभा के विघटन के लिए। 21 मई, 2005 को फिर से बिहार के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा और यह 679 पर महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

रामेश्वर प्रसाद बनाम. यू. क्यू. आई. [बालकृष्णन। जे.]

जिसके तहत बिहार राज्य विधानसभा को भंग कर दिया गया था

174 (2) ((ख) संविधान। पत्र इस प्रकार है: - " " आदरणीय राष्ट्रपति जी,

मैं 27 अप्रैल के अपने डी. ओ. पत्र संख्या 52/जी. बी. का संदर्भ आमंत्रित करता हूं।

कुछ दलों विशेष रूप से जद (यू) और भाजपा द्वारा एक गठबंधन बनाने के लिए बहुमत और राज्य में सरकार बनाने का दावा करना। मेरे पास था

बताया गया कि एलजेपी से संबंधित लगभग 16-17 विधायकों को लुभाया जा रहा था

विभिन्न तरीकों से ताकि एलजेपी में विभाजन हो सके। ध्यान दें।

इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया गया कि राजद के विधायक भी बन गए थे

जे. डी. यू. द्वारा उठाए गए उपरोक्त कदमों के आलोक में अशांत।

जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी में विधानसभा चुनाव के बाद यह

वर्ष, कोई भी राजनीतिक दल या तो व्यक्तिगत रूप से या तब के साथ

चुनाव पूर्व संयोजन या चुनाव के बाद गठबंधन संयोजन

एक लोकप्रिय सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं क्योंकि वे कर सकते हैं

243 सदस्यीय सदन में 122 के साधारण बहुमत के समर्थन का दावा नहीं करना और इसलिए राष्ट्रपति के तहत एक घोषणा जारी करने के लिए प्रसन्न था

संविधान का अनुच्छेद 356 अधिसूचना सं। जीएसआर 162 (ई)

दिनांक 7 मार्च, 2005 और विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था

एनिमेशन।

हाल के दिनों में मीडिया के माध्यम से मुझे जो रिपोर्टें मिली हैं

और विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के माध्यम से भी, साथ ही

खुफिया रिपोर्ट, निर्वाचित प्रतिनिधियों पर जीत की प्रवृत्ति का संकेत देती है लोगों से। एलजेपी के एक विधायक की भी रिपोर्ट मिली है।

आज पंजीकृत पार्टी का महासचिव कौन है और

यह भी कि शायद 17-18 स्पष्ट रूप से जद-यू की ओर बढ़ रहे हैं।

यह दर्शाता है कि विभिन्न प्रलोभन की पेशकश की गई है जो बहुत है

परेशान करने वाली और खतरनाक विशेषता। टूटने वाले गुट का कोई भी कदम

बहुमत हासिल करने और दावा करने के लिए किसी अन्य दल के साथ गठबंधन करना

सरकार बनाने से संविधान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

उसमें बनाए गए प्रावधान और सुरक्षा उपाय निर्णय को विकृत करते हैं। जैसा कि हाल के चुनावों के परिणामों से पता चलता है। अगर ये प्रयास

अनुमति है कि यह संविधान के साथ छेड़छाड़ के बराबर होगा

प्रावधान।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं विचाराधीन हूं।

विचार है कि यदि प्रवृत्ति को तुरंत नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो यह [2006] 1 एस. सी. आर. नहीं हो सकता है।

680

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्थिति को नियंत्रित करना संभव है। इसलिए मेरे विचार में एक स्थिति है

राज्य में उत्पन्न हुआ जिसमें यह राज्य के हित में वांछनीय होगा।

बता दें कि विधानसभा को वर्तमान में निलंबित एनिमेशन में रखा गया है

भंग कर दिया गया, ताकि लोगों/मतदाताओं को एक प्रदान किया जा सके उचित समय पर लोगों से जनादेश प्राप्त करने का अधिक अवसर

उचित समय पर निर्णय लिया जाना चाहिए "।

राज्यपाल द्वारा लिखे गए पत्र का सार यह है कि राजनीतिक दल

या तो व्यक्तिगत रूप से या तत्कालीन चुनाव पूर्व संयोजन या चुनाव के बाद के गठबंधन संयोजन के साथ एक लोकप्रिय सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकते थे क्योंकि कोई भी 122 के साधारण बहुमत का दावा नहीं कर सकता था।

243 सदस्यों का एक सदन और इसलिए, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा जारी की। राज्यपाल ने आगे कहा कि उन्हें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी और विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के माध्यम से एकत्र की गई रिपोर्टों में कहा गया था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को जीतने का रुझान रहा है

जनता और 17-18 विधायक जद (यू) की ओर बढ़ रहे थे और उन्हें विभिन्न प्रलोभन दिए गए थे। राज्यपाल ने यह भी संकेत दिया कि कोई भी कदम

अलग गुट द्वारा किसी अन्य दल के साथ गठबंधन करना, बहुमत जुटाना और सरकार बनाने का दावा करना सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा

संवैधानिक प्रावधान और सुरक्षा उपाय इसमें प्रदान किए गए हैं। राज्यपाल का विचार था कि यदि विधानसभा भंग हो जाती है, तो राजनीतिक दलों को मिलेगा

लोगों से एक नया जनादेश प्राप्त करने का एक और अवसर। पत्र से यह स्पष्ट है कि किसी भी राजनीतिक दल या समूह या गठबंधन ने राज्य विधानमंडल में पूर्ण बहुमत का दावा करते हुए राज्यपाल से संपर्क नहीं किया था और न ही उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों या निर्दलीयों की मदद से सरकार बनाने का प्रयास किया था

विधायक।

राज्यपाल की रिपोर्ट भारत संघ द्वारा प्राप्त की गई थी

22 मई, 2005। केंद्रीय मंत्रिमंडल की दोपहर लगभग 1 बजे हुई बैठक में निर्णय लिया गया और बिहार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करते हुए भारत के राष्ट्रपति को एक फैक्स संदेश भेजा गया। 23 मई, 2005 को बिहार विधानसभा भंग कर दी गई और भंग करने के उस आदेश को हमारे सामने चुनौती दी गई है।

हमने विद्वान महान्यायवादी श्री मिलन के. बनर्जी को सुना; विद्वान

महान्यायवादी श्री गुलाम ई. वाहनवती; विद्वान अतिरिक्त महान्यायवादी श्री गोपाल सुब्रमण्यम; विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सोली सोराबजी; श्री पी. एस. नरसिम्हा, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और श्री विप्लव शर्मा, अधिवक्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता का समर्थन करने वाले कई अन्य वकीलों ने अपनी लिखित दलीलें प्रस्तुत कीं। अधिकांश तर्क 681

रामेश्वर प्रसाद बनाम। 0. 1 यू. [बालाकृष्णन, जे।]

एस. आर. बोम्मई और अन्य मामलों में इस माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आसपास केंद्रित। वी. भारत संघ और ओआरएस।, [1994] 3 एससीसी 1. एस. आर.

बोम्मई के मामले में निर्णय नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था और कई राय व्यक्त की गई थी। न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी ने एक अलग फैसला दिया जिससे न्यायमूर्ति एस. सी. अग्रवाल सहमत हो गए। न्यायमूर्ति ए. एम. अहमदी, न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा, न्यायमूर्ति के. रामास्वामी और न्यायमूर्ति योगेश्वर दयाल न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी द्वारा दिए गए कुछ प्रस्तावों से सहमत थे। हालांकि न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी, न्यायमूर्ति सावंत और न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह, जे. जे. द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के साथ व्यापक सहमति थी। एक अलग नोट और उनके दृष्टिकोण, तर्क और

निष्कर्ष समान नहीं हैं।

एस. आर. में निर्णय के दायरे और दायरे को समझने के लिए।

बोम्मई के मामले में राजस्थान और अन्य राज्यों में पहले के निर्णय को देखना आवश्यक है। वी. भारत संघ और ओआरएस।, [1977] 3 एस. सी. सी. 592 में सूचित किया गया। जिस तथ्य के कारण यह मामला दर्ज किया गया था, वह यह था कि मार्च, 1977 के चुनावों में

लोकसभा के लिए आयोजित किए गए थे और चुनावों के परिणाम की व्याख्या इस तरह की गई थी कि कांग्रेस पार्टी ने लोगों का जनादेश खो दिया था। द यूनियन होम

मंत्री ने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र भेजकर उनसे कहा कि वे अपने-अपने राज्यपालों को विधानसभाओं को भंग करने और नए सिरे से विधानसभा बनाने की सलाह दें।

लोगों से जनादेश। केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा दिए गए बयान के साथ पत्र को उन राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की धमकी के रूप में माना गया था। उन्होंने मुकदमे और रिट याचिकाएं दायर करके इस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उस मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ ने छह राय दी थी। हालाँकि वे सभी इस बात पर सहमत थे कि रिट याचिकाओं और मुकदमों को खारिज कर दिया जाए, लेकिन तर्क समान नहीं थे। उस निर्णय में कुछ विचारों को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है:

भगवती, जे. गुप्ता, जे और स्वयं की ओर से, के साथ काम करते हुए

" घोषणा के जारी होने से पहले राष्ट्रपति की संतुष्टि अनुच्छेद 356 (1) में कहा गया है:

" जब तक कोई सवाल उठता है कि क्या इसके तहत कोई प्राधिकरण है

संविधान ने अपनी शक्ति की सीमाओं के भीतर काम किया है या इसे पार कर लिया है,

यह निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है। वास्तव में यह उसका होगा ऐसा करना संवैधानिक दायित्व है। यह न्यायालय अंतिम है।

संविधान के दुभाषिया और इस न्यायालय को नाजुक कार्य सौंपा गया है

यह निर्धारित करने का कार्य कि प्रत्येक शाखा को क्या शक्ति प्रदान की गई है

सरकार, क्या यह सीमित है, और यदि है, तो सीमाएँ क्या हैं और

क्या उस शाखा की कोई कार्रवाई ऐसी सीमाओं का उल्लंघन करती है। इसके लिए है। इस न्यायालय को संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने और लागू करने के लिए

संवैधानिक सीमाएँ। यही कानून के शासन का सार है "।

उन्होंने आगे कहा -

" ..... यहाँ अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की शक्ति की एकमात्र सीमा है। 356 ,

खंड (1) यह है कि राष्ट्रपति को संतुष्ट होना चाहिए कि किसी स्थिति में

उत्पन्न हुआ जहाँ राज्य सरकार को चलाया नहीं जा सकता है

संविधान के प्रावधानों के अनुसार। संतुष्टि

राष्ट्रपति का पद व्यक्तिपरक होता है और संदर्भ द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता है। किसी भी वस्तुनिष्ठ परीक्षण के लिए। यह जानबूझकर और सलाह के साथ व्यक्तिपरक है।

क्योंकि जिस मामले के संबंध में उसे संतुष्ट किया जाना है वह इस प्रकार का है एक ऐसी प्रकृति कि इसका निर्णय अनिवार्य रूप से कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए

सरकार की शाखा। स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला हो सकती है

जो उत्पन्न हो सकते हैं और उनके राजनीतिक निहितार्थ और परिणाम यह तय करने के लिए मूल्यांकन करना पड़ सकता है कि क्या स्थिति है

संविधान के प्रावधानों के अनुसार। यह कोई निर्णय नहीं है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या है, उस पर आधारित हो सकता है

'न्यायिक रूप से खोज योग्य और प्रबंधनीय मानकों' के रूप में वर्णित। यह.

यह काफी हद तक विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन पर आधारित एक राजनीतिक निर्णय होगा।

और विभिन्न कारक, तेजी से बदलती परिस्थितियाँ, संभावित परिणाम,

विभिन्न वर्गों के लोगों की सार्वजनिक प्रतिक्रियाएँ, प्रेरणाएँ और प्रतिक्रियाएँ

और उनके प्रत्याशित भविष्य के व्यवहार और कई अन्य

विचार "।

उन्होंने आगे कहा:

" ..... यह निश्चित रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए कि ज्यादातर मामलों में यह होगा

कठिन, यदि असंभव नहीं है, तो सत्ता के प्रयोग को चुनौती देना

कला. 356 , खंड (1) इस सीमित आधार पर भी, क्योंकि तथ्य

राष्ट्रपति की संतुष्टि को चुनौती देने के लिए न्यायालय कि स्थिति उस खंड में विचार किया गया है "।

(जोर दिया गया)

बेग, सीजे की राय थी कि अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 74 (2) के आधार पर

683

संविधान के अनुसार, न्यायालय के लिए राष्ट्रपति की 'संतुष्टि' पर सवाल उठाना असंभव है। इसका निर्णय केवल उन तथ्यों के आधार पर किया जाना है जिन्हें स्वीकार किया गया हो या अदालत के समक्ष रखा गया हो। बेग सी. जे. की भी राय थी

कि अनुच्छेद 356 की भाषा और 1950 से चली आ रही प्रथा से पता चलता है कि

केंद्र सरकार इस सवाल के संबंध में राज्य सरकार के खिलाफ अपनी इच्छा को लागू कर सकती है कि राज्य सरकार को कैसे काम करना चाहिए और

सत्ता का शासन रखना चाहिए। लेकिन इन विचारों को अधिकांश लोगों ने स्वीकार नहीं किया। न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ ने न्यायिक समीक्षा के दायरे पर बोलते हुए कहा कि यदि भारत संघ द्वारा बताए गए कारण पूरी तरह से बाहरी हैं, तो अदालत दुर्भावना के आधार पर हस्तक्षेप कर सकती है। न्यायिक जांच ", ने कहा

विद्वान न्यायाधीश, यह देखने के सीमित उद्देश्य के लिए उपलब्ध है कि क्या कारणों का प्रस्तावित कार्रवाई के साथ कोई तर्कसंगत संबंध है। अदालत यह निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति की 'संतुष्टि' पर निर्णय में नहीं बैठ सकती है कि क्या कोई अन्य दृष्टिकोण उचित रूप से संभव है। जहाँ तक मामले में प्रकट किए गए तथ्यों का संबंध है, विद्वान न्यायाधीश का विचार था कि केंद्र सरकार द्वारा अपने जवाबी हलफनामे में प्रकट किए गए तथ्यों को अनुच्छेद 356 के लिए अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है। गोस्वामी और उन्तवालिया, जे. जे. अलग-अलग राय दी और व्यक्त किया

यह विचार कि बताए गए तथ्यों को अप्रासंगिक या अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है।

राजस्थान राज्य के मामले में निर्धारित आदेश से यह स्पष्ट है कि

न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकता है जब अनुच्छेद 356 के तहत पारित किसी आदेश को दुर्भावना के आधार पर या न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है।

पूरी तरह से बाहरी या अप्रासंगिक आधार और केवल तभी अदालत के पास इसकी जांच करने का अधिकार क्षेत्र होगा। विद्वान महान्यायवादी द्वारा उठाई गई याचिका कि अनुच्छेद 356 के तहत पारित एक घोषणा चरित्र में विधायी है और न्यायिक जांच के दायरे से बाहर है, राजस्थान राज्य के मामले में अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा खारिज कर दी गई थी।

एस. आर. में व्यक्त विभिन्न विचारों की सावधानीपूर्वक जांच पर।

बोम्मई के मामले में, यह स्पष्ट है कि बहुमत ने राजस्थान के मामले में निर्धारित आदेश को व्यापक रूप से स्वीकार किया। यह भी माना गया कि न्यायिक समीक्षा के जो सिद्धांत किसी

प्रशासनिक कार्रवाई को चुनौती दिए जाने पर लागू किए जाने हैं, उन्हें अनुच्छेद 356 के तहत पारित राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ चुनौती दिए जाने पर लागू नहीं किया जा सकता है।

पी. बी. सावंत, जे. ने अपने लिए और कुलदिप सिंह, जे. ने अलग तरीके से बात की।

उनका मानना था कि अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा को भी चुनौती दिए जाने पर वही सिद्धांत लागू होंगे। विद्वान न्यायाधीशों द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

एस. आर. बोम्मई के मामले में एक याचिका दायर की गई थी कि न्यायिक 684 के सिद्धांत

[2006] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बेरियम केमिकल्स लिमिटेड और ए. एन. आर. में दी गई समीक्षा। वी. कंपनी कानून बोर्ड और ओआरएस। , [1966] पूरक। 3 एस. सी. आर. 311 लागू होते हैं और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक संतुष्टि हो सकती है -

जाँच की गई। बेरियम केमिकल के मामले में, कंपनी लॉ बोर्ड के तहत कंपनी अधिनियम की धारा 237 (बी) ने जांच के लिए चार निरीक्षकों को नियुक्त किया

अपीलार्थी-कंपनी के कार्य इस आधार पर कि बोर्ड की राय थी कि ऐसी परिस्थितियाँ थीं जो यह सुझाव देती थीं कि अपीलार्थी-कंपनी का व्यवसाय उसके लेनदारों को धोखा देने के इरादे से किया जा रहा था,

सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति और यह कि कंपनी के मामलों के प्रबंधन में संबंधित व्यक्ति इसके संबंध में कंपनी के प्रति धोखाधड़ी, कदाचार और अन्य कदाचार के दोषी थे और

उनके सदस्य। कंपनी ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। रिट याचिका के जवाब में, कंपनी लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने एक हलफनामा दायर किया और तर्क दिया कि ऐसी सामग्री है जिसके आधार पर आदेश जारी किया गया था और उन्होंने स्वयं इस सामग्री की जांच की थी और उक्त धारा 237 (बी) के अर्थ के भीतर आवश्यक राय बनाई थी।

कम्पनी अधिनियम। अधिकांश न्यायाधीशों ने माना कि परिस्थितियाँ

हलफनामे में प्रकट की गई एकमात्र सामग्री के रूप में माना जाना चाहिए जिसके आधार पर बोर्ड ने धारा 237 (बी) के तहत जांच का आदेश देने से पहले राय बनाई और यह कि परिस्थितियां उचित रूप से यह सुझाव नहीं दे सकती हैं कि कंपनी का संचालन लेनदारों, सदस्यों या अन्य व्यक्तियों को धोखा देने के लिए किया जा रहा था और इसलिए, विवादित आदेश को धारा के अधिकार से बाहर माना गया था।

न्यायाधीश हिदायतुल्ला, जैसा कि वे तब थे, ने कहा कि धारा 237 (बी) के तहत शक्ति विवेकाधीन शक्ति है और इसके प्रयोग के लिए पहली आवश्यकता एक राय का ईमानदार गठन है कि एक जांच आवश्यक है और अगला आवश्यकता यह है कि अनुभाग में निर्धारित निष्कर्षों का सुझाव देने वाली परिस्थितियाँ हों। गणना किए गए प्रकार के अनुमान का सुझाव देने वाली परिस्थितियों पर आधारित कोई कार्रवाई मान्य नहीं होगी। यद्यपि राय का गठन व्यक्तिपरक है, निष्कर्ष के लिए प्रासंगिक परिस्थितियों का अस्तित्व

कार्रवाई के लिए अनिवार्य रूप से प्रदर्शन योग्य होना चाहिए। यदि उनके अस्तित्व पर सवाल उठाया जाता है, तो इसे कम से कम प्रथम दृष्टया साबित करना होगा। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए जो कार्रवाई की निश्चितता के निष्कर्ष की ओर ले जाए।

इन सिद्धांतों को बाद के कुछ निर्णयों में भी लागू किया गया था जहां

प्रशासनिक कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी गई थी। (एम. ए. राशिद और अन्य देखें। वी. केरल राज्य, [1975] 2 एससीआर 93)।

एक दलील यह भी थी कि न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था

"काउंसिल ऑफ सिविल सर्विसेज यूनियन एंड ओआरएस" में लॉर्ड डिप्लॉक द्वारा। वी. सिविल सेवा मंत्री, (1985) ए. सी. 374 जी. सी. एच. क्यू. राष्ट्रपति के कार्यकाल 685 में लागू होगा।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [बालाकृष्णन, जे.]

अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा को चुनौती दी गई है। यह याचिका भी स्वीकार नहीं की गई। एस. आर. बोम्मई के मामले में अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा।

सावंत द्वारा व्यक्त व्यापक दृष्टिकोण। जे., जिन पर कुलदिप सिंह, जे.

सहमत, एस. आर. में पृष्ठ 102 पर टिप्पणियों से एकत्र किया जा सकता है।
बोम्मई का मामला जो निम्नलिखित प्रभाव का है:

" इन अधिकारियों से, एक निष्कर्ष जो सुरक्षित रूप से हो सकता है

यह रेखांकित किया गया है कि अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग

यह जाँचने की सीमा तक कि क्या शर्तें पूर्ववर्ती हैं
घोषणा का जारी होना संतुष्ट हो गया है या नहीं। यह

जाँच में अनिवार्य रूप से जांच शामिल होगी कि क्या वहाँ है

राष्ट्रपति की संतुष्टि के लिए सामग्री मौजूद थी कि एक स्थिति

ऐसा उत्पन्न हुआ था जिसमें राज्य सरकार को चलाया नहीं जा सकता था

के संबंध में जानकारी का पर्याप्त प्रमाण या इससे मुक्त होना चाहिए
चीजों की स्थिति के बारे में संदेह या अनिश्चितता यह दर्शाती है कि

विचाराधीन स्थिति उत्पन्न हो गई है। यद्यपि पर्याप्तता

या अन्यथा सामग्री की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है

ऐसी सामग्री से लिया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से न्यायिक के लिए खुला है।

समीक्षा "।

उपरोक्त राय जे. सावंत द्वारा व्यक्त की गई, जिस पर जे. कुलदिप सिंह, जे.

यह भी माना गया कि अन्य न्यायाधीशों द्वारा पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था। बी. पी. जीवन रेड्डी, जे. ने अपने और अग्रवाल, जे. के लिए बोलते हुए कहा कि अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है और यह माना कि न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत, जो एक प्रशासनिक कार्रवाई को चुनौती दिए जाने पर लागू होते हैं, को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है।

फैसले के अंत में, जीवन रेड्डी, जे. ने संक्षेप में कहा

निष्कर्ष और निष्कर्ष (6) और (7) न्यायिक समीक्षा के दायरे और दायरे की बात करते हैं। खंड (1), (2), (6) और (7) इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं -

वर्तमान मामला। ये इस प्रकार हैं:

(1) संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। इसका प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जब वह संतुष्ट हो कि कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है

जहाँ किसी राज्य की सरकार को उसके अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।

संविधान के प्रावधानों के साथ, हमारे संविधान के तहत [2006] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शक्ति वास्तव में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की है जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री हैं। लेख द्वारा विचार की गई संतुष्टि है प्रकृति में व्यक्तिपरक।

(2) कला द्वारा प्रदत्त शक्ति। 356 राष्ट्रपति एक हैं

सशर्त शक्ति। यह एक पूर्ण शक्ति नहीं है। ऐसी सामग्री का अस्तित्व जिसमें रिपोर्ट (ओं) शामिल या शामिल हो सकती है

राज्यपाल-एक पूर्व शर्त है। संतुष्टि प्रासंगिक सामग्री पर बनाई जानी चाहिए। अनुच्छेद के तहत शक्ति के प्रयोग के संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिशें। 356 सभी संबंधित लोगों द्वारा गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। [3] .....

[4] .....

[5] . ...

(6) अनुच्छेद 74 (2) केवल इस सवाल की जांच को रोकता है कि क्या कोई है, और यदि ऐसा है, तो मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई थी। यह अदालत को केंद्रीय मंत्रिपरिषद (भारत संघ) से अदालत को उस सामग्री का खुलासा करने के लिए कहने से नहीं रोकता है, जिस पर राष्ट्रपति को अपेक्षित संतुष्टि मिली थी। जिस सामग्री के आधार पर सलाह दी गई थी, वह सलाह का हिस्सा नहीं बनती है। भले ही सामग्री को राष्ट्रपति द्वारा देखा जाता है या दिखाया जाता है, लेकिन यह सलाह के रूप में नहीं आता है। साक्षय अधिनियम के अनुच्छेद 74 (2) और धारा 123 में विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। ऐसा हो सकता है कि घोषणा का बचाव करते समय, मंत्री या संबंधित अधिकारी धारा 123 के तहत विशेषाधिकार का दावा कर सकते हैं। यदि और जब ऐसे विशेषाधिकार का दावा किया जाता है, तो इसका निर्णय धारा 123 के प्रावधानों के अनुसार अपने गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा।

(7) अनुच्छेद 356 (I) के तहत घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय घोषणा को खारिज कर सकता है यदि यह दुर्भावनापूर्ण या पूरी तरह से अप्रासंगिक या बाहरी आधारों पर आधारित पाया जाता है। खंड (5) को हटाना (जो था)

44 वें (संशोधन) अधिनियम द्वारा 38 वें (संशोधन) अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया, कार्रवाई की समीक्षा पर संदेह को दूर करता है। जब आह्वान किया जाता है, तो भारत संघ को सामग्री का उत्पादन करना पड़ता है जिसके आधार पर कार्रवाई की गई थी। यदि वह कार्रवाई का बचाव करना चाहता है तो वह ऐसा करने से इनकार नहीं कर सकता है। अदालत सामग्री की शुद्धता या इसकी पर्याप्तता में नहीं जाएगी। इसकी जांच यह देखने तक सीमित है कि क्या 687

रामेश्वर प्रसाद बनाम. यू. ओ. आई. [बालाकृष्णन, जे.]

सामग्री कार्रवाई के लिए प्रासंगिक थी। भले ही सामग्री का हिस्सा है

अप्रासंगिक, अदालत तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि कुछ सामग्री है जो की गई कार्रवाई के लिए प्रासंगिक है।

[जोर दिया गया]

न्यायमूर्ति रत्नवेल पांडियन ने न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी के निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त की।

उपरोक्त सभी बिंदुओं पर। वे निष्कर्षों के सारांश के केवल खंड (3) से असहमत थे। खंड (3) केवल विधान सभा को भंग करने की शक्ति से संबंधित है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा उसके बाद ही किया जाएगा। अनुच्छेद 356 के खंड (1) के तहत घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है और इस तरह के अनुमोदन तक राष्ट्रपति केवल संबंधित संविधान के प्रावधानों को निलंबित करके विधानसभा को निलंबित कर सकते हैं।

विधान सभा तक।

जे. एस. वर्मा, अहमदी और रामास्वामी, जे. एक अलग नोट लिया। अहमदी,

जे. की राय थी कि अदालत अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को प्रदत्त संवैधानिक शक्ति के उपयोग पर तब तक रोक नहीं लगा सकती जब तक कि इसे दुर्भावनापूर्ण नहीं दिखाया जाता है। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से पहले, पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए और जब तक कि कोई मजबूत और ठोस प्रथम दृष्टया मामला न हो।

राष्ट्रपति, अर्थात कार्यपालिका को आरोप का जवाब देने के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए। जे. रामास्वामी की भी यही राय थी।

वर्मा, जे. का विचार था कि वैधता का निर्णय करने के लिए परीक्षण इंगित करता है

बेरियम केमिकल्स लिमिटेड के मामले में और उस श्रेणी के अन्य मामलों में अनुच्छेद 356 के तहत जारी घोषणा को परीक्षण और अमान्य करने के लिए कोई आवेदन नहीं है। उनकी राय थी कि केवल वे मामले जो यह तय करने के लिए पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ मानकों को लागू करने की अनुमति देते हैं कि क्या संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, वे न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं और शेष मामले जिनमें कुछ अभेद्य या निष्कर्षों पर निर्भर व्यक्तिपरक संतुष्टि का कोई महत्वपूर्ण क्षेत्र है, न्यायसंगत नहीं हैं क्योंकि उस विवाद को हल करने के लिए कोई न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानक नहीं हैं और वे मामले केवल राजनीतिक जांच और सुधार के अधीन हैं, जो भी मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में इसका मूल्य है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एस. आर. बोम्मई के मामले में, अधिकांश न्यायाधीश

अभिनिर्धारित किया कि कर्नाटक, मेघालय और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में राष्ट्रपति की घोषणाएं असंवैधानिक थीं। जिन तथ्यों के कारण अंततः दो राज्यों में अनुच्छेद 356 (1) के तहत राष्ट्रपति की घोषणा हुई, वे एस. आर. बोम्मई के मामले में निर्धारित कानून को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कर्नाटक के मामले में राष्ट्रपति ने सरकार को बर्खास्त कर दिया और

राज्य विधानसभा को भंग कर दिया। जनता पार्टी राज्य में शासन कर रही थी और उसने श्री एस. आर. बोम्मई के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। विधायिका का एक सदस्य पार्टी से अलग हो गया और उसे एक पत्र प्रस्तुत किया

राज्यपाल ने मंत्रालय से अपना समर्थन वापस ले लिया। अगले दिन उन्होंने

सरकार बनाने की स्थिति और इसलिए, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करने की सिफारिश की गई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री श्री बोम्मई के विचार का पता नहीं लगाया और अगले दिन उनमें से सात ने जिन उन्नीस विधायकों ने कथित रूप से राज्यपाल को उक्त पत्र लिखे थे, उन्होंने शिकायत की कि उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे

गलत निरूपण। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को विधायिका में विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश देने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया और न ही किसी से मुलाकात की।

विधायक जो कथित तौर पर जनता पार्टी से अलग हो गए थे। यह इस पृष्ठभूमि में था कि राज्यपाल की उक्त रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा और इस तरह प्राप्त करने वाली परिस्थितियों में, दुर्भावना से समान रूप से पीड़ित थी। विधिवत गठित मंत्रालय को बर्खास्त कर दिया गया था

उस सामग्री का आधार जो राज्यपाल के इप्स डिक्सिट से अधिक नहीं था।

मेघालय के मामले में मेघालय यूनाइटेड पार्लियामेंटरी पार्टी

(एम. यू. पी. पी.) जिसके पास विधानसभा में बहुमत था, ने मार्च, 1990 में श्री बी. बी. लिंगदोह के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। एक किंडिया आरट्री प्रासंगिक समय में सदन के अध्यक्ष थे। उन्हें संयुक्त मेघालय के नाम से जाने जाने वाले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया था।

संसदीय मंच (यू. एम. पी. एफ.) अपने चुनाव पर, श्री आरट्री ने विधानसभा में अधिकांश सदस्यों के समर्थन का दावा किया और राज्यपाल से उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री श्री लिंगदोह से सदन में अपना बहुमत साबित करने को कहा। एक विशेष 7.8.91 पर सत्र बुलाए गए और मंत्रालय में विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। तीस सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन किया और 27 ने पी के खिलाफ मतदान किया।

689

रामेश्वर प्रसाद बनाम. यू. ओ. आई. [बालाकृष्णन, जे.]

यह। प्रस्ताव पर मतदान के परिणाम की घोषणा करने के बजाय, अध्यक्ष घोषणा की कि उन्हें पांच निर्दलीय विधायकों के खिलाफ शिकायत मिली थी

सत्तारूढ़ गठबंधन मोर्चा ने आरोप लगाया कि उन्हें दलबदल विरोधी कानून के तहत विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था और चूंकि वे वोट देने के लिए अयोग्य हो गए थे, वह उनके मतदान के अधिकार को निलंबित कर रहा था। इस घोषणा पर सदन में हंगामा हुआ और इसे स्थगित करना पड़ा। 11.8.1991 पर, स्पीकर

कथित दलबदलुओं को कारणदर्शक नोटिस जारी किए गए। पांचों विधायकों ने यह कहते हुए जवाब दिया कि वे किसी भी दल में शामिल नहीं हुए हैं और वे स्वतंत्र बने हुए हैं। अध्यक्ष ने पांचों विधायकों को अयोग्य घोषित करने का आदेश पारित किया। इसके बाद, राज्यपाल की सलाह पर, मुख्यमंत्री श्री लिंगदोह ने विश्वास मत पारित करने के लिए 9.9.1991 पर विधानसभा का सत्र बुलाया। मंत्रालय। हालांकि, अध्यक्ष ने अयोग्य ठहराए गए पांच निर्दलीय विधायकों को सत्र का नोटिस भेजने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने इस संबंध में संपर्क किया

अदालत। इस अदालत ने अध्यक्ष के आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किए। उनमें से केवल चार ने स्थगन के आदेश के लिए अदालत में आवेदन किया था। अध्यक्ष ने एक प्रेस वक्तव्य जारी किया जिसमें उन्होंने घोषणा की कि वह किसी भी अदालत के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए राज्यपाल ने विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। विधानसभा को फिर से बुलाया गया और चारों

अदालत से अंतरिम आदेश प्राप्त करने वाले निर्दलीय विधायकों ने अध्यक्ष के खिलाफ इस अदालत में अवमानना याचिका दायर की थी। अध्यक्ष ने इस न्यायालय के अंतरिम आदेश की अवहेलना करते हुए एक प्रेस बयान में घोषणा की। 8.10.1991 पर, इस न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिया गया कि राज्य के सभी अधिकारियों को 6.9.1991 के न्यायालय के अंतरिम आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और पांच में से चार निर्दलीय विधायकों को विधानसभा के सत्र में भाग लेने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। मंत्रालय में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए रखे जाने के बाद, अध्यक्ष ने घोषणा की कि 26 ने प्रस्ताव के पक्ष में और 26 ने इसके खिलाफ मतदान किया और चार निर्दलीय विधायकों के मतों को बाहर कर दिया। मंत्रालय का समर्थन करने वाले 26 विधायक और इसके पक्ष में मतदान करने वाले चार विधायक

प्रस्ताव ने एक नया अध्यक्ष चुना और नए अध्यक्ष ने घोषणा की कि मंत्रालय में विश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है क्योंकि 30 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया था। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल को पत्र भेजे कि उन्होंने मंत्रालय के पक्ष में मतदान किया है। हालाँकि, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर 8.10.1991 पर सत्र में जो हुआ था, उसे देखते हुए उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के पत्र के खिलाफ इस अदालत का रुख किया। इन सभी तथ्यों के बावजूद, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 (1) के तहत एक घोषणा जारी की और घोषणा में कहा गया कि राष्ट्रपति राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट और उन्हें प्राप्त अन्य जानकारी के आधार पर संतुष्ट थे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता था।

नागालैंड के मामले में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थी। तथ्य ये हैं -

विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है।

इन तीनों मामलों में जहां राष्ट्रपति की घोषणाएं जारी की गईं

अनुच्छेद 356 के तहत इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, वे राज्य थे जहां सरकार बहुमत के बल पर काम कर रही थी, जबकि तत्काल मामले में विधानसभा को भंग करने का निर्णय स्पष्ट रूप से पारित किया गया था।

राज्यपाल की रिपोर्ट पर जब विधानसभा निलंबित एनिमेशन में थी

और राज्य में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार नहीं थी और इसलिए, विधानसभा के पटल पर सरकार के बहुमत का परीक्षण करने का कोई सवाल ही नहीं था।

एस. आर. बोम्मई के निर्णय से यह समझा जा सकता है कि बहुमत

उनका विचार था कि जहां तक न्यायिक समीक्षा का दायरा और दायरा बहुत सीमित है, जब अनुच्छेद 356 के तहत एक घोषणा पर सवाल उठाया जाता है और इसी तरह

ऐसे मामले में मापदंड लागू होंगे जहां अनुच्छेद के तहत अधिसूचना पारित की जाती है।

174 (2) ((ख) राज्य विधान सभा को भंग करना। द्वारा उठाई गई याचिका

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि विधानसभा को भंग करने की अधिसूचना विधायी प्रकृति की है और इसे चुनौती दी जा सकती है केवल विधायी क्षमता के अभाव या संविधान के अधिकार से बाहर के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह याचिका राजस्थान के मामले के साथ-साथ एस. आर. बोम्मई के मामले में भी उठाई गई थी, लेकिन दोनों मामलों में इसे सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। हालांकि, राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की गई शक्ति चरित्र में असाधारण है और इसे प्रशासनिक कार्रवाई के बराबर नहीं माना जा सकता है और प्रशासनिक कार्रवाई को चुनौती देने के लिए उपलब्ध आधारों को लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 74 (2) को देखते हुए, अदालत इस सवाल पर विचार नहीं कर सकती कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को किस तरह की सलाह दी गई थी। राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति निरपेक्ष नहीं है; इसमें नियंत्रण और संतुलन है। यह सच है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की गई शक्ति का गंभीर महत्व है और यह कभी-कभी विधिवत गठित सरकार को बर्खास्त करके और विधिवत गठित विधानसभा को भंग करके राज्य के लोगों की इच्छा को पूर्ववत करने के बराबर है। ऐसी शक्ति के किसी भी दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जाना चाहिए यदि इसका उपयोग दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए या अप्रासंगिक आधारों के आधार पर पूरी तरह से बाहरी कारणों से किया जाता है। न्यायालय निश्चित रूप से राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत सामग्री में जा सकता है जिसके कारण राज्य विधानसभा को भंग करने का निर्णय लिया गया।

बिहार राज्य विधानमंडल को भंग करने की राष्ट्रपति की घोषणा

राज्यपाल द्वारा भेजी गई दो रिपोर्टों के अनुसार विधानसभा जारी की गई थी। यह याद किया जा सकता है कि अनुच्छेद 356 (1) राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा 691 थी।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. 1. [बालाकृष्णन, जे।]

7 मार्च, 2005 को जारी किया गया। इसके बाद 22 अप्रैल, 2005 को राज्यपाल ने पत्र भेजा।

एक रिपोर्ट जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल नहीं। या तो व्यक्तिगत रूप से या तत्कालीन चुनाव पूर्व संयोजन के साथ या चुनाव के बाद के गठबंधन के साथ, एक लोकप्रिय सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं जिसमें वे 243 सदस्यीय सदन में 122 के साधारण बहुमत का दावा कर सकते हैं। राज्यपाल ने भी संकेत दिया था

कि विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के माध्यम से एकत्र की गई कुछ समाचार पत्र रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टें हैं कि विभिन्न माध्यमों से लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जीतने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं।

लोकप्रिय सरकार क्योंकि धन 243 के सदन में 122 के साधारण बहुमत के समर्थन का दावा कर सकती थी। उस रिपोर्ट में राज्यपाल ने यह भी कहा था कि एलजेपी के विधायक जद (यू) की ओर बढ़ रहे हैं और उन्हें विभिन्न प्रलोभन दिए गए हैं और यह एक खतरनाक विशेषता थी और राज्यपाल की यह भी राय थी कि यह संवैधानिक प्रावधानों और उसमें बनाए गए सुरक्षा उपायों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा था और लोगों के फैसले को विकृत कर रहा था।

विद्वान ए. एस. जी., श्री गोपाल सुब्रमण्यम द्वारा आग्रह किया गया तर्क था

कि यह वह सामग्री है जिसे संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (बी) के तहत एक घोषणा जारी होने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष रखा गया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रिट याचिकाकर्ताओं के पास कोई मामला नहीं है कि जद (यू) या किसी अन्य गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया था और उन्होंने सरकार बनाने के लिए अपना दावा करते हुए राज्यपाल से संपर्क किया था। हमारे सामने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि जद (यू) या भाजपा के साथ उसके गठबंधन ने कभी राज्यपाल से यह प्रार्थना करते हुए मुलाकात की थी कि उन्हें सरकार बनाने का अधिकार मिला है। याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील है कि वे एक सरकार बनाने वाले थे और उस योजना को विफल करने के लिए राज्यपाल ने एक रिपोर्ट भेजी जिसके तहत उस योजना को विफल करने के लिए विधानसभा को भंग कर दिया गया था। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एलजेपी के 17 या 18 सदस्य जद (यू)-भाजपा गठबंधन में शामिल हो गए थे, लेकिन हमारे सामने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि वे वास्तव में सरकार बनाने के लिए गठबंधन में शामिल हुए थे। एक पत्र याचिकाकर्ताओं में से एक द्वारा प्रस्तुत किया गया है और उस पर सभी विधायकों के हस्ताक्षर नहीं हैं और उनमें से कुछ के संबंध में, कुछ अन्य ने अपने हस्ताक्षर किए थे। इसलिए, यह कहना गलत है कि राज्यपाल ने यह देखने के लिए कदम उठाए थे कि विधानसभा

राजनीतिक दल जद (यू) के नेतृत्व में सरकार के गठन को रोकने के लिए जल्दबाजी में भंग कर दिया गया था। यदि किसी जिम्मेदार राजनीतिक दल के पास कोई मामला था कि उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया था या वे 692 प्राप्त करने वाले थे

[2006] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बहुमत ने समर्थन किया या अल्पमत सरकार बनाने की स्थिति में थे

कुछ राजनीतिक दलों का समर्थन और यदि उनकी याचिका को राज्यपाल द्वारा खारिज कर दिया जाता, तो स्थिति पूरी तरह से अलग होती। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी

तत्काल मामले में पहुंचे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा के लगभग तीन महीने बाद राज्य विधानसभा को भंग करने का आदेश पारित किया गया था

इसे लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार कहा जा सकता है। यदि राज्यपाल को उचित आशंका है और विश्वसनीय जानकारी है कि राजनीतिक दलों द्वारा बहुमत प्राप्त करने के लिए इस तरह के अनैतिक साधन अपनाए जा रहे हैं, तो वे निश्चित रूप से राष्ट्रपति के ध्यान में लाए जाने वाले मामले हैं और कम से कम वे अप्रासंगिक मामले नहीं हैं। राज्यपाल निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। उनकी रिपोर्ट मंत्रिपरिषद द्वारा इसकी जांच की जाएगी और संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि बिहार राज्य विधानसभा को भंग करने का निर्णय पूरी तरह से अप्रासंगिक आधारों पर आधारित शक्ति का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग है।

इसमें राष्ट्रपति की कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के मापदंडों को लागू करना।

इस संबंध में, मुझे नहीं लगता कि इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने 23 मई, 2005 को राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने का मामला बनाया है। रिट याचिकाएं बिना किसी योग्यता के हैं जिन्हें खारिज किया जा सकता है।

अरिजीत पसायत जे. पिछले कुछ वर्षों में की गई कार्रवाइयों पर हमला

मंत्रालयों की स्थापना/विघटन के मामले में राज्यपालों की संख्या 693 बढ़ी है।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

जो अपने आप में एक परेशान करने वाली विशेषता है। एक राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रहरी और संघ और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका सौंपी गई है। एक राज्यपाल को आपसी हित के मामलों में संघ और राज्य के बीच संचार के माध्यम में एक उपयोगी खिलाड़ी के रूप में भी वर्णित किया गया है।

और जिम्मेदारी। उनके पद की शपथ उन्हें भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') और कानून की रक्षा, संरक्षण और रक्षा करने और संबंधित राज्य के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए खुद को समर्पित करने के लिए बाध्य करती है। जब यह आरोप लगाया जाता है कि वह पक्षपातपूर्ण है और/या किसी राजनीतिक दल के एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो उसके संविधान पर ध्यान न दें।

कर्तव्यों, यह स्वाभाविक रूप से एक गंभीर मामला है।

ये मामले बिहार के राज्यपाल के कृत्यों से संबंधित हैं।

इन रिट याचिकाओं में चुनौती संवैधानिकता, वैधता और

बिहार विधानसभा को भंग करने के आदेश में भारत संघ की अधिसूचना जीएसआर 333 (ई) दिनांक 23.5.2005 की वैधता। 2005 की रिट याचिका (सी) No.257 चार व्यक्तियों द्वारा दायर की गई है जो भंग विधानसभा के लिए चुने गए थे। याचिकाकर्ता संख्या 1 श्री रामेश्वर प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी (संक्षेप में 'भाजपा') के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। याचिकाकर्ता संख्या 2 श्री किशोर कुमार को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। याचिकाकर्ता संख्या 3 श्री रामप्रवेश राय को जनता दल यूनाइटेड (संक्षेप में 'जद यू') के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 4 डॉ. अनिल कुमार को लोक जनशक्ति पार्टी (संक्षेप में 'एलजेपी') के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था।

2005 की रिट याचिका (सी) No.353 श्रीमती द्वारा दायर की गई है। पूर्णिमा

यादव जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। 2005 की रिट याचिका (सी) No.258 एक अधिवक्ता श्री विप्लव शर्मा द्वारा दायर की गई है, जिसे एक जनहित याचिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

ये सभी रिट याचिकाएं संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई हैं।

संविधान। विप्लव शर्मा की रिट याचिका में अन्य दो रिट याचिकाओं में रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई चुनौतियों के अलावा, बिहार के राज्यपाल को बिहार राज्य की 13 वीं विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने और ऐसी विधानसभा को कार्यात्मक बनाने का निर्देश देने के

लिए प्रार्थना की गई है, जो कथित रूप से संविधान के अनुच्छेद 172 और 176 के संदर्भ में है और बिहार में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाए।

संविधान के अनुच्छेद 164 (1) की शर्तें। इसके अलावा, भारत के चुनाव आयोग (संक्षेप में 'चुनाव आयोग') को 14 वीं राज्य विधानसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव नहीं कराने के निर्देश के लिए परिणामी प्रार्थना की गई है। यह भी प्रार्थना की गई है कि राज्यपाल 694 की कथित रिपोर्ट के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाई जाए।

[2006] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिहार सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश की

विधानसभा और राष्ट्रपति की घोषणा दिनांक 7.3.2005 ने 13 वीं राज्य विधानसभा को निलंबित एनिमेशन के तहत रखा और राष्ट्रपति ने

घोषणा दिनांक 23.5.2005। संक्षेप में, उनका रुख यह था कि चूंकि राज्य विधानसभा अभी तक कार्यशील नहीं थी, इसलिए इसका कोई सवाल ही नहीं था।

उसी को भंग करना: दिशानिर्देशों और निर्देशों को निर्धारित करने के लिए कुछ अन्य प्रार्थनाएँ की गई हैं जिन पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि दिनांक 1 के आदेश द्वारा यह नोट किया गया था कि श्री विप्लव शर्मा ने मामले की सुनवाई करने वाली पीठ के समक्ष कहा था कि वह दबाव नहीं डालते हैं

रिट याचिका में प्रार्थना (i), (ii), (vii) और (viii)।

मूल रूप से चुनौतियों को, जैसा कि प्रस्तुतियों से निकाला गया है

याचिकाकर्ता अनिवार्य रूप से इस प्रकार हैं:

विवादित द्वारा विधान सभा का विघटन

बिहार राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जारी 7 मार्च, 2005 की उद्घोषणा संख्या जी. एस. आर. 162 (ई) के खंड (ए) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद

174 के खंड (2) के उपखंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23.5.2005 अधिसूचना बिहार के राज्यपाल की एक दूषित और स्पष्ट रूप से अस्थिर रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था। श्री सोराबजी ने कहा कि राज्यपाल की रिपोर्ट, जिसके कारण बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जमीनी वास्तविकताओं के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर आधारित नहीं थी। जब बिहार विनियोग (खाते पर वोट) विधेयक, 2005 पर राज्यसभा में चर्चा की जा रही थी, तब गृह मंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि राष्ट्रपति शासन को लंबे समय तक जारी रखना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल सका और अधिक दल सरकार बनाने के लिए एक साथ नहीं आ सके। जहां अंतर है, वहां अल्पसंख्यक सरकार स्थापित करना भी उचित नहीं होगा।

अपेक्षित बहुमत और अल्पमत के बीच का अंतर बहुत कम नहीं था। सदन को आश्वासन दिया गया कि सरकार की लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह जितनी जल्दी गायब हो जाए, उतना ही बिहार राज्य के लिए, लोकतंत्र के लिए और इस देश में अपनाई गई व्यवस्था के लिए बेहतर होगा। राज्यपाल से सरकार के गठन की संभावनाओं का पता लगाने का अनुरोध किया गया था। यह

निर्वाचित प्रतिनिधियों से बात करके इसे हासिल किया जा सकता है। गृह मंत्री द्वारा जो कहा गया था, उसके विपरीत, पूरी तरह से असमर्थनीय परिसरों में और श्री नितीश कुमार को रोकने के एकमात्र उद्देश्य के साथ, जिन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (संक्षेप में 'एनडीए') द्वारा एलजेपी और निर्दलीयों के एक अलग समूह के समर्थन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया था।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

695

जल्दबाजी में, एक रिपोर्ट दी गई, जिसे अविश्वसनीय रूप से देखा गया

गति और राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त की गई। जिस जल्दबाजी और गति से कार्रवाई की गई, वह स्पष्ट रूप से दुर्भावना का संकेत देता है। यद्यपि राज्यपाल ने कुछ घोड़ों के व्यापार या प्रलोभन का संदर्भ दिया था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से बिना किसी विवरण के अप्रमाणित सामग्री के आधार पर था। राज्यपाल की कार्रवाई उस प्रकृति की है जिसकी इस न्यायालय ने एस. आर. बोम्मई और अन्य मामलों में निंदा की थी। वी.

भारत संघ और ओआरएस।, [1994] 3 एससीसी 1. यह प्रस्तुत किया गया था कि समान विचार

संबंधित राज्यपालों द्वारा व्यक्त किए गए उक्त मामले में कर्नाटक और मेघालय में विधानसभाओं के विघटन के मामलों में स्वीकृति नहीं मिली। यद्यपि मध्य प्रदेश, राजस्थान और राजस्थान के संबंध में घोषणाएँ

हिमाचल प्रदेश को असंवैधानिक नहीं माना गया था, फिर भी न्यायिक समीक्षा के दायरे के मापदंडों को उजागर किया गया था। भले ही यह स्वीकार किया जाए कि राज्यपाल की राय को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सम्मान और सम्मान दिया जाना चाहिए कि वह एक उच्च संवैधानिक पद पर हैं, फिर भी जब विचार दुर्भावना से दूषित है।

उसी भावना को तोड़ना होगा। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार तत्काल मामले में, पृष्ठभूमि तथ्यों ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि

राज्यपाल ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे और उनका उद्देश्य बहुमत वाली सरकार की स्थापना को रोकना था। भले ही यह तर्कों के लिए स्वीकार किया जाता है कि बहुमत को अनुचित तरीकों से फंसाया गया था, यह एक ऐसा मामला है जिसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है। यह विधानसभा के अध्यक्ष के लिए है, जब फ्लोर टेस्ट होता है तो यह विचार करने के लिए कि क्या कोई फ्लोर क्रॉसिंग थी। अगर कोई

यह दिखाने के लिए सामग्री मौजूद थी कि किसी भी विधानमंडल को अनुचित तरीकों से लुभाया गया था जो मतदाताओं की देखभाल करने और मीडिया को उजागर करने के लिए है। यह राज्यपाल के लिए किसी को दावा करने से रोकने का आधार नहीं हो सकता है, जब उसके पास बहुमत वाली विधानसभाओं का समर्थन हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक कर्नाटक विधानसभा के विघटन का संबंध है, राज्यपाल की रिपोर्ट में खरीद-फरोख्त आदि के संबंध में इसी तरह के विचार रखे गए थे और एस. आर. बोम्मई के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय ने पाया कि यह विघटन का निर्देश देने का आधार नहीं हो सकता है।

पिछले कुछ वर्षों से एक पार्टी द्वारा सरकार का गठन

बहुमत दुर्लभ हो गया है। इसलिए कई राज्यों में और वास्तव में केंद्र में गठबंधन सरकारें हैं। चुनाव के बाद के समायोजन और किसी भी राजनीतिक दल के साथ वैचारिक समानता में कुछ भी गलत नहीं है।

किसी अन्य राजनीतिक दल का समर्थन करना, हालांकि चुनाव से पहले कोई गठबंधन नहीं था, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एलजेपी पार्टी की अधिकांश विधानसभाओं ने सरकार बनाने के प्रयासों में जद (यू) का समर्थन करने का फैसला किया था। इस संबंध में स्पष्ट निर्णय लिए गए।

कुछ निर्दलीयों ने भी श्री नितीश कुमार को अपना समर्थन दिया था। राज्यपाल बहुमत स्थापित होने के बाद सरकार के गठन की अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकते। एकमात्र अपवाद [2006] आई एस. सी. आर. हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

696

यह संख्या अपेक्षित संख्या से बहुत अधिक थी। राज्यपाल की कार्रवाई दिखाएँ कि वह किसी विशेष राजनीतिक की मदद करने के लिए पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा था

पार्टियाँ।

न्यायिक समीक्षा का दायरा इस न्यायालय द्वारा राज्य में चित्रित किया गया था

राजस्थान और ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस। , [1977] 3 एस. सी. सी. 592) और बोम्मई के मामले (ऊपर) में इसका और विस्तार किया गया। राजस्थान के मामले (ऊपर) और बोम्मई के मामले (ऊपर) में निर्धारित दिशानिर्देशों की कसौटी पर परीक्षण किया गया राज्यपाल की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से अस्थिर है और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति की घोषणा असंवैधानिक है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ने

घोषणा पूरी तरह से राज्यपाल की रिपोर्ट पर आधारित थी जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

भारत संघ द्वारा।

श्री पी. एस. नरसिम्हा और श्री विप्लव शर्मा ने इस रुख का समर्थन किया।

इसके अतिरिक्त, रिट याचिकाओं में उल्लिखित अपने अतिरिक्त स्टैंड के संदर्भ में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि राष्ट्रपति की अधिसूचना टिकाऊ नहीं है और असंवैधानिक है।

जवाब में, श्री मिलन के. बनर्जी, विद्वान महान्यायवादी, श्री.

गुलाम ई. वाहनवती, विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री गोपाल सुब्रमण्यम, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री पी. पी. राव, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री बी. बी. सिंह, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 356 (1) और परिणामस्वरूप अनुच्छेद 174 (2) के तहत उद्घोषणा से संबंधित मामलों में इस न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के दायरे

के बारे में कोई विवाद नहीं है। लेकिन याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक परिदृश्य वास्तव में ऐसा नहीं है।

तत्काल मामले में राज्यपाल ने वास्तव में किसी को नहीं रोका था

दावा करने से। यह किसी का मामला नहीं है कि किसी ने दावा किया था। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.5.2005 (दिनांकित 22.5.2005 नहीं जैसा कि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा रिट याचिकाओं में कहा गया है) में जो संकेत दिया था वह यह था कि

धन, जाति, पद और इस तरह के अनुचित और अन्य आपत्तिजनक साधनों जैसे प्रलोभन के माध्यम से बहुमत प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। जब दावे की नींव को कलंकित किया गया था, स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि यह एक स्थिर सरकार की ओर नहीं ले जाएगा और यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जहां तक राज्यपाल की रिपोर्ट और राष्ट्रपति द्वारा की गई परिणामी कार्रवाइयों का संबंध है, न्यायिक समीक्षा के मानदंड बेहद सीमित हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राज्यपाल मूक दर्शक नहीं हो सकते।

अनुचित तरीकों से छेड़छाड़ की जाती है। प्रयास 697 पेश करके सत्ता हथियाने का है।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

बहुमत, जिसकी नींव उन कारकों पर आधारित है जो स्पष्ट रूप से उनकी अवधारणा में लोकतांत्रिक विरोधी हैं। संसदीय लोकतंत्र संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है और जब बहुमत स्वयं गलत साधनों का परिणाम होता है तो यह स्पष्ट रूप से मतदाताओं द्वारा दिए गए जनादेश के खिलाफ होता है। यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि मतदाता चाहते थे कि उनकी विधानसभाएँ

उनका जनादेश भ्रष्ट साधनों का उद्देश्य बन जाएगा। जब एकमात्र उद्देश्य किसी भी कीमत पर अनुचित और दागी तरीकों से सत्ता हथियाना है, तो राज्यपाल ऐसी सरकार को स्थापित करने की अनुमति नहीं दे सकता है। के द्वारा

संविधान का कभी यह उद्देश्य नहीं था कि लोकतंत्र या शासन होगा हेरफेर किया गया। दलबदल प्रतिनिधि सरकार की जड़ पर हमला करते हैं। वे असंवैधानिक, अवैध, अवैध, अनैतिक और अनुचित हैं। दसवीं अनुसूची सभी स्थितियों का ध्यान नहीं रख सकती है और

निश्चित रूप से निर्दलीयों के मामले में नहीं। यह तर्क देना बहुत खोखला होगा कि शक्ति परीक्षण होगा

विधायिकाओं का समर्थन जुटाने में सभी अशुद्धियों को दूर करना। फ्लोर टेस्ट हमेशा अपनाए गए भ्रष्ट साधनों को रोकने और बहुमत को घेरने का एक उपाय नहीं हो सकता है। यह उम्मीद करना भी बहुत अधिक है कि जहां तक किसी विशेष विधानमंडल का संबंध है, जनता या मीडिया द्वारा भ्रष्ट साधनों को उजागर करने से स्थिति में सुधार होगा। चूंकि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि किसी भी पक्ष ने दावा किया है और इसके विपरीत जैसा कि प्रारंभिक से स्पष्ट है

राज्यपाल की दिनांक 1 की रिपोर्ट कि कोई भी दावा करने की स्थिति में नहीं था और तथ्य यह है कि लगभग तीन महीने बीतने से स्थिति में सुधार नहीं हुआ, राज्यपाल से अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करने और इस प्रक्रिया में दलबदल या अन्य आपत्तिजनक गतिविधियों को अपनाने को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा नहीं की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राजस्थान राज्य के मामले में (ऊपर) जहां तक दायरा है, वह अनुपात

बोम्मई के मामले (ऊपर) में न्यायिक समीक्षा का विस्तार नहीं किया गया है, और मापदंड समान हैं।

दसवीं अनुसूची के संदर्भ में विशेष रूप से उप-अनुच्छेद 2

और 4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस योग्यता को स्पष्ट रूप से एलजेपी से अलग हुए समूह के सदस्यों द्वारा प्राप्त किया गया था। वास्तव में तथाकथित अलगाववादी समूह का जे. डी. यू. के साथ कोई विलय नहीं हुआ था। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर दस्तावेजों से पता चलता है कि केवल एक प्रस्ताव था और वास्तव में कोई विलय नहीं था।

दूसरी ओर दस्तावेज़ों से पता चलता है कि तथाकथित संकल्प में भी हेरफेर किया गया था। एक व्यक्ति ने कई व्यक्तियों के लिए हस्ताक्षर किए थे और यहां तक कि हस्ताक्षर भी अलग-अलग थे। यदि वास्तव में तथाकथित बैठक में व्यक्ति उपस्थित थे, तो कथित रूप से लिए गए प्रस्ताव को अपनाया गया, तो इसका कोई कारण नहीं था कि संबंधित प्रतिभागियों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए और किसी और ने उनके पक्ष में हस्ताक्षर किए। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हेरफेर किए गए दस्तावेजों [2006] के आधार पर 1 एस. सी. आर.

इसे इस तरह पेश करने का प्रयास किया गया जैसे कि श्री नितीश कुमार के पास बहुमत हो। दिलचस्प बात यह है कि श्री नितीश कुमार ने कोई याचिका दायर नहीं की है और केवल चार हैं।

सदस्यों ने याचिकाएं दायर की हैं, हालांकि दावा किया गया था कि 122 से अधिक ने समर्थन दिया था। हालाँकि यह अपने आप में याचिकाओं को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है, फिर भी याचिकाएँ निश्चित रूप से कानूनी दुर्बलता से ग्रस्त हैं। जैसा कि पूरी तरह से साबित हो गया है, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय का रुख साफ हाथों से नहीं किया है और इसलिए वे किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डब्ल्यू. पी. (सी) No.257 और 353 में याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रपति की अधिसूचना दिनांकित 7.3.2005 की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया है, और दिलचस्प रूप से तथाकथित जनहित याचिका में इसे चुनौती दी गई है। चुनौतियों के प्रमुख हिस्से को चुनौती देने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताया गया है कि कैसे और किस तरह से उसका कोई भी अधिकार प्रभावित हुआ है। यदि प्रभावित व्यक्तियों ने दिनांकित अधिसूचना की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया है तो याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से उस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह एक जनहित याचिका की मूल आवश्यकता है कि जो व्यक्ति हैं प्रभावित न्यायालय तक पहुँचने में असमर्थ हैं। यह अजीब बात है कि विधायकों के विद्वान वकील-रिट याचिकाकर्ताओं ने दिनांकित 7.3.2005 अधिसूचना को वैध और क्रम में स्वीकार किया है। तथाकथित जनहित याचिका में ली गई याचिका इसके विपरीत है। बोम्मई के मामले (ऊपर) में तथ्यात्मक स्थिति अलग थी। यह उन मामलों से संबंधित है जहां निर्वाचित सरकारें सत्ता में थीं।

और राज्यपालों ने विघटन का निर्देश दिया। यहां की स्थिति अलग है। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति विधायी है और इसे केवल अधिकार से बाहर के आधार पर ही निरस्त किया जा सकता है। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग और सरकारिया आयोग की रिपोर्टों ने राज्यपालों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका और उनकी रिपोर्ट के साथ जुड़ी पवित्रता का पर्याप्त संकेत दिया है। यहां तक कि जब राजस्थान राज्य और बोम्मई के मामलों में न्यायिक समीक्षा के मापदंडों का उल्लेख किया गया था

(उपर्युक्त) को ध्यान में रखा जाता है, आक्षेपित रिपोर्ट और परिणामी राष्ट्रपति की

अधिसूचना में हस्तक्षेप करने के लिए कोई दुर्बलता नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चुनाव आयोग ने नए चुनावों को अधिसूचित किया था

और भले ही बहस के लिए यदि राज्यपाल की रिपोर्ट या परिणामी राष्ट्रपति की अधिसूचना में कोई दोष देखा जाता है, तो यह पहले से अधिसूचित चुनाव को रोकने का आधार नहीं हो सकता

है। लोग नए सिरे से अपना जनादेश दे सकते हैं और यह दलील कि अगर नए सिरे से चुनाव होते हैं तो बड़ी रकम खर्च की जाएगी, वास्तव में ऐसी सरकार की स्थापना को रोकने का कोई जवाब नहीं है जिसकी

नींव लड़खड़ाती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिपोर्ट स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे राज्यपाल द्वारा किसी भी राजनीतिक दल के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण की प्रवृत्ति भी नहीं दिखाती है। वास्तव में रिपोर्ट दिनांक 21.5.2005 से पहले जिस पर

राष्ट्रपति की घोषणा के लिए अंतिम निर्णय लिया गया था एक रिपोर्ट दिनांक 27.4.2005 दी गई थी जिसमें स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि कोई भी दल रामेश्वर प्रसाद बनाम की स्थिति में नहीं था।

सरकार बनाने के लिए। राज्यपाल ने स्पष्ट रूप से उस स्रोत का संकेत दिया है जिससे उन्हें अवैध तरीकों से सरकार बनाने के प्रयासों के बारे में पता चला। यह बताया गया है कि निर्णय श्री पी. एस. नरसिम्हा और श्री विप्ले शर्मा यानी उदय नारायण सिन्हा बनाम द्वारा निर्भर था। यू. पी. और अन्य राज्य।, ए. आई. आर. (1987) इलाहाबाद 293 वास्तव में कानून में सही स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है और इसे विचित्र तथ्य स्थिति में प्रस्तुत किया गया था। इसके विपरीत, के. के. अबू बनाम में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय। भारत संघ, आकाशवाणी (1965) केरल 229) सही स्थिति बनाएँ। यह मत रखिए कि संविधान के अनुच्छेद 172 या 174 के कारण सभा को बैठक आयोजित करने के लिए बुलाए जाने से पहले भंग करने की कोई गुंजाइश नहीं है, यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में 'आरपी अधिनियम') की धारा 73 के बावजूद स्वीकार्य नहीं है। यह बताया गया है कि के. के. अबू के मामले (उपरोक्त) में निर्णय को 2002 (2002 (8) एस. सी. सी. 237 के विशेष संदर्भ संख्या 1 में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सही कानून निर्धारित करने के लिए मंजूरी दी गई थी।

राज्यपाल की रिपोर्ट दिनांकित 6.3.2005,27.4.2005 और 21.5.2005

पुनरुत्पादन की आवश्यकता है। वे नीचे लिखे अनुसार हैं:

पटना, 6 मार्च, 2005

" D.O.No.33/GB

आदरणीय राष्ट्रपति जी,

वर्तमान बिहार विधानसभा समाप्त हो गई है।

और 464/बिहार-एल. ए./2005, दिनांक 4 मार्च, 2005 संलग्न है।
(संलग्नक-I)

2. सामने आए परिणामों के आधार पर, निम्नलिखित है
पार्टी-वार स्थितिः

1 .

आर. जे. डी

75

:

जे. डी (यू)

2 .

55

:

बी जे पी।

37

3 .

:

कांग. (1)

10

4 .

:

बी एस पी।

02

5 .

6. .

एलजेपी।

29

:

7 .

सीपीआई.

:

03 [2006]

1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

01

8 .

सीपीआई. (एम)

सीपीआई. (एम. एल)

07

9 .

:

10 .

एनसीपी.

03

11 .

एसपी।

04

12 .

स्वतंत्र

17

243

आर. जे. डी. और उसकी गठबंधन स्थिति इस प्रकार है:

1 .

आर. जे. डी

कांग (आई)

2 .

10

:

03

(समर्थन पत्र नहीं

3 .

सीपीआई.

:

प्राप्त हुआ)

4 .

सीपीआई. (एम)

01

:

एनसीपी.

5 .

03

:

92

एन. डी. ए. गठबंधन की स्थिति इस प्रकार है:

1 .

37

बी जे पी।

:

भारतीय

2 .

जे. डी (यू)

:

92

3. बिहार की वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती. राबड़ी देवी ने मुझसे 28.2.2005 पर मुलाकात की और अपनी परिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया। मंत्री। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है और उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा है।

4. एल. जे. पी. के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल दोपहर में मुझसे मिला और उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष श्री राम विलास पासवान द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र (अनुलग्नक II) प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि वे सरकार के गठन में न तो आर. जे. डी. का समर्थन करेंगे और न ही बी. जे. पी. का। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम जतान सिन्हा ने भी 28.2.2005 की शाम को मुझसे मुलाकात की।

5. बी. जे. पी. के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल नारायण सिंह 701 के साथ

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. 1. [पासायत, जे।]

समर्थकों ने मुझसे 1.3.2005 पर मुलाकात की। उन्होंने एक पत्र प्रस्तुत किया है

(अनुलग्नक III) में कहा गया है कि गठबंधन की संयुक्त ताकत के अलावा 92 (भाजपा और जद (यू) के पास 10 से 12 अन्य निर्दलीयों का समर्थन है। पत्र में अनुरोध है कि आर. जे. डी. को एक गठन करने की अनुमति न दी जाए

सरकार। 6. समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ददन सिंह ने एक पत्र (अनुलग्नक IV) भेजा है जिसमें आर. जे. डी. का समर्थन नहीं करने के उनके निर्णय का संकेत दिया गया है।

या सरकार के गठन में एन. डी. ए.। वह मुझसे 2.3.2005 पर भी मिले थे।

7. श्री राम नरेश राम, सी. पी. आई. के नेता (एम. एल.-लिब), विधायक दल ने 4 अन्य लोगों के साथ मुझसे मुलाकात की और एक पत्र (अनुलग्नक V) प्रस्तुत किया कि वे सरकार के गठन में किसी भी समूह का समर्थन नहीं करेंगे। 8. एल. जे. पी. के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम विलास पासवान ने 15 अन्य लोगों के साथ मुझसे मुलाकात की और एक और पत्र (अनुलग्नक VI) प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने पहले के रुख को दोहराया है।

9. आर. जे. डी. ने मुझसे पूर्वाह्न में 5.3.2005 पर मुलाकात की और उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया जो निम्नलिखित के समर्थन का संकेत देता है। पार्टियाँ:

1. कांग. (आई)

10

;

2 . एनसीपी.

03

:

3 . सीपीआई. (एम)

01

:

02 (प्रतिलिपि के रूप में संलग्न

4 . बी एस पी।

एनेक्स। VII)

उपरोक्त के साथ आर. जे. डी. में केवल 91 होंगे।

उन्होंने आगे दावा किया है कि कुछ निर्दलीय सदस्य

आर. जे. डी. का समर्थन कर सकते हैं। हालाँकि, यह स्वतंत्र M.L.As की संख्या के बारे में खुलासा नहीं किया गया है, जिनसे वे समर्थन की उम्मीद करते हैं और न ही उनके नाम।

भले ही हम पूरे निर्दलीयों को कुल 17 का विस्तार करने के लिए मान लें

आर. जे. डी. गठबंधन को समर्थन, जिसकी संयुक्त ताकत 91 है, कुल 108 होगा, जो अभी भी न्यूनतम आवश्यकता से कम है।

243 के सदन में 122।

10. श्री सुशील कुमार मोदी, एम. पी. के नेतृत्व में एन. डी. ए. के प्रतिनिधिमंडल ने आई. डी. 1 की शाम को मुझसे मुलाकात की। उन्होंने आगे कोई पत्र जमा नहीं किया है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि उनके चुनाव पूर्व गठबंधन के अलावा सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

92 में से, अन्य 10 निर्दलीय भी उनका समर्थन करेंगे और उन्होंने आगे कहा कि वे अलग से पत्र जमा करेंगे। यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यह मानते हुए भी कि उनके पास 10 का समर्थन है निर्दलीयों की संख्या केवल 102 होगी, जो 122 की न्यूनतम आवश्यकता से कम है।

11. छह निर्दलीयों M.L.As. ने मुझसे 5.3.2005 पर मुलाकात की और एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है।

सरकार और वे दूसरों का समर्थन प्राप्त कर सकेंगे (अनुलग्नक)

VIII)। उन्होंने अपने दावे का समर्थन करने वाला कोई प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

12. मैंने विशेष रूप से कानूनी विशेषज्ञों और मामले के कानूनों से भी परामर्श किया है।

ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 1918 में रिपोर्ट किया गया मामला जहां उच्चतम न्यायालय ने रिपोर्ट के पैरा 365 में निष्कर्ष का सारांश दिया। प्रासंगिक भाग पैरा 2 है, अर्थात सरकारिया आयोग की सिफारिश

सभी संबंधित लोगों द्वारा गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्यपाल

चयन की प्रक्रिया में एक ऐसे नेता का चयन करना चाहिए जिसके अपने निर्णय में विधानसभा में बहुमत हासिल करने की सबसे अधिक संभावना हो। श्री वी. एन. शुक्ला द्वारा लिखित पुस्तक "भारत का संविधान" (10 वां संस्करण) भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 और 164 पर विचार करते हुए इस विषय पर चर्चा की गई है जिसमें राज्यपाल द्वारा चयन के तरीके को निम्नलिखित शब्दों में उद्धृत किया गया है:

" सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल को कोई संदेह नहीं होना चाहिए -

नियुक्त किए जाने के लिए उचित व्यक्ति कौन है; यह बहुमत का नेता है

विधानसभा में पार्टी, लेकिन परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं

जब यह संदेह हो कि वह नेता कौन है और राज्यपाल

सी. एम. के चयन में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना होगा।

संवैधानिक योजना जिसमें परिकल्पना की गई है कि एक व्यक्ति जो

विधानमंडल का विश्वास प्राप्त करने वाले को ही नियुक्त किया जाना चाहिए

सी. एम. के रूप में "।

पैरा 153 में ऊपर निर्दिष्ट बोम्मई मामले में एस. सी. ने उस स्थिति के संबंध में कहा है जहाँ, मैं उद्धृत करता हूँ:

" मान लीजिए कि आम चुनाव के बाद कोई राजनीतिक दल या

दलों या समूहों का गठबंधन पूर्ण बहुमत हासिल करने में सक्षम है।

विधान सभा में और राज्यपाल के अन्वेषण के बावजूद

विकल्प, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें कोई राजनीतिक नहीं है
पार्टी स्थिर सरकार बनाने में सक्षम है, यह रामेश्वर प्रसाद बनाम का मामला होगा।

0. 1 यू. [पासायत, जे।]

703

विधानमंडल के सदस्य। यह विफलता का मामला होगा
संवैधानिक तंत्र "।

13. मैंने सभी संभावनाओं का पता लगाया और ऊपर बताए गए तथ्यों से, मैं हूँ

इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि कोई भी राजनीतिक दल या दलों या समूहों का गठबंधन विधानसभा में बहुमत के दावे को साबित करने में सक्षम नहीं है।

और सभी राजनीतिक दलों और समूहों और निर्दलीयों के साथ विकल्पों का पता लगाने के बाद एक ऐसी स्थिति सामने आई है जिसमें कोई भी राजनीतिक दल या समूह सरकार बनाने में सक्षम नहीं प्रतीत होता है

सदन में बहुमत प्राप्त करना। इस प्रकार, यह किसी भी राजनीतिक दल की स्थिर सरकार बनाने में पूर्ण अक्षमता का मामला है

बहुसंख्यक सदस्यों का विश्वास बढ़ाना। यह संवैधानिक तंत्र की विफलता का मामला है।

14. बिहार के राज्यपाल के रूप में मैं एक लोकप्रिय सरकार बनाने में सक्षम नहीं हूं।

बिहार में, ऊपर बताए गए चुनाव परिणामों से उत्पन्न स्थिति के कारण।

15. इसलिए, मैं सिफारिश करता हूं कि वर्तमान नई संविधान सभा को वर्तमान के लिए निलंबित एनिमेशन में रखा जाए और भारत के राष्ट्रपति से अनुरोध किया जाता है कि वे आवश्यकता के अनुसार ऐसी उचित कार्रवाई/निर्णय लें।

संबंध में,

आपकी ईमानदारी

से,

i

(बुटा सिंह)

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

भारत के राष्ट्रपति,

राष्ट्रपति भवन,

नई दिल्ली।

डी. ओ. सं. 52/जी. बी. पटना, 27 अप्रैल, 2005

आदरणीय राष्ट्रपति जी,

मैं 6 मार्च को अपने डी. ओ. No.33/जी. बी. के लिए एक संदर्भ आमंत्रित करता हूं,

2005 जिसके माध्यम से विधानसभा चुनावों के परिणामों का विस्तृत विश्लेषण किया गया और नवगठित विधानसभा (चुनाव [2006] द्वारा गठित) 1 एस. सी. आर. को बनाए रखने की भी सिफारिश की गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिसूचना के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा No.G.S.R. 162 (E), दिनांक 7 मार्च, 2005 और घोषणा को संसद द्वारा अनुमोदित और अनुमोदित किया गया है।

2. चूंकि कोई भी दल या तो व्यक्तिगत रूप से या तत्कालीन चुनाव पूर्व संयोजन के साथ या चुनाव के बाद गठबंधन संयोजन के साथ एक लोकप्रिय सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकता था, जिसमें वे 243 सदस्यीय सदन में 122 के साधारण बहुमत का दावा कर सकते थे। उपरोक्त रिपोर्ट को उक्त सिफारिश के साथ भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

3. मुझे यह समझने के लिए दिया गया है कि जद-यू और भाजपा द्वारा बहुमत हासिल करने और सरकार बनाने का दावा करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।

यदि यह विभाजित नहीं होता है तो फिर भी यह मुख्य कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद निर्दलीय, राकांपा, बसपा और सपा के विधायकों और कांग्रेस के दो तिहाई विधायकों के समर्थन से सरकार बना सकता है। जद (यू) और भाजपा के विधायक इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि इस महीने के अंत तक या मई के पहले सप्ताह तक जद (यू) सरकार बनाने की स्थिति में होगी।

जद-यू/भाजपा के उच्च दबाव वाले कदम राजद के उन विधायकों को भी प्रभावित कर रहे हैं जो अशांत हो गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लालू प्रसाद पर राजद के विधायकों का बहुत दबाव है। यादव बिहार में केंद्र में यूपीए की तर्ज पर कांग्रेस, एलजेपी और अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनाना या उन्हें कम से कम

राज्य में राष्ट्रपति शासन की निरंतरता सुनिश्चित करना।

4. संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग ने यह भी देखा है कि निर्वाचित सरकारों की बढ़ती अस्थिरता के कारणों को गैर-सैद्धांतिक और

समय-समय पर अवसरवादी राजनीतिक पुनर्गठन। एक तर्कसंगत

सरकार की स्थिरता और एक मजबूत सरकार महत्वपूर्ण है। यह भी देखा गया है कि राजनीतिक दलों के सदस्यों के बदलते संरेखण से वास्तव में हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जाता है।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [पासायत। जे.]

705

संवैधानिक योजना के तहत एक राजनीतिक दल पहले जाता है

एक विशेष कार्यक्रम के साथ मतदाता और यह ऐसे कार्यक्रमों के आधार पर चुनाव में उम्मीदवारों की स्थापना करता है। संविधान की 10 वीं अनुसूची इस आधार पर पेश की गई थी कि राजनीतिक औचित्य

और नैतिकता की मांग है कि यदि ऐसे व्यक्ति चुनाव के बाद अपनी संबद्धता बदलते हैं, तो उन्हें हतोत्साहित किया जाना चाहिए। यह इस आधार पर है कि किसी पार्टी के प्रति वफादारी एक मानक है जो साझा मान्यताओं पर आधारित है। एक विभाजित पार्टी को मतदाता संदेह के साथ देखते हैं।

5. हाल के दिनों में समाचार पत्रों की रिपोर्ट और पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं/नेताओं के साथ बैठक के माध्यम से एकत्र की गई अन्य रिपोर्ट और मुझे प्राप्त खुफिया रिपोर्ट, लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर भी विभिन्न तत्वों को धन, जाति, पदों आदि जैसे विभिन्न प्रलोभनों के माध्यम से संपर्क करने की प्रवृत्ति का संकेत देती हैं, जो एक परेशान करने वाली विशेषता है। यह संवैधानिक प्रावधानों और बनाए गए सुरक्षा उपायों को प्रभावित करेगा।

उसमें। इस तरह का कोई भी कदम लोगों के फैसले को विकृत भी कर सकता है जैसा कि हाल के चुनावों के परिणामों से पता चलता है। यदि इन प्रयासों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो यह संवैधानिक प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ के बराबर होगा।

6. उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्थिति तेजी से एक ऐसे परिदृश्य की ओर बढ़ रही है जिसमें यदि इस प्रवृत्ति को तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता निर्वाचित विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रहे विभिन्न राजनीतिक दलों/समूहों द्वारा की जा रही खरीद-फरोख्त को और बढ़ावा देगी। हो सकता है कि ऐसा न हो

लोगों को नए सिरे से चुनाव के माध्यम से अपना जनादेश देने का एक और अवसर दिए बिना स्थिति को नियंत्रित करना संभव है।

7. मैं इन तथ्यों को माननीय राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि ऐसी कार्रवाई की जा सके जो उचित समझी जाए।

संबंध में,

आपकी ईमानदारी

से,

(बुटा सिंह)

[2006]

आई एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन,

नई दिल्ली "।

पटना, 21 मई, 2005

डी. ओ. सं. 140/पीएस-जी. बी./बी. एन.

आदरणीय राष्ट्रपति जी,

मैं 27 अप्रैल के अपने डी. ओ. पत्र संख्या 52/जी. बी. का संदर्भ आमंत्रित करता हूं।

2005 जिसके माध्यम से मैंने कुछ दलों, विशेष रूप से जद-यू और भाजपा द्वारा राज्य में बहुमत हासिल करने और सरकार बनाने का दावा करने के लिए किए गए प्रयासों का विस्तृत विवरण दिया था। मेरे पास था

उन्होंने बताया कि एलजेपी से संबंधित लगभग 16-17 विधायकों को विभिन्न तरीकों से लुभाया जा रहा था ताकि एलजेपी में विभाजन हो सके। इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया कि राजद विधायक "जद-यू द्वारा उठाए गए उपरोक्त कदमों के आलोक में अशांत हो गए थे।

जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी में विधानसभा चुनाव के बाद यह

वर्ष, कोई भी राजनीतिक दल या तो व्यक्तिगत रूप से या तत्कालीन चुनाव पूर्व संयोजन के साथ या चुनाव के बाद गठबंधन संयोजन के साथ नहीं

वे एक लोकप्रिय सरकार बनाने का दावा कर सकते थे क्योंकि वे 243 सदस्यीय सदन में 122 के साधारण बहुमत का दावा नहीं कर सकते थे। और इसलिए राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अधिसूचना सं. जीएसआर-162 (ई) दिनांक 7 मार्च 2005 और विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था।

एनिमेशन।

हाल के दिनों में मीडिया के माध्यम से मुझे जो रिपोर्टें मिली हैं

और विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के माध्यम से, साथ ही खुफिया रिपोर्ट भी, लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर जीत हासिल करने की प्रवृत्ति का संकेत देती है। एलजेपी के एक विधायक, जो पार्टी के महासचिव हैं, के आज इस्तीफा देने की भी रिपोर्ट मिली है और यह भी कि शायद अधिक लोग जद-यू की ओर बढ़ रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विभिन्न प्रलोभन दिए गए हैं जो एक बहुत ही परेशान करने वाला और खतरनाक विशेषता है। बहुमत हासिल करने और सरकार बनाने का दावा करने के लिए किसी भी अन्य दल के साथ गठबंधन करने के लिए अलग-अलग कदम उठाने से उसमें बनाए गए संवैधानिक प्रावधानों और सुरक्षा उपायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और लोगों के फैसले को विकृत किया जाएगा जैसा कि हाल के चुनावों के परिणामों से पता चलता है। यदि इन प्रयासों की अनुमति दी जाती है तो यह संवैधानिक प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ के बराबर होगा।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं

स्थिति को नियंत्रित करना संभव नहीं है। इसलिए मेरे विचार से राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य के हित में यह वांछनीय होगा कि विधानसभा को वर्तमान में निलंबित एनिमेशन में रखा जाए। भंग कर दिया गया, ताकि लोगों/मतदाताओं को उचित समय पर लोगों से जनादेश प्राप्त करने का एक और अवसर प्रदान किया जा सके।

संबंध में,

आपकी

ईमानदारी से।

एसडी /

(बुटा सिंह)

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

भारत के राष्ट्रपति,

राष्ट्रपति भवन,

नई दिल्ली।

हम सबसे पहले निर्णय के सार के बारे में प्रश्न पर विचार करेंगे।

माई का मामला (ऊपर)।

बोम्मई के मामले (ऊपर) में आए बयानों के सही सार और न्यायिक समीक्षा के दायरे के रूप में व्यक्त किए गए विचार के बारे में बहुत सारे तर्क दिए गए हैं। ए. के. कौल और अन्र में। वी. भारत संघ क्र. , [1995] 4 एस. सी. सी. 73, स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया गया था:

" 21. इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि एस. आर. बोम्मई में हालांकि सभी विद्वान न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 356 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है, लेकिन राष्ट्रपति की संतुष्टि के न्यायसंगत होने के मामले में, बहुमत (पांडियन, अहमदी, वर्मा अग्रवाल, योगेश्वर दयाल और जीवन रेड्डी, जे. जे.) का विचार यह है कि कानून द्वारा बनाए गए प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर किसी कार्रवाई की वैधता का निर्णय लेने के लिए बेरियम केमिकल्स में विकसित सिद्धांत, पूरी तरह से,

अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक शक्ति के प्रयोग पर लागू नहीं होते हैं। जीवन रेड्डी, जे. के निर्णय के आधार पर, जो सावंत, जे. द्वारा लिए गए निर्णय की तुलना में संकीर्ण दृष्टिकोण रखता है, यह कहा जा सकता है कि बहुमत (पांडियन, कुलदीप सिंह) का विचार है। सावंत, अग्रवाल और जीवन रेड्डी, जे. जे.) कहते हैं:

((i) के अधीन उद्घोषणा करते समय राष्ट्रपति की संतुष्टि

अनुच्छेद 356 (1) न्यायोचित है:

((ii) यह दुर्भावना के आधार पर चुनौती देने के लिए खुला होगा या

पूरी तरह से बाहरी और या अप्रासंगिक आधारों पर आधारित होना;
(iii) भले ही कुछ सामग्री जिन पर कार्रवाई की जाती है

अप्रासंगिक पाया गया, अदालत तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक

कार्रवाई को बनाए रखने के लिए कुछ प्रासंगिक सामग्री है;

((iv) सामग्री की सच्चाई या शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है
न्यायालय और न ही यह सामग्री की पर्याप्तता में जाएगा और यह

राष्ट्रपति की राय के स्थान पर भी नहीं;

(v) दुर्भावना का आधार अन्य स्थितियों में होता है जहाँ

(vi) न्यायालय सत्ता के दुरुपयोग या दुरुपयोग को हल्के में नहीं लेगा और
इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि राष्ट्रपति और संघ

मंत्रिपरिषद स्थिति का सबसे अच्छा न्यायाधीश है और वे

जानकारी और सामग्री के कब्जे में भी हैं और कि

संविधान ने इस मामले में अपने फैसले पर भरोसा किया है; और

((vii) इसका यह अर्थ नहीं है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद

वे मामले में अंतिम मध्यस्थ हैं या उनकी राय निर्णायक है।

यदि राजस्थान राज्य का मामला (ऊपर) और बोम्मई का मामला (ऊपर)

एक साथ पढ़ें तो यह स्पष्ट है कि बोम्मई के मामले में, राजस्थान राज्य के मामले (ऊपर) में निर्धारित न्यायिक समीक्षा का दायरा विस्तृत किया गया था जैसा कि ए. के. कौल के मामले (ऊपर) के सारांश से स्पष्ट है।

लॉर्ड ग्रीन ने 1948 में प्रसिद्ध वेड्सबरी मामले (1948 (1) के. बी. में कहा था

223) कि जब कोई क़ानून किसी प्रशासक को निर्णय लेने का विवेकाधिकार देता है, तो न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित रहेगा। उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप की अनुमति तब तक नहीं है जब तक कि निम्नलिखित शर्तों में से एक या दूसरी को पूरा नहीं किया जाता है, अर्थात् आदेश कानून के विपरीत था, या प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं किया गया था, या अप्रासंगिक कारकों पर विचार किया गया था; या निर्णय ऐसा था जिसे कोई भी उचित व्यक्ति नहीं ले सकता था। सिविल सेवा संघ परिषद में लॉर्ड डिप्लॉक बनाम। सिविल सेवा मंत्री (1983) आई. ए. सी. 768 (जिसे सी. सी. एस. यू. मामला कहा जाता है) ने प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों को निम्नलिखित में से एक या दूसरे पर आधारित किया। , अवैधता, प्रक्रियात्मक रामेश्वर प्रसाद बनाम।

0. 1 यू. [पासायत, जे।]

709

दुर्लभता और अतार्किकता। हालाँकि, उन्होंने कहा कि "आनुपातिकता" थी

इसकी संभावना है "।

ओम कुमार और ओआरएस में। वी. भारत संघ, [2001] 2 एस. सी. सी. 386, यह न्यायालय

एड, अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार:

" इस सिद्धांत की उत्पत्ति उन्नीसवीं शताब्दी में प्रशिया में हुई और

इसके बाद से जर्मनी, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में इसे अपनाया गया है। देशों। लक्समबर्ग में यूरोपीय न्यायालय और

स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने आवेदन किया है

प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता का निर्णय करते समय सिद्धांत। लेकिन यहाँ तक कि

उससे बहुत पहले, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को लागू किया था 1950 से विधायी कार्रवाई के लिए "आनुपातिकता", जैसा कि विस्तार से कहा गया है

नीचे।

"आनुपातिकता" से हमारा मतलब यह है कि क्या, जबकि

मौलिक अधिकारों के प्रयोग को विनियमित करना, उपयुक्त या न्यूनतम

उपायों का प्रतिबंधात्मक चयन विधायिका या द्वारा किया गया है प्रशासक ताकि विधान के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके या

प्रशासनिक आदेश का उद्देश्य, जैसा भी मामला हो। इसके तहत

सिद्धांत रूप में, अदालत देखेगी कि विधायिका और प्रशासनिक

प्राधिकरण "प्रतिकूल प्रभावों के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखता है जो

विधान या प्रशासनिक आदेश के अधिकार हो सकते हैं,

उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता या हित जो

वे सेवा करने के लिए थे "। विधायिका और प्रशासनिक

हालाँकि, प्राधिकरण को विवेक का एक क्षेत्र या एक सीमा दी जाती है

विकल्प लेकिन क्या किया गया विकल्प अधिकारों का उल्लंघन करता है

अत्यधिक या नहीं, यह अदालत के लिए है। इसका मतलब यह है कि आनुपातिकता।

XXX XXX XXX XXX

"सख्त जांच" के सिद्धांत का विकास या

" हालाँकि, इंग्लैंड में प्रशासनिक कानून में "आनुपातिकता" हाल ही में है। प्रशासनिक कार्रवाई का पारंपरिक रूप से बुधवार को परीक्षण किया जा रहा था।

आधार। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, प्रशासनिक कार्रवाई ने प्रभावित किया
अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता की स्वतंत्रता को कई राज्यों में अमान्य घोषित किया गया है।

"सख्त जांच" के सिद्धांत को लागू करने वाले मामले। इन मामलों में

स्वतंत्रता, वेड्सबरी सिद्धांत अब लागू नहीं होते हैं। अदालतें

इंग्लैंड में स्पष्ट रूप से अनुपस्थिति में आनुपातिकता लागू नहीं कर सका

लेकिन [2006] 1 एस. सी. आर. के साथ व्यवहार करके उत्साहपूर्वक अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश की।

उक्त अधिकार सामान्य कानून के लिए बुनियादी हैं और अदालतों ने तब सख्त जांच परीक्षण लागू किया। स्पाईकैचर मामले में महान्यायवादी बनाम। गार्जियन न्यूजपेपर्स लिमिटेड (संख्या 2) (1990) 1 एसी 109 (पीपी पर। 283 284), लॉर्ड गोफ ने कहा कि सम्मेलन और सामान्य कानून के बीच कोई विसंगति नहीं थी। डर्बीशायर काउंटी परिषद बनाम। टाइम्स न्यूजपेपर्स लिमिटेड, (1993) एसी 534, लॉर्ड कीथ ने स्वतंत्रता का इलाज किया।

सामान्य कानून के हिस्से के रूप में अभिव्यक्ति। हाल ही में आर. वी. सिकरी। गृह विभाग के लिए राज्य।, पूर्व पी। सिम्स, [1999] 3 ऑल ई. आर. 400 (एच. एल.), एक कैदी के एक पत्रकार को साक्षात्कार देने के अधिकार को बरकरार रखा गया था।

मौलिक मानवाधिकारों से जुड़े निर्णयों पर आर. वी. में फिर से जोर दिया गया। लॉर्ड सेविल एक्स पी। [1999] 4 सभी ईआर 860 सीए, पीपी पर। 870 , 872) . इन सभी मामलों में, अंग्रेजी न्यायालयों ने परीक्षण को "आनुपातिकता" के रूप में वर्णित करने के बजाय "सख्त जांच" परीक्षण लागू किया। लेकिन, इसमें

इन अधिकारों के संबंध में कोई भी घटना "वेड्सबरी" नियम समाप्त हो गया है

आवेदन करें

हालांकि, "सख्त जांच" या "आनुपातिकता" का सिद्धांत

और प्राथमिक समीक्षा आर. वी. में समझाई गई। सिकरी। गृह विभाग के लिए राज्य का। एक्स पी ब्रिंड (1991) 1 एसी 696। वह मामला प्रसारण अधिनियम, 1981 के तहत गृह सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों से संबंधित था, जिसमें बी. बी. सी. और आई. बी. ए. को कुछ प्रसारणों से बचने की आवश्यकता थी। आतंकवाद की रोकथाम से संबंधित कानून के तहत प्रतिबंधित संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के माध्यम से मामले। निषेध की सीमा को संगठनों के सदस्यों द्वारा दिए गए सीधे बयान से जोड़ा गया था। हालाँकि, उदाहरण के लिए, यह ऐसे व्यक्तियों द्वारा फिल्म के माध्यम से प्रसारण को प्रतिबंधित नहीं करता था, बशर्ते कि उनके द्वारा कही गई बातों की व्याख्या करते हुए एक "वॉयस-ओवर" विवरण हो। आवेदक का दावा सीधे मानवाधिकारों के यूरोपीय सम्मेलन पर आधारित था। लॉर्ड ब्रिज ने देखा कि कन्वेंशन के अधिकारों को अभी भी स्पष्ट रूप से अंग्रेजी कानून में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सामान्य कानून के लिए बुनियादी थी और कन्वेंशन के अभाव में भी, अंग्रेजी अदालतें प्रश्न में जा सकती थीं (पी देखें। 748-49) .

" ..... क्या राज्य सचिव, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए,

उचित रूप से उस पर प्रतिबंध लगा सकता है जो उसने लगाया है
प्रसारण संगठनों के रामेश्वर प्रसाद बनाम।

यू. ओ. एल [पासायत। जे.)

711

और कि अदालतें थीं

" इस आधार से शुरू करने का पूरी तरह से हकदार नहीं है कि कोई प्रतिबंध

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को उचित ठहराने की आवश्यकता है और
एक महत्वपूर्ण लोक हित से कम कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा

इसे उचित ठहराएँ "।

लॉर्ड टेम्पलमैन ने उपरोक्त मामले में यह भी कहा कि अदालतें जा सकती हैं।

इस सवाल में कि क्या एक उचित मंत्री उचित रूप से हो सकता है निष्कर्ष निकाला कि इस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप उचित था। वह.

कहा कि "समझौते के संदर्भ में" इस तरह का कोई भी हस्तक्षेप होना चाहिए

आवश्यक और आनुपातिक दोनों (आईबीआईडी पीपी। 750-51) .

प्रसिद्ध मार्ग में, प्राथमिक के सिद्धांत के बीज और

अदालतों द्वारा द्वितीयक समीक्षा को प्रशासनिक कानून में लगाया गया था लार्ड ब्रिज इन द ब्रिंड केस (1991) 1 एसी 696। कहाँ सम्मेलन

अधिकारों पर सवाल थे कि अदालतें प्राथमिक अधिकार का प्रयोग कर सकती थीं।

समीक्षा करें। हालांकि, अदालतें माध्यमिक अधिकार का प्रयोग करेंगी।

प्रभावित न करने वाले मामलों में केवल वेड्सबरी सिद्धांतों पर आधारित समीक्षा

समझौते के तहत अधिकार। ऐसे मामलों की ओर रुख करना जहां बुनियादी

स्वतंत्रता का उपयोग नहीं किया गया था और जहां प्रशासनिक कार्रवाई की गई थी

सवाल किया गया, यह कहा गया कि अदालतें तब केवल एक तक ही सीमित थीं

द्वितीयक समीक्षा जबकि प्राथमिक निर्णय के साथ होगा

प्रशासक। लॉर्ड ब्रिज ने प्राथमिक और माध्यमिक समीक्षा की व्याख्या की। इस प्रकार है:

> " इस बारे में प्राथमिक निर्णय कि क्या विशेष प्रतियोगी
>
> लगाए गए विशेष प्रतिबंध को उचित ठहराते हुए जनहित
>
> राज्य सचिव द्वारा बनाया जाना चाहिए जिसे संसद ने
>
> विवेकाधिकार सौंपा। लेकिन, हम एक माध्यमिक अभ्यास करने के हकदार हैं
>
> यह पूछकर निर्णय कि क्या राज्य का एक उचित सचिव, पर
>
> उसके सामने की सामग्री, यथोचित रूप से प्राथमिक बना सकती थी
>
> फैसला "।

भारत संघ और ए. एन. आर. वी. जी. गनयुथम, [1997] 7 एस. सी. सी. 463, ए. एफ. 31 में इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

" 31. प्रशासनिक कानून में आनुपातिकता की वर्तमान स्थिति

इंग्लैंड और भारत को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

(1) किसी भी प्रशासनिक आदेश या वैधानिक की वैधता का न्याय करना।

विवेकाधिकार, आम तौर पर यह पता लगाने के लिए वेड्सबरी परीक्षण लागू किया जाना है

यदि निर्णय अवैध था या प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से पीड़ित था [2006] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत इस बात पर विचार करेगी कि क्या प्रासंगिक मामलों को ध्यान में नहीं रखा गया था या क्या अप्रासंगिक मामलों को ध्यान में रखा गया था या क्या कार्रवाई प्रामाणिक नहीं थी। अदालत इस बात पर भी विचार करेगी कि क्या निर्णय बेतुका था या विकृत। अदालत ने ऐसा नहीं किया

हालाँकि द्वारा किए गए चयन की शुद्धता में जाएँ

उनके लिए खुले विभिन्न विकल्पों में से एक प्रशासक है। न ही अदालत अपने फैसले को प्रशासक के फैसले से बदल सकती थी। यह वेड्सबरी (1948 1 KB 223) परीक्षण है।

(2) अदालत प्रशासक के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

जब तक कि यह अवैध था या प्रक्रियात्मक अनुचितता से पीड़ित था या था

इस अर्थ में तर्कहीन कि यह तर्क या नैतिक मानकों की अपमानजनक अवज्ञा थी। आनुपातिकता सहित अन्य परीक्षणों की संभावना

भविष्य में अंग्रेजी प्रशासनिक कानून में लाए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये सी. सी. एस. यू. (1985 ए. सी. 374) सिद्धांत हैं।

(3) (क) बगडेके (1987 एसी 514), ब्रिंड (1991 (1) एसी 696) और स्मिथ (1996 (1) ऑल ईआर 257) के अनुसार जब तक कन्वेंशन नहीं है। अंग्रेजी कानून में शामिल, अंग्रेजी अदालतें केवल यह पता लगाने के लिए एक द्वितीयक निर्णय का प्रयोग करती हैं कि

क्या निर्णय निर्माता, अपने सामने की सामग्री पर, इस तरह से प्राथमिक निर्णय पर पहुंच सकता था

उन्होंने किया है।

(3) (ख) यदि समझौते को इंग्लैंड में शामिल किया जाता है।

और पता लगाएँ कि क्या प्रतिबंध असमान है या अत्यधिक है या मौलिक स्वतंत्रता और आवश्यकता के उचित संतुलन पर आधारित नहीं है उस पर प्रतिबंध के लिए।

(4) (क) हमारे देश में प्रशासनिक कानून की स्थिति, जहाँ

जैसा कि ऊपर कहा गया है, कोई भी मौलिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है, यह है कि अदालतें/न्यायाधिकरण केवल एक गौण भूमिका निभाएंगे, जबकि तर्कसंगतता के बारे में प्राथमिक निर्णय कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण के पास रहेगा। अदालत का द्वितीयक निर्णय वेड्सबरी और सी. सी. एस. यू. सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए जैसा कि क्रमशः लॉर्ड ग्रीन और लॉर्ड डिप्लॉक ने कहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण प्राथमिक प्राधिकरण के रूप में अपने निर्णय पर यथोचित रूप से पहुंचा है।

713

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

इन सभी निर्णयों में आम धागा यह है कि

न्यायालय को प्रशासक के निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह अतार्किक न हो या प्रक्रियात्मक अनुचितता से ग्रस्त न हो या न्यायालय की अंतरात्मा के लिए चौंकाने वाला न हो, इस अर्थ में कि यह तर्क या नैतिकता की अवज्ञा में था।

मानक। वेड्सबरी के मामले (ऊपर) में जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा किए गए चयन की शुद्धता पर विचार नहीं करेगा।

प्रशासक उसके लिए खुला है और न्यायालय को अपने निर्णय को प्रशासक के निर्णय से प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। न्यायिक समीक्षा का दायरा निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी तक सीमित है न कि निर्णय तक।

वेड के अनुसार, प्रशासनिक कानून (9 वां संस्करण) संबंधित कानून है।

कार्यकारी अधिकारियों की शक्तियों के नियंत्रण के लिए। इस बात पर विचार करने के लिए कि ऐसा कानून क्यों आवश्यक हो गया, हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार करना होगा।

19 वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में राज्य के कार्य थे

(i) विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा, और (ii) देश के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित।

राज्य के कार्यों में इस विशाल विस्तार के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में

विधान और संसद द्वारा राज्य के कार्यों के व्यापक प्रत्यायोजन के लिए भी कार्यकारी प्राधिकरणों के लिए, इसलिए जनहित में इस नई स्थिति में राज्य प्राधिकरणों को प्रदान की गई इन नई शक्तियों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने और रोकने के लिए कानूनी सिद्धांतों का एक निकाय बनाने की भी आवश्यकता थी। इस प्रकार, उभरा

प्रशासनिक कानून। मैटलैंड ने अपने संवैधानिक इतिहास में बताया:

" साल दर साल इंग्लैंड की अधीनस्थ सरकार बनती जा रही है।

अधिक से अधिक महत्वपूर्ण। हम एक बहुत शासित राष्ट्र बन रहे हैं,

सभी प्रकार की परिषदों और बोर्डों और अधिकारियों द्वारा शासित, केंद्रीय

और स्थानीय, उच्च और निम्न, शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो किया गया है

आधुनिक कानूनों द्वारा उनके प्रति वचनबद्ध।

लेकिन 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में डाइसी की क्लासिक परंपरा का पालन करते हुए

उनकी प्रस्तुति: संविधान का कानून, संसदीय प्रतिनिधिमंडल पर हमलों की एक श्रृंखला थी जो 1929 में प्रकाशित इंग्लैंड के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड हेवर्ट की पुस्तक न्यू डेस्पॉटिज्म में समाप्त हुई। जवाब में, 1932 में ब्रिटिश सरकार ने इन शिकायतों और आलोचनाओं की जांच करने के लिए लॉर्ड डोनफमोर की अध्यक्षता में मंत्रिस्तरीय शक्तियों पर समिति नामक एक समिति का गठन किया। हालाँकि, डोनफमोर समिति ने लॉर्ड हेवर्ट के तर्क को खारिज कर दिया और इस वास्तविकता को स्वीकार किया कि एक आधुनिक राज्य काम नहीं कर सकता है। कार्यकारी अधिकारियों को विशाल शक्तियों के प्रत्यायोजन के बिना, हालांकि उन पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए।

आर. वी. में लंकाशायर सीसी, पूर्व पी हडलस्टन [1986] 2 ऑल ईआर 941 सीए, यह

प्रशासनिक कानून के बारे में कहा गया था कि

" अदालतों और उन लोगों के बीच एक नया संबंध बनाया है जो

सार्वजनिक कानून से अपना अधिकार प्राप्त करें, जो साझेदारी आधारित है।

एक सामान्य उद्देश्य पर, अर्थात्, उच्चतम मानकों का रखरखाव

लोक प्रशासन "।

लिवर्जिज वी. एंडरसन [194] 3 ऑल ई. आर. 338 (एच. एल.) मामला

रक्षा (सामान्य) विनियम, 1939 से संबंधित जो प्रदान करता है:

" यदि राज्य सचिव के पास किसी पर विश्वास करने का उचित कारण है

शत्रुतापूर्ण मूल या संघ का व्यक्ति वह आदेश दे सकता है

उस व्यक्ति के खिलाफ जो उसे हिरासत में लेने का निर्देश दे रहा है।

बंदी लिवरजिज ने उनके खिलाफ पारित निरोध आदेश को चुनौती दी

राज्य सचिव द्वारा। लॉर्ड एटकिन को छोड़कर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बहुमत ने माना कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि के सचिव

राज्य ने अपने आदेश में उल्लेख किया था कि उनके पास यह मानने का उचित कारण था कि लिवर्जिज शत्रुतापूर्ण मूल या संगठन का व्यक्ति था। लिवर्जिज था

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब कार्यकारी प्राधिकरण के पास किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की बेलगाम शक्तियां थीं, तब भी अदालत को यह बताए बिना कि सचिव किस आधार पर

अपने विश्वास पर पहुंचे थे। हालांकि, बाद में, ब्रिटिश अदालतों ने लॉर्ड एटकिन के असहमत दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया कि कुछ प्रासंगिक सामग्री होनी चाहिए जिसके आधार पर राज्य सचिव की संतुष्टि का गठन किया जा सकता है। इसके अलावा, विवेकाधिकार का प्रयोग उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे प्रदान किया गया था और जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की इच्छा की गई थी, और इसका प्रयोग क़ानून के चार कोनों के भीतर किया जाना चाहिए (देखें - क्लैरियंट इंटरनेशनल लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, [2004] 8 एस. सी. सी. 524)

कभी-कभी एक शक्ति को कर्तव्य के साथ जोड़ा जाता है। इस प्रकार, एक सीमित न्यायिक

प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ समीक्षा हमेशा न्यायालयों के लिए उपलब्ध होती है। बोम्मई के मामले (ऊपर) में विस्तार के बाद भी राज्यपालों की कार्रवाई के संबंध में न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश को अन्य प्रशासनिक आदेशों के समान नहीं रखा जा सकता है। जैसा कि बोम्मई के मामले (ऊपर) में फैसले के पैरा 376 में देखा गया है, न्यायिक समीक्षा का दायरा दिए गए मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। ऐसे मामले हो सकते हैं जो न्यायिक पूर्वानुमान को स्वीकार नहीं करते हैं। जब किसी प्रशासनिक कार्रवाई को चुनौती दी जाती है तो जो सिद्धांत लागू होते हैं, उन्हें अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा के संबंध में की गई चुनौतियों के लिए सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, रामेश्वर प्रसाद v में स्पष्ट रूप से जो देखा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए।

यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

715

बोम्मई का मामला (ऊपर), अनुच्छेद 356 (1) के तहत घोषणा विधायी नहीं है चरित्र में।

विवेक के साथ सौंपे गए व्यक्ति को, कहने के लिए, खुद को निर्देशित करना चाहिए।

कानून में ठीक है। उसे उन मामलों की ओर ध्यान देना चाहिए जिन पर वह बाध्य है।

विचार करें। उसे उन मामलों को अपने विचार से बाहर करना चाहिए जो उस पर विचार करने के लिए अप्रासंगिक हैं। यदि वह उन नियमों का पालन नहीं करता है तो वह वास्तव में हो सकता है

कहा जाता है कि वह अनुचित तरीके से काम कर रहा है। इसी तरह, कुछ इतना बेतुका हो सकता है

कि कोई भी समझदार व्यक्ति कभी सपने में भी नहीं देख सकता था कि यह उसकी शक्तियों के भीतर है।

प्राधिकरण।

यह कानून का एक अलिखित नियम है, संवैधानिक और प्रशासनिक, कि

केवल प्रासंगिक और निकटवर्ती मामलों के लिए, अप्रासंगिक और दूरस्थ। (देखिए: श्रीमती. शालिनी सोनी और ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य। , [1980] 4 एससीसी 544)।

वेड्सबरी सिद्धांत को अक्सर गलत समझा जाता है कि कोई भी

न्यायालय द्वारा अनुचित माने जाने वाले प्रशासनिक निर्णय को निरस्त किया जाना चाहिए। वेड्सबरी सिद्धांत की सही समझ यह है कि एक निर्णय को वेड्सबरी अर्थ में अनुचित कहा जाएगा यदि

((i) यह पूरी तरह से अप्रासंगिक सामग्री या पूरी तरह से अप्रासंगिक विचार पर आधारित है, (ii) इसने एक बहुत ही प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी की है जिसे उसे ध्यान में रखना चाहिए था, या (iii) यह इतना बेतुका है कि कोई भी समझदार व्यक्ति कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकता था।

जैसा कि सी. सी. एस. यू. के मामले (ऊपर) में लॉर्ड डिप्लॉक द्वारा देखा गया है, एक निर्णय होगा

कहा जा सकता है कि वेड्सबरी अनुचितता से पीड़ित है यदि यह "तर्क या स्वीकृत नैतिक मानकों की अवज्ञा में इतना अपमानजनक है कि कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं है जिसने तय किए जाने वाले प्रश्न पर अपना दिमाग लगाया था, वह उस पर पहुंच सकता था।

संविधान एक अद्वितीय कानूनी दस्तावेज है। यह एक विशेष प्रकार को स्थापित करता है।

मानक और मानक पिरामिड के शीर्ष पर खड़ा है। संशोधन करना मुश्किल है, इसे आने वाले वर्षों के लिए मानव व्यवहार को निर्देशित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पूरे इतिहास में राज्य के स्वरूप और उसकी आकांक्षाओं को आकार देता है। यह राज्य के मौलिक राजनीतिक विचारों को निर्धारित करता है। यह अपने सामाजिक मूल्यों की नींव रखता है। यह अपनी

प्रतिबद्धताओं और अभिविन्यासों को निर्धारित करता है। यह अतीत की घटनाओं को दर्शाता है। यह वर्तमान की नींव रखता है। यह निर्धारित करता है कि भविष्य कैसा दिखेगा। यह दर्शन, राजनीति, समाज और कानून सभी एक हैं।

संविधान द्वारा इन सभी कार्यों के लिए अपने व्यक्तिपरक संतुलन की आवश्यकता होती है और वस्तुनिष्ठ तत्व, क्योंकि "यह एक संविधान है जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं।" के रूप में

कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डिक्सन ने कहा:

" संविधान की व्याख्या करने का कार्य उससे काफी अलग है।

एक कानून का अर्थ लगाने के लिए। एक क़ानून वर्तमान अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करता है।

इसे आसानी से लागू किया जाता है और उतनी ही आसानी से निरस्त किया जाता है। एक संविधान, इसके विपरीत,

भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। इसका कार्य एक प्रदान करना है

इसके प्रावधानों को आसानी से निरस्त या संशोधित नहीं किया जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि -
नए समाज से मिलने के लिए समय के साथ विकास और विकास में सक्षम होना,

राजनीतिक और ऐतिहासिक वास्तविकताएँ अक्सर इसके निर्माताओं द्वारा अकल्पित होती हैं। द.

न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है और व्याख्या करने में आवश्यक है।

इसके प्रावधानों को ध्यान में रखें।

राजनीतिक प्रश्न सिद्धांत, विशेष रूप से, जनता के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है।

कांग्रेस और राष्ट्रपति के लिए जीवन, इस आधार पर कि संविधान इन क्षेत्रों के लिए अन्य शाखाओं को जिम्मेदारी सौंपता है, या कि उनके संकल्प में विवेकाधीन, बहु-केंद्रित निर्णय शामिल होंगे जिनमें निर्णय के लिए असतत मानदंडों का अभाव है और इस प्रकार अधिक लोकतांत्रिक शाखाओं द्वारा बेहतर तरीके से संभाला जाता है। न्यायिक समीक्षा को स्थगित करके, यहां तक कि राजनीतिक शाखाओं के विवेकाधीन विकल्पों की न्यूनतम तर्कसंगतता के बारे में भी, यह सिद्धांत संघीय न्यायाधीशों को महत्वपूर्ण रूप से "हमारे सार्वजनिक मूल्य को उचित अर्थ देने" में भूमिका से वंचित करता है।

मैदान। (हार्वर्ड लॉ रिव्यू के एक लेख से उद्धृत)।

लोकतांत्रिक सिद्धांत मानव गरिमा की धारणा पर आधारित है: प्राणियों के रूप में

अपने स्वभाव के कारण सम्मान के योग्य, वयस्कों को बड़ी मात्रा में स्वायत्तता का आनंद लेना चाहिए, जो कि आधुनिक दुनिया में मुख्य रूप से प्राप्त करने योग्य स्थिति है।

अपने समुदाय के शासन में भाग लेने में सक्षम होना। चूंकि प्रत्यक्ष शासन नागरिकों के लिए संभव नहीं है, इसलिए अधिकांश लोग स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों को अधिकार सौंपकर ही स्वशासन में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार न्यायमूर्ति ह्यूगो एल. ब्लैक ने लोकतांत्रिक सिद्धांत के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को व्यक्त किया जब उन्होंने लिखा: एक स्वतंत्र देश में कानून बनाने वालों के चुनाव में आवाज उठाने से अधिक मूल्यवान कोई अधिकार नहीं है।

हमे जीना चाहिए। "

लोकतांत्रिक सिद्धांत के लिए, क्या सरकारी निर्णयों को नैतिक रूप से बनाता है

बाध्यकारी प्रक्रिया है: जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि, उन प्रतिनिधियों की बहस और नीति को लागू करना और बाद में फिर से चुनाव के लिए खड़े होना, रामेश्वर प्रसाद v.

यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

717

और उस नीति को लागू करने वाले प्रशासक। इसलिए, लोकतांत्रिक सिद्धांत सकारात्मकवाद और नैतिक सापेक्षवाद दोनों को अपनाता है।

जबकि लोकतांत्रिक सिद्धांत नैतिक सापेक्षवाद, संविधानवाद की ओर मुड़ता है।

नैतिक यथार्थवाद की ओर मुड़ता है। यह मानता है कि सार्वजनिक नीतियां मानव गरिमा का उल्लंघन करती हैं या नहीं, यह तय करने के लिए "वहाँ से" खोज योग्य मानक छिपे हुए हैं। किसी नीति की वैधता केवल निर्णय निर्माताओं की प्रामाणिकता पर निर्भर नहीं करती है।

प्रमाण-पत्र लेकिन मूल मानदंडों पर भी। उत्साहपूर्ण आग्रह के बावजूद भी

विशाल बहुमत में से जिनके प्रतिनिधियों ने उचित प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक पालन किया है, सरकार मौलिक अधिकारों को रौंद नहीं सकती है। के लिए

संविधानवादियों, राजनीतिक नैतिकता को उस पैमाने पर नहीं तौला जा सकता है जिसमें "राय एक सर्वशक्तिमान है", केवल पवित्र के नैतिक मानदंड के खिलाफ, व्यक्तिगत अधिकार। वे जाफरसन से सहमत हैं: " एक वैकल्पिक तानाशाही वह सरकार नहीं थी जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। "(वाल्टर एफ. मर्फी द्वारा संविधान, संविधानवाद और लोकतंत्र से)

बिना किसी समर्थन योग्य आधार के दुर्भावना का आरोप अंतिम कमजोर है।

एक हारे हुए वादी का प्रयास, अन्यथा यह एक स्मोकस्क्रीन बनाएगा

न्यायिक समीक्षा का दायरा। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके आसपास इसका भाग्य है।

मामला घूमता है। जैसा कि ए. के. कौल के मामले (ऊपर) में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायसंगत है। यह माला के आधार पर चुनौती देने के लिए खुला होगा।

पूरी तरह से बाहरी या अप्रासंगिक आधारों पर आधारित होना। रिपोर्ट में दर्शाई गई तथ्यात्मक स्थिति की पर्याप्तता या शुद्धता न्यायिक समीक्षा के लिए खुली नहीं है। सामग्री की सच्चाई या शुद्धता नहीं हो सकती है।

न्यायालय द्वारा प्रश्न किया जाएगा और न ही वह सामग्री की पर्याप्तता में जाएगा और यह राष्ट्रपति की राय के स्थान पर अपनी राय भी नहीं लेगा। हस्तक्षेप

केवल तभी बुलाया जाता है जब सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला हो या कुछ ऐसा हो

समय को सत्ता पर धोखाधड़ी कहा जाता है। न्यायालय शक्ति के दुरुपयोग या दुरुपयोग को हल्के में नहीं लेगा और इस तथ्य के लिए छूट देगा कि निर्णय लेने वाला प्राधिकारी स्थिति का सबसे अच्छा न्यायाधीश है। यदि राज्यपाल ने किसी को दावा करने से रोकने के एकमात्र उद्देश्य से विघटन के लिए अपनी राय बनाई होती तो यह स्पष्ट रूप से अनावश्यक और तर्कहीन होता। यह सवाल कि क्या ऐसा व्यक्ति एक स्थिर सरकार बनाने की स्थिति में होगा, अनिवार्य रूप से राज्यपाल की व्यक्तिपरक राय है; निश्चित रूप से वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित है। इसलिए मूल मुद्दा यह है कि राज्यपाल ने

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि स्थिर सरकार की कोई संभावना नहीं थी, बाहरी और अप्रासंगिक सामग्रियों पर कार्य करना।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सवाल यह था कि क्या कोई था

प्रलोभन या हॉर्स ट्रेडिंग (ऐसे मामलों में अक्सर उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति) या

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

718

किसी भी प्रकार का प्रलोभन ऐसा मामला नहीं है जिस पर राज्यपाल विचार कर सके। राज्यपाल के निर्णय की न्यायिक समीक्षा का दायरा किसी अन्य प्रशासनिक निर्णय के समान नहीं है और न ही हो सकता है। लगभग सभी कानूनी पूछताछों में उद्देश्य से अलग इरादे ही सब कुछ है। महत्वपूर्ण कारक और आम बोलचाल में एक दुर्भावनापूर्ण कार्य बिना किसी कारण या बहाने के जानबूझकर किए गए कार्य के बराबर है। जबकि निष्पक्षता पर्यायवाची है।

"द्वेष" शब्द के विशेषताओं और व्यापक दायरे के भीतर तर्कसंगतता पूर्वाग्रह स्टैंड शामिल है, जो आम स्वीकृति में "बावजूद" या "बुरी इच्छा" का तात्पर्य है। दुर्भावना के संकेत के उद्देश्य से केवल सामान्य बयान पर्याप्त नहीं होंगे। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर ठोस सबूत उपलब्ध होने चाहिए कि क्या वास्तव में इसमें पक्षपात या दुर्भावना शामिल थी जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई। वास्तविक संभावना और उचित संदेह के परीक्षण वास्तव में एक दूसरे के साथ असंगत हैं। (एस. पार्थसारथी बनाम देखें। एपी राज्य, [1974] 3 एससीसी 459)। 'पक्षपात' शब्द समान रूप से प्रदत्त न्याय की स्थिति से प्रस्थान को दर्शाता है। (देखिए: फ्रैंकलिन वी। नगर और देश योजना मंत्री [1947] 2 सभी ई. आर. 289 (एच. एल.)।

पंजाब राज्य में बनाम। वी. के. खन्ना और अन्य।, [2001] 2 एस. सी. सी. 330, यह निम्नानुसार देखा गया:

" संयोग से, फ्रैंकलिन बनाम में लॉर्ड थैंकर्टन। नगर और देश योजना मंत्री, (1948 अधिनियम 87: [1947] 2 ऑल ई. आर. 289 (एच. एल.) ने राय दी कि "पक्षपात" शब्द समान न्याय की स्थिति से प्रस्थान को दर्शाता है। कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड बनाम। गिरजा

शंकर मामला [2001] 1 एस. सी. सी. 182 ने आगे अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित तरीके से अलग-अलग टिप्पणी का उल्लेख किया: (एससीसी पीपी। 199 201 , पैरा 30-34)

" 30. हालाँकि, हाल ही में, अंग्रेजी अदालतों ने एक अलग टिप्पणी की है, हालांकि यह पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन स्वचालित अयोग्यता सिद्धांत नियम कुछ हद तक कमजोर है। हालाँकि इस दुर्बलता की पुष्टि मुद्दे के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। आर. वी. के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स। बो स्ट्रीट मेट्रोपॉलिटन वजीफा मजिस्ट्रेट, पूर्व पी पिनोचेट उगार्ते

(संख्या 2) (2000) 1 ए. सी. 119) ने देखा:

' ..... दीवानी मुकदमेबाजी में मुद्दे के मामलों का आम तौर पर आर्थिक प्रभाव पड़ता है; इसलिए एक न्यायाधीश स्वचालित रूप से अयोग्य हो जाता है यदि वह मामले के अपने फैसले के परिणामस्वरूप वित्तीय लाभ करने के लिए खड़ा होता है: लेकिन अगर, जैसा कि वर्तमान मामले में है, 719 पर मामला

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. 1. [पासायत। जे.]

मुद्दा धन या आर्थिक लाभ से संबंधित नहीं है लेकिन है

कारण के प्रचार से संबंधित, तर्क

न्यायाधीश को अयोग्य ठहराना उतना ही लागू होता है जितना न्यायाधीश का निर्णय लागू होता है।

एक ऐसे कारण को बढ़ावा देगा जिसमें न्यायाधीश शामिल है

दलों में से एक के साथ।

31. लॉर्ड ब्राउन-विल्किंसन पी। 136 रिपोर्ट में कहा गया है:

' यह महत्वपूर्ण है कि जो तय किया जा रहा है उसे बढ़ा-चढ़ाकर न कहें। यह था।

तर्क में सुझाव दिया कि के आदेश को अलग रखने का निर्णय

25-11-1998 एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाएगा जहाँ न्यायाधीश होंगे
दान से जुड़े मामलों पर बैठने में असमर्थ जिनके काम में वे हैं

शामिल हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि इस तरह की भागीदारी के कारण, ए

न्यायाधीश को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह बात सही नहीं है। इस बात के तथ्य

वर्तमान मामला असाधारण है। महत्वपूर्ण तत्व हैं (1) कि

ए. आई. अपील का एक पक्ष था; (2) कि ए. आई. को क्रम में जोड़ा गया था

एक विशेष परिणाम के लिए बहस करना; (3) न्यायाधीश एक के निदेशक थे

चैरिटी ए. आई. से निकटता से संबद्ध है और इस संबंध में ए. आई. को साझा कर रहा है।

वस्तुएँ। केवल उन मामलों में जहां एक न्यायाधीश सक्रिय भूमिका निभा रहा है
किसी दान संस्था का न्यासी या निदेशक जो उससे निकटता से संबद्ध है और

मुकदमे में एक पक्ष के साथ कार्य करने वाले न्यायाधीश को आम तौर पर होना चाहिए

या तो खुद को अलग करने या पद का खुलासा करने के लिए चिंतित

पार्टियाँ। हालाँकि, अन्य अपवादात्मक मामले भी हो सकते हैं।
जिसे न्यायाधीश को अच्छी तरह से संभावित खुलासा करने की सलाह दी जाएगी

रुचि "।

32. लार्ड हटन ने भी पिनोशे मामले (2000) 1 एसी 119) में कहा:

' ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें न्यायाधीश का हित

विषय-उसके कठोर दंड से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही का मामला

किसी कारण या विश्वास के प्रति प्रतिबद्धता या किसी के साथ उसका संबंध

कार्यवाही में शामिल व्यक्ति या निकाय जनता को हिला सकता है

न्याय के प्रशासन में उतना ही विश्वास जितना कि

किसी सार्वजनिक कंपनी में हिस्सेदारी (जो छोटी हो सकती है)
मुकदमे में "।

33. संयोग से लोकबैल [लोकबैल (यू. के.) लिमिटेड बनाम। बेफील्ड प्रॉपर्टीज लिमिटेड, (2000)] क्यू. बी. 451 आर. वी. में अक्सर उद्धृत निर्णय के विस्तृत विश्लेषण पर अपील न्यायालय। गफ (1993 एसी 646) डाइम्स मामले के साथ (डाइम्स बनाम। ग्रैंड जंक्शन कैनाल, (1853) 3 एचएल कैस 759: 10 ई. आर. 301), पिनोचेट मामला (2000) आई. ए. सी. 119), जे. आर. एल., पूर्व पी. सी. जे. एल., री [2006] 1 एस. सी. आर. के मामले में ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय का निर्णय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1986) 161 सी. एल. आर. 342) के साथ-साथ एबनेर में संघीय न्यायालय, री (1999) 161 ए. एल. आर. 557) और के संवैधानिक न्यायालय के निर्णय पर

दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति बनाम। दक्षिण अफ्रीकी रग्बी फुटबॉल संघ, (1999) 4 एसए 147 ने कहा कि यह होगा उन कारकों को परिभाषित करने या सूचीबद्ध करने का प्रयास करना खतरनाक और व्यर्थ है जो पूर्वाग्रह के वास्तविक खतरे को जन्म दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। अपील न्यायालय ने इस प्रभाव को जारी रखा कि सब कुछ इस पर निर्भर करेगा

जिन तथ्यों में तय किए जाने वाले मुद्दे की प्रकृति शामिल हो सकती है। इसने आगे कहा:

' इसके विपरीत, पूर्वाग्रह का एक वास्तविक खतरा उत्पन्न होने के बारे में सोचा जा सकता है। यदि न्यायाधीश के बीच व्यक्तिगत मित्रता या शत्रुता थी

और मामले में शामिल जनता का कोई भी सदस्य; या यदि

न्यायाधीश जनता के किसी भी सदस्य से निकटता से परिचित थे।

मामले में शामिल, विशेष रूप से यदि उस व्यक्ति की विश्वसनीयता

मामले के निर्णय में महत्वपूर्ण हो सकता है; या यदि, किसी मामले में

जहाँ किसी भी व्यक्ति की विश्वसनीयता तय करने का मुद्दा था

न्यायाधीश द्वारा, उन्होंने पिछले मामले में सबूत को खारिज कर दिया था वह व्यक्ति इस तरह के मुखर शब्दों में कि उस पर संदेह करे

ऐसे व्यक्ति के साक्षय तक खुले दिमाग से पहुँचने की क्षमता

बाद के किसी अवसर पर; या यदि कार्यवाहियों में किसी मुद्दे पर
उनके समक्ष न्यायाधीश ने विचार व्यक्त किए थे, विशेष रूप से

सुनवाई की प्रक्रिया, इस तरह के चरम और असंतुलित शब्दों में
एक उद्देश्य के साथ मुद्दे को आजमाने की उनकी क्षमता पर संदेह करना

न्यायिक मन (वकुट बनाम। केली (1989) 167 सी. एल. आर. 568); या यदि, के लिए

उसके सामने। केवल यह तथ्य कि एक न्यायाधीश, पहले उसी मामले में
या पिछले मामले में, एक पक्ष-गवाह पर प्रतिकूल टिप्पणी की थी,

या किसी पक्ष या गवाह के साक्षय को अविश्वसनीय पाया,
इसके बिना एक स्थायी आपत्ति नहीं मिलेगी। अधिकतर में

हम सोचते हैं कि किसी न किसी मामले में जवाब स्पष्ट होगा।

लेकिन अगर किसी भी मामले में संदेह के लिए वास्तविक आधार है, तो वह संदेह

अलग होने के पक्ष में हल किया जाना चाहिए। हम दोहराते हैं: हर एक

पक्षपात के खतरे के रूप में भरोसा किया और जिस मामले में
आपत्ति उठाई जाती है, कमजोर (अन्य चीजें बराबर होती हैं)

आपत्ति होगी। ' रामेश्वर प्रसाद बनाम।

यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

721

जाहिरा तौर पर जैसा कि ऊपर देखा गया एक अलग नोट लग रहा था लेकिन
वास्तव में,
निर्णय में ही एक से अधिक बार यह स्पष्ट किया गया है कि

कि वैचारिक रूप से पूर्वाग्रह के मुद्दे को तथ्यों पर तय किया जाना चाहिए

और व्यक्तिगत मामले की परिस्थितियों में निस्संदेह थोड़ा बदलाव आया है पूर्वाग्रह की अवधारणा से संबंधित मूल सोच से

प्रभाव कि केवल पक्षपात की आशंका अन्यथा पर्याप्त हो सकती है।

बोम्मई के मामले में (ऊपर) हालांकि सभी विद्वान न्यायाधीशों ने इस अभ्यास को माना

संविधान के अनुच्छेद 356 (1) के तहत शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

लेकिन राष्ट्रपति की संतुष्टि के न्यायसंगत होने के मामले में, बहुमत का विचार इस प्रभाव पर था कि सिद्धांत बेरियम केमिकल्स लिमिटेड और ए. एन. आर. में विकसित हुए। वी. कंपनी विधि बोर्ड और अन्य।, ए. आई. आर. (1967) एस. सी. 295 संविधि द्वारा सृजित प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर किसी कार्रवाई की वैधता का निर्णय लेने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक शक्ति के प्रयोग पर पूरी तरह से लागू नहीं होता है। माला फिदे

इरादे या पक्षपाती रवैये को एक संकीर्ण सूत्र पर नहीं रखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और उस परिप्रेक्षय में न्यायिक मिसाल बहुत मददगार नहीं होगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बोम्मई के मामले (उपरोक्त) में यह न्यायालय विधानसभाओं के विघटन के मामलों से संबंधित था जब मंत्रिमंडल कार्यालय में थे। हालांकि पहली बार में फ्लश, ऐसा प्रतीत होता है

बोम्मई के मामले (ऊपर) में कर्नाटक के मामले (ऊपर) की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में हाथ में मौजूद तथ्यात्मक स्थिति के साथ बहुत समानता है, फिर भी एक गहरे विश्लेषण पर स्थिति ऐसी प्रतीत नहीं होती है। तथ्यात्मक स्थिति विशिष्ट थी। तत्काल मामले में, राज्यपाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी राय का स्रोत खुफिया रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट और विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा एक याचिका दायर की गई थी कि यह संकेत नहीं दिया गया है कि राज्यपाल ने किस पक्ष के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की थी। यह रिपोर्ट को असुरक्षित मानने का आधार नहीं हो सकता है।

जैसा कि बोम्मई के मामले (ऊपर) में उल्लेख किया गया था कि तथ्यात्मक पहलुओं की पर्याप्तता या शुद्धता से निपटा नहीं जा सकता है। इसलिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एकमात्र सवाल जिस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या राज्यपाल का यह निष्कर्ष कि यदि बहुमत को दबाने के लिए गलत तरीके अपनाए जाते हैं, तो यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ होगा। फिर से सवाल यह होगा कि क्या साधन गलत हैं क्या राज्यपाल इसे नजरअंदाज कर सकते हैं और क्या यह कहा जा सकता है कि उनका विचार बाहरी या तर्कहीन है।

दिनांकित 27.4.2005 रिपोर्ट में जिसका संदर्भ दिया गया है

आई. डी. 1 दिनांकित रिपोर्ट में धन, जाति, पद आदि जैसे प्रलोभन का उल्लेख किया गया है और इसे एक परेशान करने वाली विशेषता कहा गया है। दोनों रिपोर्टों में, राज्यपाल की राय है कि यदि इन प्रयासों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, [2006] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

722

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भले ही इसे सही माना जाए, लेकिन कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है राज्यपाल को अनुमति नहीं देने के लिए समान आधार बनाने का अधिकार देने वाला प्रावधान

लगाए जाने का दावा। यह तर्क पूरी तरह से सही नहीं लगता है।

किहोतो होल्लोहन बनाम। ज़चिल्लू और ओआरएस।, [1992] पूरक 2 एस. सी. सी. 651 द

दलबदल के खतरे को चिंता के साथ नोट किया गया और दसवीं अनुसूची की वैधता को बरकरार रखा गया। प्रावधान की वैधता को बनाए रखते हुए यह

न्यायालय ने पक्षकारों के प्रति निष्ठा में परिवर्तन और सत्ता के प्रति सनक की बिना किसी अनिश्चितता के निंदा की। से संबद्ध उद्देश्यों और कारणों का विवरण

संविधान (52 वां संशोधन) अधिनियम, 1985 राजनीतिक दलबदल की बुराई का उल्लेख करता है जो राष्ट्रीय चिंता का विषय रहा है। यह नोट किया गया था कि यदि इसका मुकाबला नहीं किया जाता है तो यह हमारी नींव को कमजोर करने की संभावना है।

लोकतंत्र और वे सिद्धांत जो इसे बनाए रखते हैं। इसे इस प्रकार नोट किया गया था:

" 26. मौलिक कानून की प्रक्रियाओं की व्याख्या करते हुए,
संविधान को एक तार्किक समग्र के रूप में माना जाना चाहिए। वेस्टल वुडबरी

संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक कानून में विलोबी (दूसरा संस्करण।

Vol.1 p. 65) कहते हैं:

" संविधान एक तार्किक समग्र है, जिसका प्रत्येक प्रावधान है -

इसका एक अभिन्न अंग है, और इसलिए यह तार्किक रूप से उचित है, और

. वास्तव में अनिवार्य है कि प्रावधानों के आलोक में एक भाग का अर्थ लगाया जाए

अन्य भागों से "।

27. एक संवैधानिक दस्तावेज केवल व्यापक और सामान्य रूपरेखा तैयार करता है।

सहन करने और लचीले अनुप्रयोग में सक्षम होने के लिए सिद्धांत
परिस्थितियों को बदलने वाला एक अंतर जो एक क़ानून को अलग करता है

एक चार्टर से जिसके तहत सभी क़ानून बनाए जाते हैं। कूली ऑन

संवैधानिक सीमाएँ (8 वां संस्करण। Vol.1, p.129) कहता है:

" संविधान में संशोधन को स्वीकार करने पर,

संशोधन उसका एक हिस्सा बन जाता है; जितना कि यह किया गया था

मूल रूप से संविधान में शामिल किया गया है और इसका अर्थ लगाया जाना है

तदनुसार "।

फिर से, पैराग्राफ 41 में, स्थिति को श्री द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था।

न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैया (जैसा कि उनका प्रभुत्त्व तब था)। चुनने का अधिकार, हालांकि यह लोकतंत्र के लिए मौलिक है, विसंगत रूप से पर्याप्त है और न ही

मौलिक अधिकार और न ही एक सामान्य कानून अधिकार। यह शुद्ध और सरल, एक वैधानिक अधिकार है। इसलिए यह निर्वाचित होने का अधिकार है। चुनाव पर विवाद करने का भी यही अधिकार है। कानून के बाहर, चुनने का कोई अधिकार नहीं है, निर्वाचित होने का कोई अधिकार नहीं है और कोई अधिकार नहीं है 723

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

एक चुनाव को रोकें। वैधानिक रचनाएँ वे हैं और इसलिए उनके अधीन हैं

आरवाई सीमा। (ज्योति बसु और ओआरएस को देखें। वी. देवी घोषाल और ओआरएस। ,

| 1 एससीसी 691)।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लोकतंत्र संविधान की मूल विशेषता है। में।

किहोतो के मामले (ऊपर) के रैफ 44 और 49 को इस प्रकार नोट किया गया था:

" 44. लेकिन एक राजनीतिक दल साझा मान्यताओं के बल पर काम करता है।
इसकी अपनी राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक उपयोगिता इस तरह के साझा कार्यों पर निर्भर करती है।

उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इसके सदस्यों की मान्यताओं और ठोस कार्रवाई

आम तौर पर माने जाने वाले सिद्धांत। इसके सदस्यों को मतदान करने की कोई भी स्वतंत्रता

वे राजनीतिक दल की घोषित नीतियों से स्वतंत्र रूप से खुश हैं

न केवल इसकी सार्वजनिक छवि और लोकप्रियता को शर्मिंदा करेगा बल्कि

इसमें जनता के विश्वास को कम करता है जो, अंतिम विश्लेषण में, है इसका स्रोत
निर्वाह-नहीं, वास्तव में, इसका अस्तित्व ही है। पार्टी के भीतर बहस

यह निश्चित रूप से एक अलग बात है। लेकिन अलग-अलग स्टैंड की सार्वजनिक छवि

एक ही राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाता है

परंपरा, एक वांछनीय स्थिति के रूप में। संसद में ग्रिफ़िथ और राइल

कार्य, अभ्यास और प्रक्रिया (1989 संस्करण, p.119) कहता है;

" साझा मान्यताओं पर आधारित होने के कारण पार्टी के प्रति वफादारी आदर्श है। ए.

विभाजित पार्टी को मतदाता संदेह के साथ देखते हैं। यह है।
सदस्यों के लिए अपने नेताओं की राय स्वीकार करना स्वाभाविक है और

विभिन्न प्रकार के मामलों पर प्रवक्ता जिन पर वे सदस्य

कोई विशेषज्ञ ज्ञान नहीं है। आम तौर पर सदस्य स्वीकार करेंगे।

असहमत होने पर भी पार्टी में बहुमत निर्णय लेते हैं। यह है।

इसलिए यह समझ में आता है कि एक सदस्य जो पार्टी को अस्वीकार करता है
एक अवसर पर भी चाबुक ध्यान आकर्षित करेगी और अधिक

सहानुभूति की तुलना में आलोचना। आवश्यकता पड़ने पर मतदान से दूर रहना

पार्टी द्वारा वोट देना कुछ हद तक अविश्वसनीयता का सुझाव देना है। वोट करने के लिए

पार्टी के खिलाफ बेवफाई है। परहेज़ में दूसरों के साथ शामिल होना या

दूसरे पक्ष के साथ मतदान करने से साजिश की गंध आती है।

49. वास्तव में, एक अर्थ में दलबदल विरोधी कानून एक वैधानिक रूप है -

इसका नैतिक सिद्धांत और औचित्य याद करने की शक्ति में अंतर्निहित है। वापस बुलाने के लिए एक प्रावधान को क्या उचित ठहरा सकता है, इसके लिए एक प्रावधान को उचित ठहराएगा

डिस-दलबदल के लिए योग्यता। सिद्धांतहीन दलबदल एक राजनीतिक स्थिति है

और सामाजिक बुराई। विधायिका द्वारा इसे ऐसा माना जाता है। लोगों को,

जाहिर है, भावनात्मक राजनीतिक उल्लास के प्रति अविश्वास बढ़ गया है।

कि इस तरह के फर्श-क्रॉसिंग स्वतंत्रता के पवित्र क्षेत्र से संबंधित हैं

विवेक, या असहमति का अधिकार या बौद्धिक स्वतंत्रता का अधिकार। द 724

दलबदल विरोधी कानून को लागू करने की व्यावहारिक आवश्यकता को पहचानने का प्रयास करता है

राजनीतिक और व्यक्तिगत आचरण के गुण-जिनका अजीब क्षरण होता है

और विचित्र अभिव्यक्तियाँ उपरोक्त समय की अभिशाप रही हैं। कुछ सैद्धांतिक धारणाएँ जो वास्तव में एक में गिर गई हैं

व्यक्तिगत और राजनीतिक पतन का दलदल। हमें सोचना चाहिए,

इस विधायी ज्ञान और धारणा को टाल दें। इन विकल्पों में
संवैधानिक निर्णय स्पष्ट रूप से इस तरह की आवश्यकता का संकेत देते हैं।

सम्मान "। अंत को वैध होने दें, इसे इसके दायरे में रहने दें।
संविधान और सभी साधन जो उपयुक्त हैं, जिन्हें अपनाया जाता है

उस उद्देश्य के लिए "संवैधानिक हैं"।

इसलिए, कानून में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त स्थिति यह है कि शुद्धता में

निर्वाचक प्रक्रिया और निर्वाचित प्रतिनिधि के आचरण को संवैधानिक आवश्यकताओं से अलग नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र "और" स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव "अविभाज्य जुड़वां हैं। उनमें लगभग एक अविभाज्य नाभि जुड़ती है। लोकतंत्र में छोटे मतदाता का अत्यधिक महत्व होता है और उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों से वंचित नहीं किया जा सकता है। अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने की उनकी स्वतंत्रता एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की नींव है। लेकिन निर्वाचित होने के बाद, यदि निर्वाचित उम्मीदवार निष्पक्षता और शुद्धता के मार्ग से भटक जाता है और एक "खरीद योग्य वस्तु" बन जाता है तो वह न केवल मतदाताओं के साथ विश्वासघात करता है, बल्कि लोकतंत्र की शुद्ध धारा को भी प्रदूषित करता है।

क्या राज्यपाल जिसका संवैधानिक कर्तव्य शुद्धता की रक्षा करना है

ऐसी स्थितियों में घोर असहायता में अपने हाथ ऊपर फेंक देते हैं?

जैसा कि इस न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) में उल्लेख किया है।

और एन. आर. वी. भारत संघ और एएनआर।, [2003] 4 एस. सी. सी. 399 एक अच्छी तरह से सूचित मतदाता लोकतांत्रिक संरचना की नींव है। यदि ऐसा है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि राज्यपाल मूक और मूक दर्शक बने रहेंगे जब निर्वाचित प्रतिनिधि उन मतदाताओं की अपेक्षाओं के विपरीत व्यवहार करेंगे जिन्होंने उन्हें वोट दिया था। इसके अनुच्छेद 94 में इस प्रकार उल्लेख किया गया है:

" 94. साधारण कहावत है कि 'लोकतंत्र लोगों के लिए है, लोगों का है
और लोगों द्वारा 'को हमेशा के लिए याद रखना होगा। लोकतांत्रिक में

गणराज्य, यह लोगों की इच्छा है जो सर्वोपरि है और बन जाती है

सरकार के अधिकार का आधार। इच्छा व्यक्त की जाती है

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर आवधिक चुनावों में

गुप्त मतदान। मतपत्र के माध्यम से ही मतदाता अपना मत व्यक्त करता है। उम्मीदवार के लिए चयन या वरीयता। " मतदान एक औपचारिक अभिव्यक्ति है

अधिकार का प्रयोग करने के हकदार व्यक्ति द्वारा इच्छा या राय विषय या मुद्दा ", जैसा कि लिली थॉमस बनाम में इस न्यायालय द्वारा देखा गया है। अध्यक्ष, 725

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

लोकसभा, [1993] 4 एस. सी. सी. 234 ब्लैक लॉ डिक्शनरी से उद्धृत करते हुए।

देश के नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार में भाग लेने में सक्षम हैं: हमारे जैसे संसदीय लोकतंत्र में, आज की सरकार अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों के प्रति उत्तरदायी है। निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों और लोगों के बीच एक जीवंत कड़ी के रूप में कार्य करता है या कार्य करता है।

सरकार। जन-प्रतिनिधि कानून निर्माताओं और सरकार के संरक्षकों की भूमिका निभाते हैं। लोग वायु संचार और अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उनकी ओर देखते हैं। वे बड़े पैमाने पर लोगों की इच्छा और अधिकार का केंद्र बिंदु हैं। जिस क्षण वे कागज़ों में डाल देते हैं

सार्वजनिक जांच। उम्मीदवार का चरित्र, ताकत और कमजोरी इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। इसलिए लोकतांत्रिक राजनीति को बनाए रखने के लिए मतदाता द्वारा अपने प्रतिनिधि का बुद्धिमान और तर्कसंगत चुनाव करने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। इसके लिए, मतदाता को अपनी राय को प्रभावी ढंग से तैयार करने और अंतत: मतदान के माध्यम से उस राय को व्यक्त करने की स्थिति में होना चाहिए। द.

मतदान के अधिकार का सहवर्ती जो मूल अभिधारणा है

इस प्रकार लोकतंत्र दो प्रकार का है: पहला, उम्मीदवारों के बारे में राय तैयार करना और दूसरा, वोट देकर अपनी पसंद की अभिव्यक्ति करना।

मतदान केंद्र पर पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में। पहला कदम दूसरे के पूरक है। कई मतदाता राय तैयार करने और उम्मीदवार का उचित चुनाव करने में विकलांग होंगे जब तक कि उम्मीदवार के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध न हो। मतदाता/नागरिक के पास चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के बारे में कम से कम बुनियादी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि गंभीर आपराधिक

अपराधों में उसकी संलिप्तता। सूचना के प्रवाह को रोकने के लिए-प्रासंगिक और आवश्यक-मतदाता की उम्मीदवार का मूल्यांकन करने की क्षमता को प्रभावित करेगा। इतना ही नहीं, उम्मीदवारों से संबंधित जानकारी मार्ग प्रशस्त करेगी।

उम्मीदवारों के गुण और दोषों पर सार्वजनिक बहस के लिए। जब एक बार संबंधित विवरणों का सार्वजनिक प्रकटीकरण होता है

उम्मीदवार, प्रेस, जन संचार और स्वैच्छिक संगठनों के एक मीडिया के रूप में जनता की राय को सही दिशा में ले जाने के लिए पर्याप्त सतर्क है

लाइनें जानकारी का प्रसार करने में सक्षम होंगी और इस तरह प्रबुद्ध होंगी।

और किसी उम्मीदवार की प्रतिकूल पृष्ठभूमि के बारे में बड़े पैमाने पर जनता को सचेत करें। यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। उस लक्षय को दो तरीकों से पूरा किया जाएगा। इससे उम्मीदवार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और प्राप्त करने में रुचि रखने वाले मतदाता को अपनी अंतरात्मा और सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार एक राय बनाने में मदद मिलेगी और दूसरी बात यह है कि यह 726 की सुविधा प्रदान करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2006] 1 एस सी आर।

किसी मामले पर जानकारी प्रदान करने में प्रेस और स्वैच्छिक संगठन

महत्वपूर्ण सार्वजनिक चिंता का विषय। एक जानकार मतदाता-क्या वह प्राप्त करता है

प्रेस और संचार के अन्य माध्यम, उन्हें पूरा कर सकेंगे।
अधिक संतोषजनक तरीके से जिम्मेदारी। एक प्रबुद्ध और

जानकार नागरिक निस्संदेह लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाएंगे।

इस प्रकार, के बारे में उचित और प्रासंगिक जानकारी की उपलब्धता

उम्मीदवार बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है और बढ़ावा देता है

जानकारी प्रदान करने और प्राप्त करने दोनों के दृष्टिकोण से।

बदले में, यह चुनावी अखंडता के संरक्षण की ओर ले जाएगा

प्रक्रिया जो लोकतंत्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। हालांकि

मैं यह टिप्पणी करने की हद तक नहीं जाता कि चुनाव एक प्रहसन होगा

यदि उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि मतदाताओं को पता नहीं है, तो मैं करूँगा

कहना है कि ऐसी जानकारी निश्चित रूप से निष्पक्षता के लिए अनुकूल होगी

चुनाव प्रक्रिया और सार्वजनिक जीवन में अखंडता। का खुलासा

सूचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुगम बनाएगी और बढ़ाएगी

मतदाताओं के साथ-साथ मीडिया के दृष्टिकोण से भी
जिसकी जानकारी को प्रचारित किया जाता है और खुले तौर पर बहस की जाती है। .

लोकतंत्र में पाखंड के लिए कोई जगह नहीं है। राज्यपाल की धारणा

उसकी शक्ति के बारे में हो सकता है। गलत है, लेकिन यह निश्चित रूप से बाहरी या तर्कहीन नहीं है। भारत संघ के विद्वान वकील द्वारा यह उचित रूप से तर्क दिया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार स्थिर है, राज्यपाल की भूमिका के अलावा, मामला दसवीं अनुसूची के दायरे में नहीं आ सकता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि अवैध या दागी द्वारा दसवीं अनुसूची से बचने का मतलब है कि यदि बहुमत इकट्ठा किया जाता है तो राज्यपाल असहाय हो जाता है, और बेईमान तरीकों से जनादेश के साथ छेड़छाड़ करने के लिए एक मूक दर्शक। यह नहीं है और न ही कहा जा सकता है कि किसी दावे को रोकने से राज्यपाल तर्कहीन रूप से या बाहरी परिसरों में कार्य नहीं करता है। यदि राज्यपाल ने किसी को भी दावा करने से रोकने के उद्देश्य से कार्रवाई की होती तो उनकी कार्रवाई कमजोर होती। राज्यपाल का आचरण संदिग्ध हो सकता है और वर्तमान मामले में ऐसा हो सकता है, लेकिन यदि दूषित साधनों को अपनाने के बारे में उनकी राय परखी गई सामग्री द्वारा समर्थित है, तो निश्चित रूप से यह बाहरी या तर्कहीन नहीं हो सकता है। यह सब प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। यदि राज्यपाल किसी विशेष मामले में बिना परीक्षित या निर्विवाद सामग्री के केवल यह टिप्पणी करता है कि दागी साधन अपनाए जा रहे हैं, तो वह न्यायिक समीक्षा को आकर्षित करेगा। लेकिन इस मामले में

कुछ ऐसी सामग्री है जिस पर राज्यपाल ने कार्रवाई की है। यह अंततः वस्तुनिष्ठ सामग्री के आधार पर व्यक्तिपरक संतुष्टि का मामला है। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर एक बात बहुत स्पष्ट है अर्थात कोई दावा नहीं किया गया था और

इसके विपरीत अभिलेख पर दी गई सामग्री से पता चलता है कि क्या पेश किया जा रहा था।

यह रामेश्वर प्रसाद वी भी है। यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

727

उन दस्तावेजों के खाली अवलोकन से स्पष्ट करें जिन्हें याचिकाकर्ताओं ने स्वयं रिट याचिकाओं के साथ संलग्न किया है कि दस्तावेजों की प्रामाणिकता

संदिग्ध है।

मानवाधिकारों के प्रति न्यायिक प्रतिक्रिया को कानूनी जोड़-तोड़ से प्रभावित नहीं किया जा सकता है।

(देखिए: भूपिंदर शर्मा बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य [2003] 8 एस. सी. सी. 551)। न्याय को सत्य के अलावा कोई पसंद नहीं है। तर्कसंगतता, तर्कसंगतता, वैधता के साथ-साथ दार्शनिक रूप से इसके अर्थ को रंग प्रदान करता है।

मौलिक अधिकार। जो नैतिक रूप से गलत है वह राजनीतिक रूप से सही नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ताओं ने स्वयं अपने दावों को उन दस्तावेजों पर आधारित किया है जिनमें बहुमत के दावे की वास्तविकता की छाया भी नहीं है। यदि राज्यपाल को लगता है कि जो किया जा रहा था वह नैतिक रूप से गलत था, तो वह ऐसा नहीं कर सकता।

राजनीतिक रूप से सही माना जाए। यह उनकी धारणा है। यह गलत हो सकता है। जहाँ तक उनकी शक्तियों का संबंध है, इसे संविधान द्वारा विशेष रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अंततः यह एक धारणा है। गलत होने के बावजूद इसे बाहरी या तर्कहीन नहीं कहा जा सकता है। इसलिए राज्यपाल का आचरण चाहे कितना भी संदिग्ध क्यों न हो, और भले ही यह स्वीकार किया जाए कि उन्होंने जल्दबाजी में काम किया था, लेकिन यह उनकी कार्रवाई को असाधारण कहने का आधार नहीं हो सकता है। ईमानदारी के बारे में संदेह की छाया दुर्भावना के बारे में एक अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाती है।

हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि राज्यपालों की इसी तरह की धारणाएँ नेतृत्व कर सकती हैं।

अराजक स्थितियों के लिए। मानवीय त्रुटियाँ हो सकती हैं। इसलिए, संबंधित राज्यपाल को सावधानी और सावधानी के साथ सावधानीपूर्वक कार्य करना होगा और परीक्षण की गई और निर्विवाद सामग्री से अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं; अन्यथा नहीं।

बी. आर. कपूर बनाम तमिलनाडु और अन्र राज्य। , आकाशवाणी (2001) एससी 3435

इस न्यायालय ने मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका पर विचार किया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं और जब बहुमत दल द्वारा चुना गया व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य बनने के योग्य नहीं है तो नियुक्ति करने से इनकार कर सकते हैं। यह देखा गया कि ऐसे मामले में संविधान लोगों की इच्छा पर हावी होता है। यह भी देखा गया कि उस मामले में की गई दलीलों को स्वीकार करते हुए कि राज्यपाल अनुच्छेद 164 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए (4) के साथ पढ़ा जाता है, वह मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य था, चाहे विधानमंडल में बहुमत वाला कोई भी दल नामित हो। नामित व्यक्ति अनुच्छेद 173 के तहत विधानमंडल का सदस्य होने के लिए योग्य था या नहीं या अनुच्छेद 191 के तहत उस ओर से अयोग्य घोषित किया गया था, और एकमात्र तरीका जिसमें एक मुख्यमंत्री जो योग्य नहीं था या जिसे अयोग्य घोषित किया गया था, उसे हटाया जा सकता था, वह था अविश्वास प्रस्ताव।

अगले चुनावों में विधायिका में या मतदाताओं द्वारा और यह कि राज्यपाल इस तरह से बाध्य था, भले ही व्यक्ति की सिफारिश राज्यपाल के 728 के लिए की गई हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2006] 1 एस सी आर।

ज्ञान, एक गैर-नागरिक, कम उम्र का, एक पागल या एक अविमुक्त दिवालिया, और एक गैर-नागरिक, या कम उम्र के या पागल या दिवालिया मुख्यमंत्री को हटाने का एकमात्र तरीका था अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करना।

विधायिका या अगले चुनाव में, आपदा को आमंत्रित करना है।

मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाने पर स्थिति अलग नहीं हो सकती।

एक ऐसे मंत्रालय का नेतृत्व करना था जिसकी नींव दाग पर थी और बहुमत है

अनैतिक साधनों या भ्रष्ट साधनों से फंसा हुआ। जैसा कि बी. आर. में देखा गया था। कपूर का मामला (ऊपर) ऐसी स्थिति में संवैधानिक शुद्धता बनाए रखनी होगी और संविधान को लोगों की इच्छा पर हावी होना होगा।

इन निष्कर्षों के साथ रिट आवेदनों का निपटारा किया जा सकता था।

से। लेकिन, कुछ की संदिग्ध और स्पष्ट रूप से अक्षम्य भूमिकाओं के बारे में विद्वान वकील द्वारा उजागर की गई कुछ परेशान करने वाली विशेषताओं पर ध्यान देते हुए राज्यपालों, कुछ प्रासंगिक पहलुओं से निपटना आवश्यक है।

सरकारिया समिति ने जो कहा था उस पर ध्यान देना प्रासंगिक है।

राज्यपालों की भूमिका के बारे में:

1. परिचय

4.1.01 . राज्यपाल की भूमिका प्रमुख भूमिकाओं में से एक के रूप में उभरी है

संघ राज्य संबंधों में मुद्दे। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य था

आजादी के बाद कई वर्षों तक एक ही पार्टी का वर्चस्व रहा।

संघ-राज्य संबंधों के कार्यकरण में उत्पन्न होने वाली समस्याएं थीं -

ज्यादातर अंतर-पार्टी मंच में समायोजन के लिए मामले और

राज्यपाल के पास अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करने का बहुत कम अवसर था।

राज्यपाल की संस्था काफी हद तक छिपी रही। केरल में घटनाएँ 1959 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, कुछ में लाया गया था

प्रमुखता राज्यपाल की भूमिका थी, लेकिन उसके बाद यह आकर्षित नहीं हुई कुछ वर्षों के लिए बहुत ध्यान। इसके बाद एक बड़ा बदलाव आया

1967 में चौथा आम चुनाव। कई राज्यों में पार्टी

सत्ता संघ में सत्ता से अलग थी। बाद के दशक

राजनीतिक दलों के विखंडन और नए दलों के उदय को देखा

क्षेत्रीय दलों का अक्सर, कभी-कभी अप्रत्याशित पुनर्गठन
गठन के उद्देश्य से राजनीतिक दल और समूह बनाए गए

सरकारें। इन विकासों ने दीर्घकालिक अस्थिरता को जन्म दिया

उन्होंने अपनी विवेकाधीन शक्तियों का अधिक बार प्रयोग करने का आह्वान किया। जिस तरह से
उन्होंने इन कार्यों का प्रयोग किया है, वह प्रत्यक्ष है।

संघ-राज्य संबंधों पर प्रभाव। संघ के बीच घर्षण के बिंदु रामेश्वर प्रसाद v.

यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

729

और राज्यों ने गुणा करना शुरू कर दिया।

4.1.02 . राज्यपाल की भूमिका जमीन पर हमले के लिए आ गई है

कि कुछ राज्यपाल उनसे अपेक्षित निष्पक्षता और दूरदर्शिता के गुणों को प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं। यह आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल

आवश्यक वस्तुनिष्ठता के साथ या तो तरीके से कार्य नहीं किया है संघ और राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अपने विवेक का या अपनी भूमिका का प्रयोग करना। कई लोगों ने इसका पता मुख्य रूप से इस तथ्य से लगाया है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, और खुशी के दौरान पद धारण करता है।

(वास्तव में, मंत्रिपरिषद का गठन)। कुछ राज्यपालों द्वारा निभाई गई भूमिका, विशेष रूप से राष्ट्रपति की सिफारिश में

राज्यपालों ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस पद की प्रतिष्ठा को कम कर दिया है। आलोचना यह भी की गई है कि केंद्र सरकार राज्यपाल का उपयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करती है। कई राज्यपालों, संघ के तहत आगे के पद या अपने कार्यकाल के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका की प्रतीक्षा करते हुए, वे खुद को संघ के एजेंट के रूप में मानने लगे।

(जोर देने के लिए रेखांकित)

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः

4.2.01 . भारत सरकार अधिनियम, 1858 ने भारत के प्रशासन की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी। गवर्नर तब क्राउन का एक एजेंट बन गया, जो गवर्नर की सामान्य देखरेख में काम करता था। जनरल। मोंटागु-चेम्सफोर्ड सुधार (1919) ने एक अल्पविकसित रूप में जिम्मेदार सरकार की शुरुआत की। हालाँकि, राज्यपाल प्रांतीय प्रशासन की धुरी बने रहे।

4.2.02 . भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने प्रांतीय लागू किया। स्वायत्तता। राज्यपाल को अब विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करने की आवश्यकता थी। फिर भी, इसने राज्यपाल को कुछ विशेष जिम्मेदारियां सौंपी, जैसे कि प्रांत की शांति या शांति के लिए गंभीर खतरे की रोकथाम, अल्पसंख्यकों के वैध हितों की रक्षा करना आदि। राज्यपाल विशिष्ट मामलों में भी अपने विवेक से कार्य कर सकता था। जब भी वे अपने व्यक्तिगत निर्णय या विवेक से कार्य करते थे, वे गवर्नर जनरल के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण में कार्य करते थे।

4.2.03 . 1937 में जब भारत सरकार अधिनियम, 1935 लागू हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने छह प्रांतों में बहुमत हासिल किया।

विधायिकाएँ। उन्होंने कार्य करने में कुछ कठिनाइयों का पूर्वानुमान लगाया

नई प्रणाली जो मंत्रियों से बिना किसी आपत्ति के स्वीकार करने की उम्मीद करती थी, निंदा निहित थी, अगर राज्यपाल अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करता है

अपनी विशेष जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए। कांग्रेस पार्टी इन प्रांतों में पद ग्रहण करने के लिए तभी सहमत हुई जब उसे एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

वायसराय से आश्वासन कि राज्यपाल निर्वाचित सरकार के साथ संघर्ष नहीं भड़काएंगे।

4.2.04 . स्वतंत्रता ने अनिवार्य रूप से राज्यपाल की भूमिका में बदलाव लाया। जब तक संविधान लागू नहीं हुआ, प्रावधान

भारत सरकार अधिनियम, 1935, जैसा कि भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा अनुकूलित किया गया था, लागू था। इस आदेश में 'अपने विवेकाधिकार में', 'अपने विवेकाधिकार में कार्य करना' और 'अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना' अभिव्यक्तियों को हटा दिया गया, जहां भी वे अधिनियम में आए। जबकि, पहले, कुछ कार्यों का प्रयोग राज्यपाल द्वारा या तो अपने विवेक से या अपने व्यक्तिगत निर्णय में किया जाना था, अनुकूलन आदेश ने राज्यपाल को इन कार्यों के साथ-साथ अन्य सभी कार्यों का प्रयोग केवल अपनी परिषद की सलाह पर करना अनिवार्य बना दिया था।

मंत्रियों का।

4.2.05 . संविधान निर्माताओं ने सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश मॉडल की सरकार की संसदीय या मंत्रिमंडल प्रणाली को स्वीकार किया।

संघ और राज्यों दोनों के लिए। जबकि सीमांकित शक्तियों के साथ सरकार के दो स्तरों का स्वरूप व्यापक रूप से स्वतंत्रता पूर्व व्यवस्थाओं के समान रहा, उनकी भूमिकाओं और अंतर-संबंधों को एक प्रमुख पुनर्विन्यास दिया गया।

4.2.06 . संविधान सभा ने राज्यपाल से संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे - विचार किया। पहला मुद्दा यह था कि क्या एक निर्वाचित राज्यपाल होना चाहिए। यह माना गया कि एक निर्वाचित राज्यपाल और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी एक मुख्यमंत्री के सह-अस्तित्व से टकराव हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप प्रशासन में कमजोरी आ सकती है। इसलिए एक निर्वाचित राज्यपाल की अवधारणा को एक नामित राज्यपाल के पक्ष में छोड़ दिया गया था। संविधान सभा में यह समझाते हुए कि राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा क्यों नामित किया जाना चाहिए और क्यों नहीं चुना जाना चाहिए

जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि "एक निर्वाचित राज्यपाल कुछ हद तक उस अलगाववादी प्रांतीय प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेगा। केंद्र के साथ बहुत कम सामान्य संबंध होंगे। "

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. 1. [पासायत, जे।]

4.2.07 . दूसरा मुद्दा विवेकाधीन शक्तियों की सीमा से संबंधित है। राज्यपाल को अनुमति दी जाए। निर्णय लेने के बाद एक

नामित राज्यपाल, संविधान के प्रारूप के विभिन्न अनुच्छेदों में निर्दिष्ट कार्य के अभ्यास से संबंधित संदर्भ राज्यपाल को 'उनके विवेकानुसार' हटा दिया गया था। एकमात्र स्पष्ट प्रावधान

असम में जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्रों को बरकरार रखा गया था, जहां प्रशासन को केंद्रीय जिम्मेदारी दी गई थी। राज्यपाल ने

संक्रमणकालीन अवधि के दौरान केंद्र सरकार का प्रतिनिधि अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। फिर भी, अनुच्छेद 143 के मसौदे में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिसमें राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख किया गया था। मसौदा अनुच्छेद 143 में यह प्रावधान (अब अनुच्छेद 163) ने काफी चर्चा पैदा की। इसका जवाब देते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि राज्यपाल को कुछ निश्चित अधिकार दिए गए हैं।

विवेकाधीन शक्तियाँ जिम्मेदार सरकार के विपरीत नहीं थीं।

एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स

4.3.09 . संविधान में कुछ प्रावधान स्पष्ट रूप से हैं। राज्यपाल को अधिनियम बनाने का प्रावधानः

((ए) अपने विवेक से; या

((ख) अपने व्यक्तिगत निर्णय में; या

((ग) राज्य मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से।

(क) (i) सभी राज्यों के राज्यपाल-विचार के लिए आरक्षण

उस स्थिति को खतरे में डालने के लिए न्यायालय जो उस न्यायालय द्वारा है संविधान को भरने के लिए बनाया गया है (अनुच्छेद 200 का दूसरा प्रावधान)।

((ii) अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के राज्यपाल,

मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उनके द्वारा अपने विवेक से किए जाने वाले कुछ विशिष्ट कार्य

(अनुच्छेद 371 ए, 371 एफ और 371 एच और छठे के पैराग्राफ 9 के माध्यम से

अनुसूची)। धारा 14 में इन पर विस्तार से चर्चा की गई है।

यह अध्याय।

(ख) अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के राज्यपालों को उनके संबंधित राज्यों में कानून और व्यवस्था के संबंध में एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस जिम्मेदारी के निर्वहन में, उन्हें अपने "व्यक्तिगत निर्णय" का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।

उनकी मंत्रिपरिषद। इस पहलू पर [2006] 1 एस. सी. आर. में भी चर्चा की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस अध्याय की धारा 14।

(ग) केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में राज्यपाल-कोई भी राज्यपाल,

राष्ट्रपति द्वारा एक पड़ोसी के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है

केंद्र शासित प्रदेश को प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग करना होता है,

राज्य मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से (अनुच्छेद 239 (2)। में। वास्तव में, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में, राज्यपाल

राष्ट्रपति के प्रतिनिधि का पद।

XX XX XX

4.4.01 . राज्यपाल की भूमिका के तीन महत्वपूर्ण पहलू

संवैधानिक प्रावधानों में से निम्नलिखित हैं:

(क) सामान्य रूप से कार्य करने वाले राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में

संसदीय लोकतंत्र की एक प्रणाली के तहत;

(ख) केंद्र सरकार और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में

सरकार; और

(ग) कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में

सामान्य समय के दौरान (जैसे अनुच्छेद 239 (2) और कई क्षेत्रों में)

असामान्य स्थितियों के दौरान (जैसे अनुच्छेद 356 (1))

4.4.02 . ऊपर) के बारे में थोड़ा विवाद है। लेकिन जिस तरह से

जिसे उन्होंने नीरस भूमिका निभाई है, जैसा कि (ए) और (बी) में परिकल्पित है।

ऊपर, बहुत आलोचना को आकर्षित किया है। शिकायतों का बोझ राज्यपालों के व्यवहार के खिलाफ, सामान्य रूप से, यह है कि वे असमर्थ हैं

अपने राजनीतिक झुकावों, पूर्वाग्रहों और पूर्वाग्रहों को छोड़ने के लिए जबकि

राज्य के भीतर विभिन्न राजनीतिक दलों से निपटना। इसके परिणामस्वरूप,

कभी-कभी वे अपने विवेक से जो निर्णय लेते हैं, वे पक्षपातपूर्ण प्रतीत होते हैं।

और संघ में सत्तारूढ़ दल के हितों को बढ़ावा देने का इरादा रखता है सरकार, विशेष रूप से यदि राज्यपाल पहले सक्रिय राजनीति में थे

राज्यों की स्वायत्तता को कम करता है, और तनाव पैदा करता है संघ राज्य संबंध।

के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट में

राज्यपाल की भूमिका को निम्नलिखित में निपटाया गया है:

:

" चयन और नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति की शक्तियाँ 733

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

राज्यपालों को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के बाद ही की जानी चाहिए।

उस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ। आम तौर पर पाँच साल के कार्यकाल का पालन किया जाना चाहिए और हटाने या स्थानांतरण नियुक्ति के लिए समान प्रक्रिया का पालन करके किया जाना चाहिए अर्थात उनके साथ परामर्श के बाद।

संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री।

(पैरा 8.14.2)

राज्यपाल के चयन के मामले में निम्नलिखित मामले हैं -

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के खंड I के पैरा 4.16.01 में उल्लिखित को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

((i) उसे जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए।
((ii) वह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए।

((iii) वह एक अलग व्यक्ति होना चाहिए और बहुत अंतरंग नहीं होना चाहिए। राज्य की स्थानीय राजनीति से जुड़ा हुआ; और

((iv) वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने इसमें बहुत अधिक भाग नहीं लिया हो।

राजनीति आम तौर पर, और विशेष रूप से हाल के दिनों में।

उपरोक्त मानदंडों के अनुसार राज्यपाल का चयन करते समय,

अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित व्यक्तियों को एक दिया जाना जारी है

(पैरा 8.14.3)

अब तक की तरह मौका।

एक समय सीमा होनी चाहिए-मान लीजिए कि इसके भीतर छह महीने की अवधि हो।

जिसे राज्यपाल को यह निर्णय लेना चाहिए कि उसे मंजूरी देनी है या नहीं।

राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक आरक्षित करना। यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित है, तो तीन महीने की समय सीमा होनी चाहिए, जिसके भीतर राष्ट्रपति को निर्णय लेना चाहिए कि क्या उसे अपनी सहमति देनी है या राज्यपाल को इसे राज्य विधानमंडल को

वापस करने का निर्देश देना है या अनुच्छेद 143 के तहत अधिनियम की संवैधानिकता के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेनी है। (पैरा 8.14.4.)

8.14. 6 . संविधान में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रपति द्वारा दी गई सहमति संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों के सभी उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो। तथापि, यह वांछनीय है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, तो संविधान के सभी अनुच्छेदों की ओर राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित करना उचित होगा।

संविधान, जो राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट की सहमति की आवश्यकता को संदर्भित करता है

एस सी आर।

इस प्रभाव से कि राष्ट्रपति द्वारा किसी अधिनियम को दी गई सहमति नहीं होगी यह तर्क देने की अनुमति है कि क्या यह एक उद्देश्य के लिए दिया गया था या

एक और। जब राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति देते हैं, तो वह होगा -

संविधान के सभी उद्देश्यों के लिए दिया गया माना जाता है। 8.14. 8 . निम्नलिखित परंतुक को अनुच्छेद 111 में जोड़ा जा सकता है

संविधान:

" बशर्ते कि जब राष्ट्रपति घोषणा करता है कि वह सहमति देता है

विधेयक, स्वीकृति को सभी के लिए एक सामान्य सहमति माना जाएगा। संविधान के उद्देश्य "।

अनुच्छेद 200 में भी उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है।

अनुच्छेद 356 को हटाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसका उपयोग संयम से किया जाना चाहिए।

और केवल अंतिम उपाय के उपाय के रूप में और थकाऊ कार्रवाई के बाद

256, 257 और 355 जैसे अन्य अनुच्छेदों के तहत।

(पैरा 8,18 और 8.19.2)

3.16 - उपयोग-अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग

" 26 जनवरी को संविधान लागू होने के बाद से,

1950 , अनुच्छेद 356 और अनुरूप प्रावधानों को लागू किया गया है।

समय समय पर। लोकसभा सचिवालय के एक अध्ययन के अनुसार, 13 मौकों पर अनुरूप प्रावधान अर्थात् सरकार की धारा 51

केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963 उन केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू किया गया था जिनमें से

केवल पांडिचेरी में उस अवसर तक एक विधान सभा थी जब

यह आखिरी बार लागू किया गया था। शेष 98 उदाहरणों में अनुच्छेद था

संविधान के यांत्रिकी के कारण तकनीकी रूप से 10 बार लागू किया गया

राज्यों के पुनर्गठन जैसी परिस्थितियों में, पूरा होने में देरी

चुनाव की प्रक्रिया, घोषणा के संशोधन के लिए और वहाँ चुनाव के अंत में स्पष्ट बहुमत वाली कोई पार्टी नहीं होना। में

शेष 88 मामलों में अभिलेखों की बारीकी से जांच से पता चलेगा कि

अनुच्छेद 356 का आह्वान। ये बड़े पैमाने के उदाहरण थे। दलबदल के कारण सत्तारूढ़ दल अल्पमत में आ जाता है,

गठबंधन सहयोगियों का समर्थन वापस लेना, स्वैच्छिक त्यागपत्र

व्यापक आंदोलनों, बड़े पैमाने पर उग्रवाद को देखते हुए सरकार, रामेश्वर प्रसाद बनाम।

यू. ओ. एल. [पासायत। जे.]

सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों की न्यायिक अयोग्यता के कारण सदन में बहुमत का नुकसान होता है और सरकार बनाने में सक्षम कोई वैकल्पिक 'दल' नहीं होता है। संभावित दुरुपयोग के लगभग 13 मामले ऐसे हैं जिनमें दलबदल और असहमति को राजनीतिक पैंतरेबाज़ी का परिणाम माना जा सकता है या ऐसे मामले हैं जिनमें शक्ति परीक्षण हो सकते हैं।

अंततः समर्थन की कमी साबित हुई लेकिन उनका सहारा नहीं लिया गया। 18 मामलों में आम धारणा स्पष्ट दुरुपयोग की है। इनमें शामिल हैं -

अप्रैल 1977 में 9 राज्य सरकारों की बर्खास्तगी और फरवरी 1980 में इतनी ही संख्या में। इस विश्लेषण से पता चलता है कि 111 में से राष्ट्रपति शासन लागू करने के मामलों की संख्या, जिन्हें राजनीतिक समस्याओं से निपटने के लिए गलत उपयोग माना जा सकता है या राज्य में कुशासन जैसे उस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए अप्रासंगिक विचार 20 से कुछ अधिक हैं। स्पष्ट रूप से राज्यों के पुनर्गठन से उत्पन्न होने वाले मामलों सहित कई मामलों में यह प्रतीत होता है कि

8.17- सरकारिया आयोग-सरकारिया आयोग का अध्याय 6 रिपोर्ट आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है, अर्थात् अनुच्छेद 352 से 360।

सरकारिया आयोग ने 12 सिफारिशें की हैं; जिनमें से 2 अनुच्छेद 356 से संबंधित हैं जबकि 1 संविधान के अनुच्छेद 355 से संबंधित है। सरकारिया आयोग ने भी निर्दिष्ट किया राज्यों को राज्यों के स्वशासन में राजनीतिक रूप से संचालित हस्तक्षेप से बचाने की दृष्टि से संविधान में संशोधन के लिए सिफारिशें। सिफारिशों का रेखांकित विषय एक ऐसी संवैधानिक संरचना और संस्कृति को बढ़ावा देना है जो संविधान द्वारा निर्धारित संघीय संस्थानों के सहकारी और निरंतर विकास को बढ़ावा देती है।

8.19 . सम्मेलनों की आवश्यकता

एक्सएक्स

XX

XX

XX

8.19. 5- राजनीतिक पतन के मामले में, आयोग सिफारिश करता है

कि अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा जारी करने से पहले संबंधित

राज्य को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और स्थिति का समाधान करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जब तक कि स्थिति ऐसी न हो कि उपरोक्त मार्ग का पालन करना राज्य की सुरक्षा या देश की रक्षा के हित में न हो, या अन्य कारणों से तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता न हो।

8.20 . राजनीतिक पतन की स्थिति

एक्सएक्स

XX

XX

XX

8.20. 3 . आयोग इस सवाल की सिफारिश करता है कि क्या किसी राज्य में मंत्रालय ने विधानसभा का विश्वास खो दिया है या नहीं, यह केवल विधानसभा के पटल पर ही तय किया जाना चाहिए और कहीं और नहीं। यदि आवश्यक हो, तो केंद्र सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि विधानसभा स्वतंत्र रूप से बैठक कर सके।

अपने व्यवसाय का लेन-देन करें। राज्यपाल को मंत्रालय को बर्खास्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि उसे सदन का विश्वास प्राप्त है। यह है।

केवल वहाँ जहाँ एक मुख्यमंत्री अपने मंत्रालय के बाद इस्तीफा देने से इनकार करता है

अविश्वास प्रस्ताव पर पराजित, कि राज्यपाल राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। राजनीतिक पतन की स्थिति में,

राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत वाली सरकार की सभी संभावनाओं का पता लगाना चाहिए। यदि ऐसी सरकार स्थापित करना संभव नहीं है और यदि बिना टालने योग्य देरी के नए चुनाव कराए जा सकते हैं, तो उन्हें निवर्तमान मंत्रालय (यदि कोई है) से कार्यवाहक सरकार के रूप में बने रहने के लिए कहना चाहिए, बशर्ते -

मंत्रालय को केवल एक मुद्दे पर हराया गया था, जो कुप्रशासन या भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप से असंबद्ध था और इसके लिए सहमत है जारी रखें। राज्यपाल को तब विधान सभा को भंग कर देना चाहिए,

8.20. 4 . राजनीतिक विघटन की समस्या काफी हद तक बनी रहेगी। यदि पैरा 4.20 में की गई सिफारिशों का समाधान किया जाता है। 7 अध्याय 4 में

सदन के नेता (मुख्यमंत्री) के चुनाव और केवल अविश्वास के रचनात्मक मत से सरकार को हटाने के संबंध में स्वीकार किया जाता है और लागू किया जाता है। 8.20. 5 . आम तौर पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा अनुच्छेद 356 (1) के तहत राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर की जानी चाहिए। राज्यपाल की रिपोर्ट एक "बोलने वाला दस्तावेज" होना चाहिए, जिसमें सभी भौतिक तथ्यों और आधारों का एक सटीक और स्पष्ट बयान होना चाहिए, जिसके आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 में अनुध्यात स्थिति के अस्तित्व या अन्यथा के बारे में खुद को संतुष्ट कर सकते हैं।

8.21 . संविधान संशोधन

8.21. 1- अनुच्छेद 356 को मुख्य रूप से खंड 356 (4) के संशोधन और परंतुक के प्रतिस्थापन/चूक के माध्यम से 10 बार संशोधित किया गया है।

अनुच्छेद 356 (5)। ये मूल रूप से प्रक्रियात्मक परिवर्तन थे।

356 , संविधान (44 वां संशोधन) द्वारा यथा संशोधित प्रावधान है कि ऐसी घोषणा जारी होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी घोषणा के लागू रहने के संबंध में कोई प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि

दो शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात्:

(i) कि आपातकाल की घोषणा पूरे देश में लागू है।

भारत का या, यथास्थिति, राज्य के पूरे या किसी भाग में; और

((ii) चुनाव आयोग यह प्रमाणित करता है कि

विस्तारित अवधि के दौरान घोषणा का बल आवश्यक है संबंधित राज्य की विधान सभा के लिए आम चुनाव कराने में कठिनाइयों का कारण।

8.21. 2 . इन दोनों शर्तों को एक साथ पूरा करना घोषणा की निरंतरता के लिए एक पूर्ववर्ती आवश्यकता है। यह समय-समय पर केवल इस खंड के उद्देश्य के लिए संविधान में संशोधन के अवसरों को जन्म दे सकता है जैसा कि पंजाब के मामले में हुआ था। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के बिना भी राज्य विधानसभा के लिए आम चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन जारी रखना आवश्यक हो सकता है। इसलिए, यह अधिक हो सकता है राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए अपनी विशिष्ट परिस्थितियों में प्रत्येक शर्त के संचालन की अनुमति देने वाली दो शर्तों को अलग करना व्यावहारिक है। यह लचीलेपन की अनुमति देगा और संविधान को समय-समय पर इसमें संशोधन करने की आवश्यकता से बचाएगा।

8.21. 3 . आयोग ने सिफारिश की है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (5) में, उपखंड (ए) में "और" अंत में आने वाले शब्द को "या" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि राज्य के आपातकाल की घोषणा के बिना भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सके।

यदि चुनाव नहीं हो सकते हैं तो जारी रखें।

8.21. 4 . जब भी संसद द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत कोई घोषणा जारी और अनुमोदित की जाती है, तो घोषणा के जारी रहने की समीक्षा करना और निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहाल करना आवश्यक हो सकता है। आयोग का विचार है कि इसे खंड (7) के अनुरूप सुरक्षा उपायों को शामिल करके सुरक्षित किया जा सकता है।

और अनुच्छेद 352 का (8)। इसलिए आयोग ने सिफारिश की है कि अनुच्छेद 356 के तहत खंड (6) और (7) को निम्नलिखित [2006] 1 एस. सी. आर. में जोड़ा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पंक्तियाँ: " (6) पूर्वगामी खंडों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, राष्ट्रपति खंड (1) के तहत जारी की गई घोषणा या ऐसी घोषणा में बदलाव करने वाली घोषणा को रद्द कर देगा यदि - लोग इस तरह की घोषणा को जारी रखने को अस्वीकार करते हुए, या, जैसा भी मामला हो, अस्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित करते हैं। (7) जहां कुल राशि के कम से कम दसवें हिस्से द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना हो।

लोक सभा के सदस्यों की संख्या, अस्वीकृति के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के उनके इरादे के बारे में दी गई है, या, जैसा भी मामला है

खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा, बल में बने रहने को अस्वीकृत करने के लिए हो सकती है:

(क) अध्यक्ष को, यदि सदन का सत्र चल रहा है; या

(ख) राष्ट्रपति को, यदि सदन का सत्र नहीं चल रहा है, तो एक विशेष बैठक

सदन की कार्यवाही उस तारीख से चौदह दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी जिस दिन अध्यक्ष को ऐसी सूचना प्राप्त होती है, या, जैसा भी मामला हो।

राष्ट्रपति द्वारा, ऐसे संकल्प पर विचार करने के उद्देश्य से "

8.22- विधानसभा का विघटन

8.22. 1 . जब अनुच्छेद 356 (1) के तहत एक घोषणा जारी करने का निर्णय लिया जाता है, तो विचार के लिए एक मामला पैदा होता है कि क्या विधानसभा को भी भंग किया जाना चाहिए या नहीं। अनुच्छेद 356 में ऐसा नहीं है।

स्पष्ट रूप से विधानसभा के विघटन का प्रावधान है। एक राय यह है कि यदि राष्ट्रपति की घोषणा से दो महीने की समाप्ति तक और संसद के दोनों सदनों से प्राप्त अनुमोदन पर विधानसभा को भंग नहीं किया जाता है, तो यह परिचालन संबंधी वैमनस्य को जन्म देगा। चूँकि संघ या राज्य की कार्यकारी शक्ति क्रमशः अपनी विधायी शक्तियों के साथ व्यापक है, इसलिए सातवीं अनुसूची की सूची दो में राज्य विधानमंडल और संसद दोनों की विधायी और कार्यकारी शक्तियों का द्विसदनीय संचालन लोकतांत्रिक सिद्धांत और संवैधानिक योजना के लिए एक अभिशाप है। हालांकि, बोम्मई के फैसले में बहुमत की राय है कि खंड (3) का तर्क कि अनुच्छेद 356 के तहत जारी की गई प्रत्येक घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी और उसका संचालन बंद हो जाएगा।

दो महीने की समाप्ति पर जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले इसे दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो।

संसद, कार्यपालिका पर संसदीय वर्चस्व स्थापित करने वाली कार्यपालिका की शक्ति पर एक हितकारी नियंत्रण प्रदान करती है। 8.22. 2 आयोग ने रामेश्वर प्रसाद बनाम द्वारा अनुच्छेद 356 के मनमाने उपयोग की बार-बार आलोचना की पृष्ठभूमि में इन दोनों विचारों पर विचार किया।

यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

` 739

कार्यपालक का विचार है कि खंड 3 के तहत प्रदान किया गया चेक अनुच्छेद 356 पहले एक अपरिवर्तनीय निर्णय से अप्रभावी होगा।

संसद को इस पर विचार करने का अवसर मिला है। की शक्ति

अनुच्छेद 354 के साथ अनुच्छेद 356 जो राज्यपाल को अधिकार देता है - विधान सभा को भंग करना। समग्र को ध्यान में रखते हुए

संवैधानिक योजना के अभ्यास को सुरक्षित करने के लिए यह आवश्यक होगा

संसद के समक्ष घोषणा पर विचार

विधानसभा भंग हो जाती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य विधानसभा राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा पहले भंग नहीं किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 356 (1) के तहत जारी की गई घोषणा को पहले रखा गया है। संसद और उसके पास इस पर विचार करने का अवसर था।

बहुत ज्ञानवर्धक चर्चाओं पर ध्यान देना भी उचित होगा।

संविधान सभा जो भूमिका पर प्रकाश डालती है

अनुच्छेद 174 और 356 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के मानदंड

संस्थान।

टचूएंट असेंबली की बैठक 1 जून, 1949 को हुई।

143

संशोधन सं। 2155 और 2156 को स्थानांतरित नहीं किया गया)

एच. वी. कामत (सी. पी. और बेरार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, 1 कदम:

" कि अनुच्छेद 143 के खंड (1) में, शब्द 'जहाँ तक को छोड़कर

वह इस संविधान द्वारा या उसके तहत अपने कार्यों का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित है

या उनमें से किसी को भी उसके विवेकानुसार 'हटा दिया जाए'।

यदि इस संशोधन को सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, तो अनुच्छेद का यह खंड

143 इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

" मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी।

राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रमुख

कार्य "।

महोदय, इस खंड को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि सरकार

1935 के भारत अधिनियम की नकल कम-से-कम अंधाधुंध रूप से की गई है।

परिपक्व विचार। [2006] 1 एस. सी. आर. देने का कोई ठोस या वैध कारण नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्यपाल को या तो अपने विवेक से या अन्यथा अपने मंत्रियों की तुलना में अधिक अधिकार दिए गए हैं, जो राष्ट्रपति को दिए गए हैं -

उनके मंत्री। यदि हम अनुच्छेद 61 (1) की ओर मुड़ते हैं, तो हम पाते हैं कि यह इस प्रकार है:

" मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी।

राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए प्रमुख

कार्य "।

महोदय, जब आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, तो दूसरे दिन डॉ. अम्बेडकर ने इस खंड को यह कहते हुए स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति अपने सभी कार्यों को करने में अपने मंत्रियों की सलाह को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन यहाँ अनुच्छेद 143 में कुछ विवेकाधीन

शक्तियाँ निहित हैं - राज्यपाल, और मुझे ऐसा लगता है कि भले ही यह था, यह काफी बुरा था, लेकिन अब राज्यपाल के चुनाव के संबंध में अनुच्छेद 131 में संशोधन करने और नामित राज्यपालों को स्वीकार करने के बाद, यह सिद्धांत रूप में गलत होगा और राज्यपाल के सिद्धांतों और सिद्धांतों के विपरीत होगा।

संवैधानिक सरकार, जिसे आप इस देश में बनाने जा रहे हैं। मैं यह कहना गलत होगा कि इनके साथ एक राज्यपाल का निवेश करना गलत होगा।

अतिरिक्त शक्तियाँ, अर्थात् विवेकाधीन शक्तियाँ। मुझे लगता है कि आपातकाल के कारणों को छोड़कर संवैधानिक सरकार के सिद्धांतों से कोई विचलन नहीं होना चाहिए और इन विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत होगा। मैं चलता हूँ, साहब।

प्रो. के. टी. शाह (बिहार: जनरल) अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूँ:

" कि अनुच्छेद 143 के खंड (1) में 'हेड ए अल्पविराम' शब्द के बाद

शब्द रखे जाएँ और 'कौन राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा'

और शब्द डाला जाएगा और 'हटा दिया जाएगा'।

ताकि संशोधित अनुच्छेद पढ़ा जा सके।

" (1) मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी और राज्यपाल को अपने कार्यों आदि के निर्वहन में सहायता और सलाह देगी। महोदय, यह इस प्रारूप संविधान के सामान्य सिद्धांत का एक तार्किक परिणाम है, अर्थात्, सरकार को विधायिका के प्रति पूरे मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी पर होना है। साथ ही मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या जो भी शीर्षक से उनका वर्णन किया जाता है, वे प्रधान सलाहकार होंगे और मैं संविधान द्वारा निश्चित रूप से 741 पर जिम्मेदारी तय करना चाहूंगा।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। 0. 1 यू. [पासायत, जे।]

मुख्यमंत्री, व्यक्तिगत मंत्री एक ही पद पर नहीं होते हैं। मंत्रिमंडल के भीतर जो भी प्रक्रिया या परंपरा हो, हालांकि मंत्रिमंडल के निर्णय लिए जा सकते हैं, जहां तक राज्यपाल का संबंध है, मैं यह मानता हूं कि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी जो इसके बारे में भी सलाह देंगे।

यदि आवश्यक हो तो उनके सहयोगियों की नियुक्ति या उन्हें हटाया जाना। यह केवल चीजों की फिटनेस में है कि उसे सीधे बनाया जाना चाहिए

के संवैधानिक प्रमुख को दी गई किसी भी सलाह के लिए जिम्मेदार

राज्य, अर्थात् राज्यपाल। जैसा कि यह, मेरी राय में, उन सिद्धांतों से एक स्पष्ट परिणाम है जिन्हें हमने अब तक स्वीकार किया है, मुझे उम्मीद है कि इस संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

(संशोधन सं। 2159 से 2163 तक स्थानांतरित नहीं किए गए थे।)

अध्यक्ष महोदय: कोई अन्य संशोधन नहीं है। अनुच्छेद और संशोधन चर्चा के लिए खुले हैं। श्री टी. टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मुझे डर है कि मुझे अपने माननीय मित्र श्री कामत द्वारा पेश किए गए संशोधन का विरोध करना पड़ेगा, केवल इस कारण से कि उन्होंने इसके दायरे को स्पष्ट रूप से नहीं समझा है और उनका संशोधन एक गलतफहमी से उत्पन्न होता है।

महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अनुच्छेद के कुछ शब्दों को हटाया जा सकता है, अर्थात् वे जो राज्यपाल द्वारा अपने कार्यों के अभ्यास का उल्लेख करते हैं, जहां उन्हें अपने मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह के बावजूद अपने विवेक का उपयोग करना होता है। वास्तव में, मुझे लगता है कि यह अधिक है

अपने मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के बावजूद अपने विवेक से कार्य करने का अधिकार। बनाने के दो तरीके हैं विचार इसके अंतर्गत आता है। एक इस अनुच्छेद 143 में इस अपवाद का उल्लेख करना है और राज्यपाल की विशिष्ट शक्ति की गणना करना है जहां वह बाद में होने वाली अपनी विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, या इस शक्ति का कोई भी उल्लेख यहां छोड़ सकता है और केवल राज्य ही उचित है। पूर्व विधि का पालन किया गया है। यहाँ सामान्य प्रस्ताव कहा गया है कि राज्यपाल को आम तौर पर इस पर कार्य करना होता है

अपने मंत्रियों की सलाह को छोड़कर जहाँ तक संविधान में उनके विवेकाधिकारों का प्रयोग किया गया है जिसमें वे विशेष रूप से शामिल हैं। अपने विवेक से कार्य करने का अधिकार। जब तक कि संविधान में बाद में आने वाले अनुच्छेद हैं जहां उन्हें अपने विवेक से कार्य करने के लिए कहा जाता है, जो पूरी तरह से [2006] 1 एस. सी. आर. से प्रस्थान के सभी मामलों को शामिल करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिस सामान्य प्रथा पर मैं अपने माननीय मित्र श्री कामत को देखता हूं, उसे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अनुच्छेद 188 का उल्लेख कर सकता हूं। हम इस अनुच्छेद के प्रावधान में कोई हानि नहीं देखते हैं। ऐसा होता है कि यह सदन निर्णय करता है कि बाद के सभी अनुच्छेदों में, विवेकाधीन शक्ति

वहाँ नहीं होना चाहिए, जैसा कि यह कल्पना की जा सकती है, इस विशेष प्रावधान का कोई उपयोग नहीं होगा और यह बेकार हो जाएगा। बात यह है कि मेरा

माननीय मित्र यह कहने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वे स्वीकार करते हैं कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति अनुच्छेद 188 के तहत दी जा सकती है, जो व्यर्थ प्रतीत होती है। यदि इसे अनुच्छेद 188 में दिया जाना है, तो यहां इसका उल्लेख करने में कोई बुराई नहीं है। कोई नुकसान नहीं हो सकता है अनुच्छेद 143 के इस अपवाद का विशिष्ट उल्लेख। अतः श्री कामत को इस अपवाद का उल्लेख करने पर जो गंभीर आपत्ति है, वह यह है -

जैसा कि है। डॉ. पी. एस. देशमुख (सी. पी. और बरारः जनरल): अध्यक्ष महोदय, श्री टी. टी. कृष्णमाचारी ने इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट की है।

अपवाद जो अनुच्छेद 143 के खंड (1) में जोड़ा गया है। यदि वास्तव में राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति होने जा रही है, तो यह आवश्यक है कि यह खंड जिसे श्री कामत छोड़ना चाहते हैं, अवश्य हटा दिया जाए।

महोदय, इसके अलावा, मुझे नहीं पता कि मसौदा समिति ने जानबूझकर इसे हटा दिया है या वे इसे बाद में प्रदान करने जा रहे हैं, और मैं डॉ. अम्बेडकर से पूछना चाहूंगा कि क्या यह आवश्यक नहीं है राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने का प्रावधान। मुझे यहाँ इस आशय का कोई प्रावधान नहीं मिलता है। चूँकि यह अनुच्छेद 143 भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 50 का मात्र पुनरुत्पादन है, जहाँ यह प्रावधान मौजूद है कि राज्यपाल अपने विवेक से मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कर सकते हैं, मुझे लगता है कि यह शक्ति बहुत आवश्यक है। अन्यथा, मंत्री राज्यपाल को किसी भी बैठक से बाहर कर सकते हैं और यह शक्ति जब तक विशेष रूप से प्रदान नहीं की जाती, तब तक राज्यपाल को उपलब्ध नहीं होगी।

राज्यपाल। मैं रामेश्वर प्रसाद v के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इसके लिए समिति का मसौदा तैयार करना और यह देखना कि क्या अनुच्छेद 143 में संशोधन को इसे छोड़कर स्वीकार करना संभव है या इस प्रावधान को किसी अन्य भाग में करना संभव है। मेरा मानना है कि राज्यपाल की मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने की यह शक्ति अनिवार्य है और होनी चाहिए।

प्रदान करने के लिए।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद में कहा गया है -

राज्यपाल को अपने कार्य में सहायता और सलाह देने के लिए
कार्य "।

महोदय, मैं एक संवैधानिक वकील नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रावधानों के अनुसार

इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब केवल यह है कि मंत्रियों को राज्यपाल को सलाह देने का अधिकार है। राज्यपाल इस तरह की सलाह को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है।

प्रशासन के एक अन्य क्षेत्र में राज्यपाल अपने विवेक से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकता है। इस क्षेत्र में मंत्रालय को कोई सलाह देने का अधिकार नहीं है। बेशक यह खुला छोड़ दिया जाता है राज्यपाल इस क्षेत्र में भी मंत्रियों की सलाह देते हैं।

मुझे लगता है कि हमने स्थिति के वर्तमान तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा है। हमने दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों की नकल करने और उनका अनुकरण करने का प्रयास किया है। समय की आवश्यकता यह है कि राज्यपाल को न केवल अपने विवेक से कार्य करने की शक्ति दी जानी चाहिए, बल्कि अपने व्यक्तिगत निर्णय में कार्य करने की शक्ति भी दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए। जिम्मेदारियाँ जो ब्रिटिश शासन के तहत राज्यपाल को इस देश में निहित थीं। मुझे लगता है कि प्रांतों में नेतृत्व की कमी है। सक्षम पुरुष उपलब्ध नहीं हैं और सभी प्रकार के हैं

विभिन्न प्रांतों में चीजें चल रही हैं। जब तक राज्यपाल नहीं है बड़ी शक्तियों के साथ प्रांतीय प्रशासन में कोई सुधार करना मुश्किल होगा। ऐसी प्रक्रिया हो सकती है

अलोकतांत्रिक लेकिन इस तरह की प्रक्रिया देश के हित में पूरी तरह से सही होगी। मुझे लगता है कि इस देश के मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों में कोई रचनात्मक ऊर्जा नहीं बची है। ऐसा

लगता है कि वे पहल और उद्यम से वंचित हो गए हैं। जिन जनता को इस देश का शासक होना चाहिए, वे हर तरह से कुचले हुए हैं और उनका शोषण किया जाता है। इन परिस्थितियों में भारत सरकार के लिए प्रांतीय प्रशासन को अपने हाथों में लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।

मैं उच्च न्यायालय की रिपोर्ट महसूस करता हूँ

[2006] 1

एस सी आर।

कि हम इस देश में क्रांति की दहलीज पर हैं। इस देश में क्रांति, रक्तपात और अराजकता होगी। मुझे लगता है कि

मैं इस अनुच्छेद का विरोध करता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि संघवाद उस देश में सफल नहीं हो सकता है जो एक अस्थायी दौर से गुजर रहा है। अवधि। अमेरिका की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से विकसित है। यह सरकार का एक संघीय रूप रखने का जोखिम उठा सकता है। ऐसे देश में जहाँ

विस्तार के लिए कोई जगह नहीं है और आर्थिक विकास के लिए केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में जब हमारे

कृषि, उद्योग, खनिज आदि विकास के प्रारंभिक चरण में हैं, यह आवश्यक है कि सत्ता हाथों में निहित हो भारत सरकार की ओर से। संघवाद 19 वीं सदी में प्रचलन में था।

उस शताब्दी में जब संचार के साधन अविकसित थे। प्राचीन काल में सरकारों के पास तकनीकी ज्ञान और संसाधन बहुत कम थे। आज स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। संचार के साधन तेजी से विकसित हुए हैं। तकनीकी ज्ञान और आवश्यक कर्मी

भारत सरकार का निपटान इतना व्यापक है कि वह उन सभी कार्यों को करने का कार्य कर सकती है जो एक आधुनिक

सरकार से प्रदर्शन करने की उम्मीद है। एक और कारण है कि मैं इस अनुच्छेद का विरोध करता हूँ। इस देश में संघवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। सभी सरकारें कमोबेश एकात्मक हो गई हैं।

चरित्र। अगर हमें राजनीतिक पराजय, आर्थिक गला घोंटने और सभी मोर्चों पर सैन्य हार से बचना है, तो हमारे नेताओं और राजनेताओं को अपरंपरागत शब्दों में सोचना सीखना चाहिए: अन्यथा इस देश का कोई भविष्य नहीं है।

पंडित हिरदे कुंजरू: (संयुक्त प्रांत: सामान्य): अध्यक्ष महोदय, मैं डॉ. अम्बेडकर से पूछना चाहता हूं कि क्या इन शब्दों के बाद यह बनाए रखना आवश्यक है कि "राज्यपाल को उनके मंत्रियों द्वारा सहायता और सलाह दी जाएगी", ये शब्द "कुछ मामलों के संबंध में हैं जिनके संबंध में उन्हें अपने विवेक का प्रयोग करना है"। मान लीजिए कि ये शब्द, जो भारत सरकार के पुराने अधिनियम और पुरानी व्यवस्था की याद दिलाते हैं, हटा दिए गए हैं, तो क्या नुकसान होगा? मंत्रियों के कार्य

कानूनी रूप से केवल राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए होगा। जिस अनुच्छेद में ये शब्द पाए जाते हैं, उसमें यह नहीं कहा गया है कि राज्यपाल अपने मंत्रियों की सलाह से निर्देशित होगा, लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि 745 में

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. (पासायत, जे।)

सभी देशों में प्रचलित संवैधानिक प्रथा के अनुसार। जहाँ जिम्मेदार सरकार है वहाँ राज्यपाल सभी मामलों में अपने मंत्रियों की सलाह स्वीकार करेगा। हालाँकि इसका यह अर्थ नहीं है कि जहां क़ानून स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट के संबंध में उस कार्रवाई को निर्धारित करता है वे मामलों को अपने अधिकार पर ले सकते हैं, यह अनुच्छेद 143 उनके रास्ते में खड़ा होगा।

मेरे मित्र श्री टी. टी. कृष्णमाचारी ने कहा कि चूंकि संविधान के अनुच्छेद 188 ने राज्यपाल को अपने मंत्रियों की सलाह की अवहेलना करने और प्रांत का प्रशासन अपने हाथों में लेने का अधिकार दिया है, इसलिए यह आवश्यक था कि इन शब्दों को बनाए रखा जाए, यानी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति को बनाए रखा जाए। लेकिन अगर,

उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अनुच्छेद 188 को बाद में हटा दिया गया था, अनुच्छेद 143 के शब्दों पर पुनर्विचार किया जा सकता है। मैं इस स्थिति को पूरी तरह से समझता हूं और इसकी सराहना करता हूं, लेकिन मुझे उन शब्दों को पसंद करना चाहिए जिन पर मेरे दोस्त ने आपत्ति जताई है।

कि यह पुरानी व्यवस्था का एक अप्रिय अनुस्मारक है और जो हमें यह महसूस कराता है कि हालांकि किसी भी निर्णय को पलटना बाद में संभव हो सकता है जिस पर सदन अभी आ सकता है, लेकिन सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इसे एक सिद्ध तथ्य के रूप में माना जा सकता है? महोदय, इन कारणों से मेरे माननीय मित्र श्री कामत के संशोधन को स्वीकार करना और फिर अनुच्छेद 157 और 188 के गुण-दोष पर चर्चा करना बेहतर होगा। बंद करने से पहले मैं

एक शब्द और कहना चाहूंगा। यदि अनुच्छेद 143 को उसके वर्तमान रूप में पारित किया जाता है, तो यह उस तरह की गलतफहमी को जन्म दे सकता है जिसके तहत मेरे माननीय मित्र डॉ. देशमुख काम कर रहे थे, जब उन्होंने कहा था कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने का अधिकार देने वाला एक प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए। संविधान का मसौदा इसके लिए प्रावधान नहीं करता है और मुझे लगता है कि बुद्धिमानी से इसके लिए प्रावधान नहीं है। यह [2006] 1 एस. सी. आर. की परंपराओं के विपरीत होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिम्मेदार सरकार के रूप में वे महान ब्रिटिश में स्थापित किए गए हैं

और ब्रिटिश अधिराज्य, कि गवर्नर या गवर्नर-जनरल को, अधिकार के रूप में, अपने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करनी चाहिए। संविधान का मसौदा केवल मुख्यमंत्रियों पर निर्भर करता है

संविधान की सावधानी से। यह एक अतिरिक्त कारण है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति का उल्लेख क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 143। मेरे मित्र श्री कृष्णमाचारी के भाषण में यह उम्मीद नहीं है कि मैंने जो सुझाव दिया है, उसे स्वीकार किए जाने की कोई संभावना है। फिर भी, मैं यह कहना अपना कर्तव्य समझता हूं कि श्री कामत द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम प्रारूपण उप-समिति द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम से बेहतर है।

प्रो. शिबबन लाल सक्सेना (संयुक्त प्रांत: सामान्य); अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने माननीय मित्र श्री कृष्णमाचारी का भाषण और शब्दों को बनाए रखने के लिए उनके तर्कों को बहुत ध्यान से सुना।

जिसे श्री कामत छोड़ना चाहते हैं। अगर राज्यपाल एक निर्वाचित राज्यपाल होते, तो मैं समझ सकता था कि उनके पास ये विवेकाधीन शक्तियां होनी चाहिए थीं। लेकिन अब हमारे पास नामित राज्यपाल हैं जो राष्ट्रपति की खुशी के दौरान कार्य करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे व्यक्तियों को ऐसी शक्तियां दी जानी चाहिए जो अनुच्छेद 188 में अनुध्यात हैं।

फिर, यदि अनुच्छेद 188 पर अभी चर्चा की जानी है और इसे अस्वीकार किया जा सकता है तो इस अनुच्छेद में इन शक्तियों को पहले से देना उचित नहीं है। यदि अनुच्छेद 188 पारित हो जाता है, तो हम इस अनुच्छेद पर पुनर्विचार कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो इस खंड को

जोड़ सकते हैं। हमें पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सदन में जो कुछ भी कहा गया है, उसके बाद हम अनुच्छेद 188 पारित करेंगे।

ये शब्द अपमानजनक अतीत की याद दिलाते हैं। मुझे डर है कि अगर इन शब्दों को बरकरार रखा जाता है, तो कुछ राज्यपाल उनकी नकल करने की कोशिश कर सकते हैं।

अतीत के राज्यपाल और उन्हें उदाहरण के रूप में उद्धृत करते हैं, कि इस तरह के अवसर पर राज्यपाल ने अपने विवेकानुसार कार्य किया। मुझे लगता है कि हमारे संविधान में जैसा कि हम अब इसे तैयार कर रहे हैं, राज्यपालों की ये शक्तियां जगह से बाहर हैं; और माननीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत से कम किसी व्यक्ति ने संशोधन की सूचना दी थी जो 747 था।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [पासायत। जे.]

आपातकाल, प्रांत के प्रीमियर खुद आगे आएंगे राज्यपाल से अनुरोध करें कि आपातकाल घोषित किया जाए और आपातकाल से निपटने के लिए केंद्र की सहायता प्राप्त की जाए। क्यों?

क्या राज्यपाल को प्रांत के प्रधानमंत्री के सिर पर आपातकाल की घोषणा करनी चाहिए? हमें यह देखना चाहिए कि किसी प्रांत के प्रधानमंत्री और राज्यपाल के बीच इस तरह के अवसर पर टकराव न हो। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जानी चाहिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्हें सरकार चलानी चाहिए, और फिर भी सरकार उनके विरोध के बावजूद उनके सिर पर आपातकाल की घोषणा करती है। यह होगा। प्रधानमंत्री को बिल्कुल नपुंसक बना दें। मुझे लगता है कि एक शरारती राज्यपाल ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश भी कर सकता है अगर वह ऐसा करने का फैसला करता है, या अगर राष्ट्रपति चाहता है कि वह किसी प्रांत में ऐसा करे जब केंद्र में सत्ता में उसके विपरीत कोई पार्टी सत्ता में हो। मेरा मानना है कि अनुच्छेद 188, भले ही इसे बनाए रखा जाना हो, को इस तरह से संशोधित किया जाना चाहिए कि प्रांत के प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए। मैं डॉ. अम्बेडकर को सुझाव देता हूं कि इन शब्दों को जगह नहीं मिलनी चाहिए।

इस अनुच्छेद में, और एक परिणामी संशोधन के रूप में, इस अनुच्छेद की उप-धारा (ii) को भी हटा दिया जाना चाहिए।

श्री महावीर त्यागी (संयुक्त प्रांत: सामान्य): महोदय, मैं अपने सम्मानित कट्टरपंथी मित्रों श्री कामत और प्रो. शिबबन लाल सक्सेना, और मुझे लगता है कि प्रांतों को जितनी अधिक

शक्तियां दी जाती हैं, केंद्र की संरक्षकता और नियंत्रण उतना ही सख्त होना चाहिए। उन शक्तियों का प्रयोग करें। यही मेरा दृष्टिकोण है। हमने अब केंद्र को छोड़ दिया है, और हम राज्यपालों को नामित करने जा रहे हैं। वे।

राज्यपालों को बिना किसी कारण के वहाँ नहीं होना चाहिए। आखिरकार, हमें यह देखना होगा कि केंद्र की नीति को लागू किया जाए। हमें राज्यों को एक साथ जोड़ना होगा और राज्यपाल एजेंट हैं या वे ही हैं।

एजेंसी जो केंद्रीय नीति के लिए दबाव डालेगी और उसकी रक्षा करेगी। वास्तव में, हमारी पिछली अवधारणा अब पूरी तरह से बदल गई है। किसी भी देश का पूरा राजनीतिक शरीर केंद्र की नीति से प्रभावित और प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए शांति या युद्ध, विदेशों के साथ संबंधों से जुड़े रक्षा जैसे विषयों को लें।

वाणिज्यिक संबंध, निर्यात और आयात। ये सभी ऐसे विषय हैं जो पूरे राजनीतिक निकाय को प्रभावित करते हैं और प्रांत नहीं रह सकते हैं। अप्रभावित, उन्हें केंद्र की नीति से मुक्त नहीं छोड़ा जा सकता है।

केंद्र में अपनाई जाने वाली नीति का सभी राज्यों को पालन करना चाहिए और यदि राज्यपाल प्रांतीय मंत्रियों के हाथों में हों तो विभिन्न प्रांतों में विभिन्न नीतियां होंगी और प्रत्येक प्रांत की नीति मंत्रालय की तरह ही अस्थिर होगी। क्योंकि विभिन्न प्रकार के मंत्री होंगे जिनके अलग-अलग पार्टी लेबल और अलग-अलग कार्यक्रम होंगे। उनकी नीतियां एक से अलग होनी चाहिए।

दूसरा; इसलिए यह और भी आवश्यक होगा कि राज्यों और राज्यों के बीच कार्यक्रमों और नीतियों का समन्वय होना चाहिए।

केंद्र सरकार। राज्यपाल केंद्र की एजेंसी होने के नाते विभिन्न प्रांतों या राज्यों को एकीकृत करने की एकमात्र गारंटी है। द. केंद्र सरकार भी प्रांतीय राज्यों के माध्यम से खुद को व्यक्त करती है; अपने स्वयं के प्रशासन के साथ, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से भी काम करना पड़ता है। राज्यपाल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

और देखेंगे कि केंद्रीय नीति को ईमानदारी से लागू किया जाता है। इसलिए राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक रुझान एक जंगली जानवर की तरह हैं। आप जो चाहें कहें, लोकतंत्र दलों और जनता की सनक और इच्छाओं के अनुसार चलता है। कुछ ऐसी मशीनरी होनी चाहिए जो इस जंगली जानवर को नियंत्रण में रखे। मैं लोकतंत्र की निंदा नहीं करता। लोकतंत्र का अपना रास्ता होना चाहिए। लेकिन इसे अराजकता में बदलने न दें। इसके अलावा राज्य सरकारें अपनी नीतियों में काफी सुसंगत नहीं हो सकती हैं।

सरकारें महीनों या वर्षों के बाद बदल सकती हैं; उनके साथ अपनी नीतियां बदलेंगी। राज्यपाल भी बदल सकते हैं, लेकिन केंद्र द्वारा राज्यपालों को दी गई नीति और निर्देश व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तित रहेंगे। राज्यों को जितनी अधिक शक्तियां दी जाएंगी, नियंत्रण उतना ही अधिक सतर्क होना चाहिए। राज्यपाल को एक तरफ केंद्रीय नीति और दूसरी तरफ संविधान के संरक्षक के रूप में रहना चाहिए। इसलिए उसकी शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

श्री बी. एम. गुप्ता (बाम्बे: जनरल): महोदय, मेरा मानना है कि मेरे माननीय मित्र श्री टी. टी. कृष्णमाचारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को सदन द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए और राज्यपाल के विवेक से संबंधित शब्दों को तब तक चलने दिया जाना चाहिए जब तक कि हम अनुच्छेद 175 और अनुच्छेद 188 का निपटारा नहीं कर देते।

माननीय डॉ. देशमुख द्वारा दिए गए सुझाव के संबंध में

राज्यपाल को मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने की शक्ति दिए जाने के बारे में मुझे इसका विरोध करना होगा। उन्होंने पूछा कि क्या मसौदा समिति बाद में उस प्रावधान को बनाने का इरादा रखती है। मुझे भविष्य के लिए मसौदा समिति के इरादों के बारे में नहीं पता है, लेकिन रामेश्वर प्रसाद बनाम के रूप में।

जहाँ तक हमारे सामने मसौदे का सवाल है, मुझे लगता है कि मसौदा समिति ने निश्चित रूप से इसे खारिज कर दिया है।

मैं माननीय सदन का ध्यान अनुच्छेद 147 की ओर आकर्षित करूंगा, जिसके तहत राज्यपाल को केवल जानकारी का अधिकार होगा। यदि हम उन्हें मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने की

अनुमति देते हैं तो हम उन्हें उस पद से हट जाएंगे जो हम उन्हें देना चाहते हैं, अर्थात् एक संवैधानिक प्रमुख का। यदि वह मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तो उसके पास प्रशासन के पूरे क्षेत्र में मंत्रिमंडल के निर्णयों को आकार देने में एक प्रभावी आवाज होगी, यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जो उसकी विवेकाधीन शक्ति के लिए आरक्षित नहीं हैं। यदि उन्हें कुछ शक्तियाँ दी जानी हैं, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उन्हें यथासंभव सीमित किया जाए, ताकि संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल का पद बनाए रखा जा सके। इसलिए महोदय, 1 डॉ. देशमुख के प्रस्ताव का विरोध करते हैं।

श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर (मद्रास: सामान्य): महोदय, वास्तव में विरोध करने वालों और अनुमोदन करने वालों में कोई अंतर नहीं है।

संशोधन। सबसे पहले, अनुच्छेद 143 में सामान्य सिद्धांत अर्थात् मंत्री जिम्मेदारी का सिद्धांत निर्धारित किया गया है, कि राज्यपाल को कार्यकारी गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में अपने मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना चाहिए। फिर लेख प्रदान करता है " सिवाय इसके कि जहाँ तक वह इस संविधान द्वारा या उसके तहत अपने या उनमें से किसी भी कार्य को अपने विवेक से करने के लिए अपेक्षित है। जब तक संविधान में ऐसे अनुच्छेद हैं जो राज्यपाल को अपने विवेक से और कुछ परिस्थितियों में कार्य करने में सक्षम बनाते हैं, तब तक यह हो सकता है कि वह मंत्रिमंडल का उल्लंघन करे या राष्ट्रपति को संदर्भित करे, यह अनुच्छेद जैसा कि इसे बनाया गया है, पूरी तरह से क्रम में है। यदि बाद में सदन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वे अनुच्छेद जो राज्यपाल को विशिष्ट मामलों में अपने विवेक से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, तो वह इस अनुच्छेद को संशोधित करने के लिए खुला रहेगा। लेकिन जब तक बाद के अनुच्छेद हैं जो राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की अनुमति देते हैं न कि मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारी पर, तब तक मसौदा तैयार किया गया अनुच्छेद पूरी तरह से क्रम में है।

एकमात्र अन्य प्रश्न यह है कि क्या पहले अनुच्छेद 143 में एक प्रावधान किया जाए कि राज्यपाल मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारी पर कार्य करेगा और फिर "अनुच्छेद 143 में कुछ भी निहित होने के बावजूद वह ऐसा कर सकता है" या "अनुच्छेद 143 में कुछ भी निहित होने के बावजूद वह अपने विवेक से कार्य कर सकता है"। मुझे लगता है कि अनुच्छेद 143 में ही यह प्रावधान करने के लिए मसौदा तैयार करने का यह एक बेहतर तरीका है कि राज्यपाल हमेशा [2006] 1 एस. सी. आर. को छोड़कर मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारी पर कार्य करेगा।

विशेष या विशिष्ट मामले जहां उसे अपने मामले में कार्य करने का अधिकार है।

विवेकपूर्ण। यदि निश्चित रूप से सदन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी भी मामले में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य नहीं करेगा, तो वह प्रत्येक मामले में मामला केवल मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारी पर कार्य करता है, तब इस अनुच्छेद में परिणामी परिवर्तन होगा। अर्थात्, उन अनुच्छेदों के बाद

इस पर विचार किया गया और पारित किया गया, यह सदन के लिए अनुच्छेद 143 के उत्तरार्द्ध भाग को हटाने के लिए काफी खुला होगा क्योंकि यह बाद के अनुच्छेदों पर सदन द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप है। लेकिन, जैसा कि यह है, यह पूरी तरह से क्रम में है और 1 को नहीं लगता कि अनुच्छेद 143 की भाषा में कोई बदलाव आवश्यक है। "अनुच्छेद 143 में कुछ भी निहित होने के बावजूद राज्यपाल अपनी जिम्मेदारी से कार्य कर सकता है", प्रत्येक के उद्घाटन पर यह कहना कठोर होगा।

श्री एच. वी. कामथ: महोदय, स्पष्टीकरण के एक बिंदु पर, महोदय, मुझे पता है कि ऐसा क्यों है कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कम से कम राज्यपालों को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, शायद इससे भी अधिक, राष्ट्रपति में इस तरह की विवेकाधीन शक्तियां निहित नहीं की गई हैं। लेकिन केवल राज्यपालों में?

पंडित ठाकुर दास भार्गव (पूर्वी पंजाब: सामान्य): महोदय, मैं श्री कामत के संशोधन का विरोध करता हूँ। अनुच्छेद 143 के तहत राज्यपाल मंत्रिपरिषद द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता की जाएगी। यह अब तक स्पष्ट है। मैंने एक संशोधन की सूचना दी जो आदेश पत्र पर अनुच्छेद 142-ए के रूप में दिखाई देता है जिसे मैंने पेश नहीं किया है। संशोधन में

मैंने सुझाव दिया है कि राज्यपाल उन सभी मामलों को छोड़कर सभी मामलों पर अपने मंत्रियों की सलाह को स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे जो इस संविधान के तहत उनके द्वारा अपने विवेक से प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि यह कहना गलत है कि राज्यपाल एक नकली या स्वचालित होगा। वास्तव में मेरे अनुसार राज्यपाल बहुत व्यापक शक्तियों और बहुत महत्वपूर्ण शक्तियों का भी प्रयोग करेगा। अगर हम अनुच्छेद 144 को देखें तो

कहते हैं:

" राज्यपाल के मंत्रियों की नियुक्ति उनके द्वारा की जाएगी और

अपनी खुशी के दौरान पद धारण करें।

इसलिए उसके पास अपने मंत्रियों को नियुक्त करने की शक्ति है। लेकिन जब मंत्री

क्या वे अस्तित्व में नहीं हैं जो उसे अपने कार्यों के निर्वहन में सलाह देंगे? जब वह अपने मंत्रालय को बर्खास्त कर देता है तो भी वह अपने विवेक के तहत अपने कार्यों का प्रयोग करेगा।

फिर, जब राज्यपाल किसी दल के नेता से रामेश्वर प्रसाद के लिए मुलाकात करता है।

मंत्रियों का चयन, पिछले मंत्रालय के भंग होने के बाद, उस स्थिति में कोई मंत्रालय अस्तित्व में नहीं होगा; और उसे सलाह देने के लिए कौन होगा? इसलिए वह अपने विवेक से अपने कार्यों का प्रयोग करेगा। यह मान लेना गलत है कि राज्यपाल को किसी भी कार्य का प्रभार नहीं दिया जाएगा जिसका वह अपने विवेक से प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 175 और 188 अन्य अनुच्छेद हैं जो उन्हें कुछ कार्य प्रदान करते हैं जिनका उन्हें अपने विवेक से प्रयोग करना होता है।

अनुच्छेद 144 (4) के तहत निर्देश पत्र का उल्लेख है जो चौथी अनुसूची में दिया गया है। इसका अंतिम अनुच्छेद चलता है।

इस प्रकार:

" राज्यपाल मानकों को बनाए रखने के लिए वह सब कुछ करेगा जो उसके अंदर झूठ है।

अच्छे प्रशासन के लिए, नैतिकता के लिए सभी उपायों को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक और आर्थिक कल्याण और सभी वर्गों के लिए उपयुक्त

सार्वजनिक जीवन और सरकार में अपना उचित हिस्सा लेने के लिए जनसंख्या राज्य का, और सभी वर्गों और संप्रदायों के बीच सुरक्षित करने के लिए

धर्म की मान्यताओं के लिए संचालन, सद्भावना और आपसी सम्मान और

भावनाएँ "।

मेरा निवेदन है कि मेरे अनुसार राज्यपाल मंत्रालय के साथ-साथ आम लोगों के लिए एक मार्गदर्शक, दार्शनिक और मित्र होगा, ताकि वह कुछ कार्यों का प्रयोग करे जिनमें से कुछ अलिखित सम्मेलनों की प्रकृति के होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो इस संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाएंगे। वह पार्टी से ऊपर के व्यक्ति होंगे और वह मंत्री और सरकार को एक अलग

दृष्टिकोण से देखेंगे। वह मंत्रियों और विधायिका के सदस्यों को इस तरह से प्रभावित करने में सक्षम होंगे कि प्रशासन सुचारू रूप से चले। वास्तव में यह कहना कि उनके जैसा व्यक्ति केवल एक नकली, एक स्वचालित या बिना शक्तियों वाला गणमान्य व्यक्ति है, पूरी तरह से उचित है। गलत है। यह बिल्कुल सही है कि जहां तक संवैधानिक राज्यपाल की हमारी अवधारणा की बात है, उसे कई मामलों में अपने मंत्रियों की सलाह स्वीकार करनी होगी, लेकिन कई अन्य मामले हैं जिनमें न तो सलाह उपलब्ध होगी और न ही वह उस सलाह को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा।

(जोर देने के लिए रेखांकित)

अनुच्छेद 147 के तहत राज्यपाल के पास सूचना मांगने की शक्ति है और भाग (सी) कहता है: यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा।

" यदि राज्यपाल ऐसा चाहता है, तो विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए

मंत्रिपरिषद का कोई भी मामला जिस पर निर्णय [2006] 1 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक मंत्री द्वारा लिया गया था लेकिन जिस पर विचार नहीं किया गया है

परिषद।"

यह विशेष रूप से एक ऐसा मामला है जिसका बहुत महत्व है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को किसी भी मामले को रखने के लिए कहने के लिए सक्षम है

वह जानकारी मांगता है कि वह अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कार्य करेगा। वह किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कॉल कर सकता है। इस शक्ति के साथ वह होगा

गैर-जिम्मेदाराना कार्य करने से मंत्रालय को नियंत्रित करने और रोकने में सक्षम। मेरी राय में राज्यपाल को ऐसे लेना जैसा कि उनके अधीन होने की कल्पना की जाती है

श्री एच. वी. पाटस्कर (बाम्बे: सामान्य): महोदय, अनुच्छेद 143 पूरी तरह से स्पष्ट है। मेरे माननीय मित्र श्री कामत के संशोधन के संबंध में

विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे, क्या राज्यपाल को केवल एक व्यक्ति-प्रमुख, चाहे वह केवल एक संवैधानिक प्रमुख होना है या उसके पास विवेकाधीन शक्तियाँ होनी हैं। मेरे विचार से इस प्रश्न को पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 143 केवल मंत्रियों के कार्यों से संबंधित है। यह मुख्य रूप से राज्यपाल की शक्ति और कार्यों से संबंधित नहीं है। यह केवल कहता है:

राज्यपाल को अपने कार्य में सहायता और सलाह देने के लिए
कार्य "।

यह मानते हुए कि हम वहाँ रुकते हैं, क्या यह संभावना है कि कोई जटिलता उत्पन्न होगी या यह विवेकाधीन शक्तियों में हस्तक्षेप करेगा जो हैं

राज्यपाल को देने का प्रस्ताव? मेरे विचार में अनुच्छेद 188 संभवतः आवश्यक है और मेरा मतलब एक पल के लिए यह सुझाव देना नहीं है कि आपातकाल में कार्य करने की राज्यपाल की शक्तियां जो अनुच्छेद 188 के तहत दी गई हैं, वहां नहीं होनी चाहिए। मेरा मुद्दा यह है, चाहे यह प्रावधान हो।, " सिवाय इसके कि जहाँ तक वह इस संविधान द्वारा या उसके तहत अपने कार्यों का या उनमें से किसी का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित है।

विवेकाधिकार ", वहाँ नहीं है, क्या यह उन शक्तियों को प्रभावित करने वाला है जो जा रहे हैं

उसे अनुच्छेद 188 के तहत अपने विवेक से कार्य करने के लिए दिया जाए? मैंने अपने माननीय मित्र और सम्मानित संवैधानिक वकील की बात ध्यान से सुनी है। श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, लेकिन मैं उनका अनुसरण नहीं कर सका।

इस तरह के प्रावधान की आवश्यकता क्यों है? उन्होंने कहा कि इसके बजाय बाद में, अनुच्छेद 188 पर विचार करते समय, हमें यह कहना पड़ सकता है कि "रामेश्वर प्रसाद बनाम के बावजूद।

यू. ओ. एल [पासायत, जे।]

753

अनुच्छेद 143 में कुछ भी निहित है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि यह आवश्यक नहीं है। अगले स्थान पर, यह मानते हुए भी कि यह बन जाता है बाद के चरण में अनुच्छेद 188 पर प्रावधान करना आवश्यक है:

" अनुच्छेद 143 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इन शब्दों को यहाँ रखना इतना अप्रिय लगता है और वे कुछ लोगों को कुछ लोगों के खिलाफ एक प्रकार का अनावश्यक और अनुचित पूर्वाग्रह पैदा करने में सक्षम बनाने की संभावना रखते हैं। अनुच्छेद 143 मुख्य रूप से इन कार्यों से संबंधित है - मंत्रियों को। इस स्तर पर मंत्रियों को राज्यपाल की शक्तियों और उनके कार्यों के बारे में याद दिलाना क्यों आवश्यक है, यह कहकर कि वे कोई सहायता या सलाह नहीं देंगे जहां तक राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है? यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसका उद्देश्य मुख्यमंत्री की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करना है। ऐसा सुझाव देने के लिए, ऐसा लगता है कि शिष्टाचार और विनम्रता की कमी है। इसलिए मुझे लगता है कि क्वेस्टिक पर इस तरह से विचार किया जाना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि क्या हम विवेकाधीन शक्ति देने जा रहे हैं

राज्यपाल हों या न हों। सवाल यह नहीं है कि वह केवल एक व्यक्ति होना चाहिए-प्रमुख या अन्यथा। इन पर उचित समय और स्थान पर बहस की जानी चाहिए। जब हम अनुच्छेद 143 पर विचार कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित करता है, तो यह कहना इतना अजीब और अनावश्यक लगता है, सिवाय इसके कि वह उनके द्वारा या उनके अधीन है।

इस संविधान को अपने विवेक से अपने या उनमें से किसी भी कार्य का प्रयोग करने की आवश्यकता थी। हालाँकि मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि अनुच्छेद 188 बिल्कुल आवश्यक है, मेरा सुझाव है कि इस अनुच्छेद 143 में ये शब्द पूरी तरह से अनावश्यक हैं और वहाँ नहीं होने चाहिए। व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह प्रावधान गलत है और यह विनम्र नहीं है, न विनम्र है, न न्यायसंगत है और न ही प्रासंगिक है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन शब्दों को हटाने से कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि मेरा सुझाव स्वीकार्य होगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह उच्च दृष्टिकोण से विचार करने योग्य है।

श्री कृष्ण चंद्र शर्मा (संयुक्त प्रांत: सामान्य): महोदय, स्थिति यह है कि अनुच्छेद 41 के तहत संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं और इनका प्रयोग वे संविधान और कानून के अनुसार कर सकते हैं। अब संघ के अध्यक्ष कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अच्छी सरकार के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य का मंत्रिमंडल विधानमंडल में बहुमत के माध्यम से लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। अब राष्ट्रपति और राज्य के बीच क्या संबंध है? लिंक गवर्नर है। इसलिए राष्ट्रपति केवल राज्यपाल के माध्यम से ही देश की अच्छी सरकार के लिए अपने कार्यों का निर्वहन कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिस्थितियों में राज्यपाल ही अनुच्छेद 188 के तहत आपातकालीन शक्तियों का सहारा ले सकता है। इसलिए उसके कार्य करने की शक्ति

अनुच्छेद 143 के तहत विवेकाधिकार का पालन किया जाता है और अनुच्छेद 188 है

यह आवश्यक है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 188 के तहत कुछ आपातकालीन शक्तियां आवश्यक हैं -

कानून और व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की व्यवस्थित सरकार को जारी रखने के अपने कार्य का निर्वहन करना।

प्रोफेसर शाह के संशोधन के संबंध में मैं कुछ और कहना चाहता हूं।

कि मंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्री के पास विधायिका में बहुमत होता है और इस तरह, बहुमत के माध्यम से, वह लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि वह राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है, जैसा कि विधानमंडल के प्रति और विधानमंडल के माध्यम से राज्य के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से अलग है, तो उसे विधानमंडल में बहुमत से उखाड़ फेंका जा सकता है और वह अपने पद को बनाए नहीं रख सकता है। वह पद पर नहीं रह सकते। इसलिए यह एक असंभव प्रस्ताव है।

कि एक मंत्री कभी भी राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी हो सकता है जो विधायिका में बहुमत के माध्यम से लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से अलग है। इसलिए उसे विधायिका और लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए न कि राष्ट्रपति के प्रति। यही एकमात्र तरीका है जिसमें संविधान के मसौदे में योजना के तहत

देश की सरकार वह जारी रख सकते हैं।

(जोर देने के लिए रेखांकित)

श्री रोहिणी कुमार चौधरी: (असम: सामान्य): मैं और अधिक बोलने के लिए उठती हूँ

इस बहस में मूल्यवान योगदान देने की किसी भी महत्वाकांक्षा के बजाय स्पष्टीकरण और ज्ञान की खोज में। महोदय, एक बात जिसने इस सदन को उस अनुच्छेद को स्वीकार करने में काफी हद तक प्रभावित किया, जिसमें राज्यपालों को नामित करने का प्रावधान था, वह यह था कि माननीय डॉ. अम्बेडकर हमें यह आश्वासन देते हुए प्रसन्न थे कि राज्यपाल केवल एक प्रतीक होगा। मैं अब माननीय डॉ. अम्बेडकर से पूछता हूं कि क्या कोई भी व्यक्ति जिसे अपने विवेक से कार्य करने का अधिकार है, उसे केवल एक प्रतीक कहा जा सकता है। मुझे बताया गया

है कि मनोनीत राज्यपाल पद के लिए यह प्रावधान ब्रिटिश संविधान के मॉडल पर किया गया था। 1

मैं डॉ. अम्बेडकर से पूछना चाहूंगा कि क्या महामहिम अंग्रेजी के राजा किसी भी मामले में अपने विवेक में कार्य करते हैं। मुझे बताया गया है-मैं शायद गलत हो सकता हूं कि महामहिम को चयन के मामले में भी कोई विवेकाधिकार नहीं है

उसकी दुल्हन से। यह उनके लिए हमेशा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।

755

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

महोदय, मैं अपनी कीमत और अपने प्रांत की कीमत के बारे में जानता हूं कि 'राज्यपाल द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कार्य करने' का क्या अर्थ है। यह वर्ष 1942 में था जब एक राज्यपाल ने अपने विवेक से काम करते हुए एक अल्पसंख्यक दल से अपने मंत्रालय का चयन किया और उस अल्पसंख्यक को अंततः बहुमत में बदल दिया गया। मुझे यह भी पता है और सदन को भी याद रहेगा कि सिंध प्रांत के राज्यपाल द्वारा अपने विवेक का प्रयोग

इसके कारण लोकप्रिय मंत्रियों में से एक-श्री अल्लाह बक्स को बर्खास्त कर दिया गया। महोदय, अगर हमारे इस अनुभव के बावजूद हमें कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है

अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कार्य करने की शक्तियों वाले राज्यपाल, मुझे डर है कि हम अभी भी अतीत में जी रहे हैं जिसे हम सभी भूलना चाहते थे।

हमने हमेशा सोचा है कि लोगों की इच्छा से शासित होना किसी एक व्यक्ति की इच्छा से शासित होने से बेहतर है जो राज्यपाल को नामित करता है जो अपने विवेक से कार्य कर सकता है। अगर यह

राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की शक्ति दी गई है और पृथ्वी पर उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोई शक्ति नहीं है। वह एक वास्तविक हो सकता है

राजा सारस। इसके अलावा, जैसा कि अनुच्छेद कहता है, जब भी राज्यपाल को लगता है कि वह अपने विवेक से काम कर रहे हैं, तो उनसे कहीं भी पूछताछ नहीं की जा सकती है। मंत्रियों और राज्यपाल के बीच विवाद हो सकता है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए पूर्व की क्षमता के बारे में; राज्यपाल की आवाज प्रबल होगी और मंत्रियों की आवाज व्यर्थ होगी। क्या

हमें इस युग में ऐसी स्थिति का सामना करना चाहिए? क्या हमें एक राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कार्य करने के विचार को खारिज करने के लिए एक मिनट से अधिक समय लेना चाहिए? यह कहा जा सकता है कि इस मामले पर आगे विचार किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार जब हम इस प्रावधान पर सहमत हो जाते हैं, तो हमें ऐसा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

समझें कि हमने गलती की है। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्या इस मामले में संदेह की कोई गुंजाइश है? क्या यह सोचने की कोई गुंजाइश है कि इस देश में किसी को भी, विधायिका के सदस्यों की बात नहीं करनी चाहिए,

क्या कभी किसी एक व्यक्ति द्वारा नामित राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कार्य करने की शक्ति देने के विचार को स्वीकार करेंगे? महोदय, अगर मेरा आधार सही है, तो हमें उन प्रावधानों को त्यागने में एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए जो लोगों को सशक्त बनाते हैं।

राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करें।

(जोर देने के लिए रेखांकित)

मैं इस अनुच्छेद के अंतिम खंड में यह भी पाता हूं कि किसी मंत्री द्वारा क्या सलाह दी गई थी, इस सवाल की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जानी चाहिए। मैं केवल इस मुद्दे पर खुद को स्पष्ट करना चाहता हूं। राज्यपाल द्वारा दो कार्यों का निर्वहन किया जाता है। एक मामले में उसे कार्रवाई करनी है [2006] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मंत्री की सलाह पर और दूसरे मामले में उसे अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कार्य करना होता है। क्या मंत्रालय सक्षम होगा

इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या मंत्री उन मामलों में राज्यपाल को सलाह देने के लिए सक्षम होंगे जहां राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। यह समझते हुए कि मंत्री राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए भी सलाह देने में सक्षम होंगे और यदि राज्यपाल ने नहीं किया

उनकी सलाह को स्वीकार करते हुए, मंत्रियों को यह कहने की स्वतंत्रता थी कि उन्होंने क्या सलाह दी। मुझे नहीं पता कि वर्तमान में क्या इरादा है। वहाँ हो सकता है ऐसे मामले हों जहां मंत्री राज्यपाल को सलाह देने के लिए सक्षम हों, लेकिन राज्यपाल उनकी सलाह को स्वीकार नहीं करता है और कुछ ऐसा करता है जो अलोकप्रिय हो। एक राज्यपाल जिसे केंद्र द्वारा नामित किया जाता है, वह उस प्रांत में अलोकप्रिय हो सकता है जहां वह राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहा है। यदि वह अपने ही प्रांत में सेवा करता है तो वह जनमत के बारे में घबरा सकता है लेकिन वह उस प्रांत में जनमत की परवाह नहीं कर सकता है जहां वह केवल कार्य कर रहा है। मान लीजिए कि एक राज्यपाल अपने मंत्री की सलाह पर कार्य करने के बजाय अलग तरीके से कार्य करता है। यदि राज्यपाल द्वारा की गई या की गई किसी भी चीज़ के लिए मंत्री की आलोचना की जाती है, और मंत्री इस तरह की आलोचना के लिए किसी पक्ष पर मुकदमा चलाना चाहते हैं, तो क्या मंत्रियों को यह कहने का अधिकार नहीं होगा कि उन्होंने राज्यपाल को सलाह दी थी?

एक निश्चित तरीके से कार्य करना लेकिन यह कि राज्यपाल ने एक अलग तरीके से कार्य किया? हमें मंत्रियों को मुकदमा चलाने की स्वतंत्रता क्यों नहीं देनी चाहिए?

कागज, एक अस्पष्ट कागज, एक गलत सूचना वाला कागज, जो मंत्रियों की इस तरह की आलोचना में लिप्त था? मंत्री क्यों नहीं होना चाहिए?

अदालत के समक्ष यह कहने की अनुमति दी गई कि उन्होंने राज्यपाल को क्या सलाह दी? मैं कहूंगा, महोदय-और मुझे यह कहने के लिए माफ किया जा सकता है कि इस अनुच्छेद के पक्ष में सबसे अच्छा यह कहा जा सकता है कि यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 में इसी तरह के प्रावधान का एक करीबी अनुकरण है, जिसे इस सदन के कई सदस्यों ने कहा था, जब प्रकाशित किया गया था, कि वे एक जोड़ी चिमटे से भी नहीं छुएंगे।

(जोर देने के लिए रेखांकित)

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री टी. टी. कृष्णमाचारी ने श्री कामत के इस संशोधन पर जो कहा था, उसके बाद मुझे नहीं लगा कि इस बहस में बोलने और भाग लेने की आवश्यकता होगी, लेकिन मेरे मित्र पंडित कुंजरू ने मुझसे स्पष्ट रूप से सवाल पूछा और जवाब मांगा, मैंने सोचा कि शिष्टाचार के लिए मुझे कुछ शब्द कहने चाहिए। महोदय, मुख्य और 757

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां होनी चाहिए? यही वह प्रश्न है जो मुख्य और प्रमुख प्रश्न है।

इस प्रश्न पर कुछ निर्णय लेने के बाद, दूसरे प्रश्न पर उपयोगी रूप से विचार किया जा सकता है कि क्या अनुच्छेद 143 के खंड (1) के अंतिम भाग में उपयोग किए गए शब्दों को उस अनुच्छेद में बनाए रखा जाना चाहिए या कहीं और स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसलिए, पहली बात जो मैं ऐसा करने का प्रस्ताव करता हूं, वह है इस प्रश्न के लिए खुद को समर्पित करना, जैसा कि मैंने कहा,

कि राज्यपाल में विवेकाधीन शक्ति को बनाए रखना भारत सरकार अधिनियम, 1935 की गंध है, जो मुख्य रूप से था अलोकतांत्रिक। अब, अपने लिए बोलते हुए, मुझे अपने मन में कोई संदेह नहीं है कि राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां सौंपना किसी भी अर्थ में इसके विपरीत या किसी भी अर्थ में निषेध नहीं है।

यह कहने के बाद, मैं कनाडा के संविधान की धारा 55 को पढ़ना चाहूंगा। " धारा 55। - जहां संसद के सदन द्वारा पारित कोई विधेयक महारानी की सहमति के लिए गवर्नर-जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, वह अपने विवेकाधिकार के अनुसार और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए या तो रानी के नाम से उस पर सहमति देगा, या रानी की सहमति को रोक देगा।

महारानी की खुशी के अर्थ के लिए विधेयक को मंजूरी दें या सुरक्षित रखें।

(जोर देने के लिए रेखांकित)

पंडित हिरदय नाथ कुंजरू: क्या मैं डॉ. अम्बेडकर से पूछ सकता हूँ कि कब

ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम पारित किया गया था?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिनियम की तारीख मायने नहीं रखती है।

श्री एच. वी. कामथ: लगभग एक शताब्दी पहले।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: यह मेरा जवाब है।

और ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने इस स्तर पर भी इस प्रावधान को हटाना आवश्यक नहीं पाया है। वे काफी संतुष्ट हैं कि इसे बरकरार रखा गया है। कनाडाई अधिनियम की धारा 55 में प्रावधान जिम्मेदार सरकार के साथ पूरी तरह से संगत है। यदि उन्होंने छोड़ दिया था कि यह प्रावधान नहीं था

जिम्मेदार सरकार के साथ संगत, उनके पास आज भी, डोमिनियन के रूप में, इस प्रावधान को निरस्त करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इसलिए पंडित कुंजरू के जवाब में मैं बहुत अच्छी तरह से कह सकता हूं कि कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई लोगों को नहीं लगता कि इस तरह का प्रावधान है

जिम्मेदार सरकार का उल्लंघन।

श्री लोकनाथ मिश्रा (उड़ीसा-सामान्य): आदेश के एक बिंदु पर, सर, हम हैं

कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का दर्जा मिलने वाला है? या हम एक गणतंत्र संविधान बनाने जा रहे हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: उन्होंने जो कहा मैं उसका पालन नहीं कर सका। यदि, जैसा कि मैं आशा करता हूँ, सदन इस बात से संतुष्ट है कि राज्यपाल को एक निश्चित मात्रा में विवेकाधिकार देने वाले प्रावधान का अस्तित्व नहीं है

जिम्मेदार सरकार के साथ असंगत या असंगत, इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि इस खंड का प्रतिधारण वांछनीय है और मेरे विचार में आवश्यक है। एकमात्र सवाल जो उठता है वह है।

पंडित हिरदय नाथ कुंजरू: खैर, डॉ. अम्बेडकर आलोचना के मुद्दे को पूरी तरह से भूल गए हैं। आलोचना यह नहीं है कि अनुच्छेद 175 में राज्यपाल को कुछ शक्तियां नहीं दी जा सकती हैं, आलोचना राज्यपाल को एक जनरल की कुछ विवेकाधीन शक्तियां सौंपने के खिलाफ है।

चर्चा के तहत लेख में प्रकृति।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: मुझे लगता है कि उन्होंने लेख को गलत पढ़ा है। मुझे खेद है कि मेरे पास संविधान का मसौदा नहीं है। जहाँ तक वे इस संविधान द्वारा या उसके तहत हैं, उन्हें छोड़कर "ये शब्द हैं। अगर शब्द "जब भी वे सोचते हैं कि उन्हें विवेक की इस शक्ति का उपयोग

इच्छाओं के खिलाफ या मंत्रियों की सलाह के खिलाफ करना चाहिए", तो मुझे लगता है कि मेरे माननीय मित्र पंडित कुंजरू द्वारा की गई आलोचना मान्य होती। खंड एक बहुत ही सीमित खंड है: वह कहता है: " सिवाय इसके कि वह इस संविधान द्वारा या उसके अधीन है। इसलिए अनुच्छेद 143 को पढ़ना होगा।

ऐसे अन्य अनुच्छेदों के साथ संयोजन जो विशेष रूप से राज्यपाल के लिए शक्ति सुरक्षित रखते हैं। यह एक सामान्य खंड नहीं है जो राज्यपाल को किसी भी मामले में अपने मंत्रियों की सलाह की अवहेलना करने की शक्ति देता है जिसमें उन्हें लगता है कि उन्हें अवहेलना करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे माननीय मित्र पंडित कुंजरू के तर्क की भ्रांति यहीं है।

759

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. 1. [पासायत, जे.}

इसलिए, जैसा कि मैंने कहा, यह कहते हुए कि कुछ भी असंगत नहीं है

राज्यपाल में विवेकाधीन शक्ति को बनाए रखने के साथ जिम्मेदार सरकार की प्रणाली के साथ निर्दिष्ट मामले, एकमात्र सवाल जो उठता है, वह यह है कि हमें इसका उल्लेख कैसे करना चाहिए।

विवेकाधीन शक्ति? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने के तीन तरीके हैं। एक तरीका यह है कि अनुच्छेद 143 के शब्दों को मेरे माननीय मित्र, पंडित के रूप में हटा दिया जाए। कुंजरू और अन्य लोग चाहते हैं और

राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करते हुए, यह कहते हुए कि अनुच्छेद 143 के बावजूद, 175 या 188 या ऐसे अन्य प्रावधानों को जोड़ना, जिन्हें सदन इसके बाद पेश कर सकता है।

उल्लेख किया गया है-अनुच्छेद 175,188,200 या जो भी वे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं कि सदन किसी भी तरह से उल्लेख करने से नहीं बच सकता है कि राज्यपाल के पास होगा

विवेकपूर्ण।

अब जो बात मेरे माननीय मित्र पंडित कुंजरू और इसी तरह बोलने वालों के पक्ष में प्रतीत होती है, वह यह है कि शब्दों को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए और कहीं और स्थानांतरित कर

दिया जाना चाहिए या विशिष्ट अनुच्छेदों का उल्लेख अनुच्छेद 143 में किया जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यह केवल मसौदा तैयार करने का एक तरीका है। सार का कोई सवाल नहीं है और सिद्धांत का कोई सवाल नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं अनुच्छेद 143 के खंड (1) के अंतिम भाग में संशोधन करने के लिए काफी इच्छुक होता अगर मुझे इस स्तर पर पता होता कि यह संविधान सभा किन प्रावधानों के साथ बनाने का प्रस्ताव करती है।

राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करने के संबंध में। मेरी कठिनाई यह है कि हम अभी तक अनुच्छेद 175 या 188 पर नहीं आए हैं और न ही हमने राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करते हुए अन्य प्रावधान किए जाने की सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया है। अगर मुझे यह पता होता, तो मैं अनुच्छेद 143 में संशोधन करने और विशिष्ट का उल्लेख करने के लिए बहुत आसानी से सहमत हो जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, मेरा निवेदन है कि कोई गलत काम नहीं किया जा सकता है यदि अनुच्छेद 143 में जो शब्द हैं वे वैसे ही बने रहें। वे निश्चित रूप से असंगत नहीं हैं।

श्री एच. वी. कामथ: क्या राष्ट्रपति और उनके मंत्रियों से संबंधित अनुच्छेद 61 (1) और इसके बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है? माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि हम राष्ट्रपति को कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं देना चाहते हैं।

[2006]

आई एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्र सरकार के अधीनता, और इसलिए, यह देखते हुए कि वे केंद्र सरकार के अधीनता में कार्य करते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति को यह देखने का अवसर देने के लिए कुछ चीजें सुरक्षित रखेंगे कि वे नियम जिनके तहत प्रांतीय

सरकारों को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए या केंद्र सरकार के अधीन रहना चाहिए।

श्री एच. वी. कामथ: क्या विवेकाधीन शक्ति के संबंध में संविधान में कुछ अनुच्छेदों को निर्दिष्ट करना बेहतर नहीं होगा?

इसे आसानी से करें। मैं विशिष्ट अनुच्छेदों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं, अगर मुझे पता हो कि कौन से अनुच्छेद हैं जिन्हें सदन संविधान में विवेकाधीन शक्तियों को निहित करने के संबंध में शामिल करने जा रहा है। राज्यपाल।

श्री एच. वी. कामथ: इसे क्यों नहीं रोकते?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: हम संशोधित कर सकते हैं। यह सदन अनुच्छेद 143 को संशोधित करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। यदि पूरे मामले को देखने के बाद, सदन को लगता है कि अनुच्छेद का विशेष रूप से उल्लेख करना बेहतर तरीका होगा, तो वह ऐसा कर सकता है। यह विशुद्ध रूप से एक लोगो मशीन है।

श्री एच. वी. कामथ: पीछे और आगे क्यों जाएँ?

अध्यक्ष महोदय: सवाल यह है:

" कि अनुच्छेद 143 के खंड (1) में, शब्द 'जहाँ तक को छोड़कर

वह इस संविधान द्वारा या उसके तहत अपना प्रयोग करने के लिए अपेक्षित है

उनके विवेकानुसार कार्य या उनमें से किसी को भी हटा दिया जाए।

संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय: सवाल यह है:

" कि अनुच्छेद 143 के खंड (1) में 'हेड' शब्द के बाद अल्पविराम है।

रखे जाएँ और शब्द जो जिम्मेदार होंगे

राज्यपाल और जोड़ा जाएगा और 'से' शब्द को हटा दिया जाएगा।

संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय: सवाल यह है:

" वह अनुच्छेद 143 संविधान का हिस्सा है।

प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। .

संविधान में अनुच्छेद 143 जोड़ा गया था।

टचूएंट असेंबली की बैठक 2 जून, 1949 को हुई।

बी.

एलई 153

अध्यक्ष महोदय: अनुच्छेद 153 सदन के विचार के लिए है। बहुत ही पहले आर्हेन्डमेंट के संबंध में, संख्या 2321, जैसा कि हमारे पास एक समान था

अनुच्छेद 69 के संबंध में संशोधन जिस पर व्यापक चर्चा की गई थी

एस.

दूसरे दिन, क्या प्रोफेसर शाह इसे स्थानांतरित करना चाहते हैं?

प्रो. के टी शाह: अगर मैं क्रम में हूं तो मैं इसे स्थानांतरित करना चाहूंगा। लेकिन अगर आप इसे खारिज कर दें, इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: इसे खारिज करने का सवाल ही नहीं है। अगर इसे स्थानांतरित किया जाता है, तो

डी.

एक बार सामने रखे जाने पर तर्क की पुनरावृत्ति होगी।

प्रो. के टी शाह: मैं सहमत हूं कि यह एक समान संशोधन है, लेकिन नहीं।

समान।

अध्यक्ष महोदय: मैंने यह नहीं कहा है कि यह समान है।

ई [1]

प्रो. के टी शाह: ठीक है। मैं इसे हिलाता नहीं हूँ, सर। अध्यक्ष महोदय: संशोधन सं। 2322 , 2323 , 2324 , 2325 और 2326 हैं

स्थानांतरित नहीं किया गया, क्योंकि वे मौखिक संशोधन हैं।

प्रो. के टी शाह: जैसा कि मेरा संशोधन संख्या 2327 संशोधन का हिस्सा है।

एफ.

संशोधन संख्या 2331 पेश नहीं किया गया है। श्री मोहम्मद। ताहिर (बिहार: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मैं आगे कहता हूँ:

जी.

" कि अनुच्छेद 153 के खंड (2) के उपखंड (ग) के अंत में,

शब्द 'यदि राज्यपाल संतुष्ट हैं कि प्रशासन विफल हो रहा है और मंत्रालय अस्थिर हो गया है 'सम्मिलित किया जाए'।

इस खंड में राज्यपाल को कुछ शक्तियां दी गई हैं -

विधान सभा को बुलाना, स्थगित करना या भंग करना। अब मुझे एच चाहिए

एक घर से। मुझे लगता है कि अनुच्छेद 153 के खंड (3) में एक संशोधन है। डॉ. अम्बेडकर जिसमें वह उस खंड को हटाना चाहते हैं जो चलता है

इस प्रकार: " (3) उपखंड (ए) और (सी) के तहत राज्यपाल के कार्य

इस अनुच्छेद के खंड (2) का प्रयोग वह अपने विवेक से करेगा।

दूसरी ओर, मैं चाहता हूँ कि इसके लिए कुछ कारण दिए जाएं।

विघटन। संविधान में कहीं भी हम इसकी गणना नहीं कर रहे हैं -

शर्तें और परिस्थितियाँ जिनके तहत सदन को भंग किया जा सकता है। अगर हम कोई शर्त नहीं लगाते हैं, तो कठिनाइयाँ हो सकती हैं। मान लीजिए।

कुछ प्रांतों में एक पार्टी सत्ता में है जिसके विचारों के साथ

विधानसभा को भंग करने और नए सिरे से चुनाव की व्यवस्था करने के कुछ कारण। यदि ऐसी चीजें होती हैं तो सदन को भंग करने का कोई औचित्य नहीं होगा। सिर्फ इसलिए कि राज्यपाल बहुमत वाले दल के विचारों से सहमत नहीं है, विधानसभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की कठिनाइयों से बचने के लिए मुझे लगता है कि यह आवश्यक है कि संविधान में कुछ शर्तों और परिस्थितियों का उल्लेख किया जाए, जिसके तहत केवल राज्यपाल ही सदन को भंग कर सकता है। सदन को भंग करने के अलावा कोई अन्य कारण नहीं होना चाहिए।

मंत्रालय का कुशासन या अस्थिरता और इसकी अयोग्यता

कुछ शर्तों और परिस्थितियों के लिए प्रावधान करते हैं जिनके तहत राज्यपाल सदन को भंग कर सकते हैं।

(जोर देने के लिए रेखांकित)

अध्यक्ष महोदय: अगला संशोधन, संख्या 2333, प्रस्तुत नहीं किया गया है। डॉ. अम्बेडकर संशोधन संख्या 2334 पेश कर सकते हैं। माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं आगे बढ़ता हूँ:

" अनुच्छेद 153 के उस खंड (3) को हटा दिया जाए।

यह खंड एक संवैधानिक राज्यपाल के लिए योजना के साथ स्पष्ट रूप से असंगत है।

अध्यक्ष महोदय: संशोधन संख्या 2335 संशोधन के समान है।

बस चला गया। संशोधन संख्या 2336 प्रस्तुत नहीं किया गया है।

श्री एच. वी. कामथ: अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपकी अनुमति ले सकता हूँ? उस संशोधन के अर्थ या व्याख्या पर जिसके पास है

मेरे विद्वान मित्र डॉ. अम्बेडकर से प्रभावित हुए? यदि इस संशोधन को सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो यह विवेकाधिकार को समाप्त कर देगा।

1 आई 763

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

राज्यपाल को दी गई शक्तियाँ। तथापि, उपखंड (बी) है। एम-ए मुझे यह समझना चाहिए कि जहाँ तक सदन के सत्रावसान का संबंध है,

राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से कार्य करता है या

मंत्रिमंडल और इसलिए खंड (3) में इसका कोई संदर्भ आवश्यक नहीं है?

अध्यक्ष महोदय: वह चाहता है कि खंड (3) को हटा दिया जाए।

बी.

श्री एच. वी. कामथ: खंड (3) में उपखंड (ए) और (सी) के संदर्भ हैं। मैं (ए) और (बी) को एक दूसरे के बराबर रखता हूं। राज्यपाल ऐसे समय और स्थान पर बैठक करने के लिए सदनों या किसी भी सदन को बुला सकते हैं।

जैसा कि वह उचित समझता है। फिर मुझे नहीं पता कि सत्रावसान का कार्य क्यों किया जाना चाहिए

एक अलग स्तर पर रहें। अध्यक्ष महोदय: ठीक यही अभी नहीं किया जा रहा है। इन सभी

तीन को बराबर रखा जा रहा है।

श्री एच. वी. कामथ: फिर मैं इसके एक अन्य पहलू का उल्लेख करना चाहूंगा। हटाना। यही वह मुद्दा है जिसे उठाने के लिए आप काफी अच्छे थे।

यह सदन दूसरे दिन, अर्थात, कि डी के अध्यक्ष

अपने कार्यों का अभ्यास करना। यहाँ संबंधित अनुच्छेद 143 है:

" मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी

राज्यपाल को उनके कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए प्रमुख। महोदय, जैसा कि आपने संबंधित एक लेख के संबंध में बताया है

राष्ट्रपति बनाम उनकी मंत्रिपरिषद में क्या कोई प्रावधान है?

संविधान जो राज्यपाल को स्वीकार करने या पालन करने के लिए बाध्य करता है

उसे इस अनुच्छेद के तहत भंग करने के लिए प्रदान किया जा रहा है विधान सभा। यह सभी लोकतंत्रों में काफी गंभीर मामला है।

विभिन्न लोकतंत्रों में, यहां तक कि हमारे अपने देशों में भी ऐसे उदाहरण रहे हैं

कभी-कभी प्रांत, जब एक मंत्रिमंडल एक के खिलाफ समय प्राप्त करने की मांग करता है

उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है विधानसभा का सत्रावसान कराने में राज्यपाल की सहायता। यह निश्चित रूप से जी

लेख आंख मूंदकर कहता है, "इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन"। के रूप में अनुच्छेद के खंड (1) के संबंध में, मुझे खुशी है कि हमारी संसद और हमारी

अन्य विधानमंडलों की बैठक अधिक बार और लंबी अवधि के लिए होती थी। 1 .

आशा है कि जिस पर विचार किया जाएगा और उस पर प्रभाव डाला जाएगा

उचित समय। इस अनुच्छेद का खंड (2) महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग करने से संबंधित है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

इसे समझा जा सकता है और पंक्तियों के बीच पढ़ने पर डॉ. अम्बेडकर कह सकते हैं कि इसका सार मौजूद है, लेकिन हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को भी समाप्त करने का निर्णय लिया

उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा उन्हें दी गई सलाह को स्वीकार करने के लिए संविधान में एक कमी है। इसके बावजूद हम

उन्हें विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करना, यह उल्लेख किए बिना कि उन्हें इस संबंध में अपने मंत्रियों से परामर्श करना चाहिए या उनकी सलाह से निर्देशित होना चाहिए। मैं यह कहने के लिए विवश हूँ कि हम राज्यपाल को जो शक्ति प्रदान कर रहे हैं, वह उस नई व्यवस्था के अनुरूप नहीं होगी जो हम देश में बनाने जा रहे हैं, जब तक कि हम राज्यपाल को उनके मंत्री द्वारा दी गई सलाह को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि इस

अनुच्छेद को समाप्त कर दिया जाएगा और मसौदा समिति बाद में संशोधन या संशोधन पर एक और प्रस्ताव लाएगी।

इस अनुच्छेद को उपयुक्त तरीके से बदलना। श्री गोपाल नारायण (संयुक्त प्रांत: सामान्य): अध्यक्ष महोदय, इस पर बोलने से पहले मैं एक शिकायत दर्ज कराना चाहता हूं और इसका निवारण चाहता हूं।

आप। मैं उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने इसकी सभी बैठकों में भाग लिया है।

सभा करें और शुरू से अंत तक बैठें, लेकिन मेरा धैर्य अब समाप्त हो गया है। मैं पाता हूँ कि इस सदन के कुछ सम्मानित सदस्य हैं जिन्होंने सभी बहसों पर एकाधिकार कर लिया है, जिन्हें प्रत्येक अनुच्छेद, प्रत्येक संशोधन और प्रत्येक संशोधन पर बोलना चाहिए।

संशोधन। श्रीमान, मुझे पता है कि आपकी अपनी सीमाएँ हैं और आप उन्हें नियमों के तहत नहीं रोक सकते हैं, हालाँकि मैं आपके चेहरे से देखता हूँ कि कभी-कभी ऊब भी लगता है, लेकिन आप उन्हें रोक नहीं सकते। मेरा सुझाव है कि

महोदय, कि कुछ सदस्यों पर कुछ समय-सीमा लगाई जा सकती है। उन्हें दो या तीन से अधिक बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियाँ। फिर भी एक सदस्य आता है और इसका विरोध करें। मैं आपसे समाधान चाहता हूं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आपको हमें कम से कम अपनी सीटों पर सोने की अनुमति देनी चाहिए या इस सदन में बैठने के अलावा कुछ और करना चाहिए। महोदय, मैं इस लेख का समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: मुझे डर है कि मैं इस मामले में असहाय हूं। मैं इसे सदस्यों की अच्छी समझ पर छोड़ता हूं।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: (बोलने के लिए गुलाब)।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

श्री प्रेसीडेन। इसके बाद क्या आप बोलना चाहेंगे? (हँसी)।

इस विषय पर अक्सर चर्चा होती रही है।
अध्यक्ष महोदय: फिर मैं संशोधनों को मतदान के लिए रखूंगा।

सवाल यह है:

" कि अनुच्छेद 153 के खंड (2) के उपखंड (ग) के अंत में,

. शब्द 'यदि राज्यपाल संतुष्ट हैं कि प्रशासन विफल हो रहा है

और मंत्रालय अस्थिर हो गया है 'सम्मिलित किया जाए'।

संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय: सवाल यह है:

" अनुच्छेद 153 के उस खंड (3) को हटा दिया जाए।

संशोधन को स्वीकार कर लिया गया।

अध्यक्ष महोदय: सवाल यह है:

प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।

संशोधित अनुच्छेद 153 को संविधान में जोड़ा गया था।

संविधान सभा की बैठक 3 अगस्त, 1949 को हुई।

अनुच्छेद 278। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान।

XXX

XXX

XXX

XXX

पंडित हिरदे नाथ कुंजरू (संयुक्त प्रांत: सामान्य): अध्यक्ष महोदय,

मुझे वास्तव में बहुत खुशी है कि संविधान निर्माताओं ने आखिरकार इस विचार को स्वीकार कर लिया है कि अनुच्छेद 188 को हमारे संविधान में जगह नहीं मिलनी चाहिए। वह अनुच्छेद प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की स्थापना और राज्यपाल की नई स्थिति के साथ असंगत था। यह संतोषजनक है कि इसे अंतत: मान्यता दे दी गई है और राज्यपाल को उस शक्ति के साथ निवेश नहीं किया जा रहा है जो अनुच्छेद 188 ने उन्हें प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। हालाँकि, अब अनुच्छेद 188 और पुराने अनुच्छेद 278 के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

अनुच्छेद 278 का पुनरीक्षण। आज हमें अपना ध्यान केवल अनुच्छेद 278 और 278-ए पर ही नहीं, बल्कि अनुच्छेद 277-ए पर भी केंद्रित करना है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा कि प्रत्येक 766 की सरकार

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2006] एस सी आर।

राज्य इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलता है। यह केवल केंद्र सरकार को राज्य की रक्षा करने के लिए अधिकृत नहीं करता है।

बाहरी आक्रामकता या आंतरिक हंगामा; यह बहुत आगे जाता है और इस पर यह देखने का कर्तव्य डालता है कि किसी प्रांत की सरकार को इस संविधान के प्रावधान के अनुसार चलाया जाए। इन शब्दों का वास्तव में क्या अर्थ है? यह स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए क्योंकि यह सुनिश्चित करने की शक्ति है कि

प्रांतीय संविधानों पर उचित तरीके से काम किया जा रहा है जो केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाली शक्तियों में काफी वृद्धि करता है किसी राज्य को बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से बचाना। महोदय, मेरा मानना है कि इस संबंध में अनुच्छेद 275 और 276 पर विचार करना वांछनीय होगा, क्योंकि उनके प्रावधानों का हमारे समक्ष रखे गए प्रावधानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 275 कहता है कि, जब राष्ट्रपति संतुष्ट होते हैं कि एक गंभीर आपातकाल

भारत या भारत के किसी भी हिस्से की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो वह उस आशय की घोषणा कर सकता है। इस तरह की घोषणा पर काम करना बंद कर देगा

दो महीने के अंत में, जब तक कि इस अवधि की समाप्ति से पहले, इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। यदि इसे इस प्रकार अनुमोदित किया जाता है, तो आपातकाल की घोषणा अनिश्चित काल तक लागू रह सकती है, यानी जब तक कार्यपालिका इसे लागू रखना चाहती है, या जब तक संसद इसे लागू रहने की अनुमति देती है। जब तक यह घोषणा लागू है, अनुच्छेद 276 के तहत केंद्र सरकार को किसी भी प्रांत की सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार होगा।

राज्य सूची में शामिल विषय। इसके अलावा, केंद्रीय विधानमंडल राज्य के अधिकारियों और अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करने और कर्तव्यों को लागू करने में सक्षम होगा। भारत सरकार किसी भी मामले के संबंध में जिसके संबंध में वह कानून पारित करने के लिए सक्षम है। अब इन दो अनुच्छेदों का प्रभाव सक्षम करना है

बाहरी या आंतरिक कारणों से भारत या उसके किसी भी हिस्से की शांति और स्थिरता को खतरा होने पर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करना। इसके अलावा, यदि किसी प्रांत में कुशासन इतना असंतोष पैदा करता है कि सार्वजनिक शांति को खतरे में डाल देता है, भारत सरकार के पास इन अनुच्छेदों के तहत स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। केंद्र सरकार को यह देखने में सक्षम बनाने के लिए कि किसी प्रांत की सरकार उचित तरीके से चल रही है, तो और क्या चाहिए। यह स्पष्ट है कि के फ्रेमर्स

संविधान देश की शांति और शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के बारे में नहीं बल्कि प्रांतों में अच्छी सरकार के बारे में सोचता है। वे न केवल बाहरी आक्रामकता और आंतरिक अशांति से प्रांतों की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करेंगे, बल्कि उनकी सीमा के भीतर अच्छी सरकार सुनिश्चित करने के लिए भी हस्तक्षेप करेंगे।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. एल (पासायत, जे।)

दूसरे शब्दों में, केंद्र सरकार के पास मतदाताओं को खुद से बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की शक्ति होगी। यदि किसी प्रांत में कुप्रबंधन या अक्षमता या भ्रष्टाचार है, तो मैं इसे अनुच्छेद 277,278 के तहत मानता हूं। और 278-ए को मिलाकर केंद्र सरकार के पास शक्ति होगी। मैं 'राष्ट्रपति' शब्द का उपयोग नहीं करता क्योंकि वह अपने मंत्रियों की सलाह से उस प्रांत की सरकार को अपने हाथों में लेने के लिए निर्देशित होगा। मेरे माननीय मित्र, श्री संथानम ने कुछ उदाहरण दिए हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि किसी प्रांत में कैसे विघटन हो सकता है, भले ही कोई बाहरी आक्रामकता, कोई युद्ध और कोई आंतरिक अशांति न हो। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चित्रण दिया। उन्होंने हमें यह मानने के लिए कहा कि एक प्रांत में कई गुट मौजूद थे जो उस प्रांत की सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चलने से रोकते थे, यानी मुझे लगता है कि कुशलता से। उन्होंने हमारे सामने अपना विचार रखा कि ऐसे मामले में

प्रांतीय विधायिका का विघटन होना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या निर्वाचक एक उचित उपाय लागू करने में सक्षम थे

स्थिति। हालाँकि, अगर नए विधानमंडल में पुराने गुट-मुझे लगता है कि गुटों से उनका मतलब दलों से था-फिर से सामने आते हैं, तो उनकी राय में केंद्र सरकार प्रांत का प्रशासन संभालने के लिए उचित होगी। महोदय, यदि किसी भी प्रांत में दलों की बहुलता है तो हम इसका स्वागत नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या यह तथ्य अपने आप में प्रांतीय प्रशासन में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की गारंटी देने के लिए पर्याप्त है? कुछ देशों में कई दल हैं जो मंत्रालयों को अस्थिर बना रहे हैं। फिर भी उन देशों की सरकारों को उनकी सुरक्षा या अस्तित्व के लिए बिना किसी खतरे के चलाया जाता है। यह खेद का विषय हो सकता है यदि किसी प्रांत में बहुत सारे दल मौजूद हैं और वे एक साथ काम करने या अपने प्रांत के हित में महत्वपूर्ण मामलों पर एक समझौते पर पहुंचने में सक्षम नहीं हैं; लेकिन यह कितना भी खेदजनक हो सकता है, यह मेरी राय में केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने और संबंधित प्रांत की सरकार के लिए जिम्मेदार संसद के साथ खुद को संयुक्त रूप से बनाने को उचित नहीं ठहराएगा। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, यदि किसी प्रांत में कुप्रबंधन इस हद तक होता है कि भारत या उसके किसी हिस्से में गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है, तो केंद्र सरकार को अनुच्छेद 275 और 276 के तहत हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। क्या इससे आगे जाना सही है? हम वर्तमान में कई प्रांतों की सरकारों के खिलाफ गंभीर शिकायतें सुनते हैं, लेकिन अभी तक यह सुझाव नहीं दिया गया है कि यह देश और संबंधित प्रांतों के अंतिम हित में होगा कि केंद्र सरकार को प्रांतीय कानूनों को दरकिनार कर देना चाहिए।

सरकारें और व्यावहारिक रूप से संबंधित प्रांतों का प्रशासन, जैसे कि वे केंद्र प्रशासित क्षेत्र थे। महोदय, यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में प्रांतीय सरकारों को हस्तक्षेप करने का अधिकार है जब कोई नगरपालिका या

जिला बोर्ड सकल और निरंतर कुशासन का दोषी है, लेकिन एक नगरपालिका या जिला बोर्ड बहुत छोटा है जिसकी तुलना [2006] 1 एस. सी. आर. में एक पल के लिए भी नहीं की जा सकती है।

केंद्र सरकार और संसद को यह शक्ति दी गई है कि अनुच्छेद 277,278 और 278-ए एक साथ उन्हें प्रदान करने का प्रस्ताव करता है, एक गंभीर खतरा है कि जब भी किसी प्रांत में उसकी सरकार के साथ असंतोष होता है, इसके बचाव में आने के लिए केंद्र सरकार से

अपील की जाएगी। प्रांतीय मतदाता अपनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के कंधों पर डाल सकेंगे। क्या यह सही है कि इस तरह की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? जिम्मेदार सरकार सरकार का सबसे कठिन रूप है। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है और जोखिम उठाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास न तो धैर्य है और न ही साहस है जिसकी आवश्यकता है, तो हमारा संविधान करेगा।

वस्तुतः स्थिर रहें-जन्म लें। इसलिए, महोदय, मेरा मानना है कि जिन लेखों पर हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 275 और 276 केंद्रीय कार्यपालिका और संसद को वह सभी शक्तियां प्रदान करते हैं जो उन्हें उचित रूप से प्रदान की जा सकती हैं ताकि वे यह देख सकें कि देश में कानून और व्यवस्था बिगड़ न जाए, या भारत के किसी भी हिस्से में कुशासन को इस हद तक नहीं चलाया जाए कि कानून और व्यवस्था के रखरखाव को खतरे में डाला जाए। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यह अत्यधिक सावधानी कि संविधान के निर्माता प्रयोग करने के इच्छुक प्रतीत होते हैं, मेरी राय में, संविधान की भावना के साथ असंगत होगी, और प्रांतीय मतदाताओं के बीच जिम्मेदारी की भावना के विकास के लिए हानिकारक, भारी हानिकारक होगी।

समापन करने से पहले, महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

भारत सरकार अधिनियम, 1935, जैसा कि भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा अपनाया गया है। धारा 93, जो मूल रूप से पारित इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, को 1947 में अपनाए गए अधिनियम से हटा दिया गया है, और मुझे लगता है कि इसे हटा दिया गया था क्योंकि इसे चीजों के नए क्रम के साथ असंगत माना जाता था। मेरे माननीय मित्र श्री संथानम ने कहा कि भारत सरकार अधिनियम। 1935 , राज्यपाल जिसे अपने विवेक से कार्य करने की अनुमति दी गई थी, वह किसी भी प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। मुझे लगता है कि,

यह एक गलती है जिसे मैं इंगित कर सकता हूं कि राज्यपाल, उन सभी शक्तियों के संबंध में जो वह अपने विवेक से प्रयोग कर सकते थे, गवर्नर-जनरल के अधिकार के अधीन थे और उनके और भारत के राज्य सचिव के माध्यम से, ब्रिटिश संसद के अधीन थे। अब अंतर केवल इतना है कि हमारी कार्यपालिका 5,000 मील दूर के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होने के बजाय भारतीय मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होगी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए, लेकिन रामेश्वर प्रसाद बनाम।

यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

मुझे नहीं लगता कि अनुकूलित भारत सरकार अधिनियम, 1935 के लागू होने के बाद से दो साल का अंतराल, अब हमारे सामने आने वाले अनुच्छेदों की स्वीकृति का समर्थन करता है। धारा 93 का उद्देश्य राजनीतिक था। इसका उद्देश्य यह देखना था कि संविधान का उपयोग अंग्रेजों को मजबूर करने के लिए नहीं किया गया था

सरकार भारत के लोगों को देने के लिए तैयार थी उससे अधिक शक्ति के साथ भाग लेने के लिए। भविष्य में जनता और भारत सरकार के बीच ऐसी कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। प्रशासनिक या वित्तीय या आर्थिक प्रश्नों के संबंध में जो भी मतभेद होंगे, वे उत्पन्न होंगे। मान लीजिए कि आर्थिक समस्याओं के संबंध में एक प्रांत, भारत सरकार की मंजूरी से अधिक कट्टरपंथी रुख अपनाता है। मुझे लगता है कि यह भारत सरकार के हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं होगा।

श्री टी. टी. कृष्णमाचारी (मद्रास: सामान्य): यदि प्रांतीय सरकार जानबूझकर इसके प्रावधानों का पालन करने से इनकार कर देती है तो क्या होगा संविधान और केंद्र सरकार को अनुच्छेद 275 और 276 के तहत कार्रवाई करने में बाधा डालता है?

पंडित हिरदय नाथ कुंजरू: कोई भी प्रांत ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यह पूरी तरह से अवैध होगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार के पास अनुच्छेद 275 और 276 के तहत तुरंत हस्तक्षेप करने की पर्याप्त शक्ति होगी। इसमें अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्रवाई करने की पर्याप्त शक्ति होगी। यह अपने स्वयं के अधिकारियों को कुछ कर्तव्यों को अपने ऊपर लेने के लिए कह सकता है और यदि उन अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुँचती है, या यदि उनके खिलाफ बल का उपयोग किया जाता है-एक चरम मामला लेने के लिए-केंद्र सरकार इस तरह की चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम होगी, हमारे सामने अब अनुच्छेदों को स्वीकार किए बिना। मैं चाहूंगा कि सदन मेरे माननीय मित्र श्री कृष्णमाचारी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर बहुत सावधानी से विचार करे। मैंने अपने मन में ऐसी स्थिति के बारे में बार-बार सोचा है, और हर बार मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अनुच्छेद 275 और 276 भारत सरकार को प्रभावी रूप से इस तरह के एक अभिव्यक्ति तेल पुनरावृत्ति, ऐसे विद्रोही रवैये का सामना करने में सक्षम बनाएगा जैसा कि श्री कृष्णमाचारी ने माना था। ऐसी गंभीर स्थिति में भारत सरकार के पास अनुच्छेद 275 और 276 के तहत प्रभावी कार्रवाई करने की शक्ति होगी। क्या ज़रूरत है? तो क्या उन अनुच्छेदों के लिए कुछ है जो हमारे सामने रखे गए हैं?

महोदय, वक्ताओं में से एक ने कहा कि हमें कानूनवादी नहीं होना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेदों पर किसी ने भी कानूनी भावना से चर्चा नहीं की है। आई.

निश्चित रूप से इस पर संकीर्ण, कानूनी तरीके से चर्चा नहीं की है। मैं इस प्रश्न पर देश के सर्वोत्तम हितों और प्रांतीय मतदाताओं द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को महसूस करने के दृष्टिकोण

से व्यापक राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार कर रहा हूं कि वे और केवल वे ही सरकार [2006] आई. एस. सी. आर. के लिए जिम्मेदार हैं।

अपने प्रांत से। उन्हें यह समझना चाहिए कि यह उन्हें ही तय करना है कि कैसे इसे जारी रखा जाना चाहिए।

महोदय, भले ही संविधान के निर्माता इससे संतुष्ट न हों

तर्क जो मैंने सामने रखे हैं और चाहते हैं कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 275 और 276 द्वारा दी गई शक्ति से अधिक शक्ति होनी चाहिए I

उन्हें रुकने और इस बात पर विचार करने के लिए कहना चाहिए कि क्या अभी इस प्रश्न पर पहुंचने का कोई बेहतर तरीका नहीं था। चर्चाओं को देखते हुए जो इस सदन में और बाहर हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि संविधान नहीं बनाने के पक्ष में एक सम्मानजनक राय है

प्रांतों का विकास कैसे होता है और उनकी सरकार कैसे चलती है। यदि अनुभव से पता चलता है कि स्थिति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार को केवल सुरक्षा के लिए खुद को जिम्मेदार बनाना चाहिए। हर प्रांत के लिए, लेकिन उसकी अच्छी सरकार के लिए भी आप संविधान के संशोधन के लिए हर औचित्य के साथ आगे आ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा आज हमारे सामने रखे गए अनुच्छेदों पर सदन को सहमत होने का कोई कारण है।

महोदय, मैं इन अनुच्छेदों का विरोध करता हूँ।

श्री एल. कृष्णस्वामी भारती (मद्रास: सामान्य): महोदय, मैं प्रेरित महसूस कर रहा था

सदन के सामने एक निश्चित दृष्टिकोण रखने के लिए कर्तव्य की भावना, अन्यथा मैं माइक के सामने नहीं आता। मुझे एक संक्षिप्त भाषण की आवश्यकता महसूस होती है। आई.

डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किए गए नए अनुच्छेदों को पूरे दिल से समर्थन।

मुझे समझाइए लेकिन मैं अनुच्छेद 188 को हटाने में मसौदा समिति के विवेक से बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हूं। यही वह दृष्टिकोण है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं।

महोदय, उस लेख के पीछे एक इतिहास है। पूरे कपड़े पहनने को लेकर बहस हुई

इसमें दो दिनों तक प्ररख्यात प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया। हमें यह समझना चाहिए कि अनुच्छेद 188 किस लिए है। यह सामान्य परिस्थितियों के लिए नहीं है। यह गंभीर आपातकाल की स्थिति है कि एक राज्यपाल को इस अनुच्छेद के तहत निवेश किया गया था। कुछ शक्तियों के साथ। मैं सदन को उस बहस की याद दिला सकता हूं जिसमें श्री मुंशी का संशोधन था जो अंततः अनुच्छेद 188 का हिस्सा बना। संशोधन पेश करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि कोई भी उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा रामेश्वर प्रसाद v.

यू. ओ. आई. [पासायत। जे.]

राज्यपाल को संविधान को निलंबित करने की अनुमति देकर और राष्ट्रपति को

तस्वीर में पहले भी आना चाहिए। अनुच्छेद 188 ऐसी संभावना का प्रावधान करता है। यह केवल यह कहता है कि जब राज्यपाल संतुष्ट होता है कि वहाँ है शांति और शांति के लिए इतना गंभीर खतरा वह संविधान को निलंबित कर सकता है।

यह कल्पना करना पूरी तरह से गलत है कि उन्हें दो सप्ताह की अवधि के लिए संविधान को निलंबित करने की शक्ति दी गई थी। खंड (3) में प्रावधान है कि यह उनका कर्तव्य है कि वे अपनी घोषणा को तुरंत राष्ट्रपति को सूचित करें और राष्ट्रपति अनुच्छेद 188 के तहत मामले को अपने हाथ में ले लेंगे। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो दृष्टिहीन प्रतीत होता है। राज्यपाल को तुरंत अपनी घोषणा को सूचित करना होता है। इस अनुच्छेद की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इसे कुछ प्रधानमंत्रियों द्वारा दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया था। ऐसी संभावना हो सकती है कि राष्ट्रपति से संपर्क करना बिल्कुल भी संभव न हो। क्या आप केंद्र सरकार से संपर्क करने में असमर्थता की स्थिति की संभावना को खारिज करते हैं? समय की बात है

विषय का सार। जब तक आप संपर्क करते हैं और अनुमति प्राप्त करते हैं, तब तक कई चीजें हो चुकी होतीं और देरी ने बहुत कुछ हरा दिया होता। हमारे सामने उद्देश्य। माननीय श्री खेर ने कहा कि इस अनुच्छेद को रखना आवश्यक नहीं है क्योंकि हमारे पास सभी प्रकार के संचार उपलब्ध हैं। बॉम्बे में मुझे ऐसे उदाहरणों के बारे में पता है जहां हम कम से कम चौबीस घंटे तक राज्यपाल से संपर्क नहीं कर पाए हैं अनुच्छेद 278 के तहत क्या प्रावधान है? मद्रास के राज्यपाल का कहना है कि शांति के लिए खतरा है और

शांति। एक पल के लिए यह मानते हुए कि संचार ठीक है, राष्ट्रपति कार्रवाई नहीं कर सकते। उसे मंत्रिमंडल बुलाना होता है; मंत्रिमंडल के सदस्य आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं; और

जब तक वह मंत्रिमंडल बुलाता है और उनकी सहमति प्राप्त करता है, तब तक अनुच्छेद का उद्देश्य विफल हो जाएगा। इसलिए, यह केवल इस दृष्टि से था कि ऐसी आकस्मिकता में जहां राज्यपाल को लगता है कि देरी उसी उद्देश्य को विफल कर देगी, जिसके लिए अनुच्छेद 188 का प्रावधान किया गया था। मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि मसौदा समिति ने अपने विवेक से ऐसी संभावना को खारिज कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अनुच्छेद दो साल पहले बनाया गया था, लेकिन उन दो वर्षों के बाद से कई चीजें हुई हैं जो दर्शाती हैं कि मौके पर मौजूद व्यक्ति को जल्दी से निर्णय लेने और कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि आपदा को रोका जा सके। आज हर जगह सत्ता की खुली अवज्ञा हो रही है और यह अवज्ञा सुव्यवस्थित है। इस अधिनियम से पहले, उन्होंने टेलीफोन के तार काट दिए, जैसा कि उन्होंने कलकत्ता एक्सचेंज में किया था। देश के कई हिस्सों में ऐसा हो रहा है। इसलिए, जब तख्तापलट होता है तो यह संभव है कि वे संचार बंद कर देंगे और कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। यह केवल इस संभावना के लिए है कि राज्यपाल को ये शक्तियां दी गई हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई राज्यपाल मूर्ख होगा जो समय मिलने पर राष्ट्रपति को सूचित करने में विफल रहे। मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि यह मूर्खतापूर्ण व्यवस्था [2006] 1 एस. सी. आर. क्यों की गई है।

राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को कह सकते हैं, "ठीक है, मैं आश्वस्त नहीं हूँ; इसे रद्द करें।" आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राज्यपाल देश को आपदा से बचाने के लिए समझदारी से काम लेते हुए जिम्मेदार होंगे। राष्ट्रपति सीधे तस्वीर में आते हैं, क्योंकि राज्यपाल को संवाद करना होता है अनुच्छेद 188 के खंड (3) के अनुसार तुरंत मामला। जैसा कि श्री राष्ट्रपति ने कहा, यह सरासर सामान्य बात है कि मौके पर मौजूद व्यक्ति को स्थिति से निपटने की शक्तियां दी जानी चाहिए, ताकि यह बिगड़ न जाए। मैं परिवर्तन के विवेक के बारे में बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हूं। जैसा कि अब प्रस्तावित प्रावधान है

उतना मूर्ख नहीं-सबूत जितना होना चाहिए।

(जोर देने के लिए रेखांकित)

इसके अलावा, मैं इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि मसौदा क्यों तैयार किया गया

समिति उस प्रावधान को हटा देती है जिस पर पहले सदन द्वारा विचार किया गया था और स्वीकार किया गया था। मेरे विचार में यह अनुचित है, क्योंकि सदन ने इसका फैसला किया था। यदि हम एक मसौदा समिति नियुक्त करते हैं, तो हम उन्हें हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर मसौदा तैयार करने का निर्देश देते हैं। क्या यह वह तरीका है जिससे उन्हें मसौदा तैयार करना चाहिए? उनका कर्तव्य पहले से ही लिए गए निर्णयों की जांच करना और फिर उस आधार पर मसौदा तैयार करना था। इसलिए, मैं एक ठोस स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि इन दो वर्षों के भीतर क्या हुआ जिसके कारण मसौदा समिति के सदस्यों ने इस संपूर्ण, स्वस्थ और उपयोगी प्रावधान को हटा दिया है।

श्री नजीरुद्दीन अहमद: अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि संशोधन

डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संविधान में चौंकाने वाले और क्रांतिकारी परिवर्तन हैं। मेरा कहना है कि हमारे अपने निर्णयों से एक मौलिक विचलन किया गया है। हमने इस सदन में संविधान के सिद्धांतों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए और हमने कुछ निश्चित सिद्धांतों और प्रस्तावों को अपनाया और उनके अनुसार संविधान का मसौदा तैयार किया गया। अब, सब कुछ छोड़ना होगा। न केवल संविधान के मसौदे को छोड़ दिया गया है, बल्कि निर्धारित अवधि के भीतर सदन के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए आधिकारिक संशोधन जो आधिकारिक ब्लू बुक में मुद्रित हैं, उन्हें भी छोड़ दिया गया है। अंतिम अवकाश के दौरान उन संशोधनों में कुछ अतिरिक्त संशोधनों को मुद्रित और प्रसारित किया गया था। इन्हें भी छोड़ दिया गया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि सभी संशोधन और संशोधन

आज पेश किए गए संशोधनों को पहली बार केवल इस सप्ताह की संशोधन सूचियों में पाया जाना चाहिए जो आज से केवल एक या दो दिन के भीतर वितरित किए गए हैं। इसलिए गंभीर और आमूलचूल परिवर्तनों को रामेश्वर प्रसाद बनाम।

यू. ओ. आई. [पासायत। जे.}

अंतिम समय में पेश नहीं किया गया है जब हमारे जैसे धीमे लोगों के लिए यह देखने के लिए पर्याप्त समय नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या ये परिवर्तन वास्तव में हमारे मूल निर्णयों और समग्र रूप से संविधान के अन्य हिस्सों के साथ फिट बैठते हैं। मेरा कहना है कि मसौदा समिति हमारे मूल निर्णयों, संविधान के मसौदे और हमारे मूल निर्णयों से भटक रही है।

संशोधन। मसौदा समिति को "ड्रिफ्टिंग कमेटी" कहना शायद अधिक उपयुक्त होगा। मेरा कहना है कि अनुच्छेद 188 को हटाना उन सिद्धांतों से बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विचलन है

जिन्हें सदन ने पहले गंभीरता से स्वीकार किया था। कुछ सम्मानित सदस्य जो आम तौर पर व्यवसाय करते हैं

सदन ने गंभीरता से इन परिवर्तनों का समर्थन करने का प्रयास किया है इस आधार पर कि कुछ आपातकालीन शक्तियाँ अत्यधिक आवश्यक हैं। मैं उनसे सहमत हूं कि आपातकालीन शक्तियां आवश्यक हैं और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि

देश में अव्यवस्था व्यवस्थित तरीके से काम कर रही है और कठोर शक्तियों की आवश्यकता है। लेकिन मैं राज्यपाल या किसी राज्य के शासक की हस्तक्षेप करने और आपातकालीन आदेश पारित करने की सामान्य शक्ति को छीनने के प्रयास की सराहना करने में विफल रहा। यही सबसे गंभीर परिवर्तन है। वास्तव में, मूल रूप से राज्यपाल का चुनाव प्रांत के वयस्क मताधिकार पर किया जाना था, लेकिन अब हमने एक गंभीर विचलन किया है कि राज्यपाल की नियुक्ति अब राष्ट्रपति द्वारा की जानी है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के लिए पहला झटका है, फिर से, हमने राज्यों में उच्च सदनों को वास्तविक शक्तियों से वंचित कर दिया है; हमने न केवल प्रांतों में उच्च सदनों से सभी प्रभावी शक्तियां छीन ली हैं, बल्कि उनके लिए ठीक से और प्रभावी ढंग से काम करना भी असंभव बना दिया है। अब हम राज्य के मंत्रियों और विधानमंडलों के सदस्यों और विशेष रूप से लोगों के अपनी समस्याओं को हल करने के अधिकार को छीनने जा रहे हैं। जैसे ही हम राज्यपाल या किसी शासक को गंभीर आपात स्थितियों में हस्तक्षेप करने के उनके अधिकार से वंचित करते हैं, हम तुरंत निर्वाचित प्रतिनिधियों और मंत्रियों को इस मामले में कोई भी बोलने से वंचित कर देते हैं। जैसे ही आपातकालीन उपायों को शुरू करने का अधिकार विशेष रूप से राष्ट्रपति के पास निहित होता है, उसी क्षण से आप स्थानीय विधानसभाओं के मंत्रियों और सदस्यों को किसी भी जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुक्त कर देते हैं। इसके प्रभाव का मतलब यह होगा कि उनकी नैतिक शक्ति और नैतिक जिम्मेदारी गंभीर रूप से कम हो जाएगी। यह समस्या का वह पहलू है जिस पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(जोर देने के लिए रेखांकित)

मेरा निवेदन है कि मामले के इस पहलू को पर्याप्त या प्राप्त नहीं हुआ है।

इस सदन में पर्याप्त विचार। यदि किसी राज्य में कोई समस्या है, तो उसे शांत करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी मंत्रियों की होनी चाहिए। यदि वे विफल हो जाते हैं, तो आपातकालीन उपाय शुरू करने का अधिकार शुरू में राज्यपाल या 774 के पास होना चाहिए।

शासक। यदि आप इसकी अनुमति नहीं देते हैं, तो परिणाम यह होगा कि स्थानीय विधायिका और मंत्रियों के पास बिना किसी शक्ति के कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी। यह आसानी से और अनिवार्य रूप से एक तरह की गैरजिम्मेदारी विकसित करेगा। अपनी अच्छी सरकार देने और सुनिश्चित करने के राज्य के अधिकार में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को न केवल मंत्रियों और सदस्यों से कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी, बल्कि राष्ट्रपति की कार्रवाई का राज्य के लोगों, विधानमंडल के सदस्यों और स्वयं मंत्रियों द्वारा मजाक उड़ाया जाएगा, वर्जित किया जाएगा और बहिष्कार किया जाएगा।

XXX

XXX

XXX

XXX

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मुझे लगता है कि संवैधानिक तंत्र

जब तक राज्यपाल द्वारा धारा 153 के तहत विघटन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब तक इसे सामान्य रूप से विफल नहीं माना जा सकता है।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

XXX

मुझे लगता है कि हम शायद अनजाने में तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं।

लोकतंत्र केवल लोकतांत्रिक वातावरण में और लोकतांत्रिक परिस्थितियों में ही पनपेगा। लोगों को गलतियाँ करने दें और अनुभव से सीखने दें।

हम जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक न जाएँ। मेरा कहना है कि हमारा जवाब वही होगा जो हमारे सम्मानित नेताओं ने ब्रिटिश सरकार को दिया था। इसलिए मेरा कहना है कि केंद्र द्वारा बहुत अधिक हस्तक्षेप राज्यों में अप्रिय प्रतिक्रिया पैदा करेगा। यदि आप प्रांतीय स्वायत्तता को

पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं तो यह तर्कसंगत होगा। लेकिन करने के लिए उन्हें शक्तिहीन बनाते हुए उन्हें जिम्मेदार बनाना उचित काम नहीं होगा।

(जोर देने के लिए रेखांकित)

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. 1. [पासायत, जे।]

फिर मैं अनुच्छेद 278 के खंड (1) के परंतुक पर आता हूं। यह सुरक्षा करता है।

उनके भीतर मामलों से निपटने में उच्च न्यायालय के अधिकारों के खिलाफ

विशेष अधिकार क्षेत्र। आपातकाल की घोषणा उच्च न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं करेगी। यही इस परंतुक का प्रभाव है। लेकिन यह आसानी से सर्वोच्च न्यायालय के अस्तित्व को भूल जाता है। जबकि यह घोषणा के खिलाफ उच्च न्यायालयों के अधिकारों की गारंटी देने का ध्यान रखता है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों की गारंटी नहीं है। मैं केवल यह आशा व्यक्त करता हूं कि परंतुक में उच्चतम न्यायालय का कोई उल्लेख न होने से उस न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री टी. टी. कृष्णमाचारी: यह आवश्यक नहीं है क्योंकि केंद्रीय

सरकार सभी शर्तों के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन है।

(जोर देने के लिए रेखांकित)

श्री नजीरुद्दीन अहमद: जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है

पिछले अवसर पर कहा गया था, यह संविधान वकीलों का स्वर्ग होगा।

अनुभव से बोलते हुए, मुझे लगता है कि इस परंतुक से बहुत कुछ कानूनी हो जाएगा

लड़ाई, और केवल वकीलों को ही इससे लाभ होगा। मैं चाहता हूं कि श्री टी. टी. कृष्णमाचारी द्वारा दी गई व्याख्या सही हो, लेकिन यह मुझे स्पष्ट नहीं है। जब हम अनुच्छेद 278 के खंड (2) पर आते हैं, तो इस खंड में यह कहा गया है कि ऐसी किसी भी घोषणा को बाद की घोषणा द्वारा निरस्त या परिवर्तित किया जा सकता है।

(जोर देने के लिए

रेखांकित)

संविधान सभा की बैठक 4 अगस्त 1949 को हुई थी।

भारत की संविधान सभा की बैठक संविधान भवन, नई दिल्ली में हुई

दिल्ली, नौ बजे, अध्यक्ष (माननीय डॉ. राजेंद्र प्रसाद)।

अनुच्छेद 188,277-ए और 278 जारी रहे।

XXX XXX XXX

XXX

फिर खंड के प्रस्तावित अनुच्छेद 278-ए उपखंड (ए) और (बी) पर आते हैं।

(1) नए हैं। खंड (ए) नया है और (बी) परिणामी है। जो नया मुद्दा पेश किया गया है वह भी क्रांतिकारी है। प्रांतीय को अनुमति देने के बजाय

आपातकाल कानून पर विधायिकाओं की अपनी राय होनी चाहिए और इस प्रकार प्रांतीय विधानसभाओं को अपराध या निर्दोषता [2006] एस. सी. आर. का आकलन करने का अवसर देना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

776

मंत्री या अन्य व्यक्ति या निर्णय देने की जिम्मेदारी संसद पर डाली जाती है। यह फिर से, जैसा कि मैंने कल प्रस्तुत किया था, केंद्र सरकार और संसद को राज्य में अलोकप्रिय बना देगा।

चिंतित हैं। ऐसा हो सकता है कि प्रांतीय मंत्री और अन्य कुप्रबंधन और कुशासन के दोषी हों; लेकिन अगर हम प्रांतीय को अनुमति नहीं देते हैं

विधानसभाओं को उन पर निर्णय लेने के लिए बैठना होगा, परिणाम यह होगा कि दोषी या निर्दोष व्यक्ति, कानून तोड़ने वाले और कानून का पालन करने वाले व्यक्ति, अच्छे या बुरे लोग

राज्य में सभी को एकजुट किया जाना चाहिए। परिणाम यह होगा कि जिनके कुकर्मों के लिए आपातकालीन शक्तियों की आवश्यकता होगी, उन्हें इतने सारे नायक बनाए जाएंगे, वे शेर बन जाएंगे, और उन्हें सबक सिखाने का उद्देश्य निराश होगा। केंद्र जमीनी स्तर पर अलोकप्रिय होगा कि यह अनावश्यक रूप से और शरारतपूर्ण तरीके से उनके घरेलू मामलों में अपनी नाक फोड़ रहा है।

तब, महोदय, इस अनुच्छेद 278-ए के खंड (1) के उपखंड (सी) में,

उम्मीद की जाती है कि राष्ट्रपति संसद के प्रमुख के रूप में बजट को अधिकृत और मंजूरी देंगे। यह प्रांतों और राज्यों के घरेलू बजट पर अतिक्रमण होगा। इसे बहुत नापसंद के साथ माना जाएगा। बेहतर होता कि राज्यपाल या शासक को काम करने दिया जाता और अपने बजट को अपने तरीके से प्रबंधित करने दिया जाता। अनुदान दिए जा सकते हैं लेकिन उस खर्च का प्रबंधन सीधे राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

खंड (घ) पर आते हुए अध्यादेशों के पक्ष में एक अपवाद है।

अनुच्छेद 102 के तहत इस प्रभाव के लिए कि "राष्ट्रपति संसद के सदनों के सत्र के अलावा अध्यादेश जारी कर सकते हैं"। उपखंड वर्तमान अनुच्छेद में गलत है। एक उपयुक्त स्थान है जहाँ अध्यादेशों पर विचार किया जाता है। उपखंड (घ) को अध्यादेशों से संबंधित अनुच्छेदों के समूह में जगह मिलनी चाहिए न कि यहां। यह फिर से जल्दबाजी में मसौदा तैयार करने का परिणाम है।

ये कुछ कठिनाइयाँ हैं जो पैदा हुई हैं। वह यहाँ नहीं है।

उनसे विस्तार से निपटना आवश्यक है। राज्य क्षेत्र पर इस अतिक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह होगा कि हम साम्यवादी तकनीकों की मदद कर रहे होंगे। उनकी तकनीक यह है कि किसी प्रांत या राज्य में परेशानी पैदा करके वे प्रशासन को आंशिक रूप से पंगु बना देंगे और इस तरह आपातकालीन शक्तियों को मजबूर कर देंगे। फिर, वे उन कठोर शक्तियों को अलोकप्रिय बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा, वे दोषी मंत्रियों को और दोषी बना देंगे

अधिकारी नायक। राज्य की विधायिका, जैसा कि मैंने प्रस्तुत किया है, चर्चा के अधिकार से वंचित होगी। यदि राष्ट्रपति स्वयं को संभालते हैं तो रामेश्वर प्रसाद v.

यू. ओ. 1. [पासायत, जे।]

आपातकालीन शक्तियों की जिम्मेदारी, फिर उसकी कार्रवाई, मुझे लगता है, नहीं हो सकती है राज्यों की विधानसभाओं में चर्चा की गई। प्रांतीय हवादार करने का एकमात्र तरीका

और राज्यों की शिकायतें प्रांतों और राज्यों को पता लगाने की अनुमति देना है

दोषी व्यक्तियों को और उन्हें उपहास और अवमानना के लिए पकड़ें और कि

पूरी तरह से खो जाएगा। यह सभी प्रकार के लाने का प्रभाव होगा

लोग अच्छे और बुरे, कानून तोड़ने वाले और कानून का पालन करने वाले व्यक्ति एक मण्डली में। केंद्र अलोकप्रिय होगा और दोषी राज्य होंगे

इतने सारे शहीदों के रूप में माना जाता है और केंद्र की अवहेलना की जाएगी और

एक दुष्ट चक्र में। तब राज्य धीरे-धीरे असंतुष्ट हो जाएँगे और वे केन्द्रत्यागी प्रवृत्तियाँ दिखाएँगे और यह सामान्य में परिलक्षित होगा

बहुत जल्द इन बहुत कठोर शक्तियों के हाथों को मजबूत करने के लिए गणना की गई केंद्र कुछ ही समय में कमजोरी का स्रोत बन जाएगा।

(जोर देने के लिए रेखांकित)

XXX

XXX

अनुच्छेद 278 में एक निहितार्थ है जो कहने जैसा है,

कि आपको अच्छाई से बुराई पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और कानून के साथ अराजकता का सामना करना चाहिए। राष्ट्रपति के पास देश में अलोकतांत्रिक ताकतों से मिलने का कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि

एक क्रैटिक तरीके से। यह कहने जैसा है कि बुराई की ताकतों पर काबू पाना चाहिए।

अहिंसा और अच्छाई की ताकतों द्वारा। व्यावहारिक राजनेता और कानून निर्माता इस प्रस्ताव को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे।

XXX XXX

XXX

अध्यक्ष महोदय: डॉ. अम्बेडकर।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बाम्बे: जनरल): श्रीमान, हालांकि

इन अनुच्छेदों ने एक बहस को जन्म दिया है जो लगभग पांच घंटे तक चली है, मुझे नहीं लगता कि इस बहस से कुछ भी सामने आया है जिसके लिए मुझे इन अनुच्छेदों में सन्निहित सिद्धांतों के प्रति अपने दृष्टिकोण को संशोधित करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं किसी भी प्रकार के विस्तृत उत्तर के साथ सदन को अधिक समय तक नहीं रोकूंगा।

सबसे पहले मैं संशोधन पर एक मिनट के लिए बात करना चाहूंगा।

मेरे मित्र श्री कामत ने अनुच्छेद 277-ए में सुझाव दिया है। उनका संशोधन यह था कि "और" शब्द को "या" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है, क्योंकि जिस संदर्भ में "और" शब्द है वह 778 है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2006] 1 एस सी आर।

रखा गया कंजंक्टिव के साथ-साथ डिसजंक्टिव दोनों है, जिसे दोनों में पढ़ा जा सकता है

"और" या "या", जैसा कि अवसर की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए उस संशोधन को स्वीकार करना आवश्यक है, हालांकि मैं संशोधन करने में उनके इरादे की सराहना करता हूं।

दूसरा संशोधन जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा वह है

मेरे दोस्त प्रो. सक्सेना, जिसमें उन्होंने एक बात प्रस्तावित की है

राष्ट्रपति घोषणा के तहत जो कर सकते हैं वह विधायिका को भंग करना है। मुझे लगता है कि यह उनका सार में संशोधन है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि यह उन चीजों में से एक है जिसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए क्योंकि लोग

प्रांत को विधायिका के संदर्भ में मामलों को सही करने का अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि यह पहले से ही उप द्वारा कवर किया गया है अनुच्छेद 278 के खंड (1) का खंड (ए), क्योंकि उपखंड (ए) प्रस्तावित करता है कि

राष्ट्रपति राज्यपाल या शासक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। एक शक्ति जो निहित है और जिसका प्रयोग राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है, वह

है सदन को भंग करना। नतीजतन, जब राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करता है और उपखंड (ए) के तहत इन शक्तियों को ग्रहण करता है, तो विधायिका को भंग करने और अभी चुनाव कराने की वह शक्ति होगी

स्वचालित रूप से राष्ट्रपति को हस्तांतरित किया जाता है जो कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सलाह पर प्रयोग करेगा। नतीजतन, मेरा निवेदन है कि मेरे मित्र प्रो. सक्सेना पहले से ही उपखंड (ए) में शामिल है, यह इसमें निहित है और इसलिए उस चरित्र का कोई स्पष्ट प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अब मैं अपने मित्र पंडित कुंजरू की टिप्पणियों पर आता हूं। सबसे पहले

अगर मुझे ठीक से याद है, तो उनके द्वारा उठाया गया मुद्दा यह था कि संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर प्रशासन को संभालने की शक्ति एक नई बात है, जो किसी भी संविधान में नहीं पाई जाती है। मैं उनसे अलग हूं और मैं उनका ध्यान अमेरिकी संविधान में निहित अनुच्छेद की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका का कर्तव्य निश्चित रूप से संविधान के रिपब्लिकन रूप को बनाए रखने के लिए व्यक्त किया गया है। जब हम कहते हैं कि संविधान को बनाए रखा जाना चाहिए

इस संविधान में निहित प्रावधानों से हमारा व्यावहारिक रूप से मतलब है कि अमेरिकी संविधान का क्या अर्थ है, अर्थात् इस संविधान में निर्धारित संविधान के रूप को बनाए रखा जाना चाहिए। इसलिए, जहाँ तक उस बिंदु का संबंध है, हमें नहीं लगता कि मसौदा समिति ने एक स्थापित सिद्धांत से विचलन किया है।

आलोचना का दूसरा बिंदु यह था कि अनुच्छेद 278 और 278-ए थे

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक है कि संविधान में पहले से ही रामेश्वर प्रसाद v हैं।

यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

अनुच्छेद 275 और 276। पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने (पंडित कुंजरू) उन उद्देश्यों और इरादों को पूरी तरह से गलत समझा है जो इसके आधार हैं।

अनुच्छेद 275 और वर्तमान अनुच्छेद 278। उनका तर्क था कि आखिरकार आप प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार चाहते हैं। यह अधिकार आपको अनुच्छेद 276 की शर्तों से मिलता है, क्योंकि इसके तहत केंद्र को, घोषणा जारी होने के बाद, सूची II में उल्लिखित सभी विषयों

पर कानून बनाने की शक्ति मिलती है। मुझे लगता है कि यह निहित प्रावधानों की बहुत सीमित समझ है।

या तो अनुच्छेद 275 और 276 में या अनुच्छेद 278 और 278-ए में।

मैं सबसे पहले सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन अवसरों पर अनुच्छेदों के दो समूह लागू होंगे

काफी अलग हैं। अनुच्छेद 275 केंद्र के हस्तक्षेप को आंतरिक या बाहरी युद्ध या आक्रामकता की स्थिति तक सीमित करता है। अनुच्छेद 278 युद्ध या आक्रामकता के अलावा अन्य कारणों से मशीनरी की विफलता को संदर्भित करता है। नतीजतन, कार्यात्मक खंड, जैसा कि मैंने कहा, काफी अलग हैं। उदाहरण के लिए, जब अनुच्छेद 275 के तहत युद्ध की घोषणा जारी की गई है, तो आपको प्रांतीय संविधान को निलंबित करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। प्रांतीय संविधान जारी रहेगा। विधायिका कार्य करती रहेगी और उसके पास वे शक्तियाँ होंगी जो संविधान उसे देता है; कार्यपालिका अपने पास रखेगी। इसकी कार्यकारी शक्ति और प्रांत के कानून के अनुसार प्रांत का प्रशासन जारी रखना। अनुच्छेद 276 के तहत जो कुछ भी होता है वह यह है कि केंद्र को कानून बनाने की समवर्ती शक्ति और कानून बनाने की समवर्ती शक्ति भी मिलती है।

प्रशासन। अनुच्छेद 276 के तहत ऐसा ही होता है। लेकिन जब अनुच्छेद 278 लागू होगा, तो स्थिति पूरी तरह से अलग होगी। प्रांत में कोई विधायिका नहीं होगी, क्योंकि विधायिका को निलंबित कर दिया गया होगा। प्रांत में व्यावहारिक रूप से कोई कार्यकारी अधिकार नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति या संसद या राज्यपाल द्वारा घोषणा द्वारा कुछ नहीं छोड़ा जाता है। दोनों की स्थितियाँ काफी अलग हैं। मुझे लगता है कि यह आवश्यक है कि हमें उस सीमांकन को बनाए रखना चाहिए जो हमने अनुच्छेद 275 और 278 के घटक शब्दों द्वारा किया है। मुझे लगता है कि दोनों चीजों को मिलाने से बहुत भ्रम पैदा होगा।

XXX XXX XXX

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: केवल तभी जब सरकार प्रांतों की संवैधानिक सरकार के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलती है, तो प्रांत में अच्छी सरकार है या नहीं, यह केंद्र को निर्धारित करना है। मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल स्पष्ट हूं।

XXX XXX XXX

780

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: मुझे अब बहुत समय लगेगा

पूरी बात की विस्तृत जांच करें और, प्रत्येक कथन का उल्लेख करते हुए, यह वह प्रिंट है जो इसमें स्थापित है और कहें, यदि कोई सरकार या कोई प्रांत की विधायिका इसके अनुसार कार्य नहीं करती है, जो कार्य करेगी।

मशीनरी की विफलता के रूप में। मुझे लगता है कि "मशीनरी की विफलता" अभिव्यक्ति का उपयोग भारत सरकार अधिनियम, 1935 में किया गया है। इसलिए हर किसी को इसके वास्तविक और न्यायिक अर्थ से काफी परिचित होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आगे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

XXX XXX XXX

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: आम बहस के बारे में

जो हुआ है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि इन अनुच्छेदों का दुरुपयोग किया जा सकता है, मैं कह सकता हूं कि मैं पूरी तरह से इस बात से इनकार नहीं करता कि इन अनुच्छेदों का दुरुपयोग या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है।

लेकिन यह आपत्ति संविधान के हर उस हिस्से पर लागू होती है जो केंद्र को प्रांतों पर हावी होने की शक्ति देता है। वास्तव में मैं अपने माननीय मित्र श्री गुप्ते द्वारा कल व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूं कि हमें उचित चीज की उम्मीद करनी चाहिए कि इस तरह के अनुच्छेदों को कभी भी लागू नहीं किया जाएगा और वे एक मृत पत्र बने रहेंगे। अगर उन्हें लागू किया जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति, जो इन शक्तियों से संपन्न हैं, उचित सावधानी बरतेंगे।

वास्तव में प्रांतों के प्रशासन को निलंबित करने से पहले। मुझे उम्मीद है कि वह जो पहला काम करेंगे वह केवल एक ऐसे प्रांत को चेतावनी जारी करना होगा जिसने गलती की है, कि चीजें नहीं हो रही थीं, जिस तरह से वे संविधान में होने वाले थे। यदि वह चेतावनी विफल हो जाती है, तो उसके लिए दूसरी बात यह होगी कि वह प्रांत के लोगों को मामलों को खुद निपटाने की अनुमति देने के लिए चुनाव का आदेश दे। जब ये दोनों उपाय विफल हो जाएँगे तभी वह इस अनुच्छेद का सहारा लेंगे। केवल उन्हीं परिस्थितियों में वह इस अनुच्छेद का सहारा लेंगे। मुझे नहीं लगता कि हम तब यह कह सकते थे कि इन अनुच्छेदों को व्यर्थ में आयात किया गया था या राष्ट्रपति ने जानबूझकर काम किया था।

श्री एच. वी. कामथ: क्या डॉ. अम्बेडकर सदन को आश्वस्त करने की स्थिति में हैं?

कि अनुच्छेद 143 को अब उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर: मैंने ऐसा कहा है और अब मैं कहता हूं कि

दूसरे वाचन के बाद जब मसौदा समिति की बैठक होगी, तो वह समग्र रूप से प्रावधानों पर विचार करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो अनुच्छेद 143 में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं संशोधन को एक के बाद एक मतदान के लिए रखूंगा।

सवाल यह है:

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

781

उस अनुच्छेद 188 को हटा दिया जाए।

प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।

अनुच्छेद 188 को संविधान से हटा दिया गया था।

. अध्यक्ष: फिर मैं अनुच्छेद 277-ए को लूंगा।

ई प्रश्न अछि:

" कि संशोधनों के संशोधन की सूची I (दूसरे सप्ताह) के संशोधन संख्या 121 में, प्रस्तावित नए अनुच्छेद 277 ए में, 'संघ' शब्द के लिए 'केंद्र सरकार' शब्द

प्रतिस्थापित "।

संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं संशोधन संख्या 221 रखूंगा।

सवाल यह है:

" कि 'और' शब्द के लिए प्रस्तावित नए अनुच्छेद 277 ए में संशोधनों की सूची I (दूसरा सप्ताह) के संशोधन संख्या 121 में, जहां यह पहली बार आता है, शब्द

' या 'प्रतिस्थापित किया जाए'।

संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय: सवाल यह है:

" कि सूची I (दूसरा सप्ताह) के संशोधन संख्या 121 में

आंतरिक शब्दों के लिए संशोधनों में संशोधन 'आंतरिक विद्रोह या अराजकता' शब्दों को बाधित करें

प्रतिस्थापित "।

संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय: सवाल यह है:

" कि अनुच्छेद 277 के बाद निम्नलिखित नया अनुच्छेद जोड़ा जाए:

' 277 - ए. प्रत्येक राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा।

बाहरी आक्रामकता और आंतरिक अशांति के खिलाफ और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है।
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।

अध्यक्ष महोदय: सवाल यह है।:

" वह अनुच्छेद 277-संविधान का एक हिस्सा है।

प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।

अनुच्छेद 277-ए को संविधान में जोड़ा गया था।

अध्यक्ष महोदय: सवाल यह है:

" वह सूची द्वितीय के संशोधन सं. 160 में। (दूसरा सप्ताह), का

प्रतिस्थापित "। संशोधन को
अस्वीकार कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय: सवाल यह है:

" कि सूची द्वितीय (दूसरा सप्ताह) के संशोधन सं. 160 में

प्रस्तावित विधेयक के खंड (1) में संशोधन

अनुच्छेद 278, शब्द या अन्यथा 'हटा दिए जाएँ'।

संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय: सवाल यह है:

" सूची द्वितीय (दूसरा सप्ताह) के संशोधन संख्या 160 में कहा गया है: में से

प्रस्तावित विधेयक के खंड (1) में संशोधन

अनुच्छेद 278, 'शब्दों के बाद संतुष्ट है कि' शब्द 'एक कब्र है
आपातकाल लगा है जो शांति और शांति के लिए खतरा है

राज्य का और वह 'जोड़ा जाए'।

संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय: सवाल यह है:

" कि सूची द्वितीय (दूसरा सप्ताह) के संशोधन सं. 160 में
खंड (4) के पहले परंतुक के लिए संशोधन

प्रस्तावित अनुच्छेद 278 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए:

' बशर्ते कि राष्ट्रपति यदि उचित समझता है तो किसी भी समय आदेश दे सकता है।

उस समय, इस अवधि के दौरान राज्य विधानमंडल का विघटन

एक नए आम चुनाव के बाद, और घोषणा
जिस दिन से नव निर्वाचित होते हैं, उस दिन से प्रभाव समाप्त हो जाता है

विधायिका की बैठक सत्र में होती है "।

संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया था।

रामेश्वर प्रसाद बनाम. 0. 1 यू. [पासायत, जे।]

783

अध्यक्ष महोदय: सवाल यह है:

" कि अनुच्छेद 278 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किए जाएं।

278 (1) . राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान। यदि राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल या शासक या अन्यथा से एक रिपोर्ट प्राप्त करने पर, संतुष्ट है कि राज्य को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा

(क) के सभी या किसी भी कार्य को स्वयं मान लें।

राज्य की सरकार और सभी या कोई भी, शक्तियाँ

राज्यपाल या शासक, जैसा भी मामला हो, या राज्य में किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण में निहित या प्रयोग करने योग्य

राज्य के विधानमंडल की तुलना में;

(ख)

घोषणा करें कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ

के अधिकार द्वारा या उसके अधीन प्रयोग किया जाएगा

संसद;

ऐसे आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान करें जैसे कि

((ग)

राष्ट्रपति को उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होता है, जिसमें इस संविधान के किसी भी प्रावधान के संचालन को पूरी तरह

या आंशिक रूप से निलंबित करने के प्रावधान शामिल हैं।
राज्य में निकाय या प्राधिकरण:

बशर्ते कि इस खंड की कोई भी बात राष्ट्रपति को किसी उच्च न्यायालय में निहित या प्रयोग करने योग्य किसी भी शक्ति को अपने पास लेने या किसी उच्च न्यायालय के संचालन को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित करने के लिए अधिकृत नहीं करेगी। उच्च न्यायालयों से संबंधित इस संविधान के प्रावधान।

(2) ऐसी किसी भी घोषणा को बाद की घोषणा द्वारा निरस्त या परिवर्तित किया जा सकता है।

(3) इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और, सिवाय इसके कि जहां यह पिछली उद्घोषणा को निरस्त करने वाली उद्घोषणा है, दो महीने की समाप्ति पर काम करना बंद कर देगी, जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले इसे संसद के दोनों सदनों के प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है:

बशर्ते कि यदि ऐसी कोई घोषणा ऐसे समय में जारी की जाती है जब लोक सभा भंग हो जाती है या [2006] एस. सी. आर. का विघटन हो जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हाउस ऑफ द पीपल दो महीने की अवधि के दौरान होता है। इस खंड में निर्दिष्ट और घोषणा को अनुमोदित नहीं किया गया है

उस अवधि की समाप्ति से पहले लोक सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा, घोषणा उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति पर काम करना बंद कर देगी जिस दिन लोक सभा अपने पुनर्गठन के बाद पहली बार बैठती है, जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले

घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए हैं।

(4) इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, जब तक कि निरस्त नहीं की जाती है, इस अनुच्छेद के खंड (3) के तहत उद्घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्तावों में से दूसरे के पारित होने की तारीख से छह महीने की समाप्ति पर काम करना बंद कर देगी:

बशर्ते कि यदि और इतनी बार अनुमोदन करने वाले प्रस्ताव के रूप में

इस तरह की घोषणा को जारी रखने के लिए पारित किया जाता है: दोनों सदनों द्वारा

संसद की घोषणा, जब तक कि निरस्त नहीं की जाती है, उस तारीख से छह महीने की और अवधि के लिए लागू रहेगी जिस दिन इस खंड के तहत यह अन्यथा काम करना बंद कर देता, लेकिन ऐसा कोई नहीं है।

घोषणा किसी भी मामले में तीन से अधिक समय तक लागू रहेगी।

वर्ष:

बशर्ते कि यदि लोक सभा का विघटन

छह महीने की किसी भी अवधि के दौरान होने पर और ऐसी घोषणा को जारी रखने को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव उक्त अवधि के दौरान लोक सभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, तो घोषणा तीस दिनों की समाप्ति पर काम करना बंद कर देगी।

जिस तारीख को लोक सभा अपने पुनर्गठन के बाद पहली बार बैठती है, उस अवधि के प्रस्तावों की समाप्ति से पहले तक

घोषणा को मंजूरी देते हुए संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। 278 - ए. जारी की गई घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग

अनुच्छेद 278 के तहत। (1) . जहां इस संविधान के अनुच्छेद 278 के खंड (1) के तहत जारी एक उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया गया है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का उपयोग संसद के अधिकार द्वारा या उसके तहत किया जाएगा, वह सक्षम होगा।

(क) संसद को राष्ट्रपति या उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी को राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति सौंपने के लिए। ((ख) संसद के लिए या राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकारी के लिए जिसे रामेश्वर प्रसाद v.

यू. ओ.] [पासायत। जे.]

785

कानून बनाने की शक्ति इस खंड के उपखंड (ए) के तहत प्रत्यायोजित है।

शक्तियाँ प्रदान करने और कर्तव्यों को लागू करने या अधिकृत करने के लिए कानून बनाना।

शक्तियों का प्रदान करना और उन पर कर्तव्यों का अधिरोपण

भारत सरकार या सरकार के अधिकारी और अधिकारी

(ग) राष्ट्रपति को अधिकृत करने के लिए जब लोक सभा नहीं है लंबित राज्य की संचित निधि से सत्र व्यय में

(घ) राष्ट्रपति के लिए संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत अध्यादेश जारी करना। इस संविधान को छोड़कर जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो।

(2) संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन बनाई गई कोई विधि जो

संसद या राष्ट्रपति या उपखंड में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी

(ए) इस अनुच्छेद के खंड (1) के लिए नहीं, लेकिन एक के मुद्दे के लिए

इस संविधान के अनुच्छेद 278 के तहत घोषणा की गई है

के बाद एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभाव पड़ता है की गई या की गई चीज़ों को छोड़कर उद्घोषणा का संचालन बंद हो गया है।

उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया जाना छोड़ दिया गया जब तक कि

जिन प्रावधानों का प्रभाव इस प्रकार समाप्त हो जाएगा, उन्हें जल्द ही निरस्त कर दिया जाएगा या विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा संशोधन के साथ या उसके बिना पुनः अधिनियमित किया गया

राज्य का "। संशोधन को स्वीकार कर लिया गया।

अध्यक्ष महोदयः सवाल यह हैः

" कि प्रस्तावित अनुच्छेद 278 संविधान का हिस्सा है।

प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। संविधान में अनुच्छेद 278 जोड़ा गया था।

अध्यक्ष महोदयः सवाल यह हैः

" उसने अनुच्छेद 278 का प्रस्ताव रखा-यह संविधान का एक स्थायी हिस्सा है।

प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अनुच्छेद 278-ए को संविधान में जोड़ा गया था।

संविधान को अपनाने में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर [2006] आई. एस. सी. आर. का भाषण

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11.1949 इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण अवलोकन शामिल थे:

बहुत बुरा होता है। संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, यह हो सकता है अच्छा साबित होता है अगर जिन्हें काम करने के लिए बुलाया जाता है, तो ऐसा होता है

बहुत अच्छा बनो। संविधान का कार्यकरण पूरी तरह से निर्भर नहीं करता है।

संविधान की प्रकृति पर। संविधान प्रदान कर सकता है

केवल राज्य के अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और

न्यायपालिका। राज्य के उन अंगों के कार्य करने के कारक

यह निर्भर करता है कि वे लोग और राजनीतिक दल किस रूप में स्थापित करेंगे उनकी इच्छाओं और उनकी राजनीति को पूरा करने के लिए उनका साधन। कौन कर सकता है?

बताइए कि भारत के लोग और उनके दल कैसा व्यवहार करेंगे? क्या वे करेंगे?

अपने उद्देश्यों या इच्छा को प्राप्त करने के संवैधानिक तरीकों को बनाए रखें

क्या वे उन्हें प्राप्त करने के क्रांतिकारी तरीकों को पसंद करते हैं? अगर वे गोद लेते हैं क्रांतिकारी तरीके, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो,

यह कहने के लिए किसी पैगंबर की आवश्यकता नहीं है कि यह विफल हो जाएगा। इसलिए ऐसा करना व्यर्थ है। भाग के संदर्भ के बिना संविधान पर कोई निर्णय

जिसे लोगों और उनके दलों द्वारा खेले जाने की संभावना है। जेफरसन,

महान अमेरिकी राजनेता जिन्होंने इसमें इतनी बड़ी भूमिका निभाई

जिन विचारों को संविधान निर्माता कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। में। एक जगह उन्होंने कहा है:

" हम प्रत्येक पीढ़ी को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान सकते हैं,

आने वाली पीढ़ी को बांधने के लिए, निवासियों से अधिक
एक और देश।

एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा है:

" यह विचार कि संस्थान राष्ट्र के उपयोग के लिए स्थापित किए गए थे

उन्हें छुआ या संशोधित नहीं किया जा सकता है, यहां तक कि उन्हें उनका जवाब देने के लिए भी नहीं

अंत में, उन लोगों में नि:स्वार्थ रूप से माने गए अधिकारों के कारण जो नियोजित हैं

जनता के विश्वास में उन्हें प्रबंधित करने के लिए, शायद एक हो सकता है

एक सम्राट के दुर्व्यवहार के खिलाफ हितकारी प्रावधान, लेकिन प्रस्ताव है
राष्ट्र के खिलाफ बेतुका। फिर भी हमारे वकील और पुजारी

आम तौर पर इस सिद्धांत को विकसित करें, और मान लीजिए कि उससे पहले के रामेश्वर प्रसाद v.

यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

787

पीढ़ियों ने पृथ्वी को हमसे अधिक स्वतंत्र रूप से रखा; एक अधिकार था

हम पर कानून लागू करने के लिए, खुद से अपरिवर्तनीय, और हम,

इसी तरह, कानून बना सकते हैं और भविष्य पर बोझ डाल सकते हैं

पीढ़ियाँ, जिन्हें उन्हें बदलने का कोई अधिकार नहीं होगा; ठीक है, कि

पृथ्वी मृतकों की है न कि जीवितों की।

मैं स्वीकार करता हूं कि जेफरसन ने जो कहा है वह केवल सच नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है।

सच है। इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। संविधान सभा थी जेफरसन
द्वारा निर्धारित इस सिद्धांत से अलग यह निश्चित रूप से होगा

निन्दा के लिए भी दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन मैं पूछता हूं, है ना? काफी हद तक

इसके विपरीत। केवल संबंधित प्रावधानों की जांच करनी है

इस संविधान पर अंतिमता और अचूकता की मुहर लगाने से लोगों को संविधान में संशोधन करने के अधिकार से वंचित करके

कनाडा या संविधान में संशोधन करके

अमेरिका में असाधारण नियमों और शर्तों की पूर्ति या

ऑस्ट्रेलिया, लेकिन संशोधन के लिए एक सबसे आसान प्रक्रिया प्रदान की है

संविधान। मैं संविधान के किसी भी आलोचक को चुनौती देता हूं कि साबित करें कि दुनिया में कहीं भी किसी भी संविधान सभा में,

जिन परिस्थितियों में यह देश खुद को पाता है, बशर्ते कि

संविधान के संशोधन के लिए आसान प्रक्रिया। अगर वे

संविधान से असंतुष्ट होने पर केवल दो-तिहाई प्राप्त करना पड़ता है

बहुमत और यदि वे दो-तिहाई बहुमत भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं

संसद वयस्क मताधिकार पर उनके पक्ष में चुनी गई, उनका असंतोष

संविधान के साथ सामान्य द्वारा साझा नहीं माना जा सकता है

सार्वजनिक।

संवैधानिक महत्व का केवल एक बिंदु है जिस पर मैं प्रस्ताव करता हूं।

एक संदर्भ बनाने के लिए। इस आधार पर एक गंभीर शिकायत की जाती है कि बहुत अधिक केंद्रीकरण हो रहा है और राज्यों को नगरपालिकाओं तक सीमित कर दिया गया है। यह स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोण केवल एक नहीं है

अतिशयोक्ति, लेकिन यह इस गलत समझ पर भी आधारित है कि संविधान वास्तव में क्या करने का प्रयास करता है। जहां तक केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का सवाल है, तो उस मौलिक सिद्धांत को ध्यान में रखना आवश्यक है जिस पर यह आधारित है। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायी और कार्यकारी प्राधिकरण केंद्र के बीच विभाजित है।

और राज्य केंद्र द्वारा बनाए जाने वाले किसी कानून द्वारा नहीं बल्कि स्वयं संविधान द्वारा बनाए जाने वाले हैं। संविधान यही करता है। हमारे संविधान के तहत राज्य अपने विधायी या कार्यकारी अधिकार के लिए किसी भी तरह से केंद्र पर निर्भर नहीं हैं। केंद्र और राज्य आई. एस. सी. आर. (2006) हैं।

इस मामले में सह-समान। यह देखना मुश्किल है कि ऐसा संविधान कैसे बनता है। इसे केंद्रीकरण कहा जा सकता है। यह हो सकता है कि संविधान ने

केंद्र अपने विधायी और कार्यपालिका के संचालन के लिए एक बड़ा क्षेत्र है

किसी भी अन्य संघीय संविधान में पाए जाने वाले अधिकार की तुलना में। यह हो सकता है

कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं न कि केंद्र को

राज्यों। लेकिन ये विशेषताएं संघवाद का सार नहीं हैं। द.

संघवाद की मुख्य पहचान, जैसा कि मैंने कहा, विधायिका के विभाजन में निहित है। और केंद्र और इकाइयों के बीच कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा

संविधान। यह हमारे संविधान में सन्निहित सिद्धांत है। वहाँ
इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। इसलिए यह कहना गलत है कि

राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है। केंद्र इसके द्वारा नहीं कर सकता है
स्वयं उस विभाजन की सीमा को बदल देगा। न ही न्यायपालिका ऐसा कर सकती है। के लिए

जैसा कि कहा गया है:

" न्यायालय संशोधित कर सकते हैं, वे प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। वे पहले संशोधित कर सकते हैं।

नए तर्कों के रूप में व्याख्याएँ, नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाते हैं,

वे सीमांत मामलों में विभाजन रेखा को स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन बाधाएं हैं वे पारित नहीं कर सकते हैं, शक्ति के निश्चित कार्य वे पुनः आवंटित नहीं कर सकते हैं।

वे मौजूदा शक्तियों का एक व्यापक निर्माण दे सकते हैं, लेकिन वे
एक प्राधिकारी को दूसरे को स्पष्ट रूप से दी गई शक्तियाँ निर्दिष्ट नहीं कर सकते।

इसलिए संघवाद को हराने के लिए केंद्रीकरण का पहला आरोप होना चाहिए। गिर जाते हैं।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राज्यपाल का बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण पद होता है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में पद। जब इन आरोपों के आधार पर उनकी विश्वसनीयता दांव पर है कि वह अपने संवैधानिक दायित्वों या कार्यों को सही तरीके से नहीं निभा रहे थे, तो यह किसी विशेष राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में चुने गए व्यक्ति पर एक दुखद प्रतिबिंब है। राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति को पद का गौरव बढ़ाना चाहिए और उन कर्तव्यों और कार्यों से अनजान एक प्रतीकात्मक व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो उससे किए जाने की उम्मीद की जाती है। दिलचस्प है।

राज्यपालों में दल जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंधित थे या संबंधित थे, और यदि राज्यपाल किसी भी समय सत्तारूढ़ दल के पदाधिकारी थे। केंद्र में जब कोई दूसरा दल सत्ता में आता है तो स्थिति नहीं बदलती है। विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाना सुविधाजनक प्रतीत होता है। सरकारिया आयोग और आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करके इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से बचा जा सकता था और किया जा सकता था। राष्ट्रीय आयोग के कामकाज की समीक्षा करने के लिए समिति

राज्यपालों की नियुक्ति के मामले में संविधान। यह पक्षों के लिए सुविधाजनक नहीं प्रतीत होता है क्योंकि वे रामेश्वर प्रसाद v का लाभ उठाना चाहते हैं।

यू. ओ. एल [पासायत। जे.]

एक विशेष समय पर स्थिति और जब स्थिति उनके लिए अनुकूल नहीं लगती है तो रोते हैं। यह उन राजनीतिक दलों की नैतिकता पर एक दुखद प्रतिबिंब है जो राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण करने का अवसर नहीं छोड़ते हैं। जल्द से जल्द उपचारात्मक उपाय किए जाने से लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। यह संविधान की कमी नहीं है जो स्थिति के लिए जिम्मेदार है। यह स्पष्ट रूप से उन लोगों के लिए जिम्मेदार है जो योग्यता के अलावा अन्य विचारों पर राज्यपालों का चुनाव करते हैं। यह एक परेशान करने वाली विशेषता है, और अगर मीडिया रिपोर्ट करता है

माना जा रहा है कि राज भवन तेजी से पार्टी कार्यालयों के विस्तार में बदल रहे हैं और राज्यपाल एक विशेष पार्टी के पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ

नहीं है। केंद्र-राज्य संबंधों में प्रमुख कर्ता राज्यपाल हैं जो केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु हैं। संस्थापक पिता जानबूझकर

गवर्नर के पद के लिए चुनाव से बचा जाता था, जैसा कि यू. एस. ए. में भाषाई रूढ़िवाद से कार्यालय को अलग करने के लिए प्रचलित है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 155 के तहत उन्हें राज्य का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।

भाग VI, अध्याय II में। राज्य की कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 154 द्वारा उनके पास निहित है और उनके द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल संविधान और कानून की रक्षा और रक्षा करने की शपथ के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। इसलिए, राज्यपाल के कार्यालय का उद्देश्य निर्वाचित कार्यपालिका द्वारा संविधान के कामकाज की संवैधानिक प्रक्रिया की सुरक्षा और निर्वाह सुनिश्चित करना है और उसे एक अंपायर की भूमिका दी जाती है। जब एक गांधीवादी अर्थशास्त्री संविधान सभा के सदस्य थे

राज्यपाल के पद को समाप्त करने के लिए अपनी याचिका के बारे में गांधीजी को एक पत्र लिखा, गांधीजी ने उन्हें इसे बनाए रखने के लिए लिखा, इस प्रकार; राज्यपाल को टीम की योजना में एक बहुत ही उपयोगी और आवश्यक स्थान दिया गया था। जब राज्य में संवैधानिक गतिरोध होता तो वह एक मध्यस्थ होते और वह एक निष्पक्ष भूमिका निभाने में सक्षम होते। ऐसा प्रशासनिक तंत्र होगा जिसके माध्यम से राज्य में संवैधानिक संकट का समाधान किया जाएगा। अत: राज्यपाल को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। राज्य के प्रमुख के रूप में अपनी दोहरी अविभाजित क्षमता में उन्हें निष्पक्ष रूप से राष्ट्रपति की सहायता करनी चाहिए। संवैधानिक संकट के समय राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख के रूप में उन्हें संयम लाना चाहिए। लिंक स्पष्ट है जब हम पाते हैं कि अनुच्छेद 356 को सामान्य रूप से राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया जाएगा। उन्हें ईमानदारी से और उच्च स्तर की संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ, शपथ के संदर्भ में, राष्ट्रपति को सूचित करना चाहिए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और राज्य सरकार 790

आवश्यक विस्तृत तथ्यात्मक आधार के साथ संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।

प्रत्येक उच्च पद के प्रत्येक अधिभोगियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे लगातार

वह उच्च पद में उस शक्ति से अवगत है जिसका उपयोग सार्वजनिक हित में और केवल सार्वजनिक भलाई के लिए किया जाना है, और यह कि इसका उपयोग किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए या केवल उस पद के वर्तमान धारक की व्यक्तिगत स्थिति को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना है।

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में यह अफसोस जताया गया कि कुछ राज्यपाल

वे उनसे अपेक्षित निष्पक्षता और दूरदर्शिता के गुणों को प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। उसके बाद से स्थिति में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है।

राज्यपालों की समिति (1971) की रिपोर्ट का संदर्भ भी दिया जाएगा।

प्रासंगिक बनें। कुछ प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:

" ब्रिटिश संवैधानिक सम्मेलनों के अनुसार, हालांकि शक्ति

प्रधान मंत्री को संसद का विघटन देना संप्रभु के व्यक्तिगत विशेषाधिकारों में से एक है, अब यह माना जाता है कि संप्रभु आम तौर पर प्रधान मंत्री की सलाह को स्वीकार करेगा क्योंकि इनकार करना बर्खास्तगी के समान होगा और संप्रभु को राजनीतिक विवाद में शामिल करेगा। जो अनिवार्य रूप से एक मंत्रालय के इस्तीफे के बाद होता है। प्रधानमंत्री को परीक्षण के लिए वैधानिक पाँच साल की सीमा के भीतर अपना समय चुनने का अधिकार है।

क्या हाउस ऑफ कॉमन्स में उनका बहुमत अभी भी उनकी इच्छा को दर्शाता है मतदाता। केवल तभी जब मुख्य राजनीतिक दलों का विभाजन होता है, तो संप्रभु का व्यक्तिगत विवेक सर्वोपरि विचार बन सकता है। हालाँकि, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब एक संप्रभु प्रधानमंत्री के खिलाफ अनौपचारिक सलाह लेने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। प्रोफेसर वेड, संवैधानिक कानून में (वेड और फिलिप्स, आठवें संस्करण। 1970), इन परिस्थितियों को इस प्रकार बताता है:

" यदि संप्रभु को संतुष्ट किया जा सकता है कि (1) एक मौजूदा संसद अभी भी है

महत्वपूर्ण और अपना काम करने में सक्षम, (2) एक आम चुनाव होगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक, विशेष रूप से यदि इसका पालन किया जाता है

पिछले चुनाव पर बारीकी से, और (3) वह एक और खोजने पर भरोसा कर सकता था

प्रधानमंत्री जो अपनी सरकार को जारी रखने के लिए तैयार थे

एक कामकाजी बहुमत के साथ उचित अवधि, संप्रभु कर सकता है

प्रधानमंत्री को भंग करने से संवैधानिक रूप से इनकार

कार्यालय "।

प्रो. वेड ने आगे कहा:

791

रामेश्वर प्रसाद बनाम. 0. 1 यू. [पासायत, जे।]

एक संवैधानिक संप्रभु के लिए खतरनाक स्थिति है जो यदि निवर्तमान प्रधानमंत्री को भंग करने से इनकार कर दिया है तो उत्पन्न होता है

उन्हें अपने उत्तराधिकारी से एक जनरल के लिए एक प्रारंभिक अनुरोध का सामना करना पड़ा

चुनाव। यदि कोई सामान्य सहमति थी तो इनकार करना उचित हो सकता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर और बाहर कि एक आम चुनाव

देरी की जानी चाहिए और स्पष्ट रूप से यह एक प्रधानमंत्री के लिए अनुचित होगा

चुनाव को सही ठहराने के लिए त्वरित मतदान पर हार पर भरोसा करना।

हुड फिलिप्स की अपनी नवीनतम पुस्तक, रिफॉर्म ऑफ द टचूशन (1970) में टिप्पणियाँ प्रासंगिक हैं:

" इस देश में प्रधानमंत्री की कोई मिसाल नहीं है, जिनके

पार्टी के पास कॉमन्स में बहुमत है, जो क्रम में विघटन की मांग कर रही है

अपनी ही पार्टी पर अपनी कमजोर पकड़ मजबूत करने के लिए। अगर वह पूछता है

विघटन के लिए बेहतर राय यह है कि रानी होगी

हकदार, शायद एक कर्तव्य होगा, मना करने के लिए। सामान्य स्थिति में

जब संप्रभु एक विघटन प्रदान करता है तो यह धारणा है कि

प्रधानमंत्री अपनी पार्टी की ओर से नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं। अन्यथा

निर्वाचकों से इस प्रश्न का निर्णय करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि

नेतृत्व। तो अगर संप्रभु को एक और प्रधानमंत्री मिल सकता है जो

एक उचित अवधि के लिए सरकार को जारी रखने में सक्षम थी, वह

विघटन से इनकार करना उचित होगा। कुछ इस तरह

1939 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ जब सवाल था कि क्या

दक्षिण अफ्रीका को युद्ध में प्रवेश करना चाहिए: गवर्नर-जनरल ने इनकार कर दिया

हर्ट्ज़ोग के लिए विघटन, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और स्मट्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिन्होंने

सरकार बनाने में सफल रहे।

XXX XXX XXX

हम पहले अनुच्छेद 356 के सटीक महत्व की जांच कर सकते हैं जो प्रतिबंध लगाता है।

संवैधानिक व्यवस्था के टूटने की स्थिति में किसी राज्य में एंट का शासन। चार हमारा वर्तमान उद्देश्य, यह भाषा को पढ़ने के लिए पर्याप्त है

(1) लेख के बारे में:

356. संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान राज्य। (1) यदि राष्ट्रपति, राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर

राज्य या अन्यथा, संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें राज्य की सरकार 792 के अनुसार नहीं चल सकती है।

इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा

(क) सरकार के सभी या किसी भी कार्य को स्वयं ग्रहण करें।

राज्य की और राज्य में निहित या उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी या कोई भी शक्ति

राज्यपाल या राज्य में इसके अलावा कोई अन्य निकाय या प्राधिकरण

राज्य का विधानमंडल;
(ख) घोषणा करें कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां -

संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत प्रयोग करने योग्य;

(ग) ऐसे आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान करें जो प्रतीत होते हैं -
राष्ट्रपति को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय होना

उच्च न्यायालय, या किसी के संचालन को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित करने के लिए उच्च
न्यायालयों से संबंधित इस संविधान का प्रावधान।

' श्री अल्लादी के शब्दों में, इस प्रावधान की मुख्य विशेषताएं

कृष्णस्वामी अय्यर (संविधान सभा में बोलते हुए), "वे हैं जैसे ही घोषणा की जाती है, (राज्य के) कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। वास्तव में इसका क्या अर्थ है? चूंकि सदस्यों को इस मुद्दे पर बार-बार याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, 'राष्ट्रपति' का अर्थ है पूरी संसद के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसमें विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधि होते हैं जो संघीय सरकार के घटक भाग होते हैं। इसलिए, राज्य तंत्र विफल होने के कारण, केंद्र सरकार राज्य मंत्रिमंडल के बजाय जिम्मेदारी लेती है। फिर, जहाँ तक कार्यकारी सरकार का संबंध है, वह राज्य में सरकार के उचित कामकाज के लिए केंद्रीय संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। यदि किसी राज्य में जिम्मेदार सरकार ठीक से काम करती है, तो केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही कर सकता है।

जब घोषणा लागू होती है, संसद बन जाती है

राज्य का विधानमंडल और केंद्र में मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में संसद के प्रति जवाबदेह है। संसद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार बनाया गया कोई भी कानून

घोषणा के आधार पर संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है और संसद द्वारा संशोधन के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, रामेश्वर प्रसाद बनाम के तहत राष्ट्रपति शासन के तहत एक राज्य।

यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

अनुच्छेद 356 वस्तुत: केंद्र सरकार की कार्यकारी जिम्मेदारी और नियंत्रण के अंतर्गत आता है। घोषणा की अवधि के दौरान राज्य में जिम्मेदार सरकार को जिम्मेदार सरकार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

आम तौर पर राज्य के क्षेत्र में मामलों के संबंध में केंद्र।

अनुच्छेद 356 पर चर्चा करते समय अनिवार्य रूप से अनुच्छेद की धारा 93 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

भारत सरकार अधिनियम, 1935। इस खंड ने राज्यपाल और राज्यपाल में निहित विशाल शक्ति को देखते हुए एक निश्चित रूप से कुख्याति प्राप्त की थी।

इसके दुरुपयोग की संभावना, गवर्नर अंग्रेजों का एजेंट है

सरकार। संविधान सभा के कई प्रमुख सदस्यों ने प्रांतीय स्वायत्तता के उद्घाटन के बाद प्रांतों में मंत्रियों के रूप में महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा कर लिया था और इस प्रकार उन्हें इस विशेष खंड के काम करने और संविधान में धारा 93 जैसे प्रावधान के संभावित प्रभाव का प्रत्यक्ष अनुभव था। इसलिए संविधान सभा और समितियों दोनों में संविधान में प्रावधान को शामिल करने की सलाह या आवश्यकता पर काफी चर्चा हुई। पंडित एच. एन. कुंजरू, जिन्हें इस प्रावधान के बारे में गंभीर आशंकाएं थीं, ने राज्यपाल के कार्यों को केवल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देने तक सीमित करने का सुझाव दिया, यह राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया कि वह ऐसी कार्रवाई करें जो उन्हें रिपोर्ट पर उचित लगे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत सैद्धांतिक रूप से पंडित कुंजरू से सहमत थे। पूर्व ने विशेष रूप से उन प्रशासनिक कठिनाइयों का उल्लेख किया जो राज्यपाल को अपने मंत्रियों के प्रमुख पर अपनी पहल पर कार्य करने की शक्तियां देने से पैदा होंगी।

23 जुलाई, 1949 को प्रांतों के प्रधानमंत्रियों के साथ मसौदा समिति की बैठक में पूरे प्रश्न की जांच की गई थी। पंडित पंत ने फिर व्यक्त किया कि

अपने विवेक से शक्तियों का प्रयोग करना। इस तरह की शक्तियों से लैस, वह एक निरंकुश व्यक्ति होगा और इससे उसके और उसके मंत्रियों के बीच टकराव हो सकता है। श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने भारत सरकार अधिनियम की धारा 93 और संविधान के अनुच्छेद

356 में किए गए प्रावधान के बीच समानता के बारे में संविधान सभा के सदस्यों के मन में आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने संविधान सभा में कहा:

" पुरानी धारा 93 (के) के बीच कोई पत्राचार नहीं है।
भारत सरकार अधिनियम, 1935) और यह कुछ भागों में भाषा के संबंध में छोड़कर। धारा 93 के तहत, धारा 93 के काम करने की अंतिम जिम्मेदारी ग्रेट ब्रिटेन की संसद थी जो निश्चित रूप से भारत के लोगों की प्रतिनिधि थी, जबकि वर्तमान अनुच्छेद 794 के तहत जिम्मेदारी भारत की संसद की है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुना जाता है, और मेरे पास नहीं है संदेह है कि न केवल प्रतिनिधियों की अंतरात्मा

अन्य इकाइयों को त्वरित किया जाएगा और वे यह देखेंगे कि प्रावधान ठीक से काम किया जाता है। उन परिस्थितियों को छोड़कर,

भावनात्मक आपत्ति कि यह सिर्फ पुरानी धारा 93 की पुनरावृत्ति है,

मुख्य सिद्धांत का अपवाद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस लेख के अंतर्गत "।

आपातकालीन प्रावधानों पर बहस को समाप्त करते हुए, डॉ. अबमेदकर

देखा गया:

" उस सामान्य बहस के संबंध में जिसमें यह हुई है

सुझाव दिया गया है कि इन लेखों का दुरुपयोग किया जा सकता है। मैं कह सकता हूँ

कि मैं पूरी तरह से इस बात से इनकार नहीं करता कि इसकी संभावना है

राजनीतिक उद्देश्यों के लिए वस्तुओं का दुरुपयोग या उपयोग किया जा रहा है। लेकिन यह

आपत्ति संविधान के हर उस भाग पर लागू होती है जो शक्ति प्रदान करता है

प्रांतों को ओवरराइड करने के लिए केंद्र को। वास्तव में मैं भावनाओं को साझा करता हूं।

कल मेरे माननीय मित्र श्री गुप्ते ने कहा कि

उचित बात जो हमें उम्मीद करनी चाहिए वह यह है कि इस तरह के लेख कभी नहीं होंगे

ऑपरेशन में बुलाया गया और वे एक मृत पत्र बने रहेंगे। अगर

उन सभी को संचालन में लाया जाता है, मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति, जो है

इन शक्तियों से संपन्न, पहले उचित सावधानी बरतेंगे
वास्तव में प्रांतों के प्रशासन को निलंबित करना "।

डॉ. अम्बेडकर को उम्मीद है कि इस प्रावधान का उपयोग संयम से किया जाएगा।

स्वीकार किया जाना चाहिए, पूरा नहीं किया गया है। बीस-एक वर्षों के दौरान

संविधान के अनुसार, चौबीस बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है-केरल में 1 नवंबर, 1956 को राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना, त्रावणकोर में राष्ट्रपति शासन की निरंतरता थी-कोच्चि पहले लागू किया गया था। 23 मार्च, 1956-केरल राज्य पाँच बार और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा। सत्रह राज्यों में से (पी. ई. पी. एस. यू., जिसका बाद में पंजाब में विलय हो गया, और हिमाचल प्रदेश, जो हाल ही में एक राज्य बना, को छोड़कर) ग्यारह राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा है। कुछ राज्यों में जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता हमने देखी है और दलबदल की राजनीति ने इस देश के राजनीतिक जीवन को इतना धूमिल कर दिया है, शायद उस समय किसी भी तरह से परिकल्पना नहीं की गई थी जब संविधान सभा ने संविधान के मसौदे पर विचार किया था। नहीं।

यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि राज्यपाल चाहते हैं कि राज्य को राष्ट्रपति शासन के तहत लाया जाए, सिवाय उन परिस्थितियों के जो उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ती हैं।

रामेश्वर प्रसाद बनाम। यू. ओ. आई. [पासायत। जे.]

जैसा कि अंत में अपनाया गया अनुच्छेद, राज्यपाल के कार्यों को राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देने तक सीमित करता है कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें संवैधानिक तंत्र की विफलता हुई है। यह निर्णय कि क्या

अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा जारी की जा सकती है जो राष्ट्रपति, यानी केंद्र सरकार के पास है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति "राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा" शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट हैं।

कि स्थिति के लिए ऐसी घोषणा जारी करने की आवश्यकता है।

जिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है, उन पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 356 का सहारा लेना राज्यपाल के लिए अंतिम उपाय होना चाहिए। इस संबंध में राज्यपाल की अक्सर आलोचना की जाती है कि वह कभी-कभी केंद्र सरकार के इशारे पर काम करते हैं। यह आलोचना मुख्य रूप से राज्यपालों के सामने आने वाली स्थितियों की सराहना की कमी से उत्पन्न होती है।

राज्य के प्रमुख के रूप में, राज्यपाल का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण राज्य का प्रशासन टूट न जाए। उन्हें समान रूप से इस बात का ध्यान रखना होगा कि राज्य में जिम्मेदार सरकार को हल्के में परेशान या प्रतिस्थापित नहीं किया जाए। इन्हें सुनिश्चित करने में न केवल राज्यपाल बल्कि राजनीतिक दलों को भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। राजनीतिक दल मतदाताओं के जनादेश के साथ सत्ता में आते हैं और वे इसके लिए ऋणी होते हैं

विधानमंडल के प्रति प्राथमिक उत्तरदायित्व। संसदीय सरकार के मानदंडों का उनके द्वारा सबसे अच्छा रखरखाव किया जाता है।

इस मुद्दे को छोड़ने से पहले, हम यह बताना चाहेंगे कि यह केवल राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में नहीं है कि राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर सकता है। इस रिपोर्ट में कहीं और संदर्भ दिया गया है

अनुच्छेद 356 के अनुसार। राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में कोई सटीक दिशा-निर्देश निर्धारित करना मुश्किल है। राज्यपाल को 796 के अनुसार प्रत्येक अवसर पर कार्य करना होता है।

(2006) 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उनका सबसे अच्छा निर्णय, मार्गदर्शक सिद्धांत, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, कि राज्य में संवैधानिक तंत्र को, जहां तक संभव हो, बनाए रखा जाना चाहिए। संयोजन:

संविधान के सम्मेलन, डाइसी की क्लासिक परिभाषा के अनुसार,

इसमें "रीति-रिवाज, प्रथाएं, सिद्धांत या उपदेश शामिल हैं जो न्यायालयों द्वारा लागू या मान्यता प्राप्त नहीं हैं", लेकिन "कानूनों का नहीं, बल्कि कानूनों का एक निकाय बनाते हैं।

संवैधानिक या राजनीतिक नैतिकता "। सम्मेलनों के संचालन का व्यापक आधार प्रो. वेड का डाइसी के नियम का परिचय

संविधान का (1962 संस्करण)। सम्मेलनों की आज्ञाकारिता को सुरक्षित करने वाले प्रमुख उद्देश्यों के बारे में कहा गया है:

" ((I) संवैधानिक सरकार की परंपराओं को जारी रखने की इच्छा;

(2) राज्य के जहाज की जटिल मशीनरी को बनाए रखने की इच्छा

काम करने का क्रम;

(3) जनता के विश्वास को बनाए रखने की चिंता, और इसके साथ

कार्यालय और शक्ति "।

ये प्रभाव यह सुनिश्चित करते हैं कि मंत्रिमंडल सरकार के सम्मेलन,

जो बाध्यकारी पूर्ववर्ती और सुविधाजनक उपयोग पर आधारित हैं, मंत्रियों की क्रमिक पीढ़ियों द्वारा देखे जाते हैं। एक सम्मेलन की सटीक सामग्री बदल सकती है या उलट भी जा सकती है, लेकिन पिछली प्रथा से प्रत्येक प्रस्थान का बचाव उन लोगों द्वारा किया जाता है जो पुराने उदाहरणों का उल्लंघन नहीं करते हैं। आपत्तियों को केवल तभी चुप कराया जाता है जब समय ने साबित कर दिया है कि पूर्ववर्ती से प्रस्थान ने एक नई परंपरा बनाई है, या खुद को एक खराब मिसाल के रूप में दिखाया है और इसलिए, अपने आप में परंपरा का उल्लंघन है।

परंपराओं की प्रकृति की यह व्याख्या बताएगी कि, यदि उनके पास है

इसका पालन किया जाए और इसका पालन किया जाए, इसके लिए प्राथमिक जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जिन पर सरकार की जिम्मेदारी होगी। संसदीय प्रणाली में, यह जिम्मेदारी निर्विवाद रूप से निर्वाचित लोगों की होती है।

विधानमंडलों में कार्य करने वाले लोगों के प्रतिनिधि। वे ज्यादातर राजनीतिक दलों के सदस्य हैं जो किए गए वादों और घोषित कार्यक्रमों के आधार पर मतदाताओं का मताधिकार चाहते हैं। राजनीतिक दल, इसलिए, स्वस्थ परंपराओं के विकास में चिंतित हैं ताकि वे "जनता का विश्वास बनाए रखें, और इसके साथ, कार्यालय और शक्ति"।

" मुझे लगता है कि यह (संविधान) व्यवहार्य है, लचीला है और यह है

शांति काल और रामेश्वर प्रसाद v दोनों में देश को एकजुट रखने के लिए पर्याप्त मजबूत।

यू. ओ. आई. [पासायत, जे।]

युद्ध के समय में। वास्तव में अगर मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर नए संविधान के तहत चीजें गलत हो जाती हैं, तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था।

हमें जो कहना होगा वह यह है कि मनुष्य नीच था।

ये शब्द डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान के मसौदे पर विचार करते हुए कहे थे। यह फैशन बन गया है, जब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जो किसी विशेष राजनीतिक दल को पसंद नहीं होती हैं, तो संविधान को दोष देना। राज्यपालों को भी अनिवार्य रूप से अपने हिस्से का दोष मिलता है, या तो यह आरोप लगाया जाता है कि वे संविधान के बारे में विकृत दृष्टिकोण रखते हैं, या, जैसा कि यह भी आरोप लगाया जाता है, क्योंकि संविधान उन्हें "असंवैधानिक" कृत्यों का सहारा लेने की अनुमति देता है। सरकार की विभिन्न शाखाओं के कामकाज से संबंधित हमारे संविधान की आवश्यक संरचना मजबूत है और सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। जिन परंपराओं या मार्गदर्शक पंक्तियों पर हमें विचार करने के लिए कहा जाता है, उन्हें इस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।

परंपराएं अनुभव और परीक्षण और त्रुटि से विकसित होती हैं। पिछले 21 वर्षों के दौरान हमारे संविधान की कार्यप्रणाली ने ऐसा कुछ नहीं होने का खुलासा किया है हमारे राजनीतिक जीवन में बहुत सारी कमजोरियाँ हैं। इस रिपोर्ट के पहले भाग में की गई चर्चाओं से कुछ कमजोरियां स्पष्ट होंगी। हमारे संविधान के तहत राज्यपाल शासन नहीं करते हैं; सरकार मंत्रिपरिषद की प्राथमिक चिंता है जो विधानमंडल और लोगों के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए,

सम्मेलनों के उद्देश्यपूर्ण विकास के लिए, राजनीतिक दलों का इच्छुक सहयोग और ऐसे सम्मेलनों का पालन करने के लिए उनकी तैयारी सर्वोपरि है। हाल के वर्षों में, कुछ राज्यों में राजनीतिक जीवन की यह एक खेदजनक विशेषता रही है कि अलग-अलग दलों की बढ़ती संख्या के साथ, जिनमें से कुछ का गठन व्यक्तिगत या समूह संरेखण के आधार पर किया जाता है, न कि परिभाषित कार्यक्रमों या नीतियों के आधार पर, कि सरकारें एक नेता-एक मुख्यमंत्री के साथ बनती हैं-जो उस पद पर अधिकार के रूप में नहीं आता है, अनुयायियों की पिछली स्वीकृति और अपने सहयोगियों के सम्मान के साथ, बल्कि उस समय के लिए सबसे "स्वीकार्य" उम्मीदवार के रूप में आता है। इसलिए, उनका अधिकांश समय और प्रयास अनिवार्य रूप से खुद को सत्ता में और मंत्रिमंडल को जीवित रखने के लिए उपाय खोजने में खर्च होते हैं।

2002 के विशेष संदर्भ संख्या 1 मामले (ऊपर) में पैराग्राफ 55 और 56 में यह निम्नानुसार देखा गया था:

" 55. तब संघ की ओर से यह आग्रह किया गया कि अनुच्छेद 174 के तहत जो भंग किया जाता है वह एक विधानसभा है जबकि जो स्थगित किया जाता है वह एक सदन है। जब विधानसभा भंग हो जाती है तब भी सदन अस्तित्व में रहता है। अध्यक्ष 798 के मामले में अनुच्छेद 94 के तहत जारी है।

[2006] आई एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लोक सभा या राज्य के मामले में अनुच्छेद 17 के तहत

नए लोक सभा या विधानसभा तक विधान सभा

गठित किया जाता है। उस आधार पर, यह आगे आग्रह किया गया कि ताजा

नई विधानसभा के गठन के लिए चुनाव कराने होंगे।
भंग विधानसभा के अंतिम सत्र से छह महीने के भीतर।

56. पहली नज़र में, तर्क बहुत आकर्षक लग रहा था, लेकिन
मामले में गहराई से जाने के बाद हमें कोई सार नहीं मिलता है

इसके बाद बताए गए कारण "

अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि का प्रावधान है। द.

संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों के चुनावों का पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के पास निहित है। अनुच्छेद 327 में प्रावधान है कि संसद निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान कर सकती है -

किसी राज्य की विधान सभा के चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में सभी मामले और विधानमंडल के सदन का उचित गठन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले। संविधान के अनुच्छेद 327 और आर. पी. अधिनियम की धारा 73 के संयुक्त पठन से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि विधानसभा का गठन किया गया था। संविधान के किसी भी प्रावधान में यह नहीं कहा गया है कि विघटन केवल विधानमंडल की पहली बैठक के बाद ही हो सकता है। एक बार आर. पी. अधिनियम की धारा 73 के संचालन से सदन या विधानसभा का गठन माना जाता है, तो इसके विघटन पर कोई रोक नहीं है।

इस दलील पर आते हुए कि कोई विधान सभा अस्तित्व में नहीं थी

जैसा कि श्री विप्लव शर्मा ने तर्क दिया है, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आर. पी. अधिनियम की धारा 73 को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज करता है। अलग से कोई प्रावधान नहीं है

संविधान में। आर. पी. अधिनियम की धारा 73 की वैधता को कोई चुनौती नहीं है, जो किसी भी तरह से आर. पी. अधिनियम के किसी भी प्रावधान के खिलाफ नहीं है।

संविधान। इस प्रकार, आर. पी. अधिनियम की धारा 73 के संचालन द्वारा विधानसभा का विधिवत गठन किया गया था। यह स्थिति कि राज्यपाल सदस्यों को शपथ दिलाने और गठन के लिए सत्र बुलाने के लिए बाध्य था

इसके बाद मंत्रिमंडल की कोई प्रासंगिकता नहीं है और यह किसी भी संवैधानिक जनादेश द्वारा समर्थित नहीं है। राज्यपाल पर सत्र बुलाने या मंत्रिमंडल की स्थापना करने की कोई बाध्यता नहीं थी जब तक कि उस संबंध में पूर्व-आवश्यकताएं पूरी नहीं की जाती थीं। राज्यपाल की रिपोर्टों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि मुख्यमंत्री चुनने या राज्यपाल के गठन के लिए सत्र बुलाना संभव नहीं था।

कैबिनेट।

भले ही काल्पनिक रूप से यह माना जाता है कि विघटन अधिसूचनाएं हैं

अस्थिर, फिर भी पूर्व स्थिति की बहाली वर्तमान मामले में नहीं है

उचित राहत। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रामेश्वर प्रसाद बनाम से पहले किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी हिस्सेदारी का दावा नहीं किया गया था।

ओवरऑल। दस्तावेजों ने यह दिखाने के लिए भरोसा किया कि बहुमत की कमी थीआसक्ति और उनमें से कुछ में हेरफेर की छाप भी है। निर्धारित कार्यक्रम एक उन्नत चरण पर पहुँच गए थे। निर्विवाद रूप से,आयोग ने विस्तृत व्यवस्था की थी। यह असमान होगाघड़ी पीछे और आंकड़ों की सीधी बहाली।पब्लिक लॉ 2005 में कुछ दिलचस्प लेख हैं जोऔर भी। वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

" न्यायिक समीक्षा-न्यायालय की अस्थायी प्रभाव को सीमित करने की शक्ति प्रशासनिक निर्णय को निरस्त करना, उस तारीख को स्थगित करना जिस पर यह प्रभाव पैदा करेगा और शून्यता की सीमा को योग्य बनाएगा। फ्रांसीसी कल्याण कानून के तहत, बेरोजगारी से संबंधित समझौते भत्ते संघों और नियोक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित निजी समझौते हैं। संघ-लेकिन वे केवल मंत्री द्वारा अनुमोदित होने पर ही लागू होते हैं

सामाजिक मामलों के लिए। फिर वे सभी के लिए अनिवार्य हो जाते हैं। कई बेरोजगारों के अधिकारों की रक्षा करने वाले संघों ने एक

इस तरह के समझौतों को मंजूरी देने वाले मंत्रिस्तरीय निर्णयों के खिलाफ कार्रवाई। ठहराव दिया गया। फैसलों को प्रक्रियात्मक आधार पर रद्द कर दिया गया था

परामर्श और जिस तरह से परामर्श हुआ। इन मुद्दों पर जिस तारीख को यह रद्द किया जाएगा, उससे संबंधित हिस्सेदारी

बल और उसके प्रभाव। मामला बेहद संवेदनशील था।

सामाजिक और राजनीतिक रूप से; बेरोजगारी का दायरा और मात्रा

भत्ते। कुछ भी नहीं कहने के लिए आवेदन का नेतृत्व किया होगा सिद्धांत जिसके अनुसार शून्यता पूर्वव्यापी है। रद्द किया गया फैसला माना जाता है कि कभी अस्तित्व में नहीं था। इसलिए इसे बनाए रखना असंभव है। एक निश्चित समय के लिए इसका प्रभाव। ये हैं सख्त शर्तेंइसके निर्णय के व्यावहारिक परिणाम, न केवल पक्षों के लिए, बल्कि एक बड़ी जनता के लिए, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र में। ये होते हैं परिणाम यह न केवल एक सार्वजनिक सेवा के कामकाज को प्रभावित कर सकता है, बल्कि व्यक्तियों के अधिकार। वे एक कानूनी शून्य और सामाजिक तबाही पैदा कर सकते हैं।

इसलिए अदालत को अनुमति देने का विचार, जब यह एक प्रशासनिक आदेश को रद्द कर देता है। निर्णय, अपने निर्णय में विशिष्ट आदेशों को शामिल करना कि क्या और कब रद्द करने से

प्रभाव पड़ेगा और, यदि ऐसा है, तो कौन से व्यक्ति दोनों यूरोपीय अदालतों द्वारा एक लंबा समय। यूरोपीय मानव न्यायालय मार्क्स बनाम में सही 'निर्णय। बेल्जियम (1979-80) 2 E.H.R.R. 330, एक [2006] 1 एस. सी. आर है।

उपयुक्त चित्रण। जहां तक ई. सी. जे. की बात है, इसका मोटे तौर पर दूसरा अर्थ है

कला का अनुच्छेद। 231 ईसी (पूर्व में Art.174) जिसके अनुसार: " तथापि, किसी विनियम के मामले में, न्याय न्यायालय, यदि वह इसे आवश्यक समझता है, तो यह बताएगा कि जिस विनियम को उसने शून्य घोषित किया है, उसके प्रभावों में से किसे निश्चित माना जाएगा। यह

पूर्व टनक प्रभाव का अपमान न केवल विनियमों से संबंधित मामलों में, बल्कि संबंधित प्रारंभिक निर्णयों में भी लागू किया गया है।

व्याख्या (केस सी-43/75 डेफ्रेने बनाम। सबीना, (1976 ई. सी. आर. 455; केस सी-61/79 डेंकजावित इटालियाना (1980 ई. सी. आर. 1205: केस सी-4/79 सोसाइटी कोऑपरेटिव प्रोविडेंस एग्रीकोल डी ला शैम्पेन (1980 ईसीआर 2823;

केस सी-109/79 मैसीज़ डी ब्यूस (1980 ई. सी. आर. 2882; मामला-145/79 सोसाइटी रोक्वेट फ्रेरेस (1980 ई. सी. आर. 2917), निर्देश (मामला सी-295/90 यूरोपीय संसद बनाम। परिषद (1992 ई. सी. आर. I-4193) और निर्णय (मामला सी-22/96) यूरोपीय संसद बनाम परिषद (1998 ई. सी. आर. 1-3231)। ई. सी. जे. ने अभिनिर्धारित किया कि इस तरह की शक्ति का उपयोग करने के लिए उचित था

"दांव पर लगे सभी सार्वजनिक और निजी हितों से संबंधित कानूनी निश्चितता के कठोर विचार" को ध्यान में रखते हुए। हालाँकि, ऐसा करने में, न्यायालय के निर्णय याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को नुकसान पहुँचा सकते हैं जो वे चाहते थे कि अदालत अपने फैसले पर पहुंचे। इसलिए कई राष्ट्रीय उच्च न्यायालयों के असहमत निर्णय, जैसे कि इतालवी

संवैधानिक न्यायालय (21 अप्रैल, 1989, फ्रैगड) और काउंसिल डी 'एटैट (28 जून, 1985, ऑफिस नेशनल इंटरप्रोफेशनल डेस अनाज ओ सोसाइटी मैसरीज़ डी ब्यूस, कॉन्क्ल। जेनेवोइस, आरटीडीई, 1986,145; 26 जुलाई, 1985; ऑफिस नेशनल इंटरप्रोफेशनल डेस अनाज, p.233, कॉन्क्ल। जेनेवोइस

ए. जे. डी. ए., 1985; 13 जून, 1986, ऑफिस नेशनल इंटरप्रोफेशनल डेस

अनाज, कॉनक्ल। बोनिचोट, आर. टी. डी. ई. 1986,533)। यही कारण है कि ई. सी. जे. ने उन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ सावधानी बरती जिन्होंने पहले कोई कार्रवाई या समकक्ष दावा किया था। ई. सी. जे. के कुछ निर्णयों के कारण ई. सी. संधि में विशेष खंडों को

शामिल किया गया, जैसा कि मामला सी-262/88 नाई बनाम में ई. सी. जे. के फैसले के बाद मास्ट्रिच संधि प्रोटोकॉल 2 ("नाई घोषणा") द्वारा दिखाया गया है। गार्जियन रॉयल एक्सचेंज एस्योरेंस ग्रुप (1991) 1 क्यू. बी. 344)। यह प्रोटोकॉल अनुच्छेद 141 ईसी के प्रभावों को सीमित करता है (17 मई, 1990 से पहले)। ई. सी. जे. इस तरह की शक्तियों का उपयोग करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले विचारों पर स्पष्ट रहा है। वे, कुल मिलाकर, कानूनी निश्चितता लेटो सेंसु से संबंधित हैं, यानी मौजूदा कानूनी स्थितियों पर इसके निर्णय के ठोस प्रभावों और कानूनी शून्य के निर्माण से बचने की वांछनीयता से। कई यूरोपीय संवैधानिक न्यायालयों के पास एक समान शक्ति है।

काउंसिल डी 'एटैट ने कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि उसके पास ऐसा संकाय है। यह 801 था।

27 जुलाई, 2001, तीत्रान, पी. 411) एसोसिएशन ए. सी. में, एक मामला जिसने इस तरह के कदम के लिए खुद को उधार दिया, काउंसिल डी 'एटैट ने नया करने और प्रशासनिक अदालतों को नया देने का फैसला किया।

शक्तियाँ। पुष्टि किए गए नए सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

1. सिद्धांत यह है कि एक रद्द किए गए प्रशासनिक निर्णय का अस्तित्व कभी नहीं माना जाता है।

निर्णय और इस प्रकार बनाई गई स्थितियों के बारे में और (बी) सामान्य हित जो इसके प्रभावों को अस्थायी रूप से बनाए रखना वांछनीय बना सकते हैं।

3. यदि ऐसा है, तो प्रशासनिक न्यायालयों को समय पर रद्द करने के प्रभावों की सीमा के बारे में विशिष्ट निर्णय लेने का अधिकार है।

4. वे निर्णय की वैधता से संबंधित सभी आधारों की जांच करने और इस तरह की सीमा पर पक्षों से उनकी राय पूछने के बाद ऐसा कर सकते हैं।

5. उन्हें (क) सार्वजनिक और निजी हितों के लिए रद्द करने की पूर्व सक्रियता के परिणामों और (ख) वैधता के सिद्धांत और एक प्रभावी उपचार के अधिकार पर ऐसी सीमा के प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए।

6. इस तरह की सीमा असाधारण होनी चाहिए।

7. अदालत के समक्ष कार्रवाई करने वाले व्यक्तियों के अधिकार रद्द किए गए निर्णय के खिलाफ निर्णय को संरक्षित किया जाना चाहिए।

8. अदालत यह तय कर सकती है कि निर्णय के सभी या आंशिक प्रभाव इसके रद्द होने से पहले निश्चित माना जाएगा, या कि रद्द करना बाद में लागू होगा जैसा कि द्वारा निर्धारित किया गया है निर्णय।

वर्तमान मामले में परिषद ने कई को रद्द कर दिया मंत्रिस्तरीय निर्णय। इसने अन्य को भी रद्द कर दिया, लेकिन केवल जुलाई से 1 इसके बाद मंत्री को सात सप्ताह का समय दिया जाता है। के अधिकार जिन व्यक्तियों ने पहले कोई कार्रवाई की थी, उन्हें स्पष्ट रूप से संरक्षित किया गया था। रद्द किए गए निर्णयों के तीसरे समूह के प्रभावों को घोषित किया गया था उसी आरक्षण के साथ निश्चित रहें।

इस महत्वपूर्ण फैसले पर कई टिप्पणियां क्रम में हैं। द. ई. सी. जे. के मामले के कानून का प्रभाव और इसके एक्स एन. यू. एन. सी./एक्स टनक के उपयोग का प्रभाव प्रभाव स्पष्ट है। यह फैसला नवीनीकरण का भी एक उपयुक्त उदाहरण है। प्रशासनिक न्यायालयों की भूमिका की अवधारणा। अब नहीं निर्णय दिए जाने पर रुक जाता है। अधिक से अधिक ध्यान दिया जाता है प्रशासन द्वारा लागू किया गया और अधिकारों पर इसके प्रभाव व्यक्तियों से। इसलिए तरीकों और साधनों पर ध्यान दिया जाता है वैधता और कानूनी निश्चितता के दो बुनियादी सिद्धांतों का मिलान करना। (प्रतिभूति न्यायिक)। उत्तरार्द्ध को अधिक से अधिक दबाव के रूप में देखा जाता है। सामाजिक आवश्यकता, यूरोपीय न्यायालय की शब्दावली को उधार लेने के लिए

मानवाधिकार। एक मजबूत उदाहरण न्यायालय का हालिया मामला कानून है। डी कैसेशन न केवल लॉइस डी वैलिडेशन के दायरे को सीमित करता है बल्किलेखों के आधार पर पूर्वव्यापी "व्याख्यात्मक कानूनों" का भी

6 (1) और 13 ईसीएचआईआर: कैस को देखें। प्लैन। जनौरी 24,2003, एम. एम. ए. एक्स. ओ. एसोसिएशन प्रमोशन डेस हैंडिकेप्स डैन्स ले लॉरैट, और कैस। सिविल. 7 अप्रैल, 2004, बुलेटिन डी 'इन्फॉर्मेशन डी ला कोर्ट डी कैसेशन, मार्च में 15 , 2004 , एम्मे फेवरे की रिपोर्ट के साथ। अदालतों का विवेकाधिकार एक दो गुना है; इस पर कि क्या इस तरह के संकाय का उपयोग करना है और कैसे करना है इसका उपयोग करें। एक अंतिम-संभावित-टिप्पणी: अगला कदम हो सकता है अदालतों द्वारा सीमा। मामले में परिवर्तन के समय के प्रभाव कानून? "एन ऊपर।जहाँ तक राज्यपाल को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 361 का दायरा रामेश्वर प्रसाद v है। संबंधित, मैं भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सम्मानजनक रूप से सहमत हूं।

(1) अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा न्यायिक समीक्षा के लिए खुली है, लेकिन बहुत सीमित सीमा तक। केवल तभी जब शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण या आधारित हो पूरी तरह से बाहरी

या अप्रासंगिक आधारों पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत जो तब लागू होते हैं जब प्रशासनिक कार्रवाई को चुनौती दी जाती है, इसे सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है।

(2) विवादित अधिसूचनाएँ किसी भी संवैधानिक अयोग्यता से ग्रस्त नहीं हैं। यदि राज्यपाल ने बहुमत के बारे में दावा करने से रोकने की कोशिश की होती जो संविधान और अधिसूचनाओं के खिलाफ होती। विघटन अमान्य होता। लेकिन, राज्यपाल ने इस आधार पर विघटन की सिफारिश की कि प्रस्तावित बहुमत की नींव अनैतिक और भ्रष्ट साधनों पर थी जो बहुमत को साधने के लिए अपनाए गए थे और अपनाए जा रहे थे, और ऐसी कार्रवाई संवैधानिक नहीं है। यह गलत हो सकता है राज्यपाल की धारणा। लेकिन यह उसका कर्तव्य है कि वह एक की स्थापना को रोके

मंत्रिमंडल जहाँ बहुमत को उपरोक्त तरीके से जोड़ा गया है। यह एक दिए गए मामले में एक गलत दृष्टिकोण हो सकता है, यह एक गलत धारणा हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से तर्कहीन या अप्रासंगिक या बाहरी नहीं है।

(3) एक जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है जहां लिया गया रुख उन लोगों द्वारा लिए गए रुख के विपरीत था जो किसी भी स्थिति से प्रभावित हैं। कार्रवाई। ऐसे मामले में जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यही यहाँ का मामला है।

(4) काल्पनिक रूप से भले ही यह कहा जाता है कि विघटन अधिसूचनाएँ

अगर यह असंवैधानिक था, तो इसका स्वाभाविक परिणाम पूर्व की यथास्थिति की बहाली नहीं है। विघटन अधिसूचनाओं को अमान्य घोषित करने वाला न्यायालय जमीनी वास्तविकताओं और प्रासंगिक कारकों का आकलन कर सकता है और परिस्थितियों के अनुसार राहतों को ढाल सकता है। वर्तमान मामले में पूर्व की स्थिति को बहाल करना उचित राहत नहीं होती, भले ही अधिसूचनाएं जारी की गई हों।

अमान्य घोषित किया गया।

(5) विधानसभा का गठन आर. पी. अधिनियम की धारा 73 के अनुसार किया गया है।

उसमें दर्शाई गई शर्तों को पूरा करने पर और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी भी तरह से उक्त के विपरीत या प्रतिकूल हो।

प्रावधान। इसके विपरीत, संविधान का अनुच्छेद 327 धारा 73 के अधिनियमन के लिए शक्ति का स्रोत है।

(6) अनुच्छेद 361 के संदर्भ में राज्यपाल को पूर्ण प्रतिरक्षा प्राप्त है। राज्यपाल शक्तियों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है और 804 उसके

पद के कर्तव्यों या उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए। हालांकि, इस तरह की प्रतिरक्षा कार्रवाई की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय की शक्ति को छीन लेती है, जिसमें शामिल हैं - दुर्भावना की जमीन।

(7) यह अनिवार्य और आवश्यक हो गया है कि सही व्यक्ति यदि किसी राज्य के एक्सई के प्रमुख के रूप में पद की पवित्रता को बनाए रखना है तो राज्यपाल के रूप में चुना जाता है। तदनुसार रिट आवेदनों को खारिज कर दिया जाता है लेकिन बिना किसी कारण के।

लागतों के बारे में।

लेखन याचिकाओं का

निपटान

जीएन.